VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

अर्थव्यवस्था

क्लासरूम स्टडी मटेरियल 2025

जून 2024 से मई 2025

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /visionias_upsc vision_ias /VisionIAS_UPSC www.visionias.in

ENGLISH MEDIUM
1 July | 5 PM

हिन्दी माध्यम
5 July | 5 PM

- द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
- मुख्य परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
- मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक वर्ष की समसामयिक घटनाओं की खंड–वार बुकलेटस (ऑनलाइन स्टूडेंटस के लिये मेटेरियल केवल सॉफ्ट कॉपी में ही उपलब्ध)
- लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यार्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग मे लचीलापन चाहते हैं।

मुख्य परीक्षा
2025 के लिए 1 वर्ष का
समसामयिक घटनाक्रम
केवल 60 घंटे में

UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

10 in Top 10 Selections in CSE 2024 (from various programs of VISIONIAS)

हिन्दी माध्यम में 30+ चयन

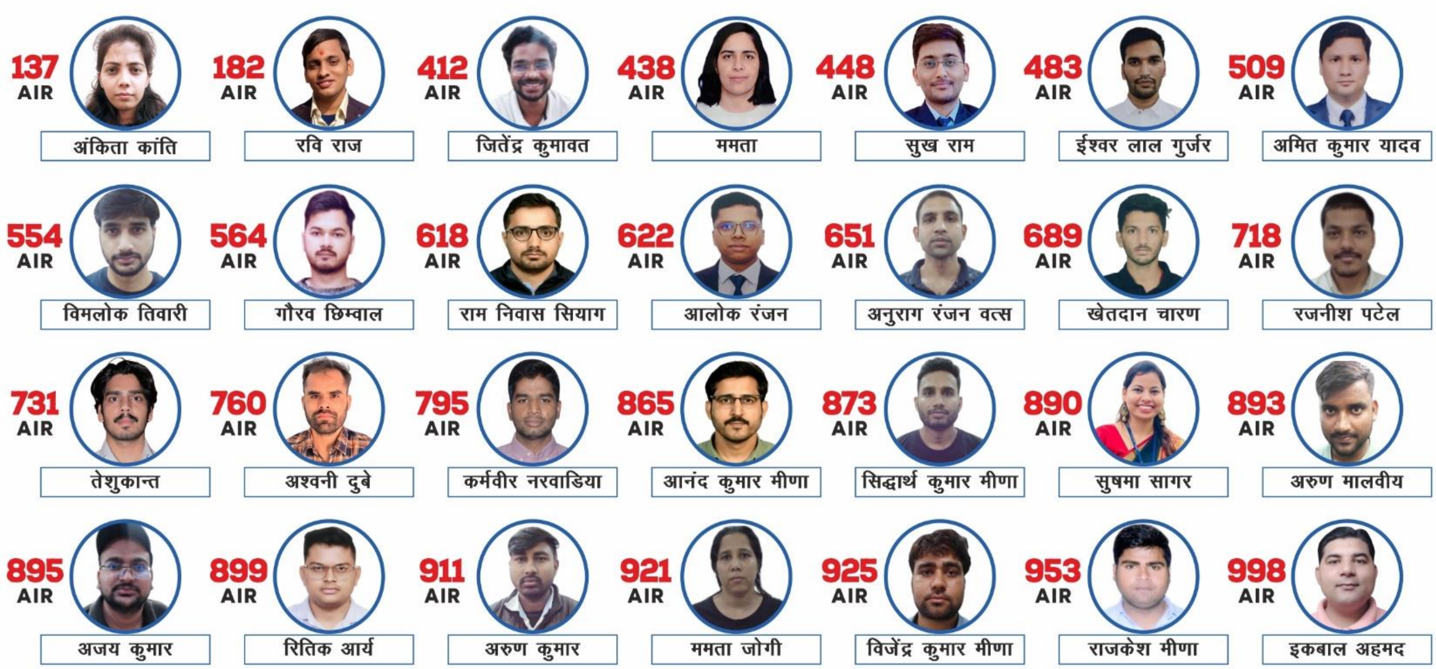

अर्थव्यवस्था (Economy)

विषय-सूची

1. भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त विवरण (Snapshot of Indian Economy) 7

1.1. भारतीय अर्थव्यवस्था: एक नज़र में 7
1.2. भारत का संरचनात्मक परिवर्तन 8
1.3. मुख्य शब्दावलियां 9
1.4. अभ्यास प्रश्न 9

2. संवृद्धि एवं विकास (Growth and Development) 10

2.1. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES), 2023-24 10
2.2. समावेशी विकास: एक नज़र में 11
2.3. 'संवृद्धि के अग्रदूत' के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र 11
2.4. मिडिल इनकम ट्रैप 14
2.5. भारत में निर्धनता: एक नज़र में 15
2.5.1. भारत में गरीबी मापन हेतु मौजूदा फ्रेमवर्क 15
2.5.2. शहरी गरीबी 16
2.6. आर्थिक संकेतक 18
2.6.1. GDP के आधार वर्ष में संशोधन 18
2.6.2. WPI के आधार वर्ष की समीक्षा 19
2.7. वित्तीय समावेशन 21
2.7.1. भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति: एक नजर में 21
2.7.2. प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के 10 वर्ष 21
2.7.3. माइक्रोफाइनेंस के 50 वर्ष 23
2.7.4. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): एक नज़र में 25
2.8. असमानता 26
2.8.1. भारत में आर्थिक असमानता: एक नज़र में 26
2.8.2. विकास में क्षेत्रीय असमानता 26
2.9. ग्रामीण विकास 28
2.9.1. ग्रामीण औद्योगीकरण: एक नज़र में 28
2.9.2. ग्रामीण विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका 28
2.10. भूमि सुधार: एक नज़र में 30
2.10.1. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण 30
2.11. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 32
2.12. मुख्य शब्दावलियां 33
2.13. अभ्यास प्रश्न 34

3. रोजगार, श्रम और कौशल विकास (Employment, Labour, and Skill Development) 35

3.1. बेरोजगारी: एक नज़र में 35
3.1.1. संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 35
3.1.2. वेतन वृद्धि में ठहराव 37
3.2. गिग इकॉनमी 37
3.3. कौशल विकास 39
3.3.1. कौशल विकास: एक नज़र में 39
3.3.2. विश्व में कार्यबल संबंधी कमियों से निपटना 40
3.4. मुख्य शब्दावलियां 41
3.5. अभ्यास प्रश्न 42

4. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) 43

4.1. राज्य वित्त 43
4.2. प्रत्यक्ष कराधान: एक नज़र में 45
4.2.1. एंजेल टैक्स 45
4.2.2. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ 46
4.2.3. इक्विलाइजेशन लेवी 47
4.3. वस्तु एवं सेवा कर: एक नज़र में 49
4.4. मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क 49
4.5. मुख्य शब्दावलियां 50
4.6 अभ्यास प्रश्न 51

5. बैंकिंग, भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार (Banking, Payment Systems and Financial Markets) 52

5.1. भारत में बैंकिंग क्षेत्रक: एक नज़र में 52
5.1.1. तरलता घाटा 52
5.1.2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार (PSL) संबंधी मानदंड में संशोधन 53
5.1.3. एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 55
5.1.4. सहकारी बैंक: एक नज़र में 57
5.1.5. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs): एक नज़र में 58
5.2. वित्तीय बाजार 59
5.2.1. भारत में पूंजी बाजार: एक नज़र में 59
5.2.2. वित्तीयकरण 59
5.3. भुगतान प्रणाली: एक नज़र में 60
5.3.1. डिजिटल भुगतान: एक नज़र में 61
5.3.2. सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा 61

© Vision IAS

5.3.3. UPI का अंतर्राष्ट्रीयकरण ____ 63
5.3.4. सीमा-पार भुगतान: एक नज़र में ____ 64
5.4. मुख्य शब्दावलियां ____ 64
5.5. अभ्यास प्रश्न ____ 65
6. बाह्य क्षेत्रक (External Sector) ____ 66
6.1. भारत का निर्यात क्षेत्रक: एक नज़र में ____ 66
6.2. बड़े व्यापार समझौतों का महत्व ____ 66
6.3. भारत का मुक्त व्यापार समझौता ____ 67
6.4. द्विपक्षीय निवेश संधि ____ 69
6.5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ____ 70
6.5.1. FPI का FDI के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए फ्रेमवर्क ____ 71
6.6. वैश्विक मूल्य श्रृंखला: एक नज़र में ____ 72
6.7. संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि ____ 72
6.8. दोहरा कराधान परिहार समझौता ____ 74
6.9. भारत में विप्रेषण: एक नज़र में ____ 75
6.10. रुपये का मूल्यह्रास ____ 75
6.11. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण: एक नज़र में ____ 77
6.12. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग ____ 77
6.13. भारत और विश्व व्यापार संगठन: एक नज़र में ____ 79
6.14. मुख्य शब्दावलियां ____ 79
6.15. अभ्यास प्रश्न ____ 80
7. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (Agriculture and Allied Activities) ____ 81
7.1. कृषि क्षेत्रक: एक नज़र में ____ 81
7.1.1. प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना ____ 81
7.1.2. डिजिटल कृषि मिशन: एक नज़र में ____ 82
7.1.3. कृषि निर्यात: एक नज़र में ____ 83
7.1.4. मखाना ____ 83
7.1.5. कपास उत्पादकता मिशन ____ 85
7.1.6. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-तिलहन) ____ 86
7.2. कृषि विपणन: एक नज़र में ____ 87
7.3. कृषि विस्तार प्रणाली ____ 88
7.4. कृषि आदान ____ 90
7.4.1. कृषि आदान (इनपुट): एक नज़र में ____ 90
7.4.2. कृषि ऋण:एक नज़र में ____ 92
7.4.2.1. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) ____ 92
7.5. संबद्ध क्षेत्रक ____ 94
7.5.1. पशुधन क्षेत्रक: एक नज़र में ____ 94
7.5.2. भारत का डेयरी सहकारी क्षेत्रक ____ 94
7.5.3. भारत में बागवानी क्षेत्रक: एक नज़र में ____ 96
7.5.4. मात्स्यिकी क्षेत्रक: एक नज़र में ____ 97
7.6. किसान उत्पादक संगठन: एक नज़र में ____ 98
7.7. अनाज भंडारण और खाद्य सुरक्षा ____ 98
7.7.1. भारत की अनाज भंडारण प्रणाली ____ 98
7.7.2. भारतीय खाद्य निगम ____ 99
7.7.2.1. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) ____ 100
7.7.3. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक: एक नज़र में ____ 102
7.8. मुख्य शब्दावलियां ____ 102
7.9. अभ्यास प्रश्न ____ 103
8. उद्योग एवं औद्योगिक नीति (Industry and Industrial Policy) ____ 104
8.1. मेक इन इंडिया के 10 वर्ष ____ 104
8.2. MSME क्षेत्रक: एक नज़र में ____ 106
8.3. राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम ____ 106
8.4. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना: एक नज़र में ____ 108
8.4.1. भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्रक ____ 109
8.5. भारत की जैव अर्थव्यवस्था: एक नज़र में ____ 110
8.6. तकनीकी वस्त्र: एक नज़र में ____ 111
8.7. मुख्य शब्दावलियां ____ 111
8.8. अभ्यास प्रश्न ____ 112
9. सेवा क्षेत्रक (Services) ____ 113
9.1. भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था ____ 113
9.2. क्रिएटिव इकोनॉमी: एक नज़र में ____ 114
9.3. भारत में पर्यटन क्षेत्रक: एक नज़र में ____ 115
9.4. भारत में बीमा क्षेत्रक: एक नज़र में ____ 116
9.5. अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था: एक नज़र में ____ 116
9.6. मुख्य शब्दावलियां ____ 117
9.7. अभ्यास प्रश्न ____ 117
10. अवसंरचना (Infrastructure) ____ 118
10.1. भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) फ्रेमवर्क: एक नज़र में ____ 118
10.2. लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स/ LEADS) 2024 ____ 119

10.3. पारगमन उन्मुख विकास: एक नज़र में ____________ 120
10.4. रेलवे ____________ 120
10.4.1. रेलवे में सुधार ____________ 120
10.4.2. भारतीय रेलवे की सुरक्षा ____________ 122
10.5. बंदरगाह और जलमार्ग ____________ 123
10.5.1. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ____________ 123
10.5.2. राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025 ____________ 124
10.6. सड़क सुरक्षा: एक नज़र में ____________ 126
10.7. मुख्य शब्दावलियां ____________ 126
10.8. अभ्यास प्रश्न ____________ 127
11. खनन गतिविधियां एवं अन्य संसाधन (Mining and other Resources) ____________ 128
11.1. राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन ____________ 128
11.2. प्रमुख एवं लघु खनिज ____________ 130
11.2.1. जिला खनिज फाउंडेशन ____________ 131
11.2.2. भारत में अपतटीय खनिज ____________ 132
11.3. भारत में कोयला क्षेत्रक: एक नज़र में ____________ 133
11.4. भारत में इस्पात क्षेत्रक: एक नज़र में ____________ 134
11.5. मुख्य शब्दावलियां ____________ 134
11.6. अभ्यास प्रश्न ____________ 135
12. नवाचार और उद्यमिता (Innovation and Entrepreneurship) ____________ 136
12.1. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ____________ 136
12.2. डीप टेक के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम ____________ 137
12.2.1. भारत में अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र: एक नज़र में ____________ 139
12.3. वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2024 और सामाजिक उद्यमिता ____________ 139
12.4. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या वैश्विक क्षमता केंद्र ____________ 141
12.5. मुख्य शब्दावलियां ____________ 142
12.6. अभ्यास प्रश्न ____________ 142
13. अर्थव्यवस्था: विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न (2013-2024) - (सिलेबस के अनुसार) {Economy Previous Year Question 2013-2024 (Syllabus-Wise)} ____________ 143
14. परिशिष्ट: प्रमुख आंकड़े एवं तथ्य (Appendix: Key Data and Facts) ____________ 157

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा **2026**

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

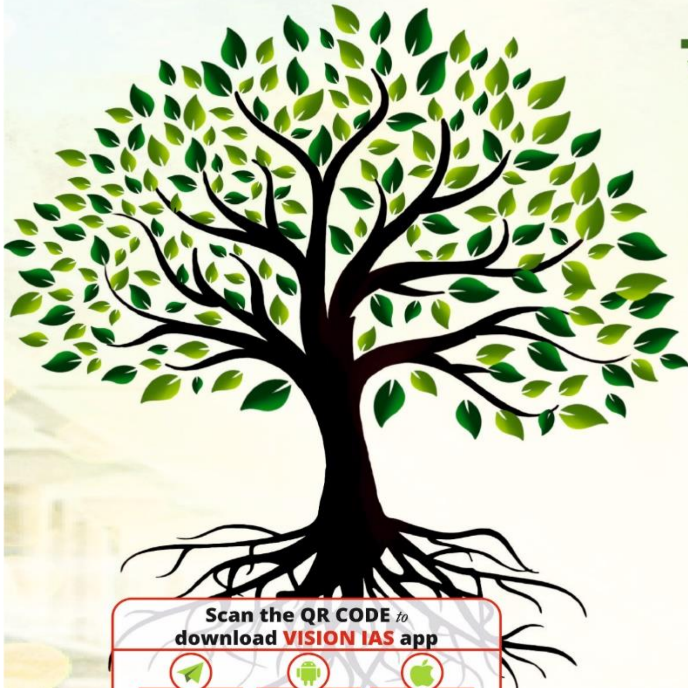

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

Scan the QR CODE *to* download **VISION IAS** app

DELHI : 15 जुलाई, 2 PM | **JAIPUR : 24 जून** | **JODHPUR : 2 जुलाई**

Lakshya

MAINS MENTORING PROGRAM 2025

45 Days Expert Intervention

A Strategic Revision, Practice, and Mentoring Program for UPSC Prelims Examination

10 JULY 2025

- Highly experienced and qualified team of Mentors for continuous support and guidance
- A structured plan of revision for GS Prelims, CSAT, and Current Affairs
- Effective Utilization of learning resources, including PYQs, Quick Revision Modules (QRMs), and PT-365

Lakshya

PRELIMS & MAINS INTEGRATED MENTORING PROGRAM

Lakshya Prelims & Mains Integrated Mentoring Program 2026

(A Strategic Revision, Practice, and Mentoring Program for UPSC Prelims and Mains Examination 2026)

VisionIAS introduces the Lakshya Prelims & Mains Integrated Mentoring Programme 2026, offering unified guidance for UPSC aspirants across both stages, ensuring comprehensive support and strategic preparation for success

2026 | **14 MONTHS** | **2 JULY**

Highlights of the Program

- Coverage of the entire UPSC Prelims and Mains Syllabus
- Highly experienced and qualified team of senior mentors
- Development of Advanced answer writing skills
- Special emphasis to Essay & Ethics

भूमिका

अभ्यर्थियों के लिए संदेश

UPSC सिविल सेवा मुख्य परीक्षा केवल ज्ञान का परीक्षण नहीं है, बल्कि यह सटीकता, स्पष्ट अभिव्यक्ति और स्मार्ट रिवीजन की एक कठिन कसौटी है। **सामान्य अध्ययन पेपर-III** के विशाल सिलेबस में 'अर्थव्यवस्था' खंड निरंतर रूप से अंक वृद्धि में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए **VISION IAS प्रस्तुत करता है — *Mains 365: अर्थव्यवस्था,*** एक सुविचारित, संक्षिप्त और परीक्षा-केंद्रित डॉक्यूमेंट जो आपकी अंतिम तैयारी का भरोसेमंद साथी है।

यह केवल समसामयिक आर्थिक घटनाओं का संकलन नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साधन है जो उत्तर लेखन की गुणवत्ता सुधारने, वर्तमान आर्थिक परिप्रेक्ष्य को सैद्धांतिक स्पष्टता के साथ जोड़ने और अंतिम चयन में निर्णायक भूमिका निभाने वाले अतिरिक्त अंकों को अर्जित करने में आपकी मदद करता है। **विषय-आधारित वर्गीकरण, उन्नत विश्लेषण** और **तत्काल उपयोग योग्य वाले कंटेंट** के साथ यह संकलन परीक्षा के अंतिम दिनों में भी तेज़, प्रभावी और समग्र रिवीजन को संभव बनाता है। ***"Mains 365: अर्थव्यवस्था"*** डॉक्यूमेंट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह आपकी तैयारी को न सिर्फ गति देता है, बल्कि आपको परीक्षा में रणनीतिक बढ़त भी दिलाता है।

रिवीजन में स्पष्टता, उत्तरों में धार, और सफलता की दिशा—इन सभी के लिए यह डॉक्यूमेंट आपका मुख्य मार्गदर्शक बन सकता है।

प्रश्न 1. अच्छे-खासे पढ़े-लिखे अभ्यर्थी भी GS-III अर्थशास्त्र में संघर्ष क्यों करते हैं?

- **बिखरे हुए स्रोत:** कई स्रोतों के उपयोग से संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है।
- **स्टैटिक-डायनामिक का एकीकरण न होना:** केवल सिद्धांत जानना पर्याप्त नहीं होता; उत्तर में वास्तविक उदाहरणों की कमी से जवाब सतही हो जाते हैं।
- **उबाऊ डेटा:** तथ्य तो बहुत हैं, लेकिन उन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करना है, यह कम ही लोगों को आता है।
- **अवधारणाओं को रटना:** विश्लेषणात्मक फ्रेमवर्क के बिना, सबसे अच्छा डेटा भी UPSC को प्रभावित करने में विफल रहता है।

"Mains 365: अर्थव्यवस्था" डॉक्यूमेंट को इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रश्न 2. GS पेपर-III (अर्थव्यवस्था) में यह डॉक्यूमेंट आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

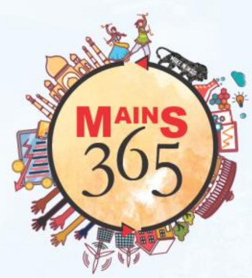

- यह UPSC की मांगों के अनुरूप इंटरलिंक्ड और विश्लेषणात्मक उत्तर लिखने की आदत विकसित करता है — जैसे कि गिग इकोनॉमी का सामाजिक सुरक्षा से संबंध, या WPI बेस रिविज़न का मुद्रास्फीति पर प्रभाव।
- सार्वजनिक निवेश, भूमि सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), स्किल इंडिया जैसे हर टॉपिक को करेंट अफेयर्स से जोड़कर **संदर्भ→विश्लेषण→आगे की राह /निष्कर्ष** के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
- **इन्फोग्राफिक्स, टैग टेबल** और डेटा बॉक्स आपको **तेजी से याद करने और समय-सीमा में धारदार उत्तर लिखने** में मदद करते हैं।

प्रश्न 3. यह उत्तर लेखन को कैसे बेहतर बनाता है?

- आइये इसे एक प्रश्न से समझते हैं: "भारत की असंगठित अर्थव्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFIs) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इस भूमिका को निभाने में वे किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करते हैं? उनकी प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु उपयुक्त उपाय सुझाइए।"
- **उत्तर: Mains 365 – अर्थव्यवस्था** आपको ऐसे प्रश्नों का उत्तर सटीकता और आत्मविश्वास से लिखने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए:

'परिचय' यहां से जोड़ा जा सकता है:

2.7.3. माइक्रोफाइनेंस के 50 वर्ष (50 Years of Microfinance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वरोजगार महिला संघ (SEWA) बैंक की 50वीं वर्षगांठ **भारत में माइक्रोफाइनेंस संस्था (MFI) के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक** है। गौरतलब है कि SEWA बैंक की स्थापना 1974 में **गुजरात** में एक **सहकारी बैंक** के रूप में हुई थी।

मुख्य भाग-1 यहां से:

माइक्रोफाइनेंस क्या है?

- **परिभाषा:** माइक्रोफाइनेंस, जिसे सूक्ष्म ऋण भी कहा जाता है, एक वित्तीय सेवा है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों और छोटे व्यवसायों को ऋण जैसी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
- **सेवाएं:** ये संस्थाएं मुख्य रूप से गरीब परिवारों और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करती हैं, लेकिन कुछ माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं जमा भी स्वीकार करती हैं, वहीं कुछ संस्थाएं बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करती हैं। कुछ संस्थाएं वित्तीय प्रबंधन के लिए अपने ग्राहकों को सलाह और प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं।

भारत में माइक्रोफाइनेंस का महत्व

- **गरीबी उन्मूलन:** NABARD का **स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP)** विश्व का सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम **17.8 करोड़ परिवारों को 144 लाख** से अधिक SHGs के माध्यम से सशक्त बना रहा है।
- **उद्यमिता को बढ़ावा:** माइक्रोफाइनेंस ऋणों में से 46% ऋण ऐसे परिवारों को दिए जाते हैं जिनकी मासिक आय 20,000 रुपये से कम है, ताकि **वे अपनी आय सृजन गतिविधियों और संपत्तियों (जैसे- पशुधन)** के प्रबंधन के लिए **कार्यशील पूंजी प्राप्त कर सकें।**
- **महिला सशक्तीकरण:** 88% SHGs महिलाओं द्वारा संचालित हैं, जैसे **केरल में कुदुम्बश्री।**
- **वित्तीय समावेशन:** माइक्रोफाइनेंस उन समुदायों की आर्थिक मदद करता है जो किन्हीं वजहों से पारंपरिक बैंकों से जुड़ नहीं पाए हैं।
  - पिछले दस वर्षों में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के ग्राहकों की संख्या में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। ये संस्थाएं वित्त वर्ष 2024 में 140 मिलियन परिवारों को सेवाएं प्रदान कर रही थीं।
- **सामाजिक प्रभाव:** जैसे- **उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक** की **'छोटे कदम'** पहल ने कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) और अस्पतालों का नवीनीकरण करके स्वास्थ्य-देखभाल क्षेत्र में अहम योगदान दिया है।

मुख्य भाग-2 यहां से:

भारत में माइक्रोफाइनेंस के समक्ष चुनौतियां

- **ऋण जाल में फंसना:** MFIs के पास जितना भी पैसा उधार देने के लिए है, उसमें से लगभग 8 से 10 प्रतिशत ऐसे लोगों को दिया गया है जिन्होंने पहले से ही चार या उससे ज्यादा जगहों से कर्ज ले रखा है। ये संस्थाएं **आमतौर पर 12% से 30% ब्याज दर** पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करती हैं।
- **विनियमन और गवर्नेंस:** भारत में **माइक्रोफाइनेंस बैंक का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा** किया जाता है, जबकि राज्य सरकारें **राज्य सहकारी** समिति अधिनियमों (सहकारी बैंकों के लिए) के तहत माइक्रोफाइनेंस सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों को विनियमित करती हैं।
- **ऋण के बदले कोलेटरल (गिरवी) नहीं रखना और ऋण वापस नहीं मिलने का जोखिम:** NPAs में वृद्धि।
- **माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं का लंबे समय तक संचालन पर संदेह:** ये संस्थाएं सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं लेकिन इससे इन्हें अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं होता है। केवल कुछ संस्थाएं ही लाभ अर्जित कर रही हैं। जाहिर है कि लंबे समय में इनका संचालन प्रभावित होगा।

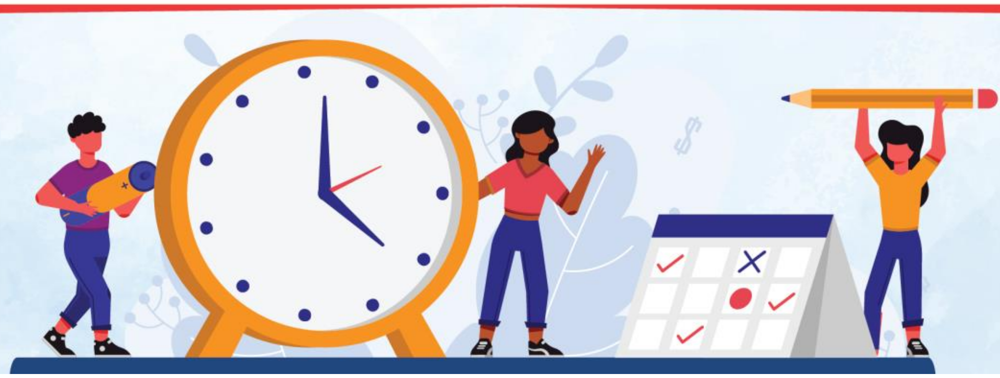

उत्तर को और प्रभावी बनाने के लिए इन्फोग्राफिक

माइक्रोफाइनेंस (सूक्ष्म वित्त) को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

SHG-बैंक लिंकेज:	मुद्रा योजना:	NBFC-MFI लचीलापन:	RBI फ्रेमवर्क (2022):	NABARD पुनर्वित्त:
उत्पादन आधारित ऋण को बढ़ावा देता है।	छोटे व्यवसायों के लिए 20 लाख तक का जमानत-मुक्त (कोलेटरल फ्री) माइक्रो क्रेडिट प्रदान करती है।	RBI (2014) ने NBFC-MFIs को बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के रूप में कार्य करने की अनुमति दी।	माइक्रोफाइनेंस ऋण और पुनर्भुगतान मानदंड परिभाषित किए गए।	MFIs को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

'आगे की राह' यहां से:

आगे की राह

- **प्रत्येक आवेदक को अधिकतम चार की बजाय केवल तीन संस्थाओं से ऋण लेने की अनुमति:** एक व्यक्ति को माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं से 3 लाख रुपये की बजाय अधिकतम दो लाख रुपये ही ऋण दिए जाएं।
- **माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं का क्षेत्रकों के आधार पर वर्गीकरण:** माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को किफायती आवास, जलवायु परिवर्तन, जल और स्वच्छता, स्वास्थ्य-देखभाल जैसे अलग-अलग क्षेत्रकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इससे वित्तीय पिरामिड के निचले स्तर तक विकास का लाभ पहुंचाया जा सकता है।
- **वित्तीय साक्षरता:** वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, बीमा के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और माइक्रोफाइनेंस उद्योग की वृद्धि में सहायक हो सकती है।
- **सर्वोत्तम उदाहरणों से सीखना:** तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में माइक्रोफाइनेंस वितरण नेटवर्क अच्छी तरह से विकसित हैं। देश के अन्य क्षेत्रों को भी इन संस्थाओं से सीखने की जरूरत है।

परिणाम?

आप सिर्फ़ प्रश्न का उत्तर नहीं देते—आप नीति की समझ, सटीक आँकड़े, और UPSC के अपेक्षित बहुआयामी दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

प्रश्न 4. इसे 'परीक्षा के लिए तैयार' क्या बनाता है?

- **GS-III के अनुरूप:** प्रत्येक अध्याय UPSC सिलेबस के शीर्षकों से जुड़ा है, जैसे- संवृद्धि, बाह्य क्षेत्रक, राजकोषीय नीति, कृषि, अवसंरचना, आदि।
- **उपयोगी तथ्य:** उदाहरण के लिए, 7.7 मिलियन श्रमिक गिग अर्थव्यवस्था में लगे हुए हैं; कृषि देश के सकल घरेलू उत्पाद में ~16% का योगदान देती है, आदि।
- **तुलनात्मक इनसाइट्स:** ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, मिडल-इनकम ट्रैप की समस्या, नोबेल पुरस्कार की प्रासंगिकता—सभी को उपयोगी प्रारूपों में समझाया गया है।

प्रश्न 5. अंततः परीक्षा हॉल में इसका क्या लाभ है?

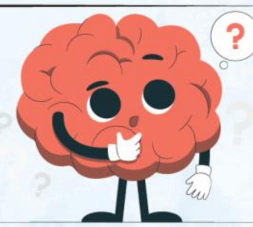

जब बाकी अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि "क्या लिखें?", आप पहले ही अपने 250 शब्दों के उत्तर की रूपरेखा तय कर चुके होंगे। Mains 365 को केवल कवरेज के लिए नहीं, बल्कि रिटेंशन, रिकॉल और रेज़र-शार्प डिलीवरी के लिए बनाया गया है।

अंतिम बात

इस डॉक्यूमेंट को अपने उत्तर बैंक की तरह मानिए। इसे अपने नोट्स को समृद्ध करने, संभावित प्रश्नों की कल्पना करने और उत्तरों को UPSC की भाषा में ढालने के लिए प्रयोग कीजिए। याद रखें - जब कंटेंट स्पष्टता और संदर्भ से मिलता है, तो अंक भी मिलते हैं।

इसे अपने लिए सिर्फ़ परीक्षा का रिसोर्स नहीं, बल्कि एक भावी प्रशासक की आर्थिक सोच का उपकरण बनाइए।

1. भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त विवरण (Snapshot of Indian Economy)

1.1. भारतीय अर्थव्यवस्था: एक नज़र में (Indian Economy at a Glance)

भारतीय अर्थव्यवस्था: एक नज़र में

प्रमुख आर्थिक संकेतक

राष्ट्रीय GDP	बाह्य (विदेशी) व्यापार	बेरोजगारी	ऋण	गरीबी
2024-25 में **चालू कीमतों पर भारत की GDP 331.03 लाख करोड़ रुपये** अनुमानित है। वर्तमान में **भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** है।	भारत से 2023-24 में 778.21 **बिलियन यू.एस. डॉलर** का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया गया। मई 2025 में भारत का वस्तु व्यापार घाटा कम होकर 21.88 बिलियन डॉलर रह गया।	मासिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, **अप्रैल 2025 में भारत में बेरोजगारी दर 5.1%** थी।	दिसंबर, 2024 में भारत का बाह्य (विदेशी) ऋण 717.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। **बाह्य ऋण-GDP अनुपात 19.1%** था।	भारत में **चरम गरीबी** 2011-12 में 16.2% था, जो 2022-23 में कम होकर केवल 2.3% रह गया (विश्व बैंक)।

वित्त वर्ष 2023-24 में नॉमिनल GVA में अलग-अलग क्षेत्रक की हिस्सेदारी

लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं 15%	कृषि, पशुधन, वानिकी और मात्स्यिकी 18%	खनन और उत्खनन (क्वैरिंग) 2%	विनिर्माण 14%	बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य यूटिलिटी सुविधाएं 2%
निर्माण 9%	व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, तथा प्रसारण से संबंधित सेवाएँ 17%	वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ 23%		

मुख्य लक्ष्य

सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है।	भारत को **2027-28 तक 5 ट्रिलियन डॉलर** और **2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर** की GDP के साथ विश्व की **तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य** रखा गया है।	विदेश व्यापार नीति-2023 का लक्ष्य 2030 तक भारत से निर्यात को बढ़ाकर **2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** करना है।	सरकार का लक्ष्य भारत की **प्रति व्यक्ति आय** को वर्तमान के लगभग 2,500 डॉलर से बढ़ाकर **4,418 डॉलर** करना है।	सरकार का लक्ष्य **2025-26 तक राजकोषीय घाटा को कम करके GDP के 4.5% से नीचे** लाना है।

प्रमुख बाधाएं

ऋण और ब्याज भुगतान का बड़ा बोझ बना हुआ है।	वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि से संकट की स्थिति बनी रहती है।	विश्व का छोटे-छोटे **भू-आर्थिक समूहों में विभाजन,** और **अति-वैश्वीकरण के कमजोर** पड़ने से व्यापार एवं आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ी चुनौती है क्योंकि **विश्व के 40% रोजगार को इससे खतरा** है।	उद्योग जगत की आवश्यकता के अनुरूप **प्रतिभाशाली और कुशल कार्यबल की कमी** है।	**अन्य चुनौतियों** में डिजिटल डिवाइड, अवसंरचना की कमी, आदि शामिल हैं।

आगे की राह

बेहतर **राजकोषीय नीति** सरकार पर अधिक कर्ज और ब्याज के बोझ को कम करेगी।	**अवसंरचना में सरकारी निवेश** को बढ़ाना चाहिए और निजी क्षेत्रक को अवसंरचना में निवेश करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देना चाहिए।	**RBI की मौद्रिक नीति को और अधिक प्रभावी बनाने** के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि मुद्रास्फीति से जुड़े जोखिमों को कम किया जा सके।	वैश्विक खतरों से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए **निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में विविधता** लानी चाहिए और **कमोडिटी (जैसे- क्रूड ऑयल) के आयात पर निर्भरता कम** करनी चाहिए।	**कर प्रणाली में सुधार** करना चाहिए, टैक्स रेट कम करना चाहिए, देश में टैरिफ (प्रशुल्क) संरचना की गहन समीक्षा के बाद आवश्यक सुधार करना चाहिए।	विशेषज्ञता और मूल्य संवर्धन गतिविधियों के माध्यम से **भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) में एकीकृत** करना होगा।	**विनिर्माण क्षेत्रक पर अधिक ध्यान** केंद्रित करते हुए भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए।

© Vision IAS

1.2. भारत का संरचनात्मक परिवर्तन (India's Structural Transformation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने **"एडवांसिंग इंडियाज स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कैच-अप टू द टेक्नोलॉजी फ्रंटियर"** शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

संरचनात्मक परिवर्तन: किसी अर्थव्यवस्था का निम्न-उत्पादकता और श्रम-गहन आर्थिक गतिविधियों से उच्च-उत्पादकता और कौशल-गहन गतिविधियों की ओर बढ़ना ही संरचनात्मक परिवर्तन कहलाता है।

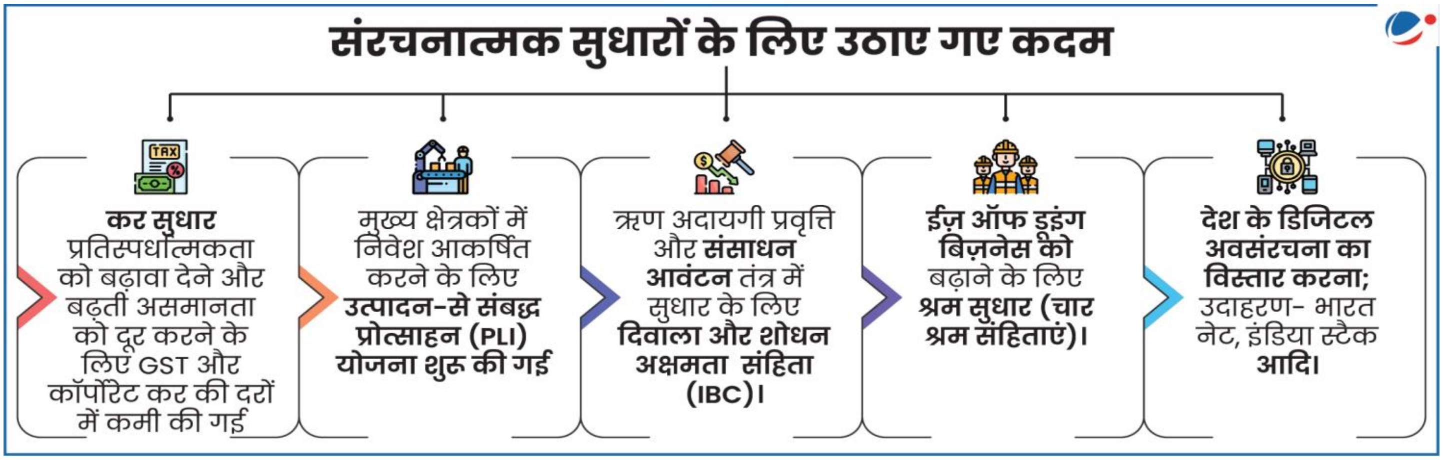

भारत के संरचनात्मक परिवर्तन पर IMF वर्किंग पेपर में उजागर किए गए प्रमुख मुद्दे

- **क्षेत्रक-वार असंतुलन:** अभी भी समग्र रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी 42% है।
- **उद्योगों में तकनीकों को अपनाने की दर एक समान नहीं होना:** टेक्नोलॉजी को अपनाने में सेवा क्षेत्रक ने विनिर्माण क्षेत्रक की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।
- **कम कौशल वाली नौकरियों में वृद्धि:** 2019 में लगभग 12 प्रतिशत वर्कर्स निर्माण (कंस्ट्रक्शन) क्षेत्रक में संलग्न थे। इस प्रकार निर्माण क्षेत्रक महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता क्षेत्रक बन गया है।
- **कम उत्पादकता:** 2019-20 में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक में **श्रम की उत्पादकता कृषि की तुलना में 4.5 गुना अधिक** थी।
- वर्किंग पेपर का अनुमान है कि भारत को 2050 तक अपनी बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए **कम-से-कम 143-324 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे**।

IMF वर्किंग पेपर में की गई मुख्य सिफारिशें

- **शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को मजबूत करना:** शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 (ASER)[1] के अनुसार **भारत की श्रम शक्ति ने** अन्य देशों की तुलना में **औपचारिक शिक्षा में कम वर्ष व्यतीत किए** हैं। साथ ही, भारत में **शिक्षा की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की** बनी हुई है।
- **श्रम बाजार सुधारों को लागू करना:** श्रम बाजार के लचीलेपन को मजबूत करने के लिए किसी राज्य में अन्य राज्यों के लोगों के रोजगार करने पर तरह- तरह के प्रतिबंधों को कम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है।
- **व्यापार एकीकरण को बढ़ावा देना:** व्यापार नीतियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- वैश्विक बाजारों के साथ एकीकरण करने के लिए **द्विपक्षीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर** करना चाहिए तथा **शुल्क और गैर-प्रशुल्क प्रतिबंधों को हटाया** जाना चाहिए।
- **लालफीताशाही को समाप्त करना:** नियमों को सरल बनाने और नौकरशाही संबंधी बाधाओं को कम करने से निजी क्षेत्रक के विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- **निरंतर सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा:** भारत के विश्व स्तरीय डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और मजबूत भौतिक सार्वजनिक अवसंरचना, दोनों निजी क्षेत्रक की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगे।
- **अन्य उपाय:** सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाना चाहिए; **लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमों को बैंकों से ऋण प्राप्ति में मदद** करने की आवश्यकता है।

---

[1] Annual Status of Education Report

निष्कर्ष

भारत के लिए संतुलित और समावेशी संरचनात्मक परिवर्तन बेहद ज़रूरी है ताकि वह तेज आर्थिक संवृद्धि बनाए रख सके, बेहतर रोजगार के अवसर पैदा कर सके, और अपनी जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) का पूरा लाभ उठा सके। शिक्षा, श्रम सुधार और व्यवसाय सुगमता के क्षेत्र में समय पर किए गए नीतिगत उपाय इस परिवर्तन को और तेज़ी से उत्पादक और समतावादी अर्थव्यवस्था की ओर ले जा सकता है।

1.3. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
संरचनात्मक परिवर्तन	टेक्नोलॉजी फ्रंटियर	क्षेत्रक-वार असंतुलन	तकनीक को अपनाने की दर	कम कौशल वाली नौकरियाँ
श्रमिक उत्पादकता	शिक्षा एवं कौशल	श्रम बाजार सुधार	व्यापार एकीकरण	द्विपक्षीय व्यापार समझौता
लालफीताशाही को समाप्त करना	सार्वजनिक निवेश	सामाजिक सुरक्षा कवरेज	व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस)	जनसांख्यिकीय लाभांश

1.4. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

भारत की संरचनात्मक रूपांतरण प्रक्रिया को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से आधुनिक औद्योगिक-सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने में बाधा डालने वाली प्रमुख समस्याओं का परीक्षण कीजिए। इस परिवर्तन को तेज करने के लिए उठाए गए प्रमुख नीतिगत उपायों पर चर्चा कीजिए और आगे के आवश्यक कदमों का सुझाव दीजिए।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
संरचनात्मक परिवर्तन का परिचय दीजिए	मुख्य समस्याएं/मुद्दे	शुरू की गई पहलों का उल्लेख कीजिए	आगे की राह

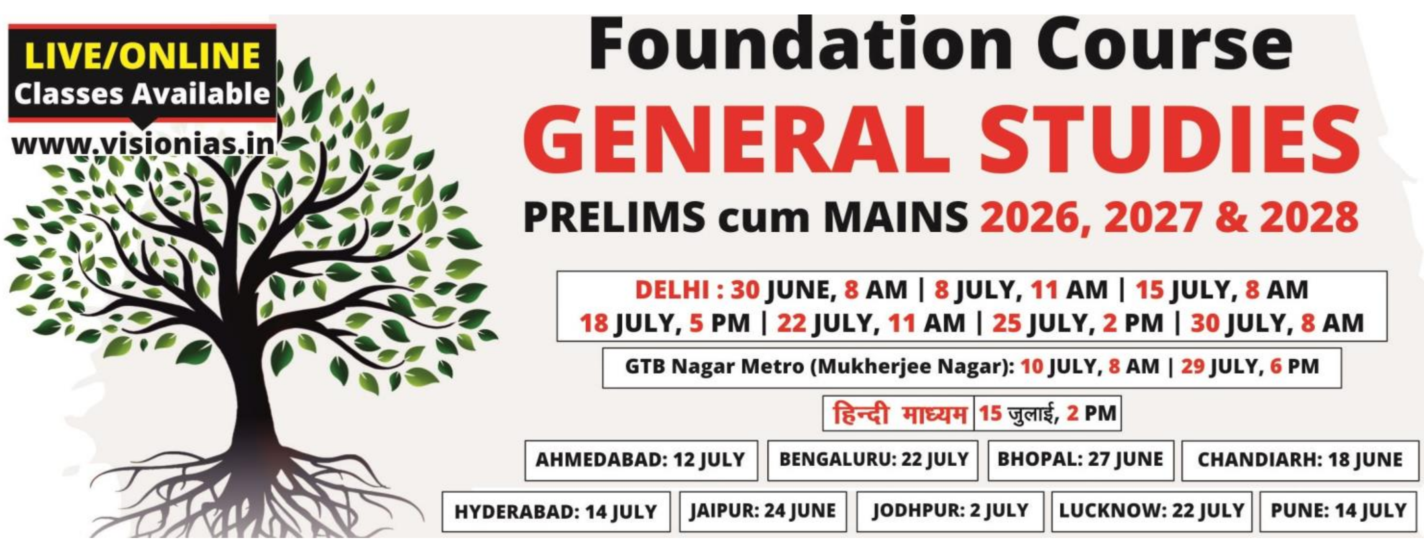

2. संवृद्धि एवं विकास (Growth and Development)

2.1. घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES), 2023-24 {Household Consumption Expenditure Survey (HCES), 2023-24}

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES), 2023-24

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES), 2023-24

- **औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE):**
  - **ग्रामीण:** 4,122 रुपये (सरकारी कार्यक्रमों के तहत प्राप्त मुफ्त मदों का मूल्य जोड़ने पर 4,247 रुपये)
  - **शहरी:** 6,996 रुपये (सरकारी कार्यक्रमों के तहत प्राप्त मुफ्त मदों का मूल्य जोड़ने पर 7,078 रुपये)
- **MPCE में वृद्धि:** 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्रों में 9% और शहरी क्षेत्रों में 8% की वृद्धि दर्ज की गई।
- **शहरी-ग्रामीण MPCE में अंतर:** यह 2011-12 में 84% था, जो 2023-24 में घटकर 70% हो गया। इससे ग्रामीण उपभोग में वृद्धि का संकेत मिलता है।
- **गैर-खाद्य मदों पर बढ़ता व्यय:** गैर-खाद्य मदें कुल व्यय का प्रमुख हिस्सा (ग्रामीण: 53%, शहरी: 60%) बन गई है। परिवहन, वस्त्र आदि पर व्यय में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।
  - औसत मासिक व्यय में खाद्य-पदार्थों की हिस्सेदारी घटी है।
- **उपभोग असमानता:** गिनी गुणांक घटकर ग्रामीण क्षेत्रों में **0.237** और शहरी क्षेत्रों में **0.284** हो गया है। यह आय असमानता में कमी को दर्शाता है।

घरेलू उपभोग सर्वेक्षण व्यय (HCES) के बारे में

- **उद्देश्य:** घरेलू उपभोग और व्यय पैटर्न पर विस्तृत डेटा एकत्र करना, जो देश में जीवन स्तर और रहन-सहन या खुशहाली का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है।
- **सर्वेक्षण का आयोजन:** इसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा नियमित अवधि पर आयोजित किया जाता है।
- **HCES के मुख्य उद्देश्य:**
  - **उपभोग पैटर्न को समझना:** यह सर्वेक्षण घरेलू (पारिवारिक) स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की खपत पर डेटा एकत्र करता है। इससे परिवार के जीवन और रहन-सहन के स्तर पता चलता है।
  - **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक:** यह सर्वेक्षण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के लिए भारांश तैयार करने में सहायक होता है, जो आर्थिक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है।
  - **आर्थिक संकेतक:** यह सर्वेक्षण GDP और CPI जैसे व्यापक आर्थिक संकेतकों के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करता है।

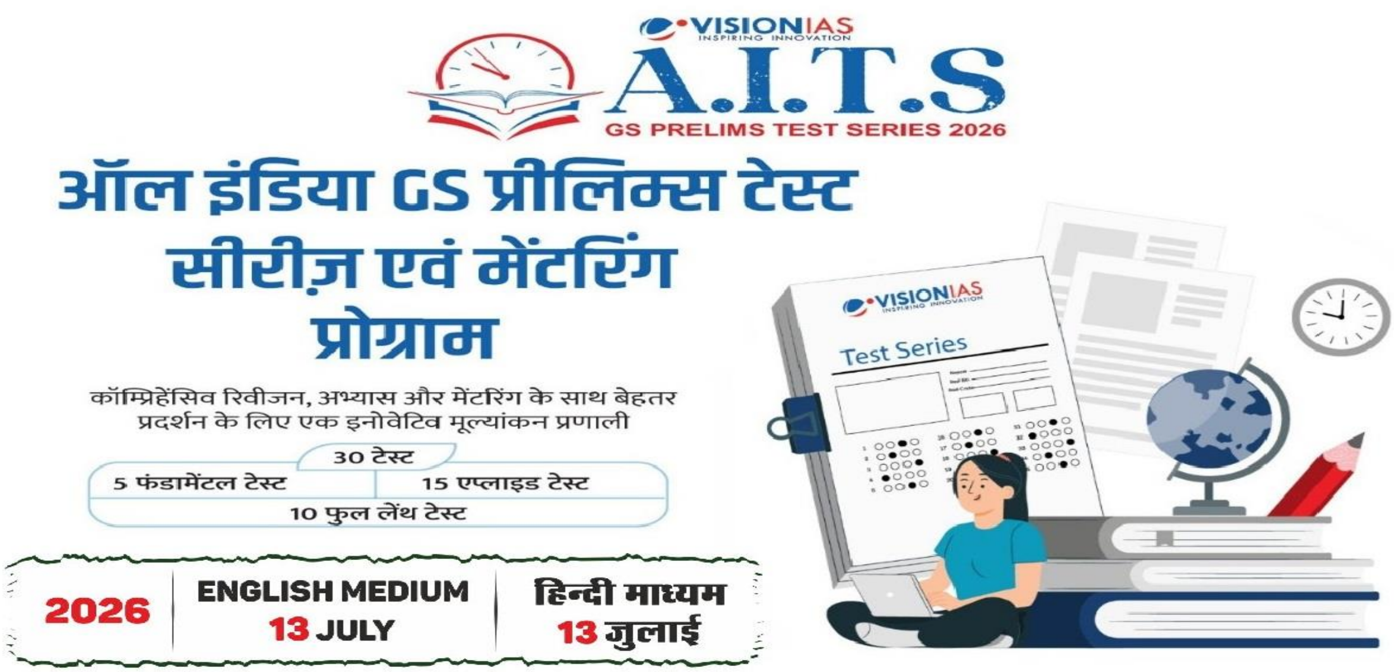

2.2. समावेशी विकास: एक नज़र में (Inclusive Growth at a Glance)

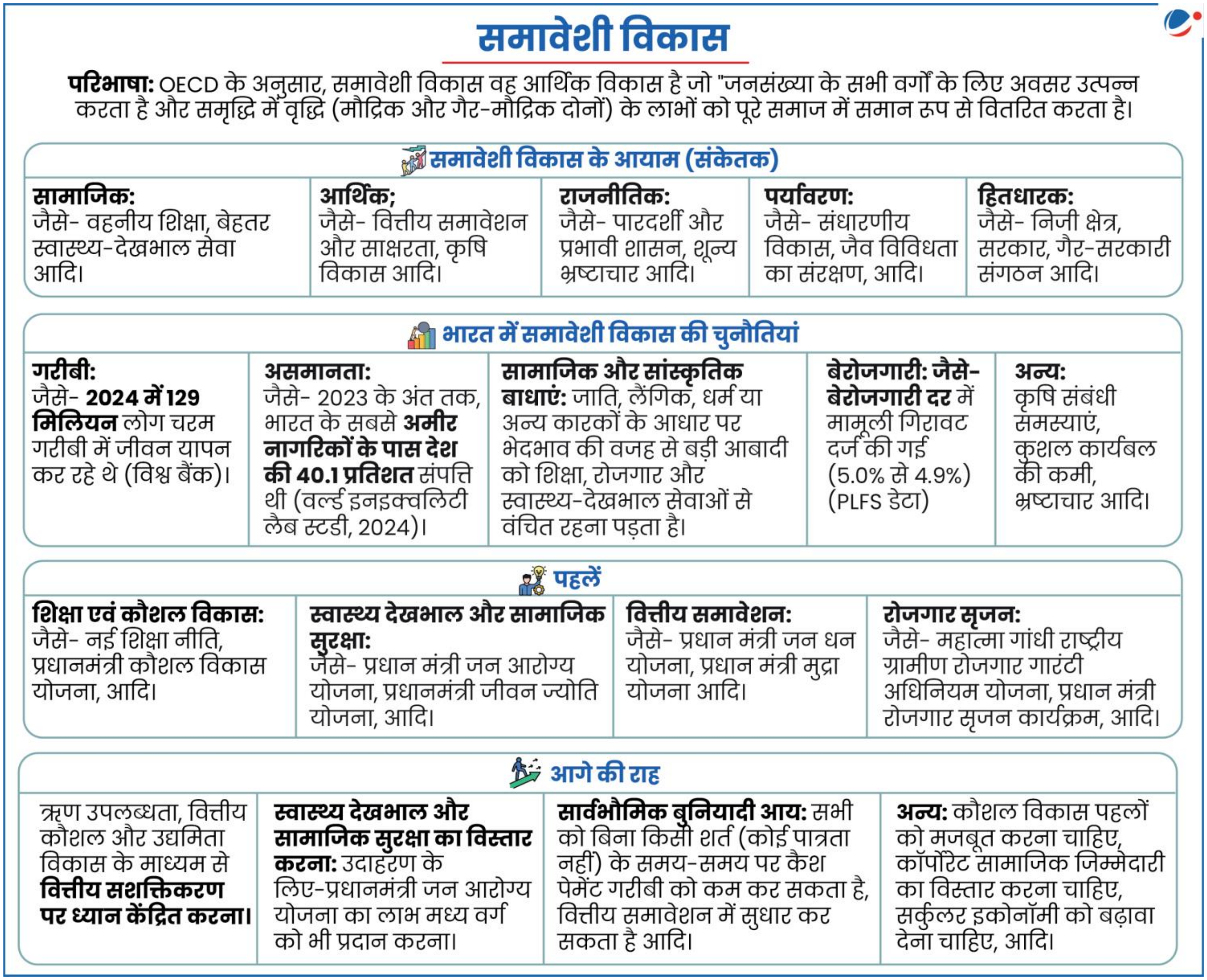

2.3. 'संवृद्धि के अग्रदूत' के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र (Northeast As 'Frontrunner of Growth')

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने **राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025** का उद्घाटन किया।

राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 में पूर्वोत्तर के फोकस क्षेत्रकों की मुख्य विशेषताएं

क्षेत्रक (सेक्टर्स)	मुख्य बिंदु
वस्त्र, हथकरघा एवं हस्तशिल्प	• पूर्वोत्तर क्षेत्र संधारणीय वस्त्र उद्योग और हस्तशिल्प का एक प्रमुख केंद्र है, जिसमें असम के जीआई-टैग प्राप्त मुगा रेशम, नागालैंड के आदिवासी शॉल, त्रिपुरा के बांस से बनी शिल्पकारी आदि शामिल हैं। • देश के 53% से अधिक करघे और 50% से अधिक बुनकर पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है।

© Vision IAS

नवीकरणीय ऊर्जा	• इस क्षेत्र में **60 गीगावाट** से अधिक की पारंपरिक जलविद्युत दोहन योग्य क्षमता विद्यमान है, जो भारत की कुल जलविद्युत क्षमता का 40% है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम में जलविद्युत उत्पादन की अधिक क्षमता मौजूद है।
सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और IT-सक्षम सेवाएं (IT & ITeS)	• इस क्षेत्र में तेजी से IT अवसंरचना का विकास हो रहा है। इनमें असम का **100 एकड़ का IT पार्क, अगरतला में स्थापित भारतीय सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STPI) कॉम्प्लेक्स,** और **2021** में **इम्फाल के मंत्रिपुखरी** में पूर्वोत्तर **क्षेत्र का पहला IT विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) एवं इनोवेशन हब** शामिल हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स	• **वित्त वर्ष 2024-25 में** 78 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) का निर्माण किया गया। इसी तरह **ढोला-सदिया** और **बोगीबील** जैसे पुलों के निर्माण से असम-अरुणाचल के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है। • 17 हवाई अड्डों (2013 में 9 हवाई अड्डे) के निर्माण के कारण **एयर-कनेक्टिविटी** में सुधार हुआ है।
शिक्षा	• **उच्च साक्षरता दर:** मिजोरम (91.3%), त्रिपुरा (87.2%), नागालैंड (80.1%)।
कृषि	• **समृद्ध एग्रो-बायोडायवर्सिटी** और अनुकूल जलवायु पूर्वोत्तर क्षेत्र में आर्गेनिक और उच्च-मूल्य वाली फसलों (जैसे- असम की चाय, जोहा चावल, कचाई नींबू, कीवी, अनानास) के उत्पादन को बढ़ावा देती है। • **पूर्वोत्तर क्षेत्र की 70% से अधिक आबादी** कृषि कार्य में लगी हुई है, जिनमें से अधिकतर लघु/ सीमांत किसान हैं।
खेल	• **पारंपरिक/ स्थानीय खेल** (तीरंदाजी, थांग-ता, पोलो आदि)।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चुनौतियां

- **बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होना:** भारत की मुख्य भूमि को पूर्वोत्तर क्षेत्र से जोड़ने वाला एकमात्र भूमि मार्ग **संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर (या चिकन नेक)** है।
- **विद्रोही समूह और सशस्त्र संघर्ष: उदाहरण के लिए,** NSCN-IM (नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड - इसाक-मुइवा) **'ग्रेटर नागालिम'** की मांग कर रहा है, मणिपुर में कूकी-मेइती संघर्ष,आदि।
- **नार्को आतंकवाद (Narco terrorism):** पूर्वोत्तर क्षेत्र, जो "गोल्डन ट्रायंगल" (म्यांमार, लाओस, थाईलैंड) के निकट स्थित है, **हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स** के लिए ट्रांजिट मार्ग के रूप में कार्य करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की पूरी बाड़बंदी नहीं की गई है और **इनकी समुचित निगरानी भी नहीं** की जाती है।
- **मानवाधिकार हनन:** सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) आदि ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत सुरक्षा बलों की जवाबदेही तय नहीं करने को लेकर चिंता व्यक्त की है।
- **प्राकृतिक आपदाओं का खतरा: उदाहरण के लिए,** हर साल ब्रह्मपुत्र में आने वाली बाढ़ के कारण असम में लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है और इससे फसलों को भी भारी नुकसान पहुँचता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए शुरू की गई पहलें

भारतीय स्तर पर	अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर
• **पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS)**। • एक्ट ईस्ट नीति • **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल (PM-DevINE)**[2]: इसका उद्देश्य राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर अवसंरचना और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र का त्वरित और समग्र विकास करना है। • **मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन (MOVCDNER)**।	• **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाएं:** कालादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना; इंडिया-म्यांमार-थाईलैंड (IMT) त्रिपक्षीय राजमार्ग; बांग्लादेश-भूटान-भारत-नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता; मेकांग-गंगा सहयोग; आदि। • **एक्ट ईस्ट फोरम (AEF):** इसे 2017 में भारत और जापान द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के

[2] Prime Minister's Development Initiative for North East Region

• **शांति और सुरक्षा से संबंधित पहलें**: नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF) शांति समझौता 2024; आदिवासी असम शांति संधि 2022; डिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (DNLA) शांति समझौता 2023; ULFA शांति संधि 2023; आदि संपन्न की गई हैं।	भीतर और इस क्षेत्र को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करना है। • **दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC)**[3]: यह बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका को **परियोजना-आधारित** साझेदारी से जोड़ता है, जिससे क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

आगे की राह

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अलग-अलग मार्गों का विकास: उदाहरण के लिए, हिली–महेंद्रगंज ट्रांसनेशनल कॉरिडोर**।
- **विद्रोही गतिविधियों को कम करना:** त्रिपुरा के पुनर्वास मॉडल ने उग्रवाद को कम किया और मिजोरम से ब्रू जनजाति को सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित किया।
- **अवैध प्रवासियों से निपटना और सीमा सुरक्षा बढ़ाना:** सीमा प्रबंधन में सुधार करके।।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत के साथ एकीकृत करना: बेजबरुआ समिति** की सिफारिशों के आधार पर भारत के अन्य हिस्सों में रहने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के खिलाफ **भेदभाव और नृजातीय हमलों** को रोकने के लिए कानूनी उपाय करने चाहिए।

निष्कर्ष

अपनी विशिष्ट रणनीतिक अवस्थिति, समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों की वजह से भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र असीम संभावनाओं वाला क्षेत्र है। कनेक्टिविटी की कमी को दूर करके, शांति सुनिश्चित करके, और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ एकीकरण सुनिश्चित करके पूर्वोत्तर क्षेत्र को समावेशी और संधारणीय विकास का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

[3] South Asia Subregional Economic Cooperation

2.4. मिडिल इनकम ट्रैप (Middle Income Trap)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व बैंक ने कहा है कि भारत को **2047 तक उच्च-आय वाला देश (HIC)** बनने के लिए अगले 22 वर्षों तक **औसतन 7.8% की आर्थिक संवृद्धि दर** प्राप्त करनी होगी।

मिडिल इनकम ट्रैप के बारे में

- यह वह स्थिति है जिसमें **तीव्र आर्थिक संवृद्धि वाली अर्थव्यवस्थाएं मध्यम आय के स्तर पर स्थिर हो जाती हैं और उच्च आय वाले देशों की श्रेणी तक पहुंचने में विफल रहती हैं।**
- **मध्यम आय वाले देश (MIC):** विश्व बैंक उन अर्थव्यवस्थाओं को **मिडिल इनकम यानी मध्यम आय वाले देश** के रूप में वर्गीकृत करता है, जिनकी **प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) 1,135 अमेरिकी डॉलर से 13,846 अमेरिकी डॉलर** के बीच है।
- **ट्रेंड:** पिछले दशक के दौरान **मिडिल इनकम यानी मध्यम आय वाले** बहुत कम **देश** उच्च आय वाले देशों की श्रेणी में शामिल हो सके हैं।
    - इसके कई कारण हैं, जैसे- **बुजुर्गों की बढ़ती आबादी और कर्ज में वृद्धि, भू-राजनीतिक और व्यापारिक संघर्ष, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक संवृद्धि को गति देने** में आने वाली चुनौतियां, आदि।

भारत के मिडिल इनकम ट्रैप में उलझने के प्रमुख कारण?

- **मानव संसाधन का ठीक से दोहन नहीं होना:**
    - **कौशल की कमी:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, केवल 51% स्नातक ही रोजगार के योग्य हैं और भारत में केवल 2.3% कार्यबल ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
    - **नवाचार क्षमता की कमी:** भारत में अनुसंधान एवं विकास पर GDP का केवल 0.64% व्यय किया जाता है। दूसरी ओर, चीन में यह अनुपात 2.4% और संयुक्त राज्य अमेरिका में 3.47% है।
- **आय असमानता में वृद्धि:** वर्ल्ड इनिक्वेलिटी लैब रिपोर्ट के मुताबिक, 2022-23 में भारत के शीर्ष 1% लोगों के पास देश की सकल राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा था।
- **औद्योगीकरण का स्थिर होना:** भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि से सीधे **सेवा क्षेत्रक** की ओर आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है कि विनिर्माण क्षेत्रक की उपेक्षा हुई है। इस वजह से देश के समग्र **उत्पादन और रोजगार में विनिर्माण क्षेत्रक की हिस्सेदारी 20% से नीचे** बनी हुई है।
- **निजी निवेश में कमी:** 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के बाद निजी निवेश में वृद्धि हुई, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद के एक हिस्से के रूप में इसमें गिरावट आई है, विशेष रूप से 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से।
- **समकालीन वैश्विक बाधाएं:**
    - विदेशी ऋण में वृद्धि हुई है (पिछले वर्ष की तुलना में मार्च, 2024 में यह 6.4% बढ़ा है)।
    - **जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने** व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने में नई चुनौती सामने आ रही है।

आगे की राह

विश्व बैंक की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि उच्च आय वाले देश का दर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखने वाले देशों को 3i रणनीति अपनानी चाहिए।

निम्न आय वाले देशों में निवेश (1i)	निम्न-MIC के लिए निवेश + समावेश (2i)	उच्च-MIC के लिए निवेश + समावेश + नवाचार (3i)
निम्न आय वाले देशों में आर्थिक सफलता मुख्य रूप से **निवेश में तेजी लाने से** ही हासिल हो सकती है। साथ ही, घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए निवेश के अनुकूल माहौल बनाने की आवश्यकता भी होती है।	जैसे-जैसे निम्न आय वाले देश **मध्यम आय वाले देशों की स्थिति** में आते हैं, उन्हें प्रगति जारी रखने के लिए अनुकूल निवेश माहौल बनाए रखने के अलावा ऐसे उपाय करने होते हैं जो **विदेशों से नए आइडियाज को प्राप्त कर सके और अर्थव्यवस्था में उन्हें अपना सकें।** इन्हें ही **"समावेश या इन्फ्यूजन"** कहा जाता है।	एक बार जब कोई MIC अपनी अर्थव्यवस्था के सबसे क्षमतावान हिस्सों में इन्फ्यूजन की क्षमता का पूरा उपयोग कर लेता है, और उसे सीखने एवं अपनाने के लिए वांछित प्रौद्योगिकियां कम पड़ जाती हैं - तो उसे नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत और मध्यम आय वाले अन्य देशों को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों और विकास चरण के अनुरूप व्यवस्थित एवं नई नीतियों को अपनाने की आवश्यकता है ताकि वे सफलतापूर्वक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कर सकें और 'मिडिल इनकम ट्रैप' से बाहर निकल सकें।

2.5. भारत में निर्धनता: एक नज़र में (Poverty in India at a Glance)

भारत में निर्धनता

भारत में निर्धनता की वर्तमान स्थिति

भारत में निर्धनता अनुपात: भारत में प्रतिदिन 3.65 डॉलर (व्यय) के आधार पर गरीबी दर 2011-12 की 61.8 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 28.1 प्रतिशत रह गई (विश्व बैंक)।	**गरीब राज्यों (उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा) में गरीबी में तेजी से गिरावट दर्ज की गई जिससे** असमानताओं में कमी का संकेत मिलता है।	चरम गरीबी में रहने वाले **भारतीयों की संख्या 431 मिलियन (1990) से घटकर 129 मिलियन (2024)** रह गई है। **(विश्व बैंक)**

भारत में निर्धनता के कारण

ऐतिहासिक कारण: उदाहरण के लिए- शोषणकारी औपनिवेशिक शासन	**कम कृषि उत्पादकता: मुख्य कारण-** भूमि जोत का आकार छोटा होना, कृषि में पूंजी की कमी और पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर निर्भरता।	**सामाजिक असमानताएं:** उदाहरण के लिए- **भारत में 53% महिलाएं घर की देखभाल की ज़िम्मेदारियों के कारण कार्य बल में शामिल नहीं हैं** (ILO)।	**पर्यावरणीय कारक:** उदाहरण के लिए- **असम और बिहार में बार-बार आने वाली बाढ़।**	**अन्य कारण:** जनसंख्या विस्फोट, आर्थिक असमानता

निर्धनता दूर के लिए उठाए गए कदम

वित्तीय समावेशन: प्रधान मंत्री जन धन योजना, पीएम-किसान सम्मान निधि आदि।	**अवसंरचना और मूलभूत सेवाएं:** प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण, उज्ज्वला योजना, आदि।	**आजीविका सुरक्षा:** मनरेगा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आदि।	**मानव पूंजी विकास:** सर्व शिक्षा अभियान, पीएम कौशल विकास योजना, आयुष्मान भारत, आदि।

आगे की राह

दोहरी रणनीति: कृषि को आधुनिक बनाकर उत्पादकता बढ़ाना तथा उद्योग और सेवा क्षेत्रकों में अधिक रोजगार सृजित करना चाहिए।	**समावेशी विकास को बढ़ावा देना:** विद्युत, सड़क जैसी मूलभूत संरचनाओं में सुधार करना चाहिए।	**नीति आयोग:** रोजगार-सृजन करने वाले सतत व तीव्र विकास को बढ़ावा चाहिए, निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना चाहिए।	**अमर्त्य सेन के "क्षमता दृष्टिकोण" पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए:** यह लोगों की क्षमताओं के विकास में निवेश करने की आवश्यकता पर बल देता है।

2.5.1. भारत में गरीबी मापन हेतु मौजूदा फ्रेमवर्क (India's Poverty Measurement Framework)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक अध्ययन में कहा गया है कि लोगों के बढ़ते जीवन स्तर को दर्शाने के लिए भारत में गरीबी मापन के मौजूदा तरीकों में तत्काल बदलाव की जरूरत है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस अध्ययन में गरीबी और असमानता में आए बदलावों पर प्रकाश डालते हुए 2022-24 के **घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण** के आंकड़ों की तुलना 2011-12 के आंकड़ों से की गई है।
- **अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र**
  - **पावर्टी हेडकाउंट रेशियो (HCR)** में काफी सुधार हुआ है। **1.90 डॉलर PPP (क्रय शक्ति समता)** पर, यह अनुपात 2011-12 में **लगभग 12%** था, जो घटकर **2023-24 में 1%** हो गया है।
    - **पावर्टी हेडकाउंट रेशियो (HCR):** गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का प्रतिशत।
  - **सबसे गरीब परिवार:** धनी परिवारों की तुलना में सबसे गरीब परिवारों के उपभोग व्यय में अधिक वृद्धि देखी गई है।
  - **मौजूदा गरीबी की रेखा (तेंदुलकर और रंगराजन समिति):** गरीबी के ये मापदंड अब पुराने हो चुके हैं, क्योंकि ये आज के गरीब परिवारों की वास्तविक स्थिति और उनके अभावों को सटीक रूप से नहीं दर्शाते हैं।

© Vision IAS

अध्ययन में सापेक्ष गरीबी की दो नई सीमाएं प्रस्तावित की गई हैं:

- **सापेक्ष गरीबी रेखा (उपभोग के एक-तिहाई पर्सेंटाइल के आधार पर):** इस पद्धति में सरकार की ओर से तय गरीबी रेखा की बजाय, समाज के **सबसे कम आय वाले 33 प्रतिशत लोगों के व्यय को गरीबी का मापदंड** बनाया जाता है।
- **आय के आधार पर सापेक्ष गरीबी रेखा:** यूरोप में, सभी व्यक्तियों की आय को क्रम में रखने पर जो मीडियन इनकम यानी मध्य आय निकलती है, उसके 60% से कम आय वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है।
    - यदि इस पद्धति को भारत में लागू किया जाए, तो **2023-24 में 16.5% आबादी इस सीमा से नीचे** थी।

नई गरीबी रेखा का महत्व

- यह वर्तमान समय में गरीबों की वास्तविक स्थिति और उनके अभावों को ध्यान में रखते हुए अपडेटेड उपभोग पैटर्न को दर्शाती है।
- यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक संवृद्धि के साथ गरीबी रेखा अपने आप समायोजित होती रहे।
- यह आधुनिक भारत में गरीबी का **अधिक सटीक माप प्रदान करती है।**

निष्कर्ष

यह अध्ययन इस बात पर बल देता है कि भारत में गरीबी मापने की रूपरेखा की तत्काल समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि बढ़ते जीवन स्तर और बदलते उपभोग पैटर्न को समुचित रूप से दर्शाया जा सके। सापेक्ष गरीबी (रिलेटिव पॉवर्टी) मापन पद्धति को अपनाने से आज की अर्थव्यवस्था में अभाव का अधिक सटीक और परिवर्तनशील आकलन प्राप्त होगा। इससे समावेशी विकास की बेहतर तरीके से निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी।

2.5.2. शहरी गरीबी (Urban Poverty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ओडिशा सरकार ने एक सहयोगात्मक पहल **'सहयोग/ SAHAYOG'** शुरू की है। इसका उद्देश्य **शहरी गरीबों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना** सुनिश्चित करना है।

भारत में शहरीकरण और शहरी गरीबी की वर्तमान स्थिति

- भारत की शहरी जनसंख्या **1951 में 17.29%** थी, जो **2011 में लगभग दोगुनी होकर 31.16%** हो गई।
- **2050** तक भारत की **50%** से अधिक आबादी **(877 मिलियन)** शहरों और कस्बों में निवास कर रही होगी।

विश्व बैंक की नवीनतम 'पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ' रिपोर्ट के अनुसार-

- **शहरों में चरम गरीबी** 2011-12 की **10.7% से घटकर** 2022-23 में मात्र **1.1%** रह गई।
- **निम्न-मध्यम आय वाले देशों** के लिए निर्धारित गरीबी रेखा **(3.65 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन)** के आधार पर, **शहरी गरीबी 2011-12 में 43.5%** थी। यह **2022-23 में घटकर 17.2%** हो गई है।
- भारत का **उपभोग-आधारित गिनी सूचकांक** 2011-12 के 28.8 से घटकर **2022-23 में 25.5** हो गया। यह **आय असमानता में कमी** को दर्शाता है।
- वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में **शहरी बेरोजगारी दर गिरकर 6.6%** हो गई, जो 2017-18 के बाद **सर्वाधिक गिरावट** है।

शहरी और ग्रामीण गरीबी के बीच अंतर

- **सापेक्ष गरीबी**: उदाहरण के लिए- मुंबई में एक ओर एशिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक **धारावी** का अस्तित्व है, तो दूसरी ओर गगनचुंबी इमारतों, लग्जरी होटलों, आदि की मौजूदगी भी है।
- **आय के स्रोत**: शहरी गरीब अक्सर अनौपचारिक (असंगठित क्षेत्र) रोजगार पर निर्भर होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी मुख्यतः जमीन, जल और अन्य कृषि संसाधनों तक सीमित पहुंच से जुड़ी होती है।
- **सेवाओं की प्राप्ति:** ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर पर्याप्त बुनियादी ढांचा और आवश्यक सेवाओं की कमी होती है। दूसरी ओर, शहरी गरीबों को इन सेवाओं की उपलब्धता के बावजूद उन्हें प्राप्त करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **सामाजिक नेटवर्क:** शहरी परिवेश में गरीबों के पास सामाजिक नेटवर्क और सहयोग तंत्र अपेक्षाकृत कम हो सकते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संबंध और पारंपरिक सहारा व्यवस्था अधिक मजबूत हो सकती हैं।

शहरी गरीबी के बने रहने के लिए जिम्मेदार कारक

- **योजनाबद्ध शहरी विकास का अभाव:** अव्यवस्थित शहरीकरण, गांव से शहर की ओर पलायन तथा शहरों की बढ़ती आबादी एवं नीति निर्माण में शहरी गरीबों को अनदेखा करना। उदाहरण के लिए- किफायती आवास योजनाओं की कमी।
- **शहरीकरण में क्षेत्रीय असमानता: टियर-II और टियर-III शहरों के अपर्याप्त विकास के कारण** दिल्ली, मुंबई जैसे महानगर अत्यधिक जनसंख्या के बोझ से जूझ रहे हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच का अभाव:** शहरी क्षेत्रों में रहने वाले **कई गरीब प्रवासियों के पास पहचान-पत्र या निवास प्रमाण-पत्र नहीं** होता, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते और गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रह जाते हैं।
- **गरीबी का दुष्चक्र:** गरीबी के कारण लोगों को **शिक्षा, नौकरी आदि के सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के अवसर नहीं** मिलते, जिससे **पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी** बनी रहती है।

शहरी गरीबी को कम करने के लिए सरकारी पहलें

- **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड**: आधार आधारित आधारित यह योजना देश में कहीं से भी राशन लेने की सुविधा देती है। इससे गरीब और आंतरिक प्रवासी मजदूरों को भोजन की सुरक्षा मिलती है।
- **स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0**: शौचालयों के निर्माण और प्रबंधन के लिए स्वच्छता योजना।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-Urban)**: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग (MIG) और झुग्गीवासियों के लिए आवास सुविधा।
- **दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)**: यह योजना शहरी गरीबों को **लाभकारी स्वरोजगार और कौशल प्रदान करके रोजगार** के अवसर प्रदान करती है।
- **पी.एम. स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि):** इसके तहत **स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती दर पर ऋण** प्रदान किया जाता है।
- **अन्य:** अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 (AMRUT 2.0), स्मार्ट सिटीज़ मिशन, आदि।

आगे की राह

- **समावेशी शहरीकरण: लोगों की सक्रिय भागीदारी** के साथ-साथ निर्णय प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने की भी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए- केरल में **'कुदुम्बश्री'** महिला नेटवर्क, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
- **टियर-II और टियर-III शहरों का विकास:** ग्रामीण क्षेत्रों में **अवसंरचना विकास और रोजगार के अवसरों में सुधार करके ग्रामीण** क्षेत्रों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर रोक लगाई जा सकती है।
- **सतत शहरीकरण: शहरी नियोजन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में संधारणीयता** को प्राथमिकता देना। उदाहरण के लिए- स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर का स्वच्छता अभियान।
- **शहरी गरीबों का सशक्तीकरण: कौशल विकास, श्रम-गहन उद्योगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के विकास** को बढ़ावा देना चाहिए।
- **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का लक्षित वितरण:** योजनाओं की **पोर्टेबिलिटी** को बढ़ावा देने, **समावेशन-अपवर्जन त्रुटियों** को सुधारने और योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी में सुधार करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

2050 तक भारत के शहरों द्वारा **GDP में 75% से अधिक योगदान देने और इनसे लगभग 60% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन** होने की संभावना है। इसलिए, **शहरी गरीबी की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है**, ताकि शहरी क्षेत्रों का संधारणीय विकास सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रयास **'विकसित भारत'** के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक होगा और भारत को **5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था** बनाने की दिशा में मजबूत कदम होगा।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
UPSC के लिए करेंट अफेयर्स
की समग्र तैयारी हेतु एकमात्र समाधान
Digital Current Affairs 2.0
मुख्य विशेषताएं:
विजन इंटेलिजेंस
डेली प्रैक्टिस
डेली न्यूज समरी
स्टूडेंट डैशबोर्ड
क्विक नोट्स और हाइलाइट्स
संधान तक पहुंच की सुविधा
QR कोड स्कैन करें

2.6. आर्थिक संकेतक (Economic Indicators)

2.6.1. GDP के आधार वर्ष में संशोधन (GDP Base Year Revision)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का आधार वर्ष **2011-12** से बदलकर **2022-23** करने के लिए **राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS)**[4] पर 26 सदस्यीय **सलाहकार समिति** का गठन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह समिति **बिस्वनाथ गोलदार** की अध्यक्षता में **राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS)** का गठन किया गया है।
    - **केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)** हर साल **राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी** जारी करता है। इसमें अलग-अलग तरीकों से GDP का अनुमान प्रस्तुत किया जाता है।
- **NAS** पर गठित यह सलाहकार समिति GDP को मुद्रास्फीति और औद्योगिक सूचकांकों के साथ समायोजित करने हेतु डेटा स्रोतों की समीक्षा करेगी।
- इससे पहले **2015 में आधार वर्ष में संशोधन** हुआ था। तब **आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2011-12** कर दिया गया था।
    - नई श्रृंखला में, CSO ने **कारक लागत (फैक्टर कॉस्ट) पर GDP** की गणना समाप्त कर दी थी। इसकी जगह उद्योग-वार अनुमानों को **बुनियादी मूल्य (बेसिक प्राइस) पर सकल मूल्य वर्धन (GVA)** के रूप में मापने की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अपनाई गई है।

आधार वर्ष (Base Year) क्या है?

- आधार वर्ष वह **संदर्भ वर्ष (Reference year)** होता है जिसकी कीमतों का उपयोग राष्ट्रीय आय में वास्तविक वृद्धि (मुद्रास्फीति को घटाकर) की गणना के लिए किया जाता है।
- इस प्रकार, आधार वर्ष **GDP की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बेंचमार्क** है।
    - उदाहरण के लिए, यदि **2011-12** आधार वर्ष है, तो अन्य वर्षों की GDP को 2011-12 की कीमतों के आधार पर समायोजित किया जाता है।

GDP आधार वर्ष को अपडेट करने की जरूरत क्यों है?

- **मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर करना:** पुराने आधार वर्ष का उपयोग करने से वास्तविक GDP संवृद्धि को अधिक बढ़ाकर दिखाया जा सकता है, क्योंकि इसमें बढ़ती कीमतों को ध्यान में नहीं रखा जाता है।
- **डेटा गुणवत्ता में वृद्धि:** डिजिटलीकरण से नया डेटा उपलब्ध हुआ है, जो GDP आकलन को अधिक **विश्वसनीय** बनाता है।
- **वैश्विक तुलना:** इसे अन्य देशों के GDP आकलन के साथ तुलना योग्य बनाएगा।
- **अन्य कारण:** कोविड-19 महामारी के बाद की स्थिति को अपनाएगा, नीति निर्धारण का समर्थन करेगा, आदि।
- आधार वर्ष में संशोधन अन्य प्रमुख संकेतकों के लिए भी प्रासंगिक है, जैसे-
    - **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production: IIP),**
    - **थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index: WPI),** और
    - **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index: CPI)**

GDP के बारे में

- **GDP को मापने का तरीका:** GDP को सैद्धांतिक रूप से तीन तरीकों से मापा जाता है और सभी तरीकों से समान परिणाम मिलना चाहिए (इन्फोग्राफिक देखें)।
    - **नॉमिनल GDP:** इसे **चालू बाजार कीमतों** पर मापा जाता है। इसमें **मुद्रास्फीति का समायोजन नहीं** किया जाता है।
    - **रियल GDP:** इसे **आधार वर्ष की कीमतों** का उपयोग करके और मुद्रास्फीति को समायोजित कर मापा जाता है। यह **वास्तविक आर्थिक संवृद्धि** को प्रदर्शित करती है।

[4] National Accounts Statistics

GDP की सीमाएं

- इसकी गणना में **गैर-बाजार आधारित गतिविधियां शामिल नहीं** होतीं हैं, जैसे- घरेलू कामकाज।
- इसमें **आय असमानता की उपेक्षा** की जाती है।
- **पर्यावरण को होने वाले नुकसान की उपेक्षा** की जाती है।
- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के योगदान** को सही तरीके से नहीं मापा जाता है।
- यह **कल्याण या जीवन स्तर का आकलन नहीं** करती है।

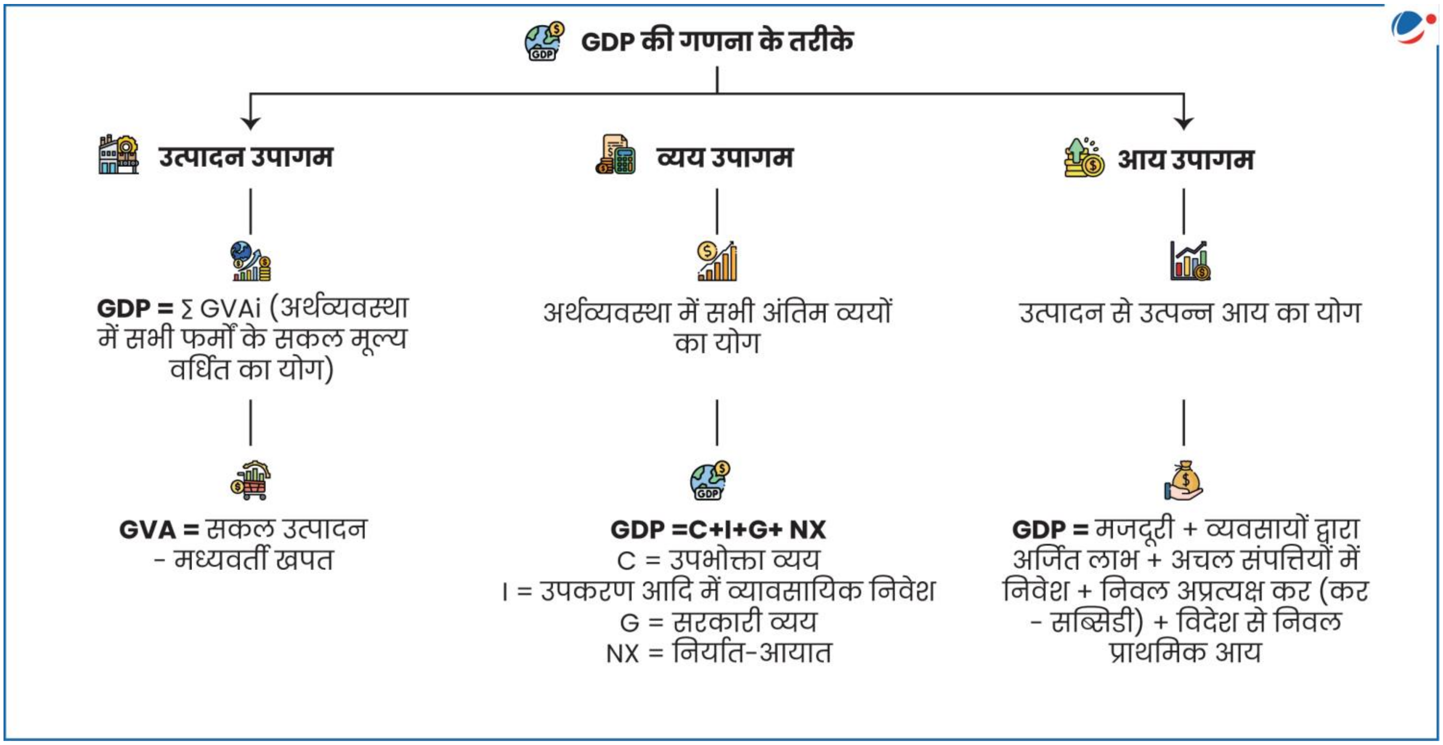

निष्कर्ष

GDP के आधार वर्ष को अपडेट कर 2022-23 करना एक समयानुकूल कदम है, जो अधिक सटीक, मुद्रास्फीति-समायोजित और नीतिगत दृष्टि से प्रासंगिक आर्थिक आंकड़ों को सुनिश्चित करेगा। यह बदलते आर्थिक परिदृश्य को दर्शाता है, डेटा की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और भारत की वैश्विक मानकों के अनुरूप अपनी विकास गति को मापने की क्षमता को सुदृढ़ करता है।

2.6.2. WPI के आधार वर्ष की समीक्षा (WPI Base Year Revision)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत सरकार ने **थोक मूल्य सूचकांक (WPI)** की मौजूदा श्रृंखला का **आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23** करने के लिए **प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन** किया है।

WPI के बारे में

- WPI एक आर्थिक संकेतक है जो **एक निश्चित अवधि के दौरान देश के घरेलू बाजार में वस्तुओं की थोक कीमतों में होने वाले बदलाव को मापता है।** यह उत्पादन और वितरण स्तर पर मुद्रास्फीति को समझने में मदद करता है और नीतिगत निर्णयों के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य करता है।
- **जारीकर्ता:** इसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** के तहत कार्यरत **आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा जारी** किया जाता है।
- **माप:** इसे WPI बास्केट में शामिल कुछ निश्चित मदों (वस्तुओं) के भारित औसत के रूप में मापा जाता है।
- **बास्केट की संरचना:** इसमें कुल **697 मदें** शामिल हैं, जिन्हें तीन प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है:

- **प्राथमिक मद (भारांश: 100 में से 22.618):** इसमें चार उप-समूह शामिल हैं: खाद्य वस्तुएं; गैर-खाद्य वस्तुएं; खनिज; तथा कच्चा पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस।
- **ईंधन और बिजली (न्यूनतम भारांश: 100 में से 13.152):** इसमें तीन उप-समूह शामिल हैं: कोयला; खनिज तेल; और बिजली।
- **विनिर्मित उत्पाद (उच्चतम भारांश: 100 में से 64.230):** इसमें 22 उप-समूह शामिल हैं।

उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI) के बारे में: यह **उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत बदलाव** को मापता है, जो **घरेलू बाजार** में बेची जाती हैं या निर्यात की जाती हैं और जिनकी कीमत उत्पादकों को प्राप्त होती है।

WPI की जगह PPI को अपनाने की आवश्यकता क्यों है?

- **मल्टीपल गणना संबंधी पूर्वाग्रह:** WPI में **एक ही उत्पाद की दोहरी गणना** की वजह से मल्टीपल गणना संबंधी पूर्वाग्रह मौजूद होता है। मल्टीपल गणना तब होती है, जब किसी विशिष्ट वस्तु के मूल्य और उसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त इनपुट को समग्र सूचकांक में शामिल कर लिया जाता है। **PPI में दोहरी गणना की संभावना नहीं** रहती है।
- **सेवाओं को शामिल नहीं किया जाना:** WPI में सेवा क्षेत्रक (भारत की GDP का लगभग 55%) से संबंधित मदों को शामिल नहीं किया जाता है।
- **करों को शामिल नहीं करना:** नवीनतम WPI श्रृंखला (2011-12) में केवल मूल कीमतों को शामिल किया जाता है। इसमें कर, छूट/ व्यापार छूट, परिवहन और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं।
- **PPI के लाभ:** इसमें **सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है** और अप्रत्यक्ष करों को बाहर रखता है। **विकसित अर्थव्यवस्थाओं (जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका) में PPI का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है,** जिससे इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक मान्यता प्राप्त है।

निष्कर्ष

WPI आधार वर्ष में संशोधन और **PPI को अपनाना वास्तव में मुद्रास्फीति को मापने का अधिक सटीक और विश्वस्तरीय तरीका हो सकता** है। PPI को अपनाने से आर्थिक नीति निर्माण में भी सुधार हो सकता है। अर्थव्यवस्था के **सभी क्षेत्रकों की कीमतों में परिवर्तन की गणना की जा सकती** है। साथ ही, ये कदम **परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था में डेटा-संचालित निर्णय लेने के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क** भी प्रदान कर सकते हैं।

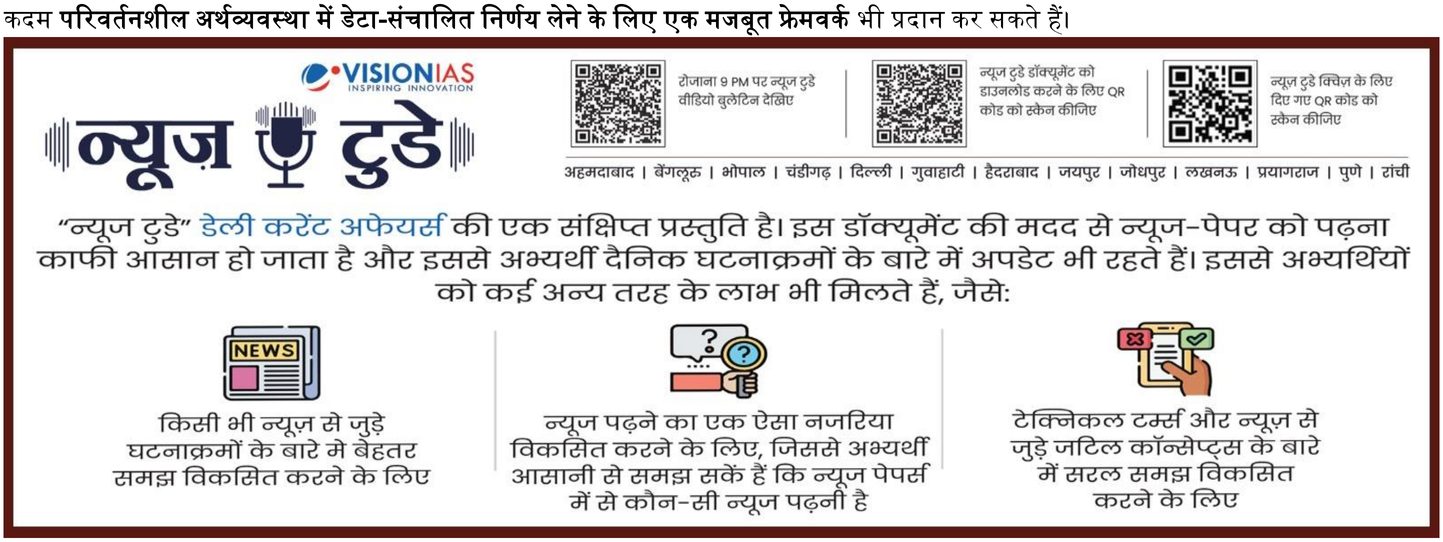

2.7. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)

2.7.1. भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति: एक नजर में (Status of Financial Inclusion in India at a Glance)

भारत में वित्तीय समावेशन

भारत में वित्तीय समावेशन की स्थिति

भारत में लगभग 78% वयस्क आबादी के पास बैंक खाता है **(विश्व बैंक ग्लोबल फ़िनडेक्स डेटाबेस, 2021)**	भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का मार्च 2024 के लिए **वित्तीय समावेशन सूचकांक मूल्य 64.2** था, जबकि मार्च 2023 में यह 60.1 था।

वित्तीय समावेशन संबंधी पहलें

प्रधान मंत्री जन धन योजना	**राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति**	UPI, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), आधार-सक्षम ई-KYC प्रणाली	किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC)	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, लघु वित्त बैंक आदि

वित्तीय समावेशन का महत्व

ऋण नहीं मिलने की समस्या को दूर करना: उदाहरण के लिए- यह MSMEs को बैंकों से ऋण लेने में मदद करता है।	**बचत की आदतों को बढ़ावा देना:** यह **देश में पूंजी निर्माण को बढ़ाने** में मदद कर सकता है।	**समावेशी विकास:** यह शिक्षा और स्वास्थ्य-देखभाल में निवेश को प्रोत्साहित करके **गुणक प्रभाव (Multiplier effect)** पैदा करता है	**सब्सिडी वितरण में खामियों को दूर करना:** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के उपयोग की वजह से वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान **63,000 करोड़ रुपये** से अधिक की बचत हुई।	**वित्तीय समावेशन के जरिए 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 7 लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।**

वित्तीय समावेशन के समक्ष चुनौतियां

मांग पक्ष कारक: निम्न आय होना या अपने नाम से परिसंपत्ति नहीं होना, वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता की कमी	**आपूर्ति पक्ष:** वित्तीय संस्थान ऐसे लोगों को ऋण देने से बचते हैं जिनकी आय कम है या जिन्हें अधिक राशि का ऋण देकर लाभ नहीं कमाया जा सकता।	**विनियामकीय बाधाएं:** नो-योर-कस्टमर (KYC) का सख्ती से पालन करने की अनिवार्यता	**लैंगिक और सामाजिक-आर्थिक बाधाएं**	**अन्य: डिजिटल सेवाओं और अवसंरचना की कमी, वित्तीय साक्षरता का अभाव, आदि**

आगे की राह

सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना: जैसे-JAM त्रिनिट्री (सार्वजनिक अवसंरचना, निजी बैंक बैंक-कॉरेस्पोंडेंट्स+फिनटेक सहायता)	**वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना**	**फिनटेक नवाचारों का लाभ उठाना:** जैसे-मोबाइल बैंकिंग	**आम लोगों की जरूरत के अनुरूप वित्तीय सेवाएं:** उदाहरण के लिए, **प्रधान मंत्री अटल पेंशन योजना।**	सुरक्षित डेटा शेयरिंग प्रोटोकॉल के जरिये **साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण को मजबूत करना।**

2.7.2. प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के 10 वर्ष (10 Years of PMJDY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) की 10वीं वर्षगांठ** मनाई गई। **PMJDY का मूल उद्देश्य** भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) के बारे में

- **शुरुआत:** यह योजना अगस्त, 2014 में शुरू की गई थी।
- **प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY)** वास्तव में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन (NMFI) है। यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है।

- **उद्देश्य: प्रत्येक भारतीय के लिए** बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (BSBDA)[5], रेमिटेंस, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी **वित्तीय सेवाओं को किफायती दरों पर उपलब्ध** करवाना।
- **मंत्रालय: केंद्रीय वित्त मंत्रालय** (वित्तीय सेवाएं विभाग)
- **योजना की मुख्य विशेषताएं:**
  - **PMJDY के छह स्तंभ** हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - **बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना: बैंकिंग सुविधा से वंचित प्रत्येक वयस्क** का बैंक खाता खोलना इस योजना का सबसे प्रमुख उद्देश्य है।
  - **बीमा कवरेज प्रदान करना:** नकद निकासी और मर्चेंट लेन-देन वाले स्थानों पर भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना।
    - 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए **PMJDY खातों के तहत जारी रुपे (RuPay) कार्ड पर निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर** 1 लाख रुपये से बढ़ाकर **2 लाख रुपये** कर दिया गया है।
  - **वित्तीय सेवा से वंचित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना:** अन्य वित्तीय उत्पाद जैसे कि माइक्रो-इंश्योरेंस; उपभोग बढ़ाने के लिए ओवरड्राफ्ट की सुविधा, माइक्रो-पेंशन और माइक्रो-क्रेडिट।

PMJDY की प्रमुख उपलब्धियां

- **बड़ी संख्या में नए खाते खोले गए:** अगस्त, 2024 तक **53.13 करोड़ जन धन खाते** खोले जा चुके थे, जबकि मार्च, 2015 तक यह संख्या 14.72 करोड़ थी।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा:** PMJDY खाताधारकों को **36.14 करोड़ रुपे कार्ड** जारी किए गए हैं। इससे कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा मिला है और खाताधारकों को दुर्घटना बीमा कवरेज भी प्राप्त हुआ है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय संसाधन की कमी को दूर करना:** जन धन दर्शक ऐप के अनुसार, देश के लगभग सभी गावों के 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध हैं।
- **PMJDY खातों में औसत जमा राशि में वृद्धि:** 2015 से 2024 के बीच जमा-राशि में 4.12 गुना वृद्धि हुई है और **कुल जमा राशि 2.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।**
- **जीरो बैलेंस वाले खातों की संख्या में कमी:** ऐसे खातों की संख्या 2015 में 8.52 करोड़ थी, जो अब कम होकर 4.26 करोड़ रह गई है।

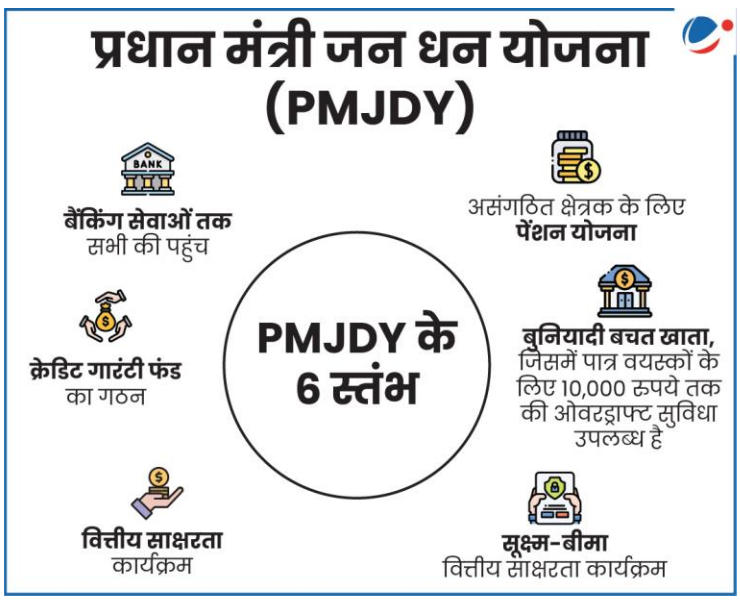

निष्कर्ष

PMJDY की दस साल की यात्रा **भारत के वित्तीय समावेशन परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी बदलाव को उजागर करती** है। इसने लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है। ग्रामीण-शहरी वित्तीय अंतर को पाटने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के द्वारा, PMJDY ने **समावेशी और लचीले आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत नींव रखी** है।

[5] Basic Savings Bank Deposit Account

2.7.3. माइक्रोफाइनेंस के 50 वर्ष (50 Years of Microfinance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्वरोजगार महिला संघ (SEWA)[6] बैंक की 50वीं वर्षगांठ **भारत में माइक्रोफाइनेंस संस्था (MFI) के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक** है। गौरतलब है कि SEWA बैंक की स्थापना **1974** में **गुजरात** में एक **सहकारी बैंक** के रूप में हुई थी।

माइक्रोफाइनेंस क्या है?

- **परिभाषा:** माइक्रोफाइनेंस, जिसे सूक्ष्म ऋण भी कहा जाता है, एक वित्तीय सेवा है जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों और छोटे व्यवसायों को ऋण जैसी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
- **सेवाएं:** ये संस्थाएं मुख्य रूप से गरीब परिवारों और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करती हैं, लेकिन कुछ माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं जमा भी स्वीकार करती हैं, वहीं कुछ संस्थाएं बीमा जैसी वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करती हैं। कुछ संस्थाएं वित्तीय प्रबंधन के लिए अपने ग्राहकों को सलाह और प्रशिक्षण भी प्रदान करती हैं।

भारत में माइक्रोफाइनेंस का महत्व

- **गरीबी उन्मूलन:** NABARD का **स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP)** विश्व का सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम **17.8 करोड़ परिवारों को 144 लाख** से अधिक SHGs के माध्यम से सशक्त बना रहा है।
- **आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा:** माइक्रोफाइनेंस ऋणों में से 46% ऋण ऐसे परिवारों को दिए जाते हैं जिनकी मासिक आय 20,000 रुपये से कम है, ताकि **वे अपनी आय सृजन गतिविधियों और संपत्तियों (जैसे- पशुधन) के प्रबंधन के लिए कार्यशील पूंजी प्राप्त कर सकें।**
- **महिला सशक्तीकरण:** बैंकों से जुड़े 88% SHGs महिलाओं द्वारा संचालित हैं।
  - **केरल में कुदुम्बश्री** अपने **बचत और ऋण कार्यक्रम** के माध्यम से राज्य में वंचित महिलाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने में अहम भूमिका निभा रही है।
- **वित्तीय समावेशन:** माइक्रोफाइनेंस उन समुदायों की आर्थिक मदद करता है जो किन्हीं वजहों से पारंपरिक बैंकों से जुड़ नहीं पाए हैं।
  - पिछले दस वर्षों में माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं के ग्राहकों की संख्या में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। ये संस्थाएं वित्त वर्ष 2024 में 140 मिलियन परिवारों को सेवाएं प्रदान कर रही थीं।
- **सामाजिक प्रभाव:** उदाहरण के लिए, **उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक** की **'छोटे कदम'** पहल ने कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) और अस्पतालों का नवीनीकरण करके स्वास्थ्य-देखभाल क्षेत्र में अहम योगदान दिया है।

भारत में माइक्रोफाइनेंस के समक्ष चुनौतियां

- **ऋण जाल में फंसना:** कई मामलों में, व्यक्ति अपने ऋण को चुकाने के लिए कई अन्य माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं से ऋण ले लेते हैं। इस तरह वे ऋण जाल में फंस जाते हैं।
  - MFIs की कुल 'प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियां (AUM)[7]' यानी उनके पास जितना भी पैसा उधार देने के लिए है, उसमें से लगभग 8 से 10 प्रतिशत ऐसे लोगों को दिया गया है जिन्होंने पहले से ही चार या उससे ज्यादा जगहों से कर्ज ले रखा है।
- **विनियमन और गवर्नेंस:** भारत में **माइक्रोफाइनेंस बैंक का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा** किया जाता है, जबकि **राज्य सरकारें** राज्य सहकारी समिति अधिनियमों (सहकारी बैंकों के लिए) के तहत माइक्रोफाइनेंस सहकारी बैंकों और सहकारी समितियों को विनियमित करती हैं।
- **ऋण के बदले कोलेटरल (गिरवी) नहीं रखना और ऋण वापस नहीं मिलने का जोखिम:** इससे NPAs में वृद्धि होती है।।
- **माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं का लंबे समय तक संचालन पर संदेह:** ये संस्थाएं सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं लेकिन इससे इन्हें अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त नहीं होता है। केवल कुछ संस्थाएं ही लाभ अर्जित कर रही हैं। जाहिर है कि लंबे समय में इनका संचालन प्रभावित होगा।

[6] Self Employed Women's Association

[7] Assets Under Management

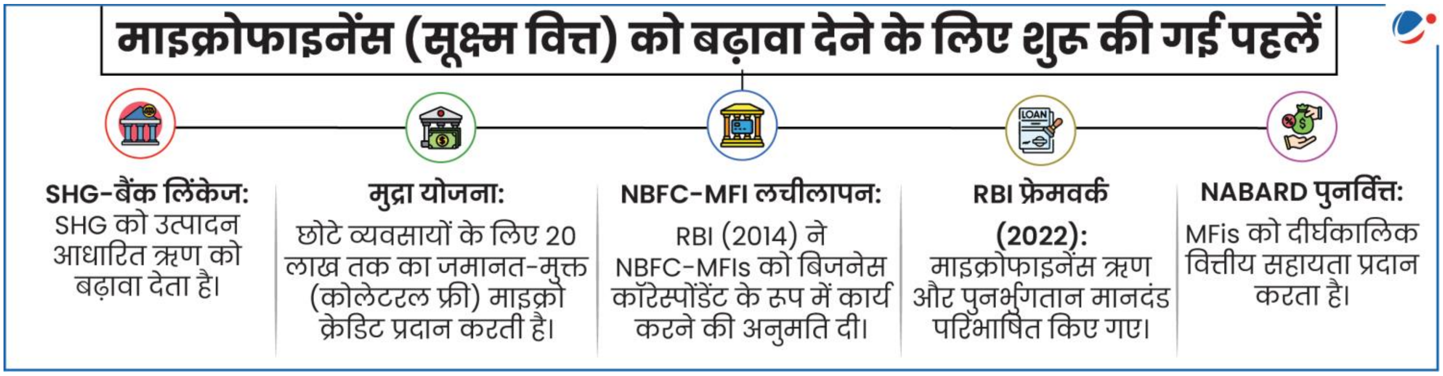

आगे की राह

- **प्रत्येक आवेदक को अधिकतम चार की बजाय केवल तीन संस्थाओं से ऋण लेने की अनुमति**: एक व्यक्ति को माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं से 3 लाख रुपये की बजाय **अधिकतम 2 लाख रुपये ही ऋण** दिए जाएं।
- **माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं का क्षेत्रकों के आधार पर वर्गीकरण**: माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को किफायती आवास, जलवायु परिवर्तन, जल और स्वच्छता, स्वास्थ्य-देखभाल जैसे अलग-अलग क्षेत्रकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।
- **वित्तीय साक्षरता:** वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, बीमा के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और माइक्रोफाइनेंस उद्योग की वृद्धि में सहायक हो सकती है।
- **सर्वोत्तम उदाहरणों से सीखना:** तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिणी राज्यों में माइक्रोफाइनेंस वितरण नेटवर्क अच्छी तरह से विकसित हैं। देश के अन्य क्षेत्रों को भी इन संस्थाओं से सीखने की जरूरत है।

निष्कर्ष

भारत में माइक्रोफाइनेंस की 50 वर्षों की विकास यात्रा यह दर्शाती है कि इसने **गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन** में परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। भविष्य में, इसका प्रभाव भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास पर और अधिक गहराई से पड़ सके, इसके लिए **अधिक सतत, प्रौद्योगिकी-आधारित और विनियमित माइक्रोफाइनेंस प्रणाली** अत्यंत आवश्यक होगा।

2.7.4. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): एक नज़र में {Direct Benefit Transfer (DBT) at a Glance}

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

SBI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न योजनाओं के तहत DBT के माध्यम से महिलाओं को दी राशि 2 ट्रिलियन रुपये को पार कर गई है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

कैश ट्रांसफर: उदाहरण- प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (किसान आय सहायता), पेंशन (वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन), छात्रवृत्ति आदि।	**वस्तुओं (मद) के रूप में सहायता:** उर्वरक सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज वितरण (PDS), मिड डे मील (पी.एम. पोषण), आदि।

DBT को संभव बनाने वाले घटक

JAM (जन धन-आधार नंबर-मोबाइल) ट्रिनिटी	मोबाइल मनी	बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स (BC) इंफ्रास्ट्रक्चर	पेमेंट बैंक

DBT का प्रभाव

योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन: 2016 से अब तक DBT के माध्यम से **90 करोड़ लोगों को 450 से अधिक योजनाओं का लाभ पहुंचाया** गया है।	लॉकडाउन के दौरान आवश्यक राहत पैकेज प्रदान की गई, उदाहरण के लिए- 11.42 करोड़ लाभार्थियों को 27,442 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।	**भ्रष्टाचार में कमी:** पात्र लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिली है।	**वित्तीय समावेशन:** IMF **ने भारत की DBT पहल की प्रशंसा करते हुए इसे एक "लॉजिस्टिक मार्वेल"** करार दिया है।

DBT के कार्यान्वयन में चुनौतियां

लाभार्थियों की पहचान में समस्या	नियमों का अनुपालन और परिचालन संबंधी समस्याएं	**भुगतान प्रणालियों की समस्याएं:** केवल 27% गांवों में ही बैंकों की वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हैं।	कम वित्तीय समावेशन, डिजिटल डिवाइड होना और डिजिटल साक्षरता की कमी

आगे की राह

अनौपचारिक श्रमिकों जैसे वंचित समूहों की पहचान करना और उन तक लाभ पहुंचाना	**ग्रामीण आबादी में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना**	डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करना	**सिंगल विंडो शिकायत-निवारण प्रणाली**

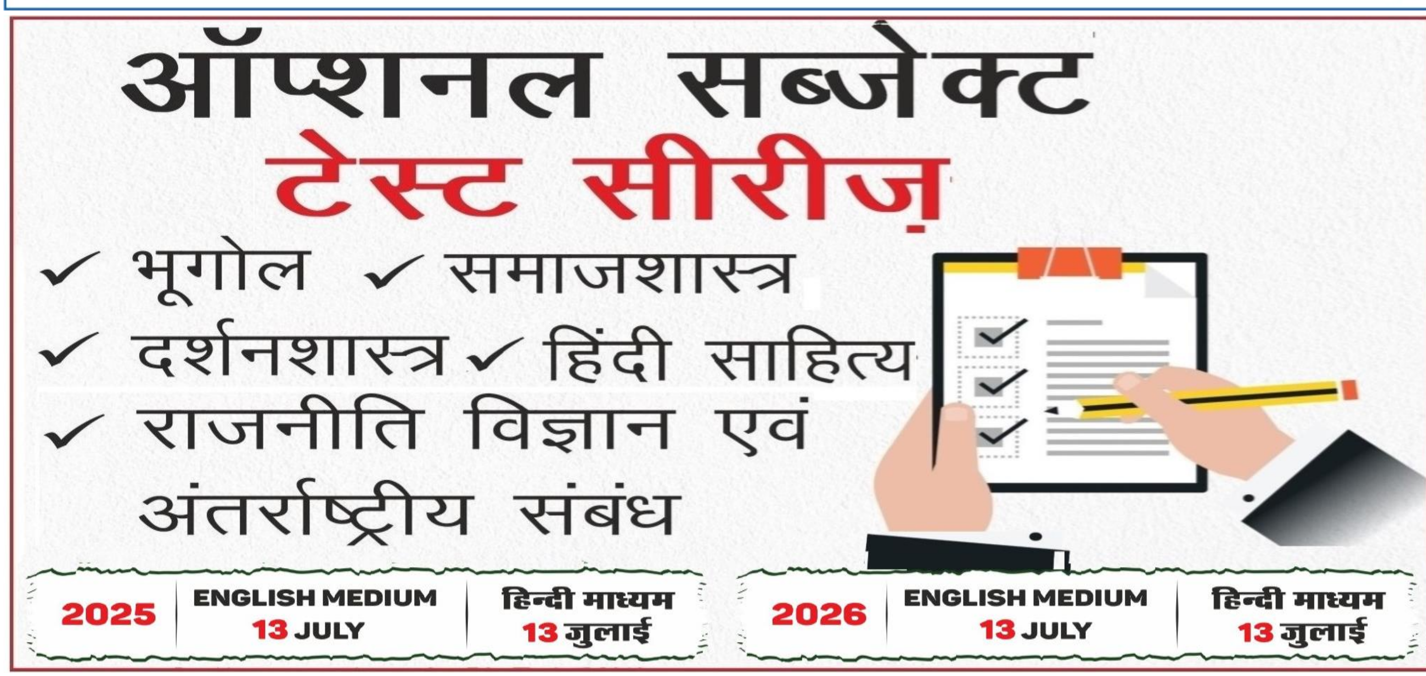

2.8. असमानता (Inequality)

2.8.1. भारत में आर्थिक असमानता: एक नज़र में (Economic Inequality in India at a Glance)

भारत में आर्थिक असमानता

भारत में असमानता की स्थिति

आय असमानता: भारत के **सबसे धनी 1%** लोगों के पास देश की सकल राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा है (वर्ल्ड इक्वेलिटी लैब रिपोर्ट, 2022-23)	**धन की असमानता: सबसे धनी** 5% भारतीयों के पास देश की 60% से अधिक संपत्ति है।	**ग्रामीण-शहरी विभाजन:** औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE) **ग्रामीण भारत में 4,122 रुपये** और **शहरी भारत में 6,996 रुपये** है।	**पुरुषों और महिलाओं की पारिश्रमिक में अंतर: भारतीय महिलाएं पुरुषों द्वारा अर्जित प्रत्येक 100 रुपये की तुलना में लगभग 40 रुपये अर्जित करती हैं,** (ग्लोबल गैप रिपोर्ट 2024)।

बढ़ती आर्थिक असमानता के कारण

असमान आर्थिक संवृद्धि: कुछ राज्य और कुछ सेक्टर्स असमान रूप से अधिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं।	**कोविड-19 महामारी:** कोविड-19 के कारण भारतीय आबादी में सबसे कम आय वाले 50% लोगों की संपत्ति में कमी आई है।	**कर प्रणाली:** कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया, जबकि उत्पाद शुल्क और GST में उल्लेखनीय वृद्धि की गई।	**गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य-देखभाल सेवा की कमी:** यह पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी के दुष्चक्र को बनाए रखती है और आर्थिक उन्नति को सीमित करती है

आर्थिक असमानता कम करने के लिए उठाए गए कदम

समावेशी विकास: दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा आदि।	**वित्तीय समावेशन:** पीएम जन-धन योजना, पीएम मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया स्कीम,आदि।	**सामाजिक सुरक्षा योजनाएं:** अटल पेंशन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना आदि।	**लैंगिक समानता:** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, स्वाधार गृह आदि।

संपत्ति और आय असमानता को कम करने में चुनौतियां

भारत के पास सीमित वित्तीय संसाधन होना	**सामाजिक असमानताओं का दुष्चक्र:** जातिगत, लैंगिक असमानता, आदि	**कम-प्रभावी शासन:** नीतियों को सही से लागू नहीं करना, भ्रष्टाचार।	**संरचनात्मक सुधारों का विरोध,** जैसे भूमि सुधार, प्रगतिशील कराधान (प्रोग्रेसिव टैक्स) आदि।

आगे की राह

रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाली नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए,	शिक्षा और स्वास्थ्य-देखभाल सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना।	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सही से लागू करना	सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करना	भारत के सबसे धनी लोगों पर कर लगाना।

2.8.2. विकास में क्षेत्रीय असमानता (Regional Disparity in Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) द्वारा **"भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन[8]: 1960-61 से 2023-24"** शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया गया। इसमें भारतीय राज्यों में असमान विकास को रेखांकित किया गया है।

वर्किंग पेपर में रेखांकित मुख्य ट्रेंड्स पर एक नज़र

- **सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय में असमानता: भारत के पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र** इस मामले में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 250.8% (2.5 गुना अधिक) है।

[8] Relative Economic Performance of Indian States

- **भारत की GDP में दक्षिणी राज्यों का प्रभुत्व:** कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु ने 2023-24 में भारत की GDP में 30% से अधिक का योगदान दिया।
- कुल मिलाकर **समुद्र तटीय राज्यों का प्रदर्शन बेहतर** रहा है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी समुद्र तटीय राज्यों ने अन्य राज्यों की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर प्रदर्शन किए हैं।
- **पूर्वी क्षेत्र के राज्य चिंता का विषय बने हुए हैं:** पिछले कई दशकों में, पश्चिम बंगाल का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन कमजोर हुआ है। वहीं बिहार की सापेक्ष स्थिति पिछले दो दशकों में स्थिर बनी हुई है, फिर भी यह अन्य राज्यों से काफी पीछे है।

क्षेत्रीय असमानता के लिए जिम्मेदार कारक

- **ऐतिहासिक:** ब्रिटिश नीतियों में संसाधन संपन्न क्षेत्रों (जैसे- कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) को अधिक तरजीह दी गई थी।
- **भौगोलिक:** दुर्गम भू-भाग (जैसे- पूर्वोत्तर राज्य) वाले क्षेत्रों में प्रशासन और परियोजना क्रियान्वयन की लागत बढ़ जाती है। बिहार और असम में बार-बार बाढ़ आने से वहां का विकास धीमा हो जाता है।
- **आर्थिक:**
  - **प्राथमिक क्षेत्रक का आर्थिक गतिविधियों का प्रभुत्व:** कृषि पर निर्भर अधिक आबादी वाले राज्यों की तुलना में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक में अधिक कार्यरत आबादी वाले राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र और गुजरात।
  - **खराब अवसंरचना का प्रभाव:** खराब परिवहन अवसंरचना और बैंकिंग सेवाएं पिछड़े क्षेत्रों में विकास को सीमित करती हैं।
- **गवर्नेंस:**
  - **राजनीतिक अस्थिरता:** अस्थिर सरकारें तथा कानून और व्यवस्था से जुड़ी चिंताएं निवेश को हतोत्साहित करती हैं और पूंजी के बहिर्वाह यानी बाहर जाने को बढ़ावा देती हैं।
  - **सरकारी योजनाओं की विफलता:** उद्योग ऐसे स्थानों पर अधिक स्थापित किए जाते हैं, जहां आधारभूत संसाधन (जैसे कि बिजली और जल की निरंतर आपूर्ति, बेहतर सड़क और रेलवे अवसंरचना, कुशल श्रम आदि) पहले से उपलब्ध होते हैं।

विकास में क्षेत्रीय असमानता के प्रभाव

- **सुरक्षा संबंधी खतरे:** उदाहरण के लिए, नक्सलवाद मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में केंद्रित है, जहां विकास कम हुआ है।
- **राजनीतिक विखराव:** उदाहरण के लिए, तेलंगाना राज्य का गठन तथा महाराष्ट्र में विदर्भ और असम में बोडोलैंड राज्य की मांग, आदि।
- **बेहतर आजीविका के लिए प्रवासन:** उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे अधिक लोग प्रवास करते हैं, जबकि महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे अधिक प्रवासी आते हैं (जनगणना 2011)।
- **असंतुलन को बढ़ावा:** समृद्ध क्षेत्र अधिक निवेश आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर दूसरे शहरों की तुलना में तेजी से विकसित हो गए हैं।
- **पर्यावरण पर प्रभाव:** एक ही क्षेत्र में बहुत अधिक औद्योगिक विकास के कारण वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होता है, उदाहरण के लिए- दिल्ली में प्रदूषण।

विकास में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए आगे की राह

- **अप्रोच में सुधार:** उदाहरण के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए एक जैसी योजना बनाने और लागू करने के बजाय, अलग-अलग क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना बनाई जानी चाहिए। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र विकास तथा शुष्क क्षेत्रों में सूखा प्रवण क्षेत्र विकास जैसे कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **प्रदर्शन के आधार पर वित्त-पोषण:** वित्त-पोषण प्रदान करने के तरीके को विकास मानक लक्ष्यों को पूरा करने से जोड़ा जाना चाहिए।
- **पिछड़े राज्यों में सुशासन को बढ़ावा देना:** प्रभावी प्रशासन से विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में राज्यों को राजस्व बढ़ाने, निवेश आकर्षित करने तथा संसाधनों के उपयोग में सुधार करने में मदद मिलती है।
- **संतुलित अवसंरचना विकास:** अविकसित राज्यों में अवसंरचना (बिजली, परिवहन, दूरसंचार, सिंचाई) में सुधार, निवेश और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देने की कुंजी है।
- **क्षेत्रीय निवेश:** विशेष रूप से **पिछड़े क्षेत्रों में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज** पर ध्यान केंद्रित करके कृषि में निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

© Vision IAS

निष्कर्ष

सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे अनुकूल माहौल बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो नवाचार को बढ़ावा दे, निवेश को आकर्षित करे और संसाधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करे। गवर्नेंस और अवसंरचना में सुधार तथा सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के जरिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना अन्य आवश्यक कदम हो सकते हैं।

2.9. ग्रामीण विकास (Rural Development)

2.9.1. ग्रामीण औद्योगीकरण: एक नज़र में (Rural Industrialization at a Glance)

ग्रामीण औद्योगीकरण

राष्ट्रीय विकास में ग्रामीण औद्योगीकरण की भूमिका

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण	अतिरिक्त और ऑफ-सीजन रोजगार प्रदान करता है	समावेशी राष्ट्रीय विकास	संतुलित औद्योगिकीकरण	**अन्य:** भारत की समृद्ध संस्कृति का संरक्षण; महिला सशक्तीकरण, आदि।

ग्रामीण उद्योगों के विकास में प्रमुख बाधाएं

संरक्षण सिंड्रोम जिसमें 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों के बाद लघु उद्योगों के लिए आरक्षित क्षेत्र आयातित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ था।	समय पर **आवश्यक ऋण प्राप्त करने में असमर्थता**	विपणन, परिवहन, वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं आदि **के लिए अवसंरचना की कमी**	**कच्चे माल की खरीद के लिए** शहरी उद्योगों के साथ **प्रतिस्पर्धा**	उपयुक्त प्रौद्योगिकी की कमी और **उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को अपनाने में असमर्थता**

चुनौतियों से निपटने और ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहलें

औपचारिक संस्थागत व्यवस्था: खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) लिमिटेड	**पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा:** 'स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (SFURTI)', 'अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स/क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट (USTAD) योजना	**लघु उद्यमों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना:** नाबार्ड और सिडबी की स्थापना, सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देना	**प्रशिक्षण प्रदान करना और कौशल विकास:** सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम	**कृषि आधारित उद्योगों के लिए योजनाएं:** कृषि आधारित उद्योगों के लिए एस्पायर (ASPIRE) योजना, खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रधान मंत्री संपदा योजना, आदि।

ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने और तेज करने की दिशा में आगे की राह

ग्रामीण औद्योगिक नीति बनाना	ग्रामीण उद्योगों को परिभाषित करना	**उत्पादन की तकनीकों को अपग्रेड करना**	**कौशल विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण**	**अन्य: ग्रामीण महिलाओं की कौशल क्षमता का उपयोग करना; अवसंरचना में कमियों को दूर करना, आदि।**

2.9.2. ग्रामीण विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका (Role of Technology in Rural Growth)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हरियाणा के मंडौरा में **"रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप (रूटेज/ RuTAGe) स्मार्ट विलेज सेंटर (RSVC)"** का शुभारंभ किया गया।

RSVC के बारे में

- RSVC को **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय के तत्वाधान** में विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य **ग्रामीण जरूरतों के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना,** उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना एवं संधारणीय समाधानों के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना है।

- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय ने **2003-04 में RuTAGe की अवधारणा** तैयार की थी।

RSVC मॉडल की मुख्य विशेषताएं

- **भौतिक उपस्थिति:** यह पंचायत स्तर पर **दीर्घकालिक तकनीकी सहायता प्रदान** करता है, आदि।
- **बाजार तक पहुंच:** ग्रामीण उत्पादकों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए **ONDC, अमेजन और मार्केट मिर्ची** जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग पर जोर देता है।
- **व्यापकता:** RSVC मॉडल का विस्तार करने हेतु देश भर में 20 नए केंद्र खोलने की योजना है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए **टेकप्रेन्योर्स कार्यक्रम** के माध्यम से **महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने** की भी योजना है।

ग्रामीण विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका

- **कृषि नवाचार: ई-नाम (e-NAM)** जैसे प्लेटफॉर्म किसानों को बाजारों से जोड़ते हैं तथा कृषि उपज का बेहतर मूल्य और पारदर्शी व्यापार प्रदान करते हैं।
- **उद्यमिता: ई-कॉमर्स** और **3D प्रिंटिंग** जैसी तकनीक छोटे व्यवसायों का समर्थन करती हैं। इससे उन्हें वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है।
- **शिक्षा: पी.एम.ई-विद्या (PM e-VIDYA)** और **स्वयं (SWAYAM)** जैसे कार्यक्रम, ऑनलाइन तरीके से बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही, छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार भी करते हैं। इसके अलावा, इस तरह के तकनीकी नवाचार समाज में डिजिटल विभाजन को खत्म करने का कार्य भी करते हैं।
- **वित्तीय समावेशन: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कार्यक्रम और पी.एम. जन धन योजना** प्रत्यक्ष व नकद रहित अंतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये धोखाधड़ी को कम करते हैं और पारदर्शिता बढ़ाते हैं।
- **जल प्रबंधन: राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM)** भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। इससे कृषि क्षेत्रक में जल का दक्ष उपयोग सुनिश्चित होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई सरकारी पहलें

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तकनीकी उन्नति (Technological Advancement in Rural Areas: TARA)
'कौशल संवर्धन शिक्षा एवं विकास कार्यक्रम' का एक भाग। इसका लक्ष्य ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी समाधानों को लागू करने वाले विज्ञान-आधारित संस्थानों को सहायता प्रदान करना है।

ई-श्रम प्लेटफॉर्म
यह असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ और सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने में मदद करता है।

राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क
यह इंटरनेट बैंडविड्थ और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य की राजधानियों, जिलों और 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ता है।

डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम
यह भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण करता है तथा राज्य-विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार भूमि संबंधी जानकारी के प्रबंधन के लिए तकनीक विकसित करता है।

निष्कर्ष

RSVC की शुरुआत प्रौद्योगिकी-आधारित ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो इनोवेशन और स्थानीय आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटने का कार्य करती है। यह पहल बदलती जरूरतों को पूरा करने वाले समाधानों, बाजार तक पहुंच और स्थानीय लोगों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर समावेशी और सतत ग्रामीण विकास को गति देने की क्षमता रखती है।

2.10. भूमि सुधार: एक नज़र में (Land Reform at a Glance)

भूमि सुधार

मुख्य तथ्य

2010-11 में कृषि जोत का औसत आकार **1.15 हेक्टेयर** था।	भूमि का **10% से अधिक हिस्सा** गैर-कृषि उपयोग में है।	कुल भौगोलिक क्षेत्र के **25% हिस्से** पर वन है।

मुख्य उद्देश्य

लैंड लीजिंग को सरल और **वैधानिक** बनाना।	किसानों के **छोटे प्लॉट्स को एकत्रित करना,** ताकि कृषि दक्षता और समता को बढ़ाया जा सके।	**डिजिटल और एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रणाली** का निर्माण करना, जो सभी राज्यों में सुलभ हो।	**वन भूमि के प्रबंधन** में दक्षता बढ़ाना।	**संपत्ति अधिकारों,** खासकर वन भूमि पर समुदायों के अधिकारों को मजबूत बनाना।

बाधाएं

भू-स्वामित्व में असमानता: उदाहरण के लिए-भारत में टॉप 10% के पास 45% कृषि-भूमि का स्वामित्व है।	**भूमि का छोटा आकार:** उदाहरण के लिए-राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुसार 35.6% किसानों के पास एक हेक्टेयर से कम जमीन है (2019)।	**कानूनी बाधाएं:** भूमि राज्य सूची का विषय है, इस वजह से राज्यों में भूमि से जुड़े अलग-अलग कानून हैं।	**ऋण नहीं मिलना:** भू-स्वामित्व का रिकॉर्ड (भू-अभिलेख) नहीं होना, एक ही जमीन पर अलग-अलग दावे जैसी वजहों से औपचारिक संस्थाओं (बैंकों) से ऋण मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

प्रमुख पहलें

डिजिटल इंडिया भूमि-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernisation Programme: DILRM)	**स्वामित्व/SVAMITVA** (सर्वे ऑफ विलेजेज़ एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम)	**राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (NLRMP)** जिसे अब DILRMP में मिला दिया गया है।	**मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट, 2016**

आगे की राह

मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट, 2016 को अपनाना: राज्य सरकारें भूमि पट्टे को औपचारिक बनाने और आसान बनाने के लिए इसे अपनाने पर विचार कर सकते हैं।	**विखंडित भूमि को एकीकृत करना (चकबंदी):** किसानों की बिखरी हुई कृषि-भूमियों को एक जगह करना चाहिए ताकि कृषि-उत्पादकता बढ़ाई जा सके।	**शहरी विकास के लिए भूमि का लाभ उठाना:** शहरी विकास को समर्थन देने के लिए भूमि का उपयोग वित्तीय संसाधन के रूप में करना।	**भूमि रिकॉर्ड प्रणालियों का आधुनिकीकरण; सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना:** बंजर भूमि के विकास के लिए, आदि।

2.10.1. भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण (Digitization of Land Records)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अधिसूचित किया कि **2016 से ग्रामीण भारत में लगभग 95% भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण** का कार्य पूरा किया जा चुका है। यह उपलब्धि **डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP)**[9] के कारण प्राप्त की जा सकी है।

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के बारे में

- **कार्यक्रम की शुरुआत: 2016** में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को नया रूप देकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
- **संबंधित मंत्रालय:** यह **ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग** के तहत **केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है।

[9] Digital India Land Records Modernization Programme

- इस योजना की कार्यावधि **2021-22 से बढ़ाकर 2025-26** तक कर दी गई है। इसमें **दो नए घटक शामिल** किए गए हैं।
  - देश के सभी **राजस्व न्यायालयों** का कम्प्यूटरीकरण करना और भूमि अभिलेखों के साथ उनका **एकीकरण** करना।
  - सहमति के आधार पर **आधार संख्या को अधिकार अभिलेखों (RoRs) से जोड़ना।**

- **उद्देश्य:** मैनुअल रूप से आनुमानित (Presumptive) भू-स्वामित्व प्रणाली को डिजिटल रूप से निर्णायक भू-स्वामित्व प्रणाली से बदलना।
- **DILRMP के अंतर्गत प्रमुख पहलें:** भू-आधार, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, ई-कोर्ट एकीकरण, भूमि सम्मान।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण की आवश्यकता क्यों है?

- **भूमि स्वामित्व विवाद:** निर्णायक स्वामित्व की कमी, जालसाजी के माध्यम से अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण और बेनामी संपत्ति आदि, भू-स्वामित्व संबंधी विवादों में वृद्धि का कारण बने हैं।
  - भारत में **60% से अधिक मुकदमे भूमि से संबंधित** हैं।
  - निर्णायक भू-स्वामित्व प्रणाली में, भूमि अभिलेख **वास्तविक स्वामित्व का निर्धारण** करते हैं। स्वामित्व सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
- **अकुशल प्रशासनिक प्रक्रियाएं:** भूमि अभिलेखों को अपडेट करने और सुधारने की प्रणाली बहुत **जटिल, विस्तृत और धीमी** है। इसमें भ्रष्टाचार, भूमि को हड़पना आदि शामिल हो सकता है।
- **अप्रचलित मानचित्रण:** अपडेटेड अभिलेखों की कमी के कारण मौजूदा अभिलेख, कब्जे और स्वामित्व से संबंधित वर्तमान जमीनी हकीकत के अनुरूप नहीं हैं।
- **लक्षित सार्वजनिक सेवा वितरण:** उदाहरण के लिए- **पीएम-किसान योजना** के माध्यम से सरकार सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करती है।
- **राजस्व प्रशासन को मजबूत करना:** संपत्ति कर और भूमि-आधारित कर **स्थानीय निकायों** के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है।

भूमि के डिजिटलीकरण से संबंधित अन्य पहल

- **स्वामित्व (SVAMITVA) योजना:** यह योजना ड्रोन से सर्वेक्षण कराकर ग्रामीण आवासीय भूमि के स्वामित्व को कानूनी दर्जा प्रदान करती है।
  - इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को प्रॉपर्टी कार्ड देकर उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि उन्हें बैंकों से ऋण लेने, जमीन विवादों के समाधान और भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद मिल सके।

भूमि के डिजिटलीकरण में मौजूद चुनौतियां

- **अनुमानित भू-स्वामित्व (Presumptive land titling): संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882** के आधार पर भूमि के हस्तांतरण के लिए **भूमि के स्वामित्व** की बजाय **बिक्री विलेखों (sales deeds) के पंजीकरण** की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, **संपत्ति का वास्तविक लेन-देन** भी हमेशा **स्वामित्व की गारंटी** नहीं देता है।
- **विभागों का अलग-अलग दृष्टिकोण: उदाहरण के लिए-** बिक्री विलेख पंजीकरण विभाग में संग्रहित किए जाते हैं, नक्शे सर्वेक्षण विभाग में संग्रहित किए जाते हैं, और संपत्ति कर रसीदें राजस्व विभाग के पास होती हैं।
- **पंजीकरण से संबंधित कानूनी प्रावधान:** सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण, एक साल से कम समय के लिए दी जाने वाली संपत्ति का पट्टा, और **1908 के पंजीकरण अधिनियम** के तहत होने वाला उत्तराधिकार विभाजन, इन सभी के लिए पंजीकरण करवाना जरूरी नहीं है। इससे **मुकदमेबाजी में वृद्धि** हुई है।
- **अन्य:** विरासत डेटा से जुड़ी समस्याएं, परिवर्तन के लिए हितधारकों का प्रतिरोध, कुछ क्षेत्रों में अवसंरचना की कमी, प्रक्रियात्मक जटिलताएं, तकनीकी बाधाएं आदि।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा प्रमाणित भू-स्वामित्व अधिकार को अपनाने सहित कानूनी सुधारों, प्रौद्योगिकी को अपनाने और क्षमता निर्माण से भूमि अभिलेख प्रबंधन की पारदर्शिता, सटीकता और दक्षता में वृद्धि होगी।

ऑप्शनल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़
✓ भूगोल ✓ समाजशास्त्र ✓ दर्शनशास्त्र ✓ हिंदी साहित्य
✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध
2025 ENGLISH MEDIUM 13 JULY हिन्दी माध्यम 13 जुलाई
2026 ENGLISH MEDIUM 13 JULY हिन्दी माध्यम 13 जुलाई

2.11. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Economics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार **डारोन ऐसमोग्लू, साइमन जॉनसन** और **जेम्स ए. रॉबिन्सन** को दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार **"संस्थाओं का निर्माण कैसे किया जाता है और समृद्धि पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है[10]"** विषय पर उनके शोध कार्य के लिए दिया गया है।

पुरस्कार विजेताओं के शोध के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **समृद्धि पर औपनिवेशिक शासन का प्रभाव:** औपनिवेशिक सरकारों ने 16वीं शताब्दी से ऐसी संस्थाएं स्थापित कीं, जिससे उपनिवेशों का "भाग्य पलट गया (Reversal of Fortunes)", और कभी सबसे गरीब रहे देश सबसे अमीर बन गए।
- **औपनिवेशिक संस्थाओं के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारक:** नए बसने वालों की मृत्यु दर और जनसंख्या घनत्व ने औपनिवेशिक काल के दौरान स्थापित संस्थाओं के प्रकार और प्रकृति को गहराई से प्रभावित किया।
    - गौरतलब है कि भूमध्यरेखा के नजदीक रोगों के खतरे वाले क्षेत्रों में मृत्यु दर अधिक थी।
- **संस्थाओं के प्रकार:** कुछ समाज शोषक संस्था बनकर रह गए हैं, जो प्रगति को सीमित कर रहे हैं। हालांकि, नोबेल पुरस्कार विजेता इस बात पर जोर देते हैं कि इनमें परिवर्तन संभव है। वे मानते हैं कि सुधारों को अपनाने से लोकतंत्र और कानून का शासन स्थापित हो सकता है, जिससे गरीबी कम हो सकती है।

राष्ट्रीय समृद्धि को दिशा देने में आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका

- **संसाधन आवंटन और संपत्ति का अधिकार:** आर्थिक संस्थाएं संसाधनों के आवंटन और सुरक्षा का निर्धारण करती हैं।
    - उदाहरण के लिए- भारत के संविधान का **अनुच्छेद 300A** (संपत्ति का अधिकार) यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्रावधान के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
- **निवेश के लिए प्रोत्साहन:** समावेशी संस्थाएं प्रतिस्पर्धा और उद्यमशीलता को बढ़ावा देती हैं, जिससे विकास को बढ़ावा मिलता है।
    - उदाहरण के लिए- भारत में **राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन (NIF)** जमीनी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देता है।
- **संधारणीयता:** प्रभावी संस्थाएं संसाधनों का संधारणीय तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित करती हैं। वहीं खराब संस्थाएं अत्यधिक शोषण का कारण बन सकती हैं, जिससे पर्यावरण और भविष्य में विकास को नुकसान पहुँच सकता है। उदाहरण के लिए- **नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल**।
- **विनियमन:** बेहतर विनियमन वाली संस्थाएं प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देती हैं। उदाहरण के लिए- **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)**।
- **गवर्नेंस और कानून का शासन:** राजनीतिक संस्थाएं स्थिर गवर्नेंस और कानून का शासन सुनिश्चित करती हैं। इससे भ्रष्टाचार में कमी आती है और निवेश के लिए निष्पक्ष व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।
    - उदाहरण के लिए- देश के लोक प्रशासन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए **केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)** का गठन किया गया है।
- **समावेशी:** लोकतांत्रिक संस्थाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में जन-भागीदारी को बढ़ावा देती हैं। इससे ऐसी नीतियां बनती हैं जो देश की आबादी की जरूरतों को पूरा करती हैं।
    - उदाहरण के लिए- राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति के लिए **जनजातीय सलाहकार परिषद (TAC)** का गठन किया गया है।
- **संघर्ष का समाधान:** संघर्ष का समाधान प्रदान करने वाली प्रभावी संस्थाएं राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती हैं, निवेश को आकर्षित करती हैं और आर्थिक विकास में सहायता करती हैं।
    - उदाहरण के लिए- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)** अन्य विधिक सेवा संस्थानों के साथ मिलकर **लोक अदालतों** का आयोजन करता है। यह अदालत विवादों को दक्षतापूर्वक सुलझाने और कानूनी अड़चनों को कम करने में मदद करती है।

[10] How institutions are formed and their impact on prosperity

मजबूत आर्थिक संस्थाओं के निर्माण के लिए भारत में उठाए गए कदम	भारत में मजबूत राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण के लिए उठाए गए कदम
• **बैंकों का राष्ट्रीयकरण:** 1960 के दशक के उत्तरार्ध में, भारत में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इससे देश में ऋण वितरण तथा कृषि और लघु उद्योगों जैसे प्रमुख क्षेत्रकों को सीधे संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिली। • **उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) संबंधी सुधार:** इसने विदेशी निवेश को आकर्षित किया है और विकास को प्रोत्साहित किया है। • **प्रवर्तन निदेशालय (ED):** यह मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों को रोकता है। • **संसदीय समितियां:** जवाबदेही सुनिश्चित करना और सार्वजनिक बहस को बढ़ावा देना।	• **भारत का लोकतांत्रिक ढांचा:** नियमित चुनाव और बहुदलीय प्रणाली भारत में जवाबदेही एवं प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देती है। • **विकेंद्रीकरण:** 73वें और 74वें संविधान संशोधनों ने स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया है। • **भ्रष्टाचार-रोधी उपाय:** लोकपाल एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जैसी संस्थाएं शासन में जवाबदेही को बढ़ावा देती हैं तथा भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करती हैं। • **नागरिक समाज की भागीदारी:** गैर-सरकारी संगठन और नागरिक समाज का सहयोग समावेशिता को बढ़ाता है।

निष्कर्ष

आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं के बीच संबंध राष्ट्रीय समृद्धि की कुंजी है। मजबूत आर्थिक संस्थाएं संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करती हैं और निवेश को प्रोत्साहित करती हैं। ये संस्थाएं प्रभावी राजनीतिक संस्थाओं के साथ मिलकर सुशासन और समावेशी विकास सुनिश्चित करती हैं तथा संवृद्धि को बढ़ावा देती हैं।

2.12. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
संवृद्धि के अग्रदूत	नवीकरणीय ऊर्जा	वस्त्र एवं हस्तशिल्प (GI-टैग प्राप्त मुगा रेशम)	एक्ट ईस्ट नीति	मिडिल इनकम ट्रैप
GDP के आधार वर्ष में संशोधन	थोक मूल्य सूचकांक	उत्पादक मूल्य सूचकांक (PPI)	घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES)	वित्तीय समावेशन
क्षेत्रीय असमानता	ग्रामीण औद्योगीकरण	कृषि निर्यात नीति	गरीबी मापने का फ्रेमवर्क	सार्वजनिक निवेश

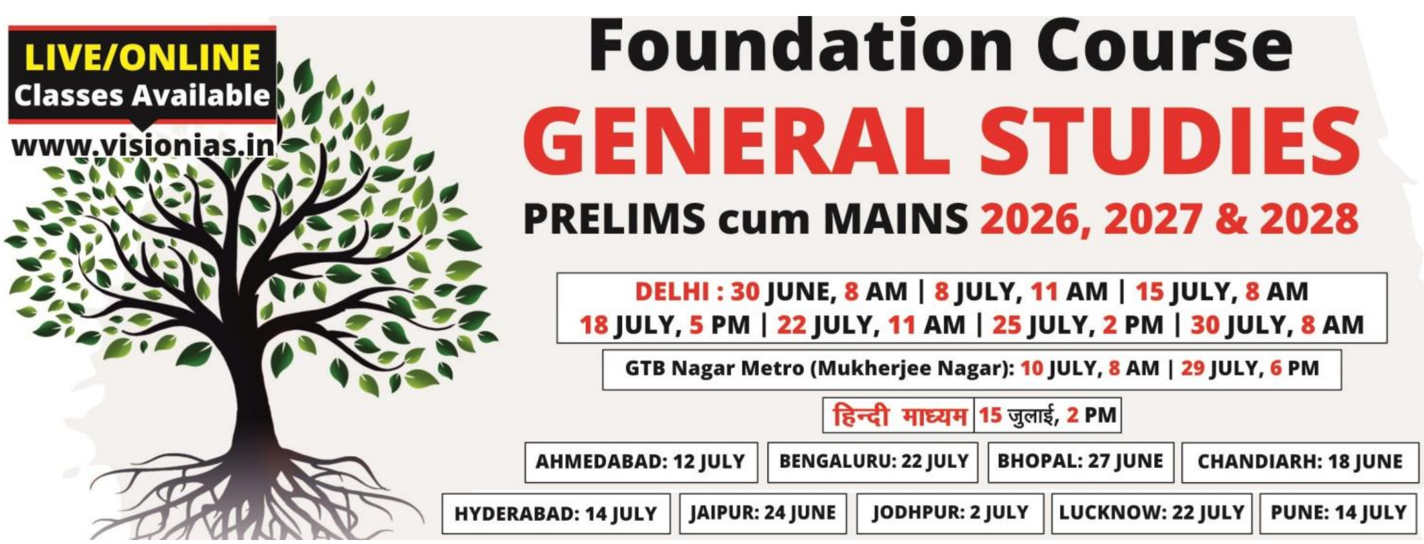

2.13. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

GDP की गणना के तीन पारंपरिक तरीकों की व्याख्या कीजिए। यह स्पष्ट कीजिए कि भारत में आर्थिक कल्याण को मापने के लिए GDP क्यों एक अपर्याप्त सूचक बना हुआ है और राष्ट्रीय लेखांकन में हाल ही में किए गए पद्धतिगत (मेथडोलॉजिकल) परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
GDP का परिचय दीजिए	GDP की गणना करने के तरीके बताइये	सीमाएँ	आगे की राह

3. रोजगार, श्रम और कौशल विकास (Employment, Labour, and Skill Development)

3.1. बेरोजगारी: एक नज़र में (Unemployment at a Glance)

भारत में बेरोजगारी

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), 2024

अप्रैल 2025 में भारत में बेरोजगारी दर 5.1% थी। (मासिक PLFS)	**श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 59.6% है।**	शहरी बेरोजगारी दर 6.5% है, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.5% दर्ज की गई है।

भारत में उच्च बेरोजगारी के कारण

श्रम बल की मांग और आपूर्ति में अंतर: भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन से अधिक है, जिनमें से लगभग 65% कार्यशील आयु वर्ग (15-64 वर्ष) के हैं।	**युवाओं में कौशल का अभाव:** 15-29 वर्ष आयु वर्ग के केवल 4.4% युवाओं को औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है (आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24)	**रोजगारविहीन संवृद्धि:** हाल के वर्षों में आर्थिक संवृद्धि **पूंजी-प्रधान** रही है, **श्रम-प्रधान (श्रम की मांग) नहीं।**	**कृषि:** कुल कार्यबल का लगभग 45.76% हिस्सा कृषि में लगा हुआ है। (मौसमी रोजगार)	**अन्य:** धीमी औद्योगिक एवं विनिर्माण संवृद्धि, तकनीकी प्रगति, आदि।

शुरू की गई पहलें

कौशल भारत मिशन	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना	अन्य: पी.एम.-स्वनिधि योजना, मेक इन इंडिया, आदि।

आगे की राह

श्रम-प्रधान (अधिक श्रम की मांग) उद्योगों को बढ़ावा देना: **जैसे-**टेक्सटाइल, चर्म उद्योग	**शिक्षा और कौशल विकास में सुधार**	**MSME क्षेत्र को बढ़ावा:** जैसे कि क्लस्टर आधारित MSME विकास	**स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना:** वित्तीय सहायता प्रदान करके, योजनाओं में समन्वय सुनिश्चित करके	**अन्य:** अनौपचारिक क्षेत्रक को औपचारिक बनाना

3.1.1. संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण {Revamped Periodic Labour Force Survey (PLFS)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने जनवरी 2025 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में संशोधन कर उसे नया रूप दिया है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के बारे में

- **संचालन एजेंसी:** राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)
- **मंत्रालय: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** द्वारा **2017** में प्रस्तुत किया गया।
- **उद्देश्य:**
  - **'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS)**[11] में शहरी क्षेत्रों (अब ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल) के लिए **केवल तीन महीने के लघु समय अंतराल में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित प्रमुख संकेतकों** का अनुमान लगाना।
  - ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में **वार्षिक रूप से 'सामान्य स्थिति यानी यूजुअल स्टेटस' (ps+ss) और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS), दोनों में रोजगार और बेरोजगारी के संकेतकों** का अनुमान लगाना।

[11] Current Weekly Status

© Vision IAS

PLFS में किए गए मुख्य बदलाव

- **राष्ट्रीय स्तर (देश के स्तर) पर प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों का मासिक अनुमानों की उपलब्धता।**
- **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) में त्रैमासिक अनुमान को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करना:** पहले PLFS केवल शहरी क्षेत्रों के लिए त्रैमासिक श्रम बाजार संकेतक प्रदान करता था।
- **कैलेंडर वर्ष पर आधारित रिपोर्टिंग:** वर्ष 2025 से, वार्षिक PLFS परिणाम कैलेंडर वर्ष के आधार पर जारी होंगे।
- **सैंपल के आकार में वृद्धि:** PLFS में शामिल किए जाने वाले परिवारों के सैंपल में 2.65 गुना वृद्धि की गई है।
- **कवर किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र में वृद्धि:** जिले को **प्राथमिक भौगोलिक इकाई** बनाया गया है।
- **सामाजिक संकेतकों के आंकड़ों की बेहतर उपलब्धता:** इसमें शिक्षा; कब्जे वाली भूमि और पट्टे पर दी गई भूमि; और किराया; पेंशन, ब्याज और रेमिटेंस से प्राप्त परिवारों की सामान्य मासिक आय से संबंधित अतिरिक्त विवरण भी शामिल किए गए हैं।

PLFS में शुरू किए गए परिवर्तनों का महत्व: सैंपल साइज में वृद्धि करने, निर्णय सहायता प्रणाली (इंडस्ट्री सपोर्ट सिस्टम) अपनाने और भारत के श्रम बाजार के आंकड़ों को समय पर अपडेट करने से समय पर ग्रामीण श्रमिकों के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं, जिला स्तरीय योजना बनाई जा सकती है, आदि।

भारत में रोजगार संबंधी संकेतकों की गणना के लिए अन्य पद्धतियां/ रिपोर्ट

- **रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम[12]:** यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोजगार की संरचना के बारे में क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर नियमित अंतराल पर जानकारी प्रदान करता है, साथ ही रोजगार के स्तर में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी भी करता है।
- **ILO रिपोर्ट्स:** जैसे कि **वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक,** आदि।
- **जनगणना:** इसमें मुख्य और सीमांत (Marginal) श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्र किया जाता है, जो अलग-अलग सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं को कवर करता है।
- **श्रम ब्यूरो (Labour Bureau):** यह केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय (MoL&E) के अधीन एक संबद्ध कार्यालय है। इसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। यह विभिन्न श्रम कानूनों, जैसे- बागान श्रम अधिनियम, 1951; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; आदि के अंतर्गत वैधानिक और स्वैच्छिक रिटर्न्स (इच्छानुसार, अनिवार्य नहीं) के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करता है।
    - श्रम सांख्यिकी के आंकड़े वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI), ग्रामीण श्रमिक जांच, तथा ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) - ग्रामीण श्रमिक/ कृषि श्रमिक आदि के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं।

भारत में रोजगार से जुड़े संकेतकों को मापने की पद्धतियों से संबंधित समस्याएं

- **डेटा में असंगतता**: सैंपलिंग पद्धतियों, सर्वेक्षण का समय, और पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार में अंतर के कारण अलग-अलग आंकड़े सामने आते हैं।
- **कमजोर मापदंड**: वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) में यदि कोई व्यक्ति पिछले सप्ताह में **कम से कम 1 घंटे कार्यरत रहा**, तो उसे "रोजगार प्राप्त (नियोजित)" माना जाता है, जिससे **बेरोजगारी का वास्तविक आकलन नहीं हो पाता** और आंकड़े अधूरे रह जाते हैं।
- **परिभाषा में विसंगति**: भारत में रोजगार की परिभाषा **अंतर्राष्ट्रीय मानकों** के अनुरूप नहीं है।
- **कई सर्वेक्षणों की सीमित प्रकृति:** त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण केवल रोजगार के आंकड़े प्रस्तुत करता है लेकिन बेरोजगारी से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं देता।
- **सैंपल का आकार छोटा होना:** PLFS में मात्र **2,72,304 परिवारों** को शामिल किया जाता है।

निष्कर्ष

नवीन रूप से विकसित PLFS श्रम बाज़ार से जुड़े आंकड़ों की सटीकता, आवृत्ति और कवरेज को बेहतर बनाता है, जिससे समय पर और साक्ष्य-आधारित नीतिनिर्माण में सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हुए, एक मजबूत श्रम डेटा प्रणाली के लिए विभिन्न स्रोतों का समन्वय (हॉर्मोनाइज़ेशन) और तकनीकी एकीकरण बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे।

[12] Employment Market Information Programme

3.1.2. वेतन वृद्धि में ठहराव (Stagnant Wages)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में अलग-अलग क्षेत्रकों में **रोजगार के अवसरों में लगातार वृद्धि** देखी जा रही है। हालांकि, इस सकारात्मक रुझान के बावजूद, वेतन (पारिश्रमिक) में वृद्धि बढ़ती मुद्रास्फीति यानी बढ़ती महंगाई के अनुरूप नहीं है।

वेतन वृद्धि में ठहराव की स्थिति

- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) वार्षिक रिपोर्ट 2023-24:**
  - **रोजगार में वृद्धि:** श्रमिक-जनसंख्या अनुपात 2017-18 के **34.7%** से बढ़कर 2023-24 में **43.7%** हो गया, जो दर्शाता है कि रोजगार वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से अधिक है।
  - **वेतन संबंधी असमानता:** अस्थायी श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी बढ़ी है, लेकिन नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों का पारिश्रमिक **मुद्रास्फीति के कारण स्थिर बना** हुआ है।
- **आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24:**
  - **कॉर्पोरेट जगत की लाभप्रदता:** यह वित्त वर्ष 2024 में 15 साल में सर्वाधिक हो गई थी। वित्त वर्ष 2024 में **कॉर्पोरेट जगत का लाभ 22.3% बढ़ा है, लेकिन रोजगार में मात्र 1.5% की वृद्धि** हुई है।
  - **वेतन वृद्धि में ठहराव:** पिछले चार वर्षों में भारतीय कंपनियों की EBITDA मार्जिन 22% पर स्थिर बने रहने के बावजूद, वेतन वृद्धि विशेष रूप से प्रवेश स्तर के IT संबंधी पदों पर धीमी रही है।

चिंताएं

- **अर्थव्यवस्था में गिरावट:** अधिक कॉर्पोरेट लाभ और स्थिर वेतन वृद्धि से मांग में कमी आ सकती है, जिससे अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो सकती है।
- **आय में असमानता:** मुख्य रूप से बड़ी कंपनियों सहित कॉर्पोरेट जगत के मुनाफे में असमान वृद्धि से आय संबंधी असमानता बढ़ने का खतरा है।

निष्कर्ष

सतत आर्थिक संवृद्धि के लिए रोजगार से होने वाली आय में वृद्धि होना जरूरी है। इससे सीधे तौर पर उपभोक्ता द्वारा खर्च में वृद्धि होती है तथा उत्पादन क्षमता में निवेश को बढ़ावा मिलता है। दीर्घकालिक सतत आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पूंजी और श्रम के बीच आय का निष्पक्ष व तर्कसंगत वितरण अनिवार्य है।

3.2. गिग इकॉनमी (Gig Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कर्नाटक सरकार ने '**कर्नाटक प्लेटफॉर्म-बेस्ड गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा और कल्याण) अध्यादेश, 2025**' जारी किया।

विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **'कल्याण बोर्ड' की स्थापना**
- **कल्याण कोष:** गिग श्रमिकों के लिए एक समर्पित कोष बनाया जाएगा, जिसमें एग्रीगेटर कंपनियों, गिग श्रमिकों और सरकार की ओर से योगदान किया जाएगा।
- **अधिकार-आधारित विधेयक:** इसका उद्देश्य गिग श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना है।
- **अन्य विशेषताएं:** इसमें **अनुचित तरीके से बर्खास्तगी से सुरक्षा, दो-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र** और प्लेटफॉर्म्स (जैसे- जोमाटो) द्वारा इस्तेमाल स्वचालित निगरानी और निर्णय लेने वाले सिस्टम में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
- वर्तमान में, **राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य** है जहां **गिग वर्कर्स के कल्याण से संबंधित कानून लागू है।**

फैक्ट शीट
भारत में गिग वर्कर्स (नीति आयोग के अनुसार)

- 7.7 मिलियन वर्कर्स गिग अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं (2020-21) 1
- गैर-कृषि क्षेत्रक कार्य-बल में 2.6% या कुल कार्य-बल में 1.5% हिस्सेदारी गिग वर्कर्स की है।
- भारत में 2029-30 तक गिग वर्कर्स की संख्या बढ़कर 23.5 मिलियन होने की संभावना है।

 © Vision IAS

गिग श्रमिक

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** के अनुसार, गिग वर्कर वह व्यक्ति होता है जो **पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध** से बाहर की कार्य-दशाओं में काम करता है और उससे आय अर्जित करता है।

गिग इकॉनमी के लाभ	
वर्कर्स को होने वाले लाभ	• ऑफिस कार्य-घंटों से बंधा नहीं होना, और कहीं से भी (रिमोट) कार्य करने का अवसर, कार्य करने की स्वायत्तता। • एक ही साथ फ्रीलांसर के रूप में दो या उससे अधिक कंपनियों के लिए कार्य करने का अवसर मिलना।
नियोक्ताओं को होने वाले लाभ	• कम स्थायी कर्मचारियों के होने से खर्च में कमी आना और अन्य प्रकार के दैनिक ऑफिस खर्चों की बचत से समस्त लागत में कमी आना। • कई नए सेवा क्षेत्रकों में व्यवसाय का विस्तार करने का अवसर मिलना (जैसे; Uber राइड द्वारा भारत में Uber Eats शुरू करना)।
उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ	• **सस्ती कीमतों पर उत्पाद और सेवाएं मिलना।** • व्यक्तिगत पसंद के आधार पर सेवाएं/ उत्पाद मिलने से **अधिक संतुष्टि मिलना।**

गिग वर्कर्स के लिए चुनौतियां: नौकरी सुरक्षित नहीं होना, स्थायी कर्मचारियों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिलना, एल्गोरिदम आधारित प्रबंधन से परेशानी, कंपनी के 'कर्मचारी' का दर्जा नहीं मिलना, आदि।

भारत में गिग इकॉनमी के लिए उठाए गए कदम

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** इसमें गिग वर्कर्स को भी सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने का प्रावधान है।
- **वेतन संहिता, 2019:** यह गिग वर्कर्स सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन (यूनिवर्सल मिनिमम वेज) और फ्लोर पारिश्रमिक का प्रावधान करता है।
- **ई-श्रम (e-SHRAM) पोर्टल:** यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। इस पर गिग वर्कर्स भी पंजीकृत हो सकते हैं।
- **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY):** इसके तहत असंगठित क्षेत्र के सभी पात्र पंजीकृत श्रमिकों सहित गिग वर्कर्स को एक वर्ष के लिए 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है।

आगे की राह

- **गिग वर्कर्स की संख्या का उचित आकलन:** इनकी अलग से गणना करने की आवश्यकता है।
- **वित्तीय समावेशन में तेजी लाना:** फिनटेक उद्योग का लाभ उठाकर।
- **सामाजिक समावेशन को बढ़ावा:** महिला श्रमिकों, दिव्यांगजनों जैसे श्रमिकों के अलग-अलग वर्गों का कौशल विकास करके और ऋण उपलब्ध कराकर उनकी प्लेटफॉर्म क्षेत्र में **रोजगार प्राप्ति में मदद की जा सकती है।**
- **प्लेटफॉर्म जॉब्स के लिए कौशल विकास:** कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए **आउटकम** आधारित, प्लेटफॉर्म-आधारित मॉडल का अनुसरण करना चाहिए।
  - ई-श्रम और राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल या उद्यम पोर्टल जैसे रोजगार और कौशल विकास पोर्टल्स को असीम (ASEEM) पोर्टल के साथ एकीकृत करना चाहिए।
- **सभी को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करना:** साझेदारी मोड में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कवरेज का विस्तार करना चाहिए, जैसा कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रावधान किया गया है।

निष्कर्ष

गिग श्रमिकों के लिए प्रस्तावित कल्याणकारी पहलें तेजी से बदलते श्रम बाजार में उनके कार्यों की औपचारिक मान्यता देने और उनके अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। हालांकि, उनकी कार्य स्थिति में वास्तविक बदलाव के लिए यह आवश्यक है कि श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, अनुकूल कार्य-दशाएं उपलब्ध कराई जाए, और सरकार द्वारा वास्तविक सुरक्षा प्रदान की जाए जो महज सांकेतिक कल्याणकारी प्रावधानों तक सीमित न हों।

3.3. कौशल विकास (Skill Development)

3.3.1. कौशल विकास: एक नज़र में (Skill Development at a Glance)

कौशल विकास

कौशल विकास की आवश्यकता

- **रोजगार योग्य बनाने में सुधार:** भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की है।
- **रोजगार योग्य कौशल का अभाव: 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के केवल 4.4% युवाओं ने औपचारिक व्यावसायिक/ तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)**
- **कार्य की प्रकृति में बदलाव:** अगले पांच वर्षों में, वैश्विक स्तर पर 23% नौकरियों की प्रकृति में बदलाव आएगा (WEF की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, 2023)।
- **बेहतर रोजगार उपलब्ध कराना:** कौशल की कमी के कारण भारत के 90% से ज्यादा कामगार अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं।

कौशल विकास के समक्ष अन्य चुनौतियां

- **नकारात्मक धारणा:** व्यावसायिक (वोकेशनल) प्रशिक्षण को अकादमिक शिक्षा से निम्नतर माना जाता है।
- **तेजी से बदलता जॉब मार्केट:** जॉब मार्केट में लगातार बदलाव हो रहा है, जिसके लिए अपस्किलिंग और रीस्किलिंग जरूरी है।
- **उत्कृष्ट कौशल विकास का अभाव:** सुप्रशिक्षित फैकल्टी और अच्छे पाठ्यक्रम (कोर्सेज) का अभाव।
- **कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों में संसाधनों और उचित रखरखाव की कमी, अवसंरचना का अभाव**
- **लैंगिक भेदभाव:** महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम है

शुरू की गईं पहलें

- **SANKALP/ संकल्प (आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता)**
- **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना,** एवं पीएम-दक्ष योजना।
- **संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना (2025)**
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:** व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान।
- **प्रधान मंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS)**
- **अन्य:** कौशल भारत मिशन, पीएम विश्वकर्मा योजना, स्किल इम्पैक्ट बॉण्ड, आदि।

आगे की राह

- **उद्योग जगत और शिक्षा जगत के बीच समन्वय को बढ़ावा**
- **शिक्षा एवं कौशल विकास में सुधार,** समावेशी कौशल विकास आदि।
- **शारदा प्रसाद समिति की निम्नलिखित सिफारिशें: पुनर्भुगतान योग्य उद्योग अंशदान** (Reimbursable Industry Contribution: RIC) का सृजन; विशेष व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली (VETCs); शिक्षा और कौशल के द्वारा विद्यार्थियों की उन्नति (अपवर्ड मोबिलिटी)।

© Vision IAS

3.3.2. विश्व में कार्यबल संबंधी कमियों से निपटना (Bridging Global Workforce Gaps)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) ने **"इंडिया एम्प्लॉयमेंट आउटलुक 2030"** शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि अगले दशक में वृद्धिशील वैश्विक कार्यबल का लगभग 24.3% भारत से होगा।

वैश्विक श्रम बाजार की स्थिति

- **कामकाजी उम्र की जनसंख्या में कमी:** उच्च आय वाले कई देशों में **जन्म दर में गिरावट** के कारण तेजी से जनसांख्यिकीय बदलाव देखा जा रहा है।
    - 2050 तक, इन देशों में कामकाजी उम्र की आबादी में **92 मिलियन से अधिक की कमी** हो सकती है।
- **वृद्ध होती आबादी: उच्च आय वाले कई देशों** में बुज़ुर्ग व्यक्तियों (65 और इससे अधिक उम्र के व्यक्ति) की आबादी में 100 मिलियन से अधिक की वृद्धि होने की संभावना है।
- **वैश्वीकृत रोजगार बाजार:** डिजिटल सिस्टम के उपयोग में वृद्धि हो रही है।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बदलाव:** भू-राजनीतिक परिस्थितियों, व्यापार प्रतिबंध एवं फ्रेंडशोरिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव एवं परिवर्तन देखे जा रहे हैं। इसने जॉब मार्केट और उससे जुड़े हुए पारिश्रमिकों में बदलाव को प्रभावित किया है।

भारत के जनसांख्यिकीय लाभ

- **कामकाजी आबादी:** वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन से अधिक है। इनमें से लगभग 65% लोग कामकाजी आयु वर्ग (15-64 वर्ष) के हैं और 27% से अधिक लोग 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के हैं।
- **कौशल में कमी की समस्या को दूर करना:** राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) की 'ग्लोबल स्किल गैप स्टडी' से पता चलता है कि दुनिया भर के अलग-अलग क्षेत्रकों में भारतीय प्रतिभाओं की मांग बढ़ रही है।

श्रम गतिशीलता के प्रभाव

- **वैश्विक उत्पादकता में वृद्धि:** श्रम गतिशीलता यानी लेबर मोबिलिटी भविष्य के प्रवासियों को जरूरतमंद नियोक्ताओं से जोड़ सकती है। इससे वैश्विक समानता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- **गरीबी उन्मूलन:** अमीर देशों में जाने वाले श्रमिक **अपनी आय में 6 से 15 गुना वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं,** जिससे गरीबी में काफी कमी आएगी।
- **सामाजिक कल्याण:** कार्यबल के विदेश जाने से केवल व्यक्तिगत प्रवासियों को ही लाभ नहीं मिलता है, बल्कि इनके द्वारा घर वापस भेजी गई मुद्रा यानी रेमिटेंस से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने में भी मदद मिलती है।
    - वर्ष 2022 में, भारत को **रेमिटेंस के रूप में 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की धनराशि** प्राप्त हुई। इस तरह भारत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रेमिटेंस प्राप्त करने का आंकड़ा पार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया।
- **भारत के श्रम बाजार पर दीर्घकालिक प्रभाव:** बड़े पैमाने पर श्रमिकों के बाहर प्रवास कर जाने से **भारत के कौशल विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता** है **और प्रतिभा पलायन** (ब्रेन ड्रेन) की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इससे स्वास्थ्य देखभाल सेवा और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

श्रम गतिशीलता की चुनौतियां

- **प्रवासन विरोधी नीतियां और स्थानीय भावनाएं:** प्रवासी-विरोधी भावनाएं एवं प्रतिबंधात्मक नीतियां भविष्य में आने वाले प्रवासियों के लिए बाधाएं पैदा करती हैं।
- **प्रवासन की जटिल प्रक्रियाएं:** जैसे कि H1B1 वीज़ा समस्या।
- **व्यापक एकीकरण कार्यक्रमों की कमी:** प्रवासियों को उनके नए वातावरण के अनुकूल होने में मदद करना।
- **ऑटोमेशन और प्रौद्योगिकी में उन्नति:** ऑटोमेशन एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी प्रौद्योगिकियों में अभूतपूर्व प्रगति होने से कार्य की प्रकृति में बुनियादी बदलाव हो रहे हैं।

आगे की राह

- **वैश्विक मांग के अनुरूप तैयारी:** भारत रणनीतिक रूप से अपने सरप्लस वर्कफोर्स को विकसित अर्थव्यवस्थाओं की मांगों के अनुरूप व्यवस्थित कर सकता है। इससे द्विपक्षीय आर्थिक विकास और एकीकरण सुनिश्चित हो सकेगा।
- **अंतरराष्ट्रीय समझौते:** द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को मज़बूत करना और प्रवास प्रक्रिया को सरल बनाना।
- **प्रवासन की लागत कम करना: प्रवासी कार्यबल के प्रवासन की लागत को कम करना चाहिए** और भारतीय श्रम बाजार में वापस लौटने वाले कार्यबल के लिए आसानी से श्रम बाजार में रोजगार सुनिश्चित कराना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत अपनी जनसांख्यिकीय लाभ को पहचानते हुए खुद को वैश्विक प्रतिभा केंद्र (Global Talent Hub) के रूप में स्थापित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इसके लिए **स्किल इंडिया मिशन, पुनर्गठित स्किल इंडिया प्रोग्राम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020)** के अंतर्गत प्रारंभिक व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी पहलें की जा रही हैं। **इटली, फ्रांस और जर्मनी** जैसे देशों के साथ किए गए 'प्रवासन और कौशल साझेदारी समझौते' भी एक देश से दूसरे देश में श्रम आवाजाही को बढ़ावा देने की भारत की रणनीतिक पहल को दर्शाते हैं।

3.4. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
वेतन में वृद्धि	गिग इकॉनमी	सामाजिक सुरक्षा	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)	कॉर्पोरेट जगत की लाभप्रदता
आय असमानता	एल्गोरिदम प्रबंधन	निफाइड पेंशन स्कीम (UPS)	स्किल इंडिया प्रोग्राम	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
विश्व में कार्यबल संबंधी कमियां	रेमिटेंस	जनसांख्यिकी लाभांश	अप्रेंटिसशिप	राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)

3.5. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

युवा आबादी होने के बावजूद, भारत अपने कार्यबल में एक महत्वपूर्ण कौशल-असंगति का सामना कर रहा है। भारत की कौशल विकास प्रणाली में प्रमुख चुनौतियों की समीक्षा कीजिए और उन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहलों का उल्लेख कीजिए।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
कौशल-असंगति का परिचय दीजिए	भारत के कौशल विकास में प्रमुख चुनौतियाँ	हाल ही में सरकार द्वारा की गई पहलें	कौशल विकास पर आगे की राह

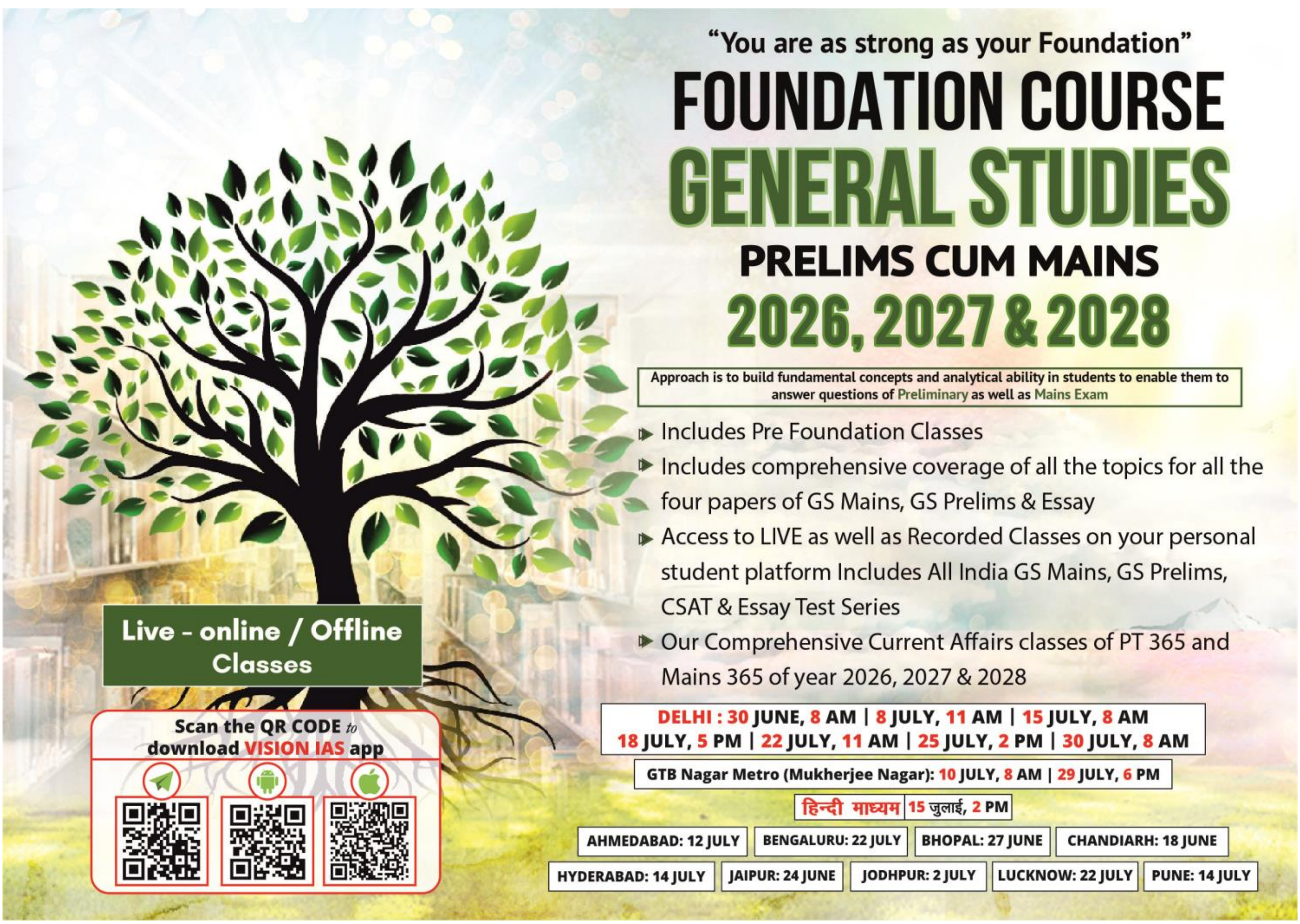

4. राजकोषीय नीति (Fiscal Policy)

4.1. राज्य वित्त (State Finances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **'राज्य वित्त: 2024-25 के बजट का अध्ययन**[13] शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति

- **सकल राजकोषीय घाटा (GFD) में गिरावट:** भारतीय राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा **1998-99 से 2003-04** के दौरान **GDP के औसतन 4.3%** के बराबर था। यह **2004-05 से 2023-24 के दौरान से घटकर 2.7%** हो गया।
  - राज्य सरकारों ने 2021-22 से 2023-24 के दौरान अपने **सकल राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3% के नीचे** नियंत्रित रखा है।
- **राजस्व घाटा:** राज्यों ने 2021-22 से 2023-24 के दौरान राजस्व घाटा **GDP के 0.2%** स्तर पर बनाए रखा है।
- **व्यय की गुणवत्ता में सुधार:** पूंजीगत व्यय **2022-23 में GDP का 2.2%** था, जो बढ़कर **2023-24 में 2.6%** हो गया।
- **राज्यों का ऋण:** यह मार्च, 2004 के अंत में **GDP के 31.8%** के बराबर था, जो **घटकर मार्च, 2024 के अंत में GDP के 28.5%** पर आ गया।

कुछ राज्यों का राजकोषीय घाटा अब भी अधिक क्यों है?

- **केंद्र से राज्यों को धन अंतरण में कमी:** वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्षतिपूर्ति की समाप्ति और वित्त आयोग के अनुदानों में कमी के कारण केंद्र से राज्यों को मिलने वाले **अनुदानों में गिरावट** दर्ज की गई है। वित्त आयोग द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुदान 2022-23 से 2023-24 के दौरान **18% से अधिक घट गए (बजट 2024-25)।**
- **बिजली क्षेत्रक में नुकसान:** विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) की कुल संचयी हानि 2022-23 तक 6.5 लाख करोड़ रुपये (GDP का 2.4%) हो गई।
- **बढ़ता सब्सिडी बोझ:** कृषि ऋण माफी; मुफ्त/ सब्सिडी सेवाएं (जैसे कि कृषि और घरेलू उपयोग के लिए बिजली सब्सिडी, मुफ्त परिवहन सेवा, आदि); किसानों, युवाओं, महिलाओं आदि को नकद अंतरण जैसी योजनाओं के कारण राज्यों पर सब्सिडी का बोझ बढ़ रहा है।

राज्यों में राजकोषीय प्रबंधन से जुड़े मुद्दे/ समस्याएं			
राजकोषीय डेटा का अभाव: कई राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश तिमाही डेटा जारी करने में देरी करते हैं या जारी ही नहीं करते हैं।	**राज्य वित्त आयोगों की स्थापना में देरी:** स्थानीय निकायों को फंड्स हस्तांतरण पर प्रभाव।	**केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं:** राज्यों के खर्च करने के लचीलेपन को सीमित करती हैं।	**बढ़ती अनिश्चितताएं:** आर्थिक, जलवायु और भू-राजनीतिक कारक राजकोषीय जोखिम और बजट अनुमानों से विचलन को बढ़ाते हैं।

राज्यों द्वारा किए गए राजकोषीय सुधार

- **राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून (FRLs):** राज्य सरकारों द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम/ FRLs के कार्यान्वयन से राजकोषीय नीतिगत रणनीतियों के निर्माण, मध्यम अवधि की राजकोषीय योजनाओं (MTFPs)[14] के विकास और पारदर्शिता में सुधार को बढ़ावा मिला है।
- **संस्थागत सुधार:** नीति आयोग की सहायता से असम, गुजरात तथा कुछ अन्य राज्यों ने **"स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉरमेशन"** की स्थापना की है।
- **व्यय सुधार:**
  - **डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) को अपनाना:** इससे नकली/ डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाने और लीकेज को रोकने में मदद मिली है।
  - **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS):** पुरानी पेंशन योजना को बदलकर इसे अपनाया गया है।
  - **सिंगल नोडल एजेंसी (SNA):** इसकी स्थापना से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बेहतर प्रबंधन में मदद मिली है।

---

[13] State Finances: A Study of Budgets of 2024-25 Report

[14] Medium-Term Fiscal Plans

© Vision IAS

* **कर सुधार:** वस्तु एवं सेवा कर (GST) को अपनाया गया है; कर प्रशासन का आधुनिकीकरण किया गया है।
* **बाजार से फंड जुटाने पर अधिक निर्भरता:** 2005-06 में सकल राजकोषीय घाटे (GFD) के वित्त-पोषण में बाजार उधारी की हिस्सेदारी **17%** थी, जो बढ़कर 2024-25 में **79%** हो गई।
* **बिजली क्षेत्रक में सुधार: उदय/ UDAY (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) योजना;** पंद्रहवें वित्त आयोग ने बिजली क्षेत्रक में सुधार के लिए राज्यों को उनके GSDP के 0.5% के बराबर अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी।
* **फिस्कल हेल्थ इंडेक्स (FHI) रिपोर्ट 2025:** हाल ही में नीति आयोग ने भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए FHI रिपोर्ट 2025 जारी की।

आगे की राह: रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

* **"नेक्स्ट जनरेशन" के राजकोषीय नियम:**
  * बाहरी संकट का सामना करने के लिए **प्रति-चक्रीय राजकोषीय नीति**[15] के लिए कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए।
  * **जोखिम-आधारित राजकोषीय फ्रेमवर्क अपनाना:** जैसे, अधिक ऋण स्तर और धीमी संवृद्धि दर वाले राज्यों के लिए **सख्त राजकोषीय नियम** आवश्यक हो सकते हैं।
  * **मध्यम-अवधि व्यय फ्रेमवर्क (MTEF)**[16] **अपनाना:** यह फंड उपलब्धता के लिए अग्रिम योजना निर्माण सुनिश्चित करके और जवाबदेही में सुधार करके नीति निर्माण को बजट से जोड़ती है।
* **डेटा-आधारित राजकोषीय नीति निर्माण:** कराधान प्रणाली में सुधार के लिए डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाना चाहिए।
* **DISCOMs के घाटे को कम करना:** उत्पादकता बढ़ाना, ट्रांसमिशन और वितरण हानियों को कम करना, आदि।
* **"गोल्डन रूल" लागू करना:** यह सुनिश्चित करता है कि सभी चालू/ राजस्व व्यय को चालू राजस्व से वित्त-पोषित किया जाए, जबकि **पूंजीगत व्यय** को उधारी के माध्यम से पूरा किया जाए।

निष्कर्ष

रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकारों ने **राजकोषीय अनुशासन** का प्रदर्शन किया है। हालांकि, विकासात्मक व्यय और देनदारियों के कारण राज्य वित्त पर बोझ बढ़ सकता है। इसलिए, **लोक वित्त को मजबूत करने और राजकोषीय स्थिरता व प्रबंधन** सुनिश्चित करने के लिए **सुधार आवश्यक** हैं।

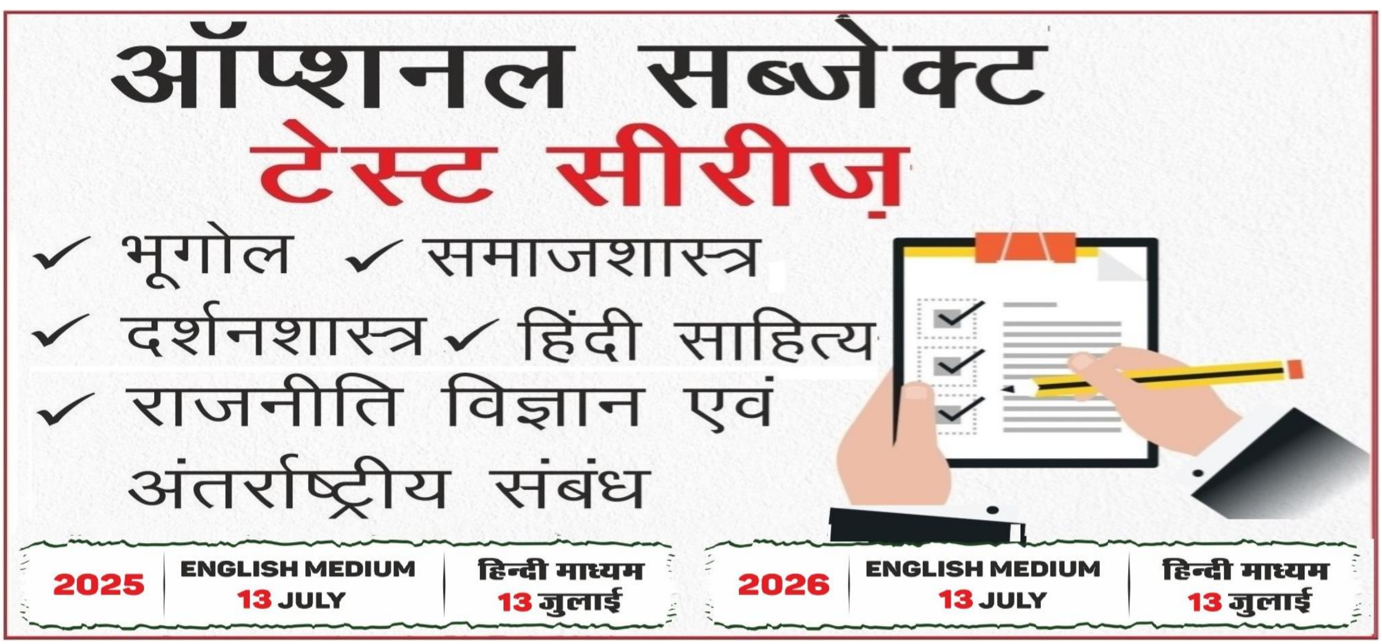

[15] Counter-cyclical fiscal Policy

[16] Medium-Term Expenditure Framework

4.2. प्रत्यक्ष कराधान: एक नज़र में (Direct Taxation at a Glance)

प्रत्यक्ष कराधान

भारत में प्रत्यक्ष कराधान की स्थिति

वित्त वर्ष 2024-25 में कर-GDP अनुपात 11.7% (प्रत्यक्ष करों के लिए 6.7% और अप्रत्यक्ष करों के लिए 5.0%)	**निगम कर (कॉर्पोरेट टैक्स) और व्यक्तिगत आयकर** का प्रत्यक्ष कर में सर्वाधिक योगदान है।	वित्त वर्ष 2021-22 में **डायरेक्ट टैक्स बॉयंसी** 2.52 थी, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक थी, लेकिन **2022-23 में यह घटकर 1.18** हो गई।

मुख्य उपलब्धियां

भारत के प्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 में 16.15% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 25.86 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।	यह वृद्धि उच्च कॉर्पोरेट कर राजस्व (12.40 लाख करोड़ रुपये) और गैर-कॉर्पोरेट कर राजस्व (12.90 करोड़ रुपये) संग्रह के कारण हुई है।

नीतियां/ योजनाएं/ पहलें

पारदर्शी और करदाता-अनुकूल कर व्यवस्था प्रदान करने के लिए **टैक्सपेयर्स चार्टर।**	**फेसलेस असेसमेंट स्कीम**	**वर्चुअल डिजिटल एसेट्स** को कवर करने के लिए **आयकर अधिनियम में संशोधन।**	प्रत्यक्ष कर भुगतान में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए **विवाद से विश्वास योजना।**	**डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट (DTAA) और टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट (TIEA)**

सीमाएं/ बाधाएं

कर-GDP अनुपात OECD देशों (2020 में 33.5%) की तुलना में बहुत कम है।	**कर चोरी और भ्रष्टाचार की समस्या,** कर दरों पर **विश्व के देशों में सहमति का अभाव।**	**उच्च कर-छूट सीमा** और देय कर में कटौती लाभ (डिडक्शन्स)।	**बहुराष्ट्रीय कंपनियां कम टैक्स दर वाले देशों/ टैक्स हैवेन्स में अपने कार्यालय स्थापित कर रही हैं।**	**डिजिटल कराधान से जुड़ी समस्याएं।**

आगे की राह

GST की तर्ज़ पर **प्रत्यक्ष कर संहिता लागू करना और** करदाताओं की संख्या में वृद्धि करके **कर-आधार (टैक्स-बेस) का विस्तार करना।**	कृषि आय पर कर लगाने **की संभावनाओं पर विचार करना।**	आर्थिक प्रोत्साहन प्रावधानों को **तार्किक बनाना।**	कर चोरी को रोकने के लिए **OECD-AEOI (ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ़ इनफार्मेशन)** जैसे अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में शामिल होना।

4.2.1. एंजेल टैक्स (Angel Tax)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2024-25 में, सरकार ने सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजेल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की है।

एंजेल टैक्स क्या है?

- **परिभाषा: एंजेल टैक्स गैर-सूचीबद्ध कंपनियों या स्टार्ट-अप्स** द्वारा जुटाई गई **अतिरिक्त राशि पर लगाया जाने वाला आयकर** है। इसके तहत स्टार्ट-अप का उचित बाजार मूल्य (फेयर मार्केट वैल्यू) और उसके द्वारा इससे अधिक जुटाई गई राशि को आय माना जाता है और इस अतिरिक्त आय पर एंजेल टैक्स लगाया जाता है।
    - उदाहरण के लिए- यदि किसी स्टार्टअप का उचित बाजार मूल्य 1 करोड़ रुपये है, और वह एंजेल निवेशकों से 1.5 करोड़ रुपये जुटाता है तो वैल्यूएशन की अतिरिक्त 50 लाख रुपये की राशि पर कर लगेगा।
- **उद्देश्य:** इसे मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए 2012 में शुरू किया गया था।

© Vision IAS

- **कानूनी प्रावधान:** यह **आयकर अधिनियम, 1961** के तहत लगाया जाता था।
- **कवरेज:** पहले यह केवल स्थानीय निवेशकों पर लागू होता था लेकिन बजट 2023-24 में इसका विस्तार करते हुए विदेशी निवेश (कुछ अपवादों के साथ) को भी इसके दायरे में लाया गया है।

एंजेल टैक्स क्यों खत्म किया गया?

- **व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए:** एंजेल टैक्स ने स्टार्ट-अप पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ और नियमों के पालन का बोझ बढ़ा दिया था। इससे उनकी विकास करने की क्षमता के साथ-साथ सुगम तरीके से व्यवसाय करने की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई।
    - एंजेल टैक्स समाप्त होने से स्टार्ट-अप की **रिवर्स फ़्लिपिंग** को बढ़ावा मिलेगा।
- **निवेश को व्यवस्थित करना:** भारतीय स्टार्ट-अप में 2023 में वैल्यू के स्तर पर फंडिंग में 60% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई।
    - इसके अलावा, विदेशी निवेशकों पर एंजेल टैक्स लगाने से फंडिंग के अवसर कम हो गए। गौरतलब है कि स्टार्ट-अप्स का वैल्यूएशन बढ़ाने में विदेशी निवेशकों ने अहम भूमिका निभाई थी।
        - उदाहरण के लिए- टाइगर ग्लोबल नामक विदेशी निवेशक ने 1 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन वाले एक-तिहाई भारतीय स्टार्ट-अप **(यूनिकॉर्न)** में निवेश किया हुआ है।

एंजेल टैक्स खत्म करने से जुड़ी चिंताएं

- इसे खत्म करने से सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। साथ ही, स्टार्ट-अप का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है या फर्जी स्टार्ट-अप बनाए जा सकते हैं।

निष्कर्ष

एंजेल टैक्स की समाप्ति से उद्यमियों के लिए फंड की उपलब्धता बढ़ेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी न हो, सरकार एंजेल निवेशकों के पंजीकरण और निजी इक्विटी/ वेंचर कैपिटलिस्ट/ एंजेल फंड में लाभकारी स्वामित्व के डिस्क्लोजर पर बल दे सकती है। इससे स्टार्ट-अप के किसी अन्य उद्देश्य से दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति को रोकने में मदद मिलेगी।

4.2.2. दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (Long-Term Capital Gains: LTCG)

सुर्ख़ियों में क्यों?

लोक सभा ने **अचल संपत्तियों (इमूवेबल प्रॉपर्टी)** पर **दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर** प्रावधानों में संशोधन करने वाले वित्त विधेयक, 2024 को मंजूरी प्रदान की।

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्रीय बजट 2024 में **सभी संपत्तियों** (23 जुलाई, 2024 से पहले अर्जित संपत्तियों को छोड़कर) के लिए **इंडेक्सेशन लाभ को समाप्त करने की घोषणा** की गई थी।
- **इंडेक्सेशन** का आशय पूंजीगत लाभ की गणना करते समय **मुद्रास्फीति के अनुरूप किसी संपत्ति के खरीद मूल्य को समायोजित करने** से है।
- यह करदाताओं के लिए कर देयता को कम करते हुए उन्हें **मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाता है।** यह सुनिश्चित करता है कि करदाताओं पर बाजार कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पन्न लाभ की बजाए **केवल वास्तविक लाभ पर ही कर लगाया जाए**। इस प्रकार, संपत्ति की कीमतों में होने वाली सामान्य वृद्धि पर ही कर लगाया जाता है, न कि मुद्रास्फीति जनित वृद्धि पर।

संशोधन अधिनियम के मुख्य प्रावधान

- **करदाताओं के लिए विकल्प:** करदाता निम्नलिखित दो विकल्पों में से किसी एक का चयन कर **कम टैक्स का भुगतान कर** सकते हैं:
    - **पुरानी योजना/ व्यवस्था:** 23 जुलाई, 2024 से पहले अर्जित संपत्ति की बिक्री पर इंडेक्सेशन लाभ के साथ **20% LTCG टैक्स का भुगतान करना।**
    - **नई योजना/ व्यवस्था: इंडेक्सेशन के बिना 12.5% LTCG टैक्स का भुगतान** करना (पहले के 20% टैक्स की तुलना में कम कर)।
        - हालांकि, 23 जुलाई, 2024 की **कट-ऑफ तिथि के बाद अर्जित संपत्ति की खरीद के लिए, केवल नई व्यवस्था** लागू होगी।
- **छूट में वृद्धि: सूचीबद्ध इक्विटी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड** और **बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स** पर LTCG टैक्स के लिए **छूट सीमा को** 1 लाख रुपये से **बढ़ाकर 1.25 लाख** रुपये कर दिया गया है।
    - इसी प्रकार, लॉन्ग-टर्म के लिए इन परिसंपत्तियों पर लागू **कर की दर** 10% से बढ़ाकर **12.5%** कर दी गई है।

दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ यानी लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स क्या है?

- **पूंजीगत लाभ कर** रियल एस्टेट, स्टॉक और बॉण्ड जैसी **पूंजीगत परिसंपत्तियों की बिक्री** से अर्जित लाभ पर लगाया जाता है।
    - पूंजीगत लाभ कर के 2 प्रकार हैं- **लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स** और **शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स।**
- **LTCG टैक्स**, लंबी अवधि तक रखी गई **संपत्तियों की बिक्री** से अर्जित लाभ पर लगाया जाता है।
    - लॉन्ग टर्म होल्डिंग अवधि **परिसंपत्ति के प्रकार के आधार पर अलग-अलग होती है**। जैसे- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए 12 महीने से अधिक; गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, घर/ भूमि जैसी अचल संपत्तियों के लिए 24 महीने; तथा सोने जैसी चल संपत्तियों के लिए 36 महीने।
- **LTCG पर कर कैसे लगाया जाएगा?**
    - **इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड** के लिए, **1.25 लाख रुपये से अधिक के LTCG** पर इंडेक्सेशन लाभ प्रदान किए बिना **12.5% कर** लगाया जाएगा।
    - अन्य परिसंपत्तियों, जैसे- अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियों (Property) पर, हाल के संशोधनों के अनुसार LTCG पर कर लगाया जाएगा।

वर्तमान संशोधनों का महत्व		
कर गणना में लचीलापन: यह संपत्ति के मालिकों को **दो व्यवस्थाओं में से किसी भी एक का चयन करने का विकल्प** प्रदान करता है। इसमें करदाताओं को कम कर देनदारी वाला विकल्प चुनने का अवसर मिलता है।	**रियल एस्टेट में संवृद्धि:** इंडेक्सेशन को बनाए रखने से संपत्ति की बिक्री से जुड़े वित्तीय बोझ को कम करके **रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ावा** मिलेगा।	**काला बाज़ार पर अंकुश:** कर के बोझ को कम करके, इंडेक्सेशन को बनाए रखने से कर कानूनों के अधिक अनुपालन को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

संशोधनों से जुड़ी चिंताएं

- **उच्च कर देयता: इंडेक्सेशन के बिना** 12.5% LTCG कर कई मामलों में इंडेक्सेशन के साथ 20% कर की तुलना में **उच्च कर देयता** का कारण बन सकता है।
- **काले धन के लेन-देन में वृद्धि हो सकती है:** सर्किल दरों पर संपत्तियों की बिक्री दिखा कर काले धन के रूप में लेन-देन किया जा सकता है। सर्किल दर वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर कोई अचल संपत्ति बेची जा सकती है।
- **कर चोरी:** उच्च कर देयता से **संपत्तियों के मूल्य को कम दिखाने की प्रवृत्ति** को बढ़ावा मिल सकता है। इससे सरकार को कर राजस्व का नुकसान हो सकता है।
- **निवेश हतोत्साहित होगा:** उच्च कर देयता **व्यक्तियों को संपत्तियों में निवेश करने से हतोत्साहित** कर सकती है, विशेष रूप से दीर्घकालिक परिसंपत्ति के रूप में।

निष्कर्ष

संपत्तियों की बिक्री पर लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) के लिए इंडेक्सेशन लाभ को बनाए रखना एक उचित और न्यायसंगत उपाय है जो करदाताओं और अर्थव्यवस्था, दोनों को लाभ पहुंचाता है। हालांकि, यह **अनुचित कटऑफ तिथि, परिसंपत्तियों के मूल्य को जानबूझकर कम दिखाने, कर अपवंचन** आदि के बारे में चिंताएं भी पैदा करता है। इस प्रकार, **सभी करदाताओं के लिए एक निष्पक्ष और न्यायसंगत प्रणाली** सुनिश्चित करने के लिए **LTCG कर व्यवस्था पर सावधानीपूर्वक विचार करने और आवश्यक समायोजन** की आवश्यकता है।

4.2.3. इक्विलाइजेशन लेवी (Equalisation Levy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ऑनलाइन विज्ञापनों पर इक्विलाइजेशन लेवी या डिजिटल कर **1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद लागू नहीं** होगा।

इक्विलाइजेशन लेवी के बारे में

- यह **वित्त अधिनियम, 2016** द्वारा शुरू किया गया एक **प्रत्यक्ष कर** है। यह लेवी **डिजिटल लेन-देन** यानी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को भारत से होने वाली आय पर लगाई जाती है।
- इसमें विदेशी कंपनियों को **विज्ञापन (सर्च इंजन या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन) से होने वाली आय** पर टैक्स भी शामिल है। इस टैक्स का उद्देश्य **दो व्यवसायों के बीच के लेन-देन** (विज्ञापन देने वाला और विज्ञापन दिखाने वाले प्लेटफॉर्म्स) पर टैक्स लगाना है।

© Vision IAS

* **वित्त अधिनियम, 2020** के तहत इस लेवी के दायरे में ई-कॉमर्स **आपूर्ति और सेवाओं** को भी लाया गया है।

इक्विलाइजेशन लेवी लगाने के कारण			
निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा: इसका उद्देश्य **घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए समान अवसर** सुनिश्चित करना था।	**विदेशी कंपनियों को कर के दायरे में लाना:** कई विदेशी कंपनियां डिजिटल माध्यमों से भारत से राजस्व अर्जित करती रही हैं लेकिन वे कर का भुगतान करने से बच जाती थीं क्योंकि भारत में उनका कोई ऑफिस नहीं होता था। ऐसी ही कंपनियों को इक्विलाइजेशन लेवी के दायरे में लाया गया।	**विदेशी डिजिटल कंपनियों पर कर लगाना:** यह सुनिश्चित करना कि बड़ी विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियां भारत में अर्जित राजस्व पर कर का भुगतान करें।	**राजस्व के स्रोत बढ़ाने का अवसर:** विशेष रूप से कोविड महामारी की वजह से डिजिटल लेन-देन में अधिक वृद्धि दर्ज की गई। सरकार को इस लेनदेन पर कर लगाकर राजस्व अर्जित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ।

इक्विलाइजेशन लेवी लगाने से जुड़ी चिंताएं

* **अमेरिका के साथ व्यापार विवाद:** अमेरिका की "फॉरेन ट्रेड बैरियर्स" रिपोर्ट में भारत की इक्विलाइजेशन लेवी को **विदेशी व्यापार के लिए बाधक** बताया गया है।
* **भारत पर जवाबी कर:** भारत की **इक्विलाइजेशन लेवी के प्रत्युत्तर में कई** अन्य देश भी भारतीयों पर इस तरह की लेवी लगा सकते हैं। इससे विदेशों में संचालित भारतीय कंपनियों का व्यवसाय प्रभावित हो सकता है।
* **दोहरा कराधान और अनुपालन संबंधी बोझ:** विदेशी कंपनियों को दोहरे कराधान (अपने देश में और भारत में) का भुगतान करना पड़ता है। इससे उनकी व्यवसाय लागत बढ़ रही है।

निष्कर्ष

इक्वलाइजेशन लेवी ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में कर निष्पक्षता को बढ़ावा दिया, लेकिन इसके चलते व्यापारिक तनाव और अनुपालन संबंधी जटिलताएं भी उत्पन्न हुईं। 1 अप्रैल, 2025 से इसका हटाया जाना संतुलित व न्यायसंगत डिजिटल कराधान की दिशा में वैश्विक कर सहयोग और समन्वय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

4.3. वस्तु एवं सेवा कर: एक नज़र में {Good and Service Tax (GST) at a Glance}

वस्तु एवं सेवा कर (GST)

GST एकीकृत कर प्रणाली है। इसे **101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के जरिए जुलाई, 2017 में लागू** किया गया था।

प्रमुख विशेषताएं

एक राष्ट्र, एक कर: GST ने केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों का अपने में समाहित कर लिया।	**दोहरी संरचना:** जिसमें केंद्रीय GST (CGST) और राज्य GST (SGST) शामिल हैं। इनके अलावा एकीकृत GST (IGST) भी लगाई जाती है।	**डेस्टिनेशन-बेस्ड अप्रत्यक्ष कर:** आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लगाया जाता है।	**अलग-अलग कर स्लैब: 5%, 12%, 18% और 28%.**	**अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद:** यह GST के अलग-अलग पहलुओं पर निर्णय लेती है।

GST की उपलब्धियां

कर संग्रह: 2023-24 में 20.18 लाख करोड़, जिसमें 1.68 लाख करोड़ का औसत मासिक संग्रह शामिल है, जो बेहतर प्रदर्शन है।	राज्यों की **टैक्स बॉयंसी में सुधार,** जो GST के लागू होने से पहले 0.72 थी, अब बढ़कर 1.22 हो गई।	इसने आपूर्ति श्रृंखला में व्यवसायों को इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने की सुविधा देकर टैक्स कैस्केडिंग (प्रत्येक चरण में टैक्स पर टैक्स लगाने का बोझ) को समाप्त कर दिया, जिससे समग्र कर बोझ कम हो गया।	**बाजार का एकीकरण** और ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा।

GST से जुड़ी मुख्य समस्याएं (संसदीय समिति द्वारा रेखांकित)

MSMEs की चिंताएं: इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की जटिलता कारण कर नियमों का अनुपालन करने में परेशानी।	**निर्यातकों की चिंताएं:** इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिफंड में देरी।	**स्टील रोलिंग मिल्स की चिंताएं:** स्क्रैप डीलर्स द्वारा GST से बचने (चोरी) के प्रयासों के कारण मिल्स को दोहरा कर भुगतान करना पड़ता है।	**ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर द्वारा कर चोरी:** 1 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाने के कारण कर चोरी बढ़ना।

आगे की राह

GST भुगतान बढ़ाने के लिए **कर दरों को कम करना चाहिए।**	लीकेज और कर चोरी को रोकने के लिए **प्रावधानों को सख्त** बनाना चाहिए।	**GST भुगतान की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी** का उपयोग करना चाहिए।	**GST कर नेटवर्क का विस्तार करके** शराब, पेट्रोलियम जैसे उत्पादों को इसके दायरे में लाना चाहिए।	**विशेष फास्ट-ट्रैक रिफंड प्रोसेसिंग सिस्टम** लागू करना चाहिए।

4.4. मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क (Inflation Targeting Framework)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक सर्वेक्षण 2024 में यह सुझाव दिया गया है कि भारत के **मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क से खाद्य कीमतों को बाहर** किया जाए। इससे **नीतिगत उपायों पर बहस** फिर से शुरू हो गई है।

भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के बारे में

- **मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क:** भारत ने औपचारिक रूप से 2016 में मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क को अपनाया था। इसके तहत RBI को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित मुद्रास्फीति को 4% ± 2% की सीमा (यानी 2% से 6% के बीच) में बनाए रखना होता है।
- **खाद्य मदें:** CPI बास्केट में **लगभग 45% भारांश खाद्य मदों का होता है।** इसलिए, खाद्य पदार्थों की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर हेडलाइन मुद्रास्फीति पर पड़ता है।

© Vision IAS

- ○ भारत में दलहन और तिलहन उत्पादन की कमी के साथ-साथ टमाटर और प्याज के उत्पादन में उतार-चढ़ाव की वजह से इनकी कीमतें प्रभावित होती हैं।

खाद्य मदों को बाहर रखने के पक्ष में तर्क	खाद्य मदों को बाहर रखने के विपक्ष में तर्क
• **आपूर्ति-पक्ष आधारित मुद्रास्फीति:** खाद्य पदार्थों की कीमतें गैर-मौद्रिक कारकों (जैसे- मौसम, कीट, वैश्विक संकट, आदि) से भी प्रभावित होती हैं, जिन्हें नीतिगत ब्याज दरों में बदलावों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। • **प्रो-साइक्लिक मौद्रिक नीति से बचना:** बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि से **आर्थिक संवृद्धि दर कम** हो सकती है। • **अंतर्राष्ट्रीय अनुभव:** विश्व के कई केंद्रीय बैंक (जैसे- अमेरिकी फेडरल रिजर्व) मौद्रिक नीति निर्धारित करते समय **कोर मुद्रास्फीति** पर ध्यान केंद्रित करते हैं। • **दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना:** बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के अल्पकालिक उपायों (ब्याज दर में वृद्धि) से बचने से निवेश हेतु अनुकूल और स्थिर माहौल तैयार होता है।	• **आम लोगों पर असर पड़ना और मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होना:** खाद्य मुद्रास्फीति का निर्धन लोगों के दैनिक जीवन पर सीधा असर पड़ता है। यदि इसे नजरअंदाज किया गया, तो सरकारी नीतियों के प्रति असंतोष उत्पन्न होने का खतरा बढ़ सकता है। • **सेकंड-राउंड इफेक्ट्स:** अधिक समय तक उच्च खाद्य मुद्रास्फीति बने रहने से इसके प्रभाव में कोर मुद्रास्फीति भी आ सकती है। • **मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क को कमजोर करना:** खाद्य मदों को हटाने से मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण के उद्देश्य की वैधता और जवाबदेही कम हो सकती है। • **डेटा सीमाएं:** कोर मुद्रास्फीति के आंकड़े भी गलत या अधूरे हो सकते हैं और इस पर अधिक-निर्भरता जोखिमपूर्ण हो सकता है।

आगे की राह

- **हाइब्रिड फ्रेमवर्क:** हेडलाइन मुद्रास्फीति नियंत्रण को मुख्य लक्ष्य बनाना चाहिए, लेकिन मौद्रिक नीति के निर्णयों को निर्देशित करने के लिए कोर मुद्रास्फीति का उपयोग करना चाहिए।
- **खाद्य मदों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना चाहिए:** खाद्य पदार्थों की आपूर्ति से जुड़ी बाधाओं को कम करने के लिए वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन और लॉजिस्टिक्स में निवेश बढ़ाना चाहिए तथा e-NAM में भागीदारी बढ़ानी चाहिए।
- **बफर स्टॉक एवं व्यापार नीति का उपयोग करना:** खाद्य पदार्थों की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकारी अनाज भण्डार का बेहतर प्रबंधन और निर्यात-आयात नीतियों का सक्रिय रूप से उपयोग करना चाहिए।
- **मुद्रास्फीति पूर्वानुमान मॉडल में सुधार करना:** मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान टूल्स में जलवायु पूर्वानुमान मॉडल, खाद्य कीमतों की वैश्विक स्थिति और रियल टाइम के आंकड़ों को शामिल करना चाहिए।

निष्कर्ष

आर्थिक सर्वेक्षण में **मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क में** खाद्य मदों की कीमतों को शामिल न करने का प्रस्ताव वास्तव में मौद्रिक नीति को और अधिक प्रभावी बना सकता है। हालांकि इस फ्रेमवर्क की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इसका सावधानीपूर्वक क्रियान्वयन बहुत ज़रूरी है। इस संबंध में एक संतुलित हाइब्रिड तरीका अपनाना बेहतर होगा, जिसमें हेडलाइन मुद्रास्फीति नियंत्रण को औपचारिक लक्ष्य बनाना चाहिए लेकिन मौद्रिक नीति के निर्धारण के लिए कोर मुद्रास्फीति का उपयोग करना चाहिए। इससे भविष्य में संतुलित मार्ग सुनिश्चित होगा।

4.5. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
सकल राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	पूंजीगत व्यय	ऋण-GDP अनुपात	GST क्षतिपूर्ति
DISCOMs	सब्सिडी का बोझ	राजकोषीय जिम्मेदारी कानून	मध्यम अवधि राजकोषीय योजनाएं	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
एंजल टैक्स	दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर	इंडेक्सेशन लाभ	इक्विलाइजेशन लेवी	मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण फ्रेमवर्क

4.6 अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

हाल के वर्षों में कई भारतीय राज्यों ने अपने राजकोषीय सूचकों में सुधार दिखाया है, फिर भी कुछ राज्य अब भी गंभीर राजकोषीय दबाव का सामना कर रहे हैं। इस राजकोषीय दबाव में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों का विश्लेषण कीजिए तथा इन चुनौतियों का समाधान करने हेतु हाल ही में किए गए सुधारों पर चर्चा कीजिए।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
हालिया संदर्भ दीजिए	सुधार दर्ज करने वाले राजकोषीय संकेतक और राजकोषीय दबाव संबंधी /कारक	हालिया सुधार	आगे की राह

5. बैंकिंग, भुगतान प्रणाली और वित्तीय बाजार (Banking, Payment Systems and Financial Markets)

5.1. भारत में बैंकिंग क्षेत्रक: एक नज़र में (Banking Sector in India at a Glance)

भारत में बैंकिंग क्षेत्रक

भारत में बैंकिंग क्षेत्रक की स्थिति (मार्च 2024)

भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs), 21 निजी क्षेत्रक के बैंक, 45 विदेशी बैंक आदि हैं।	2023-24 में **बैंकों की लाभप्रदता** में लगातार छठे वर्ष भी सुधार हुआ।	**सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA)** अनुपात 13 वर्षों में सबसे कम होकर 2.7% पर आ गया।	GNPA अनुपात कृषि क्षेत्रक के लिए सबसे अधिक (6.2%) और रिटेल लोन के लिए सबसे कम (1.2%) रहा है।

बैंकिंग क्षेत्रक के लिए शुरू की गई पहलें

सार्वजनिक क्षेत्रक के **बैंकों का विलय** (2019 में सार्वजनिक क्षेत्रक के 10 बैंकों का विलय करके 4 बैंक बनाना), **सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों** का बेसल III मानदंडों के अनुसार पुनर्पूंजीकरण।	बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन, ताकि **गवर्नेंस की विफलताओं के मामले में बैंक बोर्डों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का अधिकार RBI को मिल सके।**	NPAs के समयबद्ध समाधान के लिए **परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई फ्रेमवर्क, आदि।**	**डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा:** जैसे, UPI, आधार-लिंक्ड बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आदि।

चुनौतियां

डिजिटल फ्रॉड: 2023-24 में, कुल फ्रॉड्स में इंटरनेट और कार्ड की हिस्सेदारी राशि के मामले में 44.7% और फ्रॉड की संख्या के मामले में 85.3% थी।	**कमजोर गवर्नेंस:** जैसे सरकारी हस्तक्षेप के कारण PSBs में स्वायत्तता की कमी और निर्णय लेने में अक्षमता।	**विनियामक अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव:** RBI, SEBI, IRDAI, CCI जैसी कई विनियामक संस्थाओं की वजह से यह स्थिति आती है।	**अन्य:** बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां; कम वित्तीय समावेशन; प्रौद्योगिकी को अपनाने की मंद गति आदि।

आगे की राह

पी. जे. नायक समिति की सिफारिशें: सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों को स्वायत्तता प्रदान करना, बैंक अधिकारियों के वेतन को मुनाफे से जोड़ना, आउटकम-आधारित नीति को बढ़ावा देना।	RBI को रियल टाइम पर रिपोर्टिंग के माध्यम से निर्णय लेने और फाइनेंसियल डिस्क्लोजर में **पारदर्शिता को मजबूत करना।**	**नरसिम्हम समिति-II की सिफारिशें: मजबूत व्हिसलब्लोअर तंत्र स्थापित करना,** RBI, सेबी, IRDAI आदि के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विनियामक संस्थाओं के बीच समन्वय को सरल एवं कारगर बनाना।

5.1.1. तरलता घाटा (Liquidity Deficit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग प्रणाली में उच्च तरलता घाटा यानी लिक्विडिटी डेफिसिट को कम करने के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की है। वर्तमान लिक्विडिटी डेफिसिट पिछले 15 वर्षों में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- RBI ने निम्नलिखित की मदद से बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी बढ़ाए:
  - RBI ने **खुले बाजार परिचालन (OMOs)** के माध्यम से **50,000 करोड़ रुपये की दो समान किस्तों में बाजार से कुल 1,00,000 करोड़** रुपये मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की है।
  - RBI ने 36 माह की अवधि के लिए **10 बिलियन अमेरिकी डॉलर** की **USD/ INR खरीद/ बिक्री स्वैप नीलामी** आयोजित की है।

- **बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी या बैंकिंग तरलता:** केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली को उपलब्ध कराए गए रिजर्व को बैंकिंग तरलता कहा जाता है।
- जनवरी 2025 में यह तरलता घाटा बढ़कर **3.15 ट्रिलियन रुपये** तक पहुँच गया, जो पिछले 15 वर्षों का उच्चतम स्तर है।

लिक्विडिटी डेफिसिट के लिए जिम्मेदार कारक

- **कर भुगतान के लिए बैंकों से धन निकासी:** दिसंबर, 2024 में कंपनियों ने **अग्रिम कर** के रूप में **3 ट्रिलियन रुपये का भुगतान** किया। इसकी वजह से बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी में भारी गिरावट दर्ज की गई।
- **जस्ट इन टाइम (JIT) - सिंगल नोडल अकाउंट (SNA)-SPARSH ट्रांजिशन:** सरकार द्वारा नई JIT प्रणाली लागू किए जाने के कारण केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्यों को केंद्र सरकार से मिलने वाले फंड के ट्रांसफर की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। SNA-SPARSH प्रणाली के तहत RBI के माध्यम से फंड ट्रांसफर की प्रकिया में थोड़ा अधिक समय लग रहा है। इससे कुछ समय के लिए बैंकिंग प्रणाली में लिक्विडिटी की कमी हो जाती है।
- **विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) बाजार:**
    - **पूंजी निवेश में अस्थिरता:** शेयर बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा की गई बिकवाली से देश से बड़ी मात्रा में पूंजी बाहर चली गई है।
    - **विदेशी मुद्रा बाजार में RBI का हस्तक्षेप: RBI रुपये के मूल्यह्रास को रोकने के लिए डॉलर की बिक्री** करता है, परन्तु डॉलर की बिक्री से बैंकिंग प्रणाली में मौजूद नकदी की मात्रा कम हो सकती है।

लिक्विडिटी डेफिसिट का प्रभाव				
उच्च उधार लागत: बैंक आम लोगों और NBFCs को अधिक ब्याज दर पर उधार देते हैं। इससे आवासन और MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) जैसे अहम क्षेत्रकों के लिए ऋण लेना महंगा और मुश्किल हो जाता है।	**मौद्रिक नीति के लाभों को पहुंचने में देरी:** जब तक अधिक नकदी नहीं होगी, तब तक मौद्रिक नीतिगत दरों में कटौती वास्तविक रूप से प्रभावी नहीं हो सकती।	**ऋण की उपलब्धता:** लिक्विडिटी की कमी के दौरान बैंक ऋण देना कम कर देते हैं। इससे आम लोगों और व्यवसायियों के लिए ऋण लेना कठिन हो जाता है जिससे खर्च और निवेश में गिरावट आती है।	**बैंकों के मुनाफे में कमी:** नकदी की कमी की स्थिति में बैंकों को फंड जुटाने के लिए उच्च ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है। इस वजह से **उनके मुनाफे पर नकारात्मक प्रभाव** पड़ता है।	**बाजार में अस्थिरता:** नकदी की कमी से बाजार में लोगों का विश्वास कम होता है और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका असर शेयर बाजार और अन्य निवेश साधनों की कीमतों पर भी पड़ता है।

लिक्विडिटी डेफिसिट के प्रबंधन के लिए RBI के पास विकल्प: चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF), खुला बाजार परिचालन (OMOs), बाजार स्थिरीकरण योजना (MSS), नकद आरक्षित अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR), विदेशी मुद्रा स्वैप, आदि।

निष्कर्ष

हालिया तरलता घाटा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए लचीले और संतुलित मौद्रिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

5.1.2. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार (PSL) संबंधी मानदंड में संशोधन (Revised Priority Sector Lending Norms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने **PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग संबंधी दिशा-निर्देशों** में संशोधन किया है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य उन जिलों में लघु ऋणों यानी कम राशि वाले ऋण को बढ़ावा देना है जहां आर्थिक स्थिति कमजोर है और लोगों को औसतन कम ऋण मिलता है।

प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग संबंधी संशोधित मानदंड

- **इंसेंटिव फ्रेमवर्क:** इसके तहत जिन जिलों में **ऋण वितरण कम** (प्रति व्यक्ति 9,000 रुपये से कम) है, वहां PSL संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को **अधिक भारांश (125%)** दिया जाएगा।
- **डिसइनसेंटिव फ्रेमवर्क:** पहले से ही **अधिक ऋण प्राप्त** करने वाले जिलों में **(प्रति व्यक्ति 42,000 रुपये से अधिक)**, PSL संबंधी नए ऋण हेतु बैंकों को **कम भारांश (90%)** दिया जाएगा।

- **अन्य जिले:** कम ऋण प्राप्त करने वाले कुछ जिलों और उच्च ऋण प्राप्त करने वाले जिलों को छोड़कर, **अन्य सभी जिलों में भारांश 100%** के मौजूदा स्तर पर जारी रहेगा।
- **MSME ऋण:** MSMEs को दिए गए सभी बैंक ऋण **PSL श्रेणी** में आएंगे।

प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रक को उधार (PSL) के लिए नए मानदंडों की आवश्यकता क्यों है?

- ऋण पोर्टफोलियो / ऋण वितरण के मामले में **क्षेत्रीय असमानताओं** को दूर करने के लिए।
- **MSME क्षेत्रक के लिए ऋण प्रवाह की कमी** को दूर करने के लिए।
- **विनिर्माण उद्योग अथवा वस्तुओं के उत्पादन देने के लिए।**

"प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार (PSL)" के बारे में

- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक** का आशय उन क्षेत्रकों से है जिन्हें **सरकार और RBI देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण** मानते हैं। बैंक ऋण के मामले में अन्य क्षेत्रों की तुलना में इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।
- **PSL लक्ष्य:** बैंकों को अपने **समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC)**[17] **या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर के ऋण के समान राशि (CEOBE)**[18] का एक हिस्सा (जो भी अधिक हो) PSL के लिए अनिवार्य रूप से आवंटित करना होगा।
    - अनिवार्य लक्ष्य अलग-अलग बैंकों के लिए अलग-अलग है। यह **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और 20 या अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों के लिए 40% है, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा लघु वित्त बैंकों के लिए यह 75% है।**

भारतीय अर्थव्यवस्था पर PSL का सकारात्मक प्रभाव

- **वित्तीय समावेशन:** PSL मानदंड यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लघु एवं सीमान्त किसान, महिलाएं, कमजोर वर्ग जैसे समुदायों को भी ऋण का लाभ मिले।
- **कृषि का समर्थन:** अन्य नीतियों के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों हेतु PSL दिशा-निर्देश के कारण कृषि क्षेत्रक के लिए अनिवार्य 18% ऋण देने का प्रावधान करने के चलते कृषि ऋण में 2000 से 2020 तक 19.81% की CAGR[19] दर्ज की गई।
- **MSMEs को बढ़ावा मिलना:** PSL के तहत MSMEs के लिए ऋण प्राप्त करना आसान हो गया है। इसके चलते रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिला है।
- **आय वृद्धि:** आंध्र प्रदेश में की गई एक केस स्टडी में यह बात सामने आई है कि लाभार्थियों की आय में वृद्धि हुई है।
- **PSL संबंधी लक्ष्य प्राप्त करना:** अलग-अलग अवधियों और बैंक श्रेणियों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को दिया जाने वाला ऋण लगातार 40% से अधिक रहा है, जो अलग-अलग बैंकों की रणनीतियों से प्रभावित है।

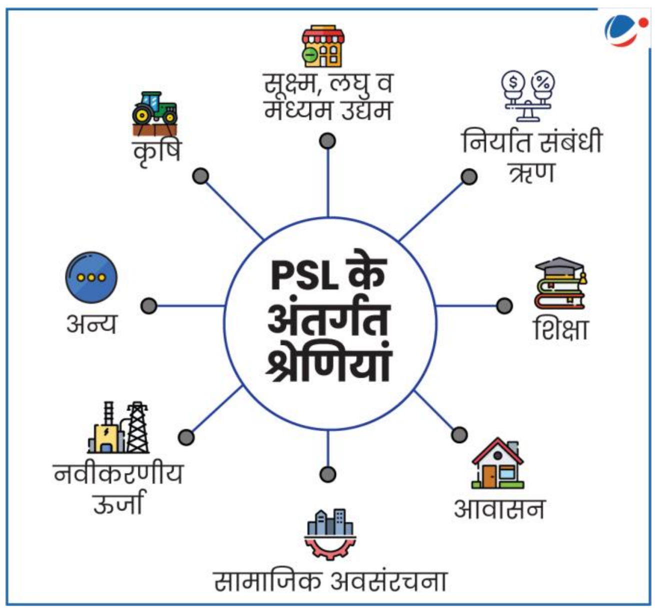

PSL से जुड़ी समस्याएं

- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs):** कुछ अध्ययनों के अनुसार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक ऋण के चलते अधिक NPA बना है और **NPA को बट्टे खाते में डाला गया (राइट ऑफ)** है।
- **लागत में वृद्धि होना:** PSL संबंधी शर्तों के पालन की वजह से बैंकों की प्रशासनिक और लेन-देन लागत में वृद्धि हुई है।
- **PSL से जुड़ी अन्य समस्याएं:** बैंकों की लाभप्रदता कम हुई है, बैंकों के कामकाज में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा है, आदि।

---

17 Adjusted Net Bank Credit

18 Credit Equivalent of Off-Balance Sheet Exposure

19 Compound annual growth rate/ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

आगे की राह

- **सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों को मजबूत करना और "लघु" वित्त बैंक खोलने के लिए प्रोत्साहित करना:** सूक्ष्म वित्तीय संस्थान अपने विशाल सेवा वितरण नेटवर्क और **"लास्ट माइल कनेक्टिविटी"** के व्यवसाय मॉडल के माध्यम से बैंक रहित ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ऋण देने की सुविधा बढ़ा सकते हैं।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** उदाहरण के लिए- किसानों को ऋण मंजूरी के लिए मोबाइल बैंकिंग ऐप्स के बारे में जागरूक करना चाहिए। इससे बैंकों की ऋण वितरण की लागत कम होगी तथा विशेष रूप से ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण वितरण और दक्षता में वृद्धि होगी।
- **मजबूत ऋण अवसंरचना और जोखिम मूल्यांकन टूल बनाना:** ऋण लेने वालों के ऋण चुकाने की क्षमता का बेहतर तरीके से मूल्यांकन करने और NPAs में कमी लाने के लिए टूल्स यानी मैकेनिज्म बनाए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

भारत में PSL एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। जहां यह फ्रेमवर्क दशकों से वंचित क्षेत्रों तक संस्थागत ऋण पहुँचाने में सफल रहा है, वहीं अब इसकी प्रगति के लिए संरचनात्मक सुधारों व तकनीकी नवाचारों दोनों की आवश्यकता है।

5.1.3. एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (One State, One RRB)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने **"एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" सिद्धांत के आधार पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के विलय** को अधिसूचित किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्र सरकार ने RRBs का विलय **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया है।
- यह **विलय का चौथा चरण** है। इस विलय के बाद, **26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अब 28 RRBs होंगे**, जो पहले **43** थे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks: RRBs) के बारे में

- **उत्पत्ति: नरसिंहम वर्किंग ग्रुप (1975)** की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर, 1975 को RRB की स्थापना हुई थी।
- **RRBs का स्वामित्व:** संयुक्त रूप से -
  - **केंद्र सरकार: 50%** हिस्सेदारी;
  - **राज्य सरकार: 15%** हिस्सेदारी; तथा
  - **प्रायोजक वाणिज्यिक बैंक: 35%** हिस्सेदारी
- **विनियमन और पर्यवेक्षण:** RRBs का विनियमन **भारतीय रिजर्व बैंक** द्वारा **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के अंतर्गत किया जाता है। **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड/ NABARD)** इनका **पर्यवेक्षण** करता है।
  - कर उद्देश्यों से **आयकर अधिनियम, 1961** के अंतर्गत इन्हें **सहकारी संस्थाओं** के रूप में दर्जा प्राप्त है।
- **RRBs के लिए मुख्य आवश्यकताएं:**
  - इन्हें **समायोजित निवल बैंक ऋण (ANBC)** या **क्रेडिट एक्विवैलेन्ट ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर (CEOBE)** (जो भी अधिक हो) का **75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण (PSL)** के रूप में वितरित करना पड़ता है। सरल शब्दों में, RRBs को अपने कुल ऋण का 75% हिस्सा PSL को देना पड़ता है।

एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का महत्व

- **व्यावसायिक गतिविधियों में तीव्र गति से वृद्धि:** RRBs का कुल कारोबार, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में, **वित्त वर्ष 2030 तक लगभग 5.2%** तक पहुंचने की उम्मीद है, जो **वित्त वर्ष 2024 में लगभग 3.7%** था।
- **वित्तीय लाभ:** एकीकृत RRBs के पास-
  - **अधिक पूंजी आधार होगा:** इससे वे RBI द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता मानदंडों को पूरा कर सकेंगे।

© Vision IAS

- **नियमों एवं मानदंडों का बेहतर अनुपालन:** एकीकृत RRB नियमों के पालन को केंद्रीकृत कर सकता है, जैसे कि धन-शोधन विरोधी जांच, KYC सत्यापन तथा RBI और नाबार्ड को रिपोर्ट करना।

- **प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि:** एकत्रित संसाधन और विशेषज्ञता से विविधीकृत एवं स्थानीय रूप से तैयार उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा, जैसे- **सूक्ष्म वित्त के विविध विकल्प**, **बीमा सुविधाओं के साथ संयुक्त उत्पाद,** आदि।
- **एकीकृत आई.टी. और तकनीकी अवसंरचना:** इससे **साइबर सुरक्षा में सुधार**, **धोखाधड़ी की बेहतर निगरानी**, तथा **बिग डेटा एनालिटिक्स** के माध्यम से **स्मार्ट निर्णय-निर्माण** जैसी क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं।
- **अन्य लाभ:** शाखा नेटवर्क की पुनर्संरचना, अनावश्यक प्रक्रियाओं को समाप्त करने के लिए परिचालन या कामकाज में दक्षता; विविध कौशलों में सक्षम **कार्मिकों के एक बड़े समूह की उपलब्धता सुनिश्चित** होगी। क्षेत्रीय रूप से मजबूत प्रायोजक बैंकों के साथ RRBs को एकीकृत करके **निरीक्षण और परिचालन संबंधी गाइडलाइन को बेहतर** किया जा सकता है।

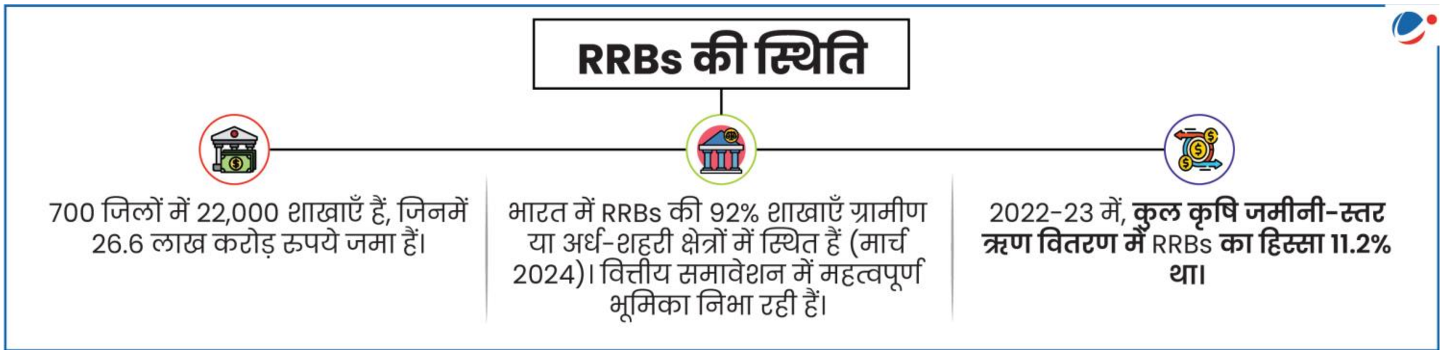

RRBs के एकीकरण में चुनौतियां

- **परिचालनात्मक (Operational):** एकीकृत होने वाले बैंकों की **परिचालनात्मक और संगठनात्मक संरचना में अंतर।**
- **वित्तीय:** एकीकरण के बाद CRAR अनुपात पर **प्रतिकूल प्रभाव की संभावना;** प्रतिभूतियों, निधियों और निवेशों के **प्रवाह में जटिलताएं।**
- **प्रशासनिक और हितधारक प्रबंधन:** एकीकृत होने वाले बैंकों में **कार्यबल पुनर्गठन और कर्मचारियों की आवाजाही** से संबंधित मुद्दे; विभागों और प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के बीच **अपडेट को ट्रैक करने में कठिनाइयां।**
- **तकनीकी:** ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और माइग्रेट किए गए डेटा के बैकअप सहित विशाल मात्रा में डेटा का सुरक्षित और सही तरीके से स्थानांतरण सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

निष्कर्ष

"एक राज्य-एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" की सफलता सुनिश्चित करने के लिए, मानव संसाधन नीतियों को सुसंगत बनाना, डिजिटल प्रणालियों को एकीकृत करना, शाखा संचालन को सुव्यवस्थित करना और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप उत्पादों को तैयार करना महत्वपूर्ण है। इससे NPA की वसूली में तेजी लाने, राज्य स्तरीय निगरानी समितियों का गठन करने और नियमित वित्तीय समीक्षा करने से चुनौतियों का समाधान करने तथा वित्तीय स्थिरता एवं ग्रामीण समावेशन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

5.1.4. सहकारी बैंक: एक नज़र में (Cooperative Banks at a Glance)

सहकारी बैंक: एक नजर में

सहकारी बैंक सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और इनका **स्वामित्व और संचालन** सदस्यों के हाथ में होता है। इन्हें **ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों (UCBs)** में विभाजित किया जा सकता है।

शहरी सहकारी बैंकों का महत्त्व

वित्तीय समावेशन: मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।	**स्थानीय जरूरतों पर ध्यान: सूक्ष्म उद्यमों,** कुटीर उद्योगों आदि को **वित्त-पोषित करके स्थानीय अर्थव्यवस्था** को मजबूत करते हैं।	**प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण:** कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को समर्थन करते हैं।	**लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना: सहयोग, और लोकतंत्र के सिद्धांतों** का पालन करते हैं **और स्वशासन सुनिश्चित करते हैं।**

शहरी सहकारी बैंकों में सुधार के लिए उठाए गए हालिया कदम

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020: इस संशोधन ने RBI को शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड को भंग करने, उनके प्रबंधन में बदलाव करने और उनके लिए समाधान योजना तैयार करने का अधिकार दिया।	**संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क:** 2024 में, RBI ने शहरी सहकारी बैंकों को भी PCA फ्रेमवर्क के दायरे में ला दिया।	विनियामक दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए **RBI द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए 4-स्तरीय विनियामकीय फ्रेमवर्क पेश किया गया।**	RBI ने शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को **डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं** प्रदान करने की अनुमति दी है। अब शहरी सहकारी बैंक RBI की पूर्व मंजूरी लिए बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूद शाखाओं की कुल संख्या के **10% तक नई शाखाएं (अधिकतम 5 शाखाएं)** खोल सकते हैं।

शहरी सहकारी बैंकों के समक्ष मुख्य चुनौतियां

दोहरा विनियमन: राज्य सरकारों और **RBI/ नाबार्ड** द्वारा।	**कमजोर गवर्नेंस:** कई शहरी सहकारी बैंकों में राजनीतिक दखल, भाई-भतीजावाद, और वित्तीय कुप्रबंधन देखा जाता है	**क्षेत्रीय असमानता:** 2020 में कुल शहरी सहकारी बैंकों का **82% पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में केंद्रित है।**	**अन्य:** उच्च स्तर की NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ), पुरानी तकनीक आदि।

आगे की राह

गवर्नेंस और पर्यवेक्षण को मजबूत करना चाहिए	**विलय और अधिग्रहण को बढ़ावा देना चाहिए**	**स्वतंत्र ऑडिट को बढ़ावा**	**प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए**

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र
2025 ENGLISH MEDIUM 13 JULY | हिन्दी माध्यम 13 जुलाई
2026 ENGLISH MEDIUM 13 JULY | हिन्दी माध्यम 13 जुलाई

ऑप्शनल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़
✓ भूगोल ✓ समाजशास्त्र ✓ दर्शनशास्त्र ✓ हिंदी साहित्य
✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध
2025 ENGLISH MEDIUM 13 JULY | हिन्दी माध्यम 13 जुलाई
2026 ENGLISH MEDIUM 13 JULY | हिन्दी माध्यम 13 जुलाई

5.1.5. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs): एक नज़र में {Non-Banking Financial Companies (NBFCS) at a Glance}

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFCs)

NBFC कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के तहत पंजीकृत कंपनी है जो ऋण और अग्रिम देने, शेयर/स्टॉक/ बॉण्ड्स आदि के अधिग्रहण के कारोबार में संलग्न है।	**यह बैंकों से किस प्रकार अलग हैं:** ये मांग जमा (डिमांड डिपॉजिट) स्वीकार नहीं कर सकती (केवल सावधि जमा/टर्म डिपॉजिट स्वीकार करती हैं), पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होती हैं, और स्वयं के नाम वाले चेक जारी नहीं कर सकती।

स्थिति (2023)

RBI के पास कुल 9,356 NBFCs पंजीकृत हैं।	NBFC क्षेत्रक का वैल्यूएशन 326 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है।	NBFCs सबसे अधिक ऋण आवास और अवसंरचना क्षेत्रक को देती हैं।	वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2023 के बीच माइक्रोफाइनेंस ऋणों में इनकी हिस्सेदारी लगभग 2% से बढ़कर 3% हो गई।

मुख्य पहलें

तरलता कवरेज अनुपात (LCR) मानदंड का पालन अनिवार्य	**NBFC के लिए स्केल आधारित विनियमन फ्रेमवर्क**	RBI द्वारा NBFC को **कोर वित्तीय सेवा समाधान** अपनाने के लिए प्रेरित करना।	त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA) फ्रेमवर्क के दायरे में लाया गया (2022)

चुनौतियां

एसेट-लायबिलिटी में असंतुलन यानी ऋण वितरण और जमा राशि में असंतुलन (उदाहरण के लिए, IL&FS संकट)	कमजोर गवर्नेंस और पारदर्शिता	ग्राहकों को ऋण देने के लिए उच्च ब्याज दर पर बाजार से ऋण लेने पर अधिक निर्भरता	ऋण वापस नहीं मिलने और परिचालन संबंधी जोखिम: उदाहरण के लिए- ऋण चुकाने की क्षमता की जांच किए बिना ग्राहकों को ऋण देने से उच्च NPA अनुपात।

आगे की राह

विनियमन और पर्यवेक्षण प्रणालियों को मजबूत करना चाहिए	लिक्विडिटी या तरलता प्रबंधन को बेहतर करना चाहिए	नई प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना चाहिए	पुनर्वित्त सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए

5.2. वित्तीय बाजार (Financial Market)

5.2.1. भारत में पूंजी बाजार: एक नज़र में (Capital Market in India at a Glance)

भारत में पूंजी बाजार

पूंजी बाजार वित्तीय बाजार का ही एक हिस्सा है। इसके अंतर्गत खरीदार और विक्रेता दीर्घावधि के वित्तीय लिखतों (इंस्ट्रूमेंट्स) का व्यापार करते हैं। यहां दीर्घावधि का अर्थ एक वर्ष से अधिक की अवधि से है।

भारतीय पूंजी बाजार में चुनौतियां

कम जानकारी सार्वजनिक करना: कंपनियां संपूर्ण जानकारी सार्वजनिक नहीं करती हैं ।	**निवेशकों के निवेश को पर्याप्त संरक्षण नहीं मिलना,** जैसे- शिकायत निवारण तंत्र की कमी।	**रिटेल लोगों की कम भागीदारी** और छोटे शहरों से निवेश का अभाव।	सेबी और RBI के बीच विनियामक अधिकारों का बंटवारा।	**अन्य: कदाचार, अनुचित गतिविधियां तथा घोटाले, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRAs) को प्रभावित करना।**

पूंजी बाजार में विकास को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम

खुदरा (रिटेल) निवेशकों की भागीदारी बढ़ानी चाहिए।	**निवेशकों के निवेश का संरक्षण के लिए कानूनी और विनियामकीय व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए।**	तथ्य आधारित वित्तीय आउटकम, और वार्षिक रिपोर्ट को बढ़ावा देकर बेहतर डिस्क्लोजर सुनिश्चित करना।	**मज़बूत उपायों के ज़रिए कदाचार और घोटालों पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाना**	'इन्वेस्टर पे' मॉडल जैसे उपायों के माध्यम से **क्रेडिट रेटिंग इंडस्ट्री में सुधार करना।**

5.2.2. वित्तीयकरण (Financialisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनुसार भारत को अति 'वित्तीयकरण' (Financialisation) के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है

वित्तीयकरण क्या है?

- वित्तीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत **वित्तीय बाजार, वित्तीय संस्थान और वित्तीय अभिजात वर्ग का आर्थिक नीतियों एवं आर्थिक परिणामों पर अधिक प्रभाव स्थापित** हो जाता है।
- इस प्रकार, **वित्तीय मध्यवर्ती और प्रौद्योगिकियां हमारे दैनिक जीवन पर काफी प्रभाव** डालने लगते हैं।
- इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि पारंपरिक रूप से, **'भौतिक परिसंपत्तियों' (जैसे रियल एस्टेट, स्वर्ण आदि) की बजाय 'वित्तीय परिसंपत्तियों' (जैसे म्यूचुअल फंड) में निवेश** किया जाने लगा है।

वित्तीयकरण को बढ़ावा देने वाले कारक			
खर्च करने की बढ़ती क्षमता के साथ **मध्यम वर्ग का** उदय।	लोगों में मुद्रास्फीति के कारण फिक्स्ड डिपॉजिट की तुलना में **अन्य विकल्पों से अधिक रिटर्न हासिल करने की इच्छा।**	सरकार द्वारा **फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को दिए जा रहे प्रोत्साहन।**	डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन का **बढ़ता स्तर।**

अति वित्तीयकरण एक चिंता का विषय क्यों है?

- **असमानता में वृद्धि:** वित्तीय आय का एक बड़ा हिस्सा (जैसे कि स्टॉक और अन्य निवेशों से होने वाला लाभ) सबसे अधिक इक्विटी स्वामित्व वाले धनी व्यक्तियों को मिलता है। ये धनी व्यक्ति आबादी का शीर्ष 1% हैं।
- **अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव:** ऐसा इस कारण, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार की बजाय **वित्तीय निवेश से अधिक लाभ** होने लगता है।
  - इस प्रकार, अर्थव्यवस्था पर **शेयर बाजार का अधिक प्रभाव स्थापित हो** जाता है और रोजगार सृजन या जीवन स्तर में वृद्धि की अनदेखी होने लगती है।

© Vision IAS

- **आम लोगों द्वारा ऋण लेने में वृद्धि:** वास्तविक आय में ठहराव के चलते आम लोगों की **ऋण पर निर्भरता बढ़** सकती है (जैसा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में देखा गया है)।
- **नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव:** वित्तीयकरण से **प्रीडेटरी लेंडिंग, अधिक जोखिम लेने और श्रमिक संरक्षण की उपेक्षा करने वाली नीतियों को बढ़ावा** मिल सकता है।

निष्कर्ष

विकासशील देशों को अक्सर तब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जब उनके वित्तीय बाजार बहुत तेजी से बढ़ते हैं या जटिल नवाचार को बाजार में ले कर आते हैं, जबकि इसे संभालने के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं होती है। इससे गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसे कि 1997-98 का एशियाई वित्तीय संकट। इस कारण भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके वित्तीय बाजार सावधानीपूर्वक, स्थिर और सुव्यवस्थित तरीके से विकसित हों, ताकि अर्थव्यवस्था इसके साथ तालमेल बिठा सके और बड़े संकटों से बचा जा सके।

5.3. भुगतान प्रणाली: एक नज़र में (Payment System at a Glance)

भारत में भुगतान प्रणाली

भारत में भुगतान प्रणाली की स्थिति

RBI के अनुसार, **भारत में लगभग 50% लेन-देन कैश में होता है।**	भारत में मात्रा (वॉल्यूम) के मामले में **डिजिटल भुगतान के 50% हिस्से पर डेबिट कार्ड, UPI और IMPS का प्रभुत्व है।**	भारत में मूल्य (वैल्यू) के मामले में **डिजिटल भुगतान के 53% हिस्से पर RTGS और NEFT का प्रभुत्व है।**	**2019 में प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन-देन 22.4** रहा। (वर्ष 2014 में यह 2.4 था)।

प्रमुख लक्ष्य

रियल टाइम, सुरक्षित, सुलभ और आसान भुगतान तंत्र प्रदान करना।	**एकीकृत भुगतान प्रणाली सुनिश्चित करना तथा एक भुगतान से दूसरी भुगतान प्रणाली में लेनदेन** को आसान बनाना।	**लेन-देन की लागत को यथासंभव कम से कम** करना।	लेन-देन की उच्च मात्रा को प्रबंधित करने और बनाए रखने के लिए **संस्थागत, डिजिटल और भौतिक अवसंरचना का निर्माण करना।**

योजनाएं/ पहलें

RBI का **पेमेंट विजन 2025**	**भुगतान अवसंरचना विकास निधि (PIDF)**	RBI का **मिशन हर पेमेंट डिजिटल और 75 डिजिटल विलेज** प्रोग्राम।	RBI द्वारा **फिनटेक रिपॉजिटरी** की स्थापना।

बाधाएं

साइबर अटैक, डेटा में सेंध, कई बार भुगतान प्लेटफॉर्म का काम न करना	**डिजिटल वित्तीय लेनदेन के बारे में जागरूकता** का अभाव।	**ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की सीमित पहुंच।**	विशेष रूप से दुर्गम क्षेत्रों में **लागत और कनेक्टिविटी** से संबंधित मुद्दे।

आगे की राह

दूरसंचार जैसी **आधारभूत अवसंरचना** को भी मजबूत करना।	भुगतान प्रणाली के लिए **एकल विनियामकीय व्यवस्था** की आवश्यकता है।	**मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ऑफ-लाइन भुगतान** के लिए भी अधिक विकल्प प्रदान करना।	**विनियामकों के बीच समन्वय** को बढ़ाना, **वित्तीय समावेशन आदि।**

5.3.1. डिजिटल भुगतान: एक नज़र में (Digital Payments at a Glance)

भारत में डिजिटल भुगतान

भारत में डिजिटल भुगतान की स्थिति

भारत में **40% से अधिक भुगतान डिजिटल** माध्यम से होते हैं (विश्व में सर्वाधिक डिजिटल लेन-देन)।	2024 में, UPI के माध्यम से लगभग **172 बिलियन** लेनदेन हुए, जो **2023 के 117.64 बिलियन से 46% अधिक** है।	पांच वर्षों में क्रेडिट कार्ड की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है।

भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

तत्काल भुगतान सेवा (IMPS): रियल टाइम में, 24x7 इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा	कम मूल्य वाले भीम-UPI लेन-देन (P2M) को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना	**यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), UPI के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड का एकीकरण आदि।**	**अन्य: जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) ट्रिनिटी, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह फास्टैग आदि।**

चुनौतियां

डिजिटल डिवाइड: ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच और स्मार्टफोन की पहुंच सीमित है।	**साइबर सुरक्षा जोखिम:** ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग और डेटा चोरी की बढ़ती घटनाएं।	**विश्वास की कमी:** लेन-देन की विफलता और धन हानि का डर डिजिटल लेनदेन अपनाने को हतोत्साहित करता है।	**सीमित वित्तीय समावेशन:** हालांकि जन धन खाते खोले गए हैं, लेकिन उनमें से कई खाते निष्क्रिय बने हुए हैं।

आगे की राह

इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार करना, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।	**साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देना:** धोखाधड़ी का पता लगाने, शिकायत निवारण आदि के लिए मजबूत फ्रेमवर्क।	मजबूत और सुरक्षित भुगतान प्रणाली, डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा संबंधी कानून। **मुक्त व्यापार समझौता (FTAs) के संबंध में सुरजीत भल्ला समिति की मुख्य सिफारिशें:** तकनीकी विनियमनों पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू	जागरूकता पैदा करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने आदि के लिए बड़े पैमाने पर

5.3.2. सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा (Central Bank Digital Currency: CBDC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने **'डिजिटल डॉलर'** या अमेरिकी **'सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC)'** शुरू करने के प्रस्ताव को रोकने हेतु एक कार्यकारी आदेश जारी किया।

डिजिटल मुद्रा क्या है?

- यह केवल **डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक** रूप में उपलब्ध मुद्रा है। साधारण भाषा में, डिजिटल मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद मुद्रा है, जिसे डिजिटल रूप से स्टोर, प्रबंधित और लेन-देन किया जाता है। आमतौर पर, इसे **इंटरनेट से कनेक्टेड डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम** के माध्यम से **प्रबंधित, संग्रहित और एक्सचेंज** किया जाता है।

डिजिटल मुद्राओं के 3 प्रकार

क्रिप्टोकरेंसी	CBDCs	स्टेबलकॉइन्स
• नई यूनिट्स के निर्माण और लेन-देन को **सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक पद्धतियों का उपयोग** किया जाता है। • लेन-देन को सत्यापित करने के लिए **ब्लॉकचेन लेज़र का उपयोग** किया जाता है। • **नियंत्रण:** विकेंद्रीकृत • **उदाहरण:** बिटकॉइन	• **केंद्रीय बैंकों द्वारा जारी फिएट मुद्राओं** का डिजिटल संस्करण है। • पारंपरिक मुद्राओं की विश्वसनीयता बनाए रखती है और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। • **नियंत्रण:** केंद्रीकृत • **उदाहरण:** डिजिटल रुपया (e₹)	• यह आमतौर पर **किसी अंडरलाइंग एसेट्स के रिजर्व या एल्गोरिदम द्वारा समर्थित** होती है, जो बाजार की मांग के आधार पर आपूर्ति को नियंत्रित करती है। • इसे पारंपरिक मुद्राओं या अन्य परिसंपत्तियों की तुलना में **स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिजाइन** किया गया है। • **नियंत्रण:** केंद्रीकृत या हाइब्रिड • **उदाहरण:** टीथर (USDT)

© Vision IAS

सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में

- RBI के अनुसार **CBDC** एक **कानूनी मुद्रा (Legal Tender)** है और यह **केंद्रीय बैंक की देनदारी** होती है, जो **डिजिटल स्वरूप** में संप्रभु मुद्रा (Sovereign Currency) के रूप में जारी की जाती है और केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर दर्ज होती है।
- **CBDCs के प्रकार:**
  - **होलसेल CBDCs:** इसका उपयोग इंटर-बैंक भुगतान और प्रतिभूति लेन-देन के लिए बैंकों और अन्य लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों के बीच किया जाता है।
  - **रिटेल CBDCs**: यह आम जनता के लिए डिजिटल वॉलेट, स्मार्टफोन ऐप आदि के माध्यम से उपलब्ध है।

भारत के डिजिटल रूपी (e₹) के बारे में

- यह फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप है। इसे **भारतीय रिजर्व बैंक** द्वारा जारी और विनियमित किया जाता है। यह **सामान्य मुद्राओं (नोट) के मूल्यवर्ग** (जैसे 100 रुपये का नोट) में उपलब्ध है।
- यह **दिसंबर 2022** से **15 बैंकों** के साथ **पायलट मोड** में उपयोग में है।
- यह एक **कानूनी मुद्रा** है और **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 26** के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की देनदारी है।

CBDCs के संभावित लाभ

- **वित्तीय समावेशन:** CBDCs उन लोगों को डिजिटल भुगतान सेवाओं से जोड़ सकता है जो बैंकिंग प्रणाली से बाहर हैं या सीमित बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा होने से वे अर्थव्यवस्था में अधिक सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं।
- **लेन-देन की लागत में कमी:** वाणिज्यिक बैंकों और पेमेंट प्रोसेसर्स जैसे मध्यवर्तियों के हटने से व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए लेन-देन शुल्क में कमी आती है।
- **नकदी पर कम निर्भरता:** CBDCs सामान्य नोट (या सिक्का) की छपाई, वितरण और प्रबंधन में लगने वाली लागत को कम करने में सहायता करती है।
  - CBDCs **डिजिटल लेजर्स** पर संचालित होता है, जिससे लेन-देन का बेहतर रिकॉर्ड रखा जा सकता है तथा भ्रष्टाचार, कर चोरी एवं अवैध गतिविधियों में कमी लाई जा सकती है।
- **अन्य: मौद्रिक नीति के प्रभाव में सुधार करना;** यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भुगतान को सरल और तेज बना सकता है, जिससे **SWIFT** जैसे मध्यवर्तियों पर निर्भरता कम होगी।

CBDCs से जुड़ी चुनौतियां

- **साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिम:** CBDCs पर साइबर अटैक, हैकिंग और डेटा का अनधिकृत तरीके से प्राप्ति का खतरा बना रहता है। इससे वित्तीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है।
- **निजता के उल्लंघन का खतरा:** लेन-देन की ट्रैकिंग और पहचान का सत्यापन करने से **डेटा के सार्वजनिक होने का खतरा** बना रहता है।
- **डिजिटल डिवाइड:** CBDCs के उपयोग के लिए **तकनीकी ज्ञान** और डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता होती है। इससे **तकनीकी रूप से अधिक कुशल लोगों और कम कुशल लोगों के बीच की खाई बढ़ सकती** है।
- **अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन की चुनौतियां:** विदेशों में CBDCs के उपयोग को सुरक्षित बनाने के लिए वित्तीय अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और विभिन्न राष्ट्रीय कानूनों के दुरुपयोग को रोकने हेतु देशों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक होगा।
- **मौद्रिक संप्रभुता के लिए खतरा:** यदि लोग अपनी राष्ट्रीय मुद्रा की जगह **विदेशी CBDC (जैसे डिजिटल डॉलर या डिजिटल युआन)** का अधिक उपयोग करने लगेंगे, तो इससे स्थानीय मौद्रिक प्रणाली कमजोर हो सकती है।

निष्कर्ष

CBDC वित्तीय समावेशन बढ़ाने, नकदी पर निर्भरता घटाने और भुगतान प्रणाली की दक्षता सुधारने के लिए एक आशाजनक मार्ग प्रस्तुत करती है। हालांकि, निजता, सुरक्षा और स्थिरता से जुड़ी चिंताओं का समाधान करने के लिए सावधानीपूर्वक विनियमन और वैश्विक समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

5.3.3. UPI का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization of UPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने हेतु साझेदारी की है।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के बारे में

- UPI को 2016 में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एक रीयल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है।
- **उपलब्धियां:** 2016 में मात्र दस लाख लेनदेन से शुरू होकर, UPI ने अब 10 बिलियन (1,000 करोड़) लेनदेन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग और 5 करोड़ से ज़्यादा व्यापारी UPI का इस्तेमाल करते हैं।

UPI के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु पहलें

- **NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL):** इसे NPCI द्वारा भारत की भुगतान प्रणाली को विदेशों में स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए 2020 में स्थापित किया गया था। अब UPI के जरिये **यूनाइटेड किंगडम, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस** जैसे देशों में भुगतान किया जा सकता है।
- **UPI की वैश्विक स्वीकृति (इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट):** यह उपयोगकर्ताओं को भारतीय बैंक खातों का उपयोग करके UPI ऐप्स के जरिए सीधे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों को क्यूआर कोड स्कैन आधारित भुगतान करने में सक्षम बनाता है।
- **विदेशों से भारत में रेमिटेंस प्राप्त करना:** UPI उपयोगकर्ता अब विदेशों से सीधे रेमिटेंस प्राप्त कर सकते हैं।
- **अनिवासी भारतीयों (NRI) को शामिल करना:** अब 'अनिवासी (बाह्य) अकाउंट' धारक अनिवासी भारतीय लेनदेन के लिए UPI का प्रयोग कर सकते हैं।

UPI के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

- **अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों का विकल्प:** यह अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में स्विफ्ट (SWIFT) जैसी भुगतान प्रणालियों की जगह ले सकता है।
- **क्षेत्रीय वित्तीय एकीकरण को मजबूत करना:** यह वित्तीय एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है और व्यापारिक लेनदेन को और अधिक आसान बना सकता है।
- **ग्लोबल साउथ में नेतृत्व:** भारत की UPI ग्लोबल साउथ के देशों के लिए विकास का संधारणीय मार्ग प्रदान कर सकती है।
- **डिजिटल कूटनीति में मदद:** यह तकनीकी समाधान उपलब्ध कराकर भारत की विश्व-गुरु की छवि को और अधिक बढ़ा सकता है।
- **भारत के लिए नए अवसर:** जैसे कि भारतीय पर्यटक अब संयुक्त अरब अमीरात में नियोपे टर्मिनलों पर UPI से भुगतान कर सकते हैं।

UPI को वैश्विक स्तर पर अपनाने में चुनौतियाँ

- **अन्य देशों के अलग-अलग नियम-कानूनों को अपनाने की चुनौती:** इनमें मुद्रा विनियम, विनिमय दर और वॉलेट को वित्तीय संस्थाओं से जोड़ने जैसी चुनौतियां शामिल हैं।
- **अन्य पेमेंट सिस्टम्स से प्रतिस्पर्धा:** फोनपे और गूगल पे जैसे विदेशी स्वामित्व वाले UPI ऐप्स पहले से ही बाजार में अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं।
- **पुरानी प्रणाली की सीमाएँ:** पारंपरिक बैंकों को रियल टाइम में भुगतान प्रणाली अपनाने के लिए उच्च लागत और सिस्टम्स से जोड़ने के लिए जटिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। इससे छोटे बैंकों और फिनटेक कंपनियों के लिए UPI को अपनाना मुश्किल हो जाता है।

निष्कर्ष

भारत द्वारा UPI को दुनिया भर में प्रसारित करना वास्तव में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की दिशा में एक सोची-समझी रणनीति है। जैसे-जैसे UPI को दुनिया भर में अपनाया जा रहा है, वैसे-वैसे साझेदार देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। दीर्घावधि में, विश्व में UPI की सफलता भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के अन्य कंपोनेंट्स को भी दुनिया भर में अपनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इससे वैश्विक वित्तीय एवं तकनीकी क्षेत्रों में भारत का प्रभाव और अधिक बढ़ सकता है।

5.3.4. सीमा-पार भुगतान: एक नज़र में (Cross Border Payments at a Glance)

सीमा-पार भुगतान

सीमा-पार भुगतान एक प्रकार का वित्तीय लेन-देन है, जो वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच होता है। इस प्रकार के लेन-देन में **प्रेषक (Sender)** और **प्राप्तकर्ता (Recipient) अलग-अलग देशों में स्थित** होते हैं।

सीमा-पार भुगतान की स्थिति

भारत 2024 में सीमा पार भुगतान बाजार का मूल्य 206.5 बिलियन डॉलर था और 2034 तक इसके 414.6 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।	**वैश्विक** 2022 में वैश्विक सीमा पार भुगतान बाजार का मूल्य 181.9 ट्रिलियन डॉलर था और 2032 तक इसके 356.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सीमा-पार भुगतान का महत्व

रेमिटेंस में सरलता	यात्रा और पर्यटन को सुविधाजनक बनाना	**विदेशी निवेश में तेजी लाना**	वैश्विक बाजारों तक पहुंच

सीमा पार भुगतान में बाधाएं

अलग-अलग देशों के अलग-अलग सरकारी विनियम	वित्तीय डेटा के मानकीकरण का अभाव	**सुरक्षा संबंधी जोखिम** (मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद संबंधी वित्त-पोषण और साइबर फ्रॉड)।	लेनदेन की उच्च लागत और सेटलमेंट में देरी

पहलें

प्रोजेक्ट नेक्सस में RBI शामिल हुआ, जो **तत्काल सीमा-पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाता है।**	**ब्रिक्स ब्रिज:** ब्रिक्स देशों द्वारा प्रस्तावित भुगतान प्रणाली।	**mBridge परियोजना:** तीव्र, किफायती और अधिक सुरक्षित सीमा-पार भुगतान सक्षम करना।	UPI का अंतर्राष्ट्रीयकरण, INR में व्यापार निपटान तंत्र आदि।

आगे की राह

सुनियोजित रूप से डेटा आदान-प्रदान के लिए एक सुसंगत ISO 20022 संस्करण **अपनाना**	सीमा पार भुगतान में **विशेषज्ञता रखने वाली फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग** स्थापित करना	**सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDCs) जैसी नई पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्थाओं की संभावित भूमिका** का पता लगाना।	अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

5.4. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
तरलता घाटा	खुला बाजार परिचालन	विदेशी मुद्रा स्वैप	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को उधार	गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां
वित्तीयकरण	पूंजी बाजार	सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी	एकीकृत भुगतान इंटरफेस	एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह
माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं	वैधानिक तरलता अनुपात	सीमा-पार भुगतान	प्रणालीगत जोखिम	

5.5. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत में प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 'एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' नीति उनकी कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए कैसे कार्य करती है? इस नीति के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों पर चर्चा कीजिए।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
RRB का परिचय दीजिए	'एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' का महत्व	सफल कार्यान्वियन के उपाय	निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

- ✓ सामान्य अध्ययन
- ✓ निबंध
- ✓ दर्शनशास्त्र

2025	ENGLISH MEDIUM 13 JULY	हिन्दी माध्यम 13 जुलाई
2026	ENGLISH MEDIUM 13 JULY	हिन्दी माध्यम 13 जुलाई

Scan the QR CODE *to* download VISION IAS app

ऑप्शनल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़

- ✓ भूगोल
- ✓ समाजशास्त्र
- ✓ दर्शनशास्त्र
- ✓ हिंदी साहित्य
- ✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध

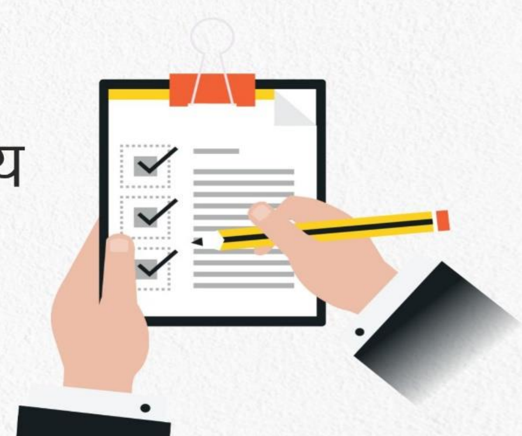

2025	ENGLISH MEDIUM 13 JULY	हिन्दी माध्यम 13 जुलाई
2026	ENGLISH MEDIUM 13 JULY	हिन्दी माध्यम 13 जुलाई

6. बाह्य क्षेत्रक (External Sector)

6.1. भारत का निर्यात क्षेत्रक: एक नज़र में (India's Export Sector at a Glance)

भारत का निर्यात क्षेत्रक

भारत के निर्यात की स्थिति

2024-25 में भारत का कुल निर्यात (वस्तुएं और सेवाओं को मिलाकर) **824.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के** बराबर था।	**आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, 2023 में, भारत का वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% और वस्तु निर्यात में 1.8% हिस्सा था।**	**अंकटाड** के अनुसार, भारत का निर्यात इसके **सकल घरेलू उत्पाद के 23% के बराबर है।**	भारत का **सेवा क्षेत्रक इसके निर्यात का एक महत्वपूर्ण घटक है।**

भारत का व्यापार घाटा (वित्त वर्ष 2023-24)

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने अपने **शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा** दर्ज किया।	**चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और हांगकांग** के साथ **भारत का व्यापार घाटा** 2022-23 की तुलना में **बढ़ा** है	**संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, ब्रिटेन, बेल्जियम** और **इटली** शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदार देश हैं जिनके साथ **भारत का व्यापार अधिशेष (ट्रेड सरप्लस)** है।	**भारत के व्यापार घाटे के कारण: आयातित इनपुट पर अधिक निर्भरता, उपभोग पैटर्न में बदलाव, घरेलू नीतियां** जैसे कि इनवर्टेड ड्यूटी व्यवस्था, आदि

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

नई विदेश व्यापार नीति 2023 और स्वचालित 'स्टेटस होल्डर' प्रमाण-पत्र।	निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना	RoDTEP (निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट) योजना	**अन्य:** निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना, निर्यात तैयारी सूचकांक आदि।

भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आगे की राह

मेड इन इंडिया उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना: ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देना, अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना।	**क्षमतावान क्षेत्रकों को मजबूत करना:** भारत के निर्यात बास्केट का विविधीकरण, आदि।	**मुक्त व्यापार समझौता (FTAs) के संबंध में सुरजीत भल्ला समिति की मुख्य सिफारिशें:** › तकनीकी विनियमनों पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करना। › FTAs के उपयोग को लेकर एक ऑब्जेक्टिव डेटाबेस विकसित करना। › एंटी-डंपिंग जैसे प्रावधानों का उपयोग करना।

6.2. बड़े व्यापार समझौतों का महत्व (Importance of Large Trade Agreements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग** के **सी.ई.ओ.** ने वैश्विक व्यापार एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिया कि भारत को **क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP)** जैसे **बड़े व्यापार समझौतों में शामिल** होना चाहिए।

बड़े व्यापार समझौतों में भागीदारी का महत्व

- **निर्यात:** व्यापार समूह भारतीय कंपनियों को **बड़े निर्यात बाजारों तक पहुंच** प्रदान कर सकते हैं। इससे भारतीय कंपनियों की विनिर्माण क्षमता का सदुपयोग सुनिश्चित होगा।
- **व्यापार में प्रतिस्पर्धी बने रहना:** भारतीय निर्यात के लिए **आसियान देश** मुख्य प्रतिस्पर्धी हैं। यदि भारत भी **आसियान देशों के बराबर का प्रशुल्क** लगाता है, तो यह निजी निवेश को और आकर्षित कर सकता है। इससे अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए विदेशी कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली **'चीन प्लस वन' रणनीति** का भी लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

- **'चीन प्लस वन' रणनीति** का आशय ऐसी नीति से है, जिसमें कंपनियां चीन में अपनी मौजूदगी बनाए रखते हुए, अपने विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी गतिविधियों को अन्य देशों में फैलाकर विविधता लाती हैं।
- **FDI:** इससे देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वृद्धि होगी, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।
- **आर्थिक संवृद्धि:** एक स्वतंत्र अध्ययन में पाया गया है कि RCEP में शामिल होने पर, **भारतीय अर्थव्यवस्था को 2030 तक 60 बिलियन यू.एस. डॉलर का लाभ हो सकता** है।
- **रणनीतिक उपयोगिता:** RCEP भारत की **एक्ट ईस्ट नीति** के उद्देश्यों के अनुरूप है।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकरण:** बड़े व्यापार समूहों/ समझौतों में शामिल होने से भारत की **आपूर्ति श्रृंखला का विकास और प्रसार** हो सकता है। इसके कारण **वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत का एकीकरण** और भी मजबूत होगा।

चुनौतियां

- **व्यापार असंतुलन:** RCEP में चीन का व्यापारिक प्रभाव अधिक है और इस व्यापार समूह से उसे ही सबसे अधिक लाभ मिलने की संभावना है। इससे चीन के साथ **भारत का विशाल व्यापार घाटा और बढ़** सकता है। गौरतलब है कि **वित्त वर्ष 2023-24 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा** 85 बिलियन यू.एस. डॉलर के आस-पास रहा था।
    - **उदाहरण के लिए, चीन** के साथ **आसियान का व्यापार घाटा** 2020 में 81.7 बिलियन डॉलर था, जो बढ़कर 2023 में 135.6 बिलियन डॉलर हो गया।
- **सीमित लाभ:** भारत का RCEP के 15 में से 13 सदस्यों के साथ पहले से ही **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** मौजूद हैं। केवल **न्यूजीलैंड और चीन के साथ ही भारत का मुक्त व्यापार समझौता नहीं** है।
- **कड़ी प्रतिस्पर्धा: प्रशुल्क दरें कम या शून्य** होने से भारत में **सस्ते आयातों की बाढ़ आने का खतरा** है। इससे घरेलू उद्योगों, विशेषकर उन उद्योगों को नुकसान हो सकता है जो आयातित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। भारत का **डेयरी सेक्टर** एक ऐसा ही उदाहरण है।
- **स्वदेशी उद्यम के लिए चुनौती:** मुक्त व्यापार समझौतों के सख्त प्रावधान **भारत की स्थानीय उद्यमिता और विनिर्माण व्यवस्था** के विकास में बाधा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि इन समझौतों में कई तरह की पाबंदियों को भी शामिल किया जाता है।

आगे की राह

- **मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर पुनर्विचार और फिर से वार्ता शुरू करना:** बड़े व्यापार समझौतों में शामिल होने से पहले **गहन चर्चा और विचार-विमर्श** की आवश्यकता होती है। इन समझौतों से **सभी हितधारकों** को होने वाले लाभ और हानि का विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- **व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार करना: गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम करने** और **व्यापार विविधीकरण को बढ़ावा देने** से वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ भारत के एकीकरण में सुधार करने में सहायता मिलेगी।
- **निरंतर वार्ता:** भारत को **बड़े व्यापार समझौतों में अपने अनुकूल शर्तों** पर वार्ता जारी रखने की आवश्यकता है।
- **दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देना:** बड़े व्यापार समझौतों में प्रवेश करते समय **आत्मनिर्भर भारत, वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने के लक्ष्य** और **रणनीतिक स्वायत्तता** को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

निष्कर्ष

भारत की **आर्थिक विकास यात्रा अनूठी** रही है। वैसे **व्यापार,** आर्थिक विकास का एक प्रमुख पहलू है लेकिन किसी भी वैश्विक व्यापार समझौते में शामिल होने से पहले उसके **बाध्यकारी शर्तों और उनसे भारत को होने वाले शुद्ध लाभों का विश्लेषण** किया जाना चाहिए। चूंकि **वैश्विक ताकतें** भारत को इन बड़े व्यापार समझौतों में शामिल होने के लिए **प्रोत्साहित कर रही हैं,** ऐसे में भारत को तर्कसंगत और व्यावहारिक विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।

6.3. भारत का मुक्त व्यापार समझौता {Free Trade Agreement (FTA) of India}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत-ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता** के उपयोग की दर कुछ उत्पादों के मामले में 90% तक पहुंच गई है। यह दिखाता है कि मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) अब अच्छे परिणाम दे रहे हैं।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA) के बारे में

- FTA दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता होता है जिसके तहत शामिल देशों के बीच व्यापार में मौजूद बाधाओं को कम या समाप्त किया जाता है।

 © Vision IAS

भारत के मुक्त व्यापार समझौते

- भारत ने अलग-अलग देशों के साथ **13 FTAs और 6 अधिमान्य व्यापार समझौतों (PTA)** पर हस्ताक्षर किए हैं।
- जिन देशों/ क्षेत्रीय समूहों के साथ भारत ने FTA जैसे व्यापार समझौते किए हैं, उन देशों/ समूहों को भारतीय निर्यात में **पिछले पांच वर्षों में 20.75% की वृद्धि** दर्ज की गई है।

भारत के FTA से संबंधित हालिया घटनाक्रम:

- **इनोवेटिव डिजाइन:** पहली बार भारत ने **UAE के साथ अपने FTA के दायरे में डिजिटल व्यापार** को शामिल किया है।
- **गैर-प्रशुल्क बाधाओं (NTBs) का समाधान करना:** हाल ही में, हस्ताक्षरित FTAs; जैसे कि भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (INDAUS ECTA) में गैर-प्रशुल्क बाधाओं (NTBs) से भी निपटने का प्रयास किया गया है।
- **सेवा क्षेत्रक पर फोकस:** पिछले मुक्त व्यापार समझौतों में सेवा क्षेत्रक को उतना महत्त्व नहीं दिया गया था।
- **स्वाभाविक व्यापारिक साझेदार:** इन देशों के व्यापार में काफी हद तक एक-दूसरे की जरूरत को पूरा करने वाले उत्पाद ही शामिल हैं।

संबंधित सुर्ख़ियां

- भारत और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) ने वस्तुओं के क्षेत्र में मौजूदा FTA की वर्ष 2025 तक समीक्षा पूरी करने पर सहमति व्यक्त की है।
- वर्ष 2009 में हस्ताक्षरित 'आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA)' की समीक्षा से व्यापार में वृद्धि और विविधता आने का अनुमान है।

भारतीय FTAs का विश्लेषण

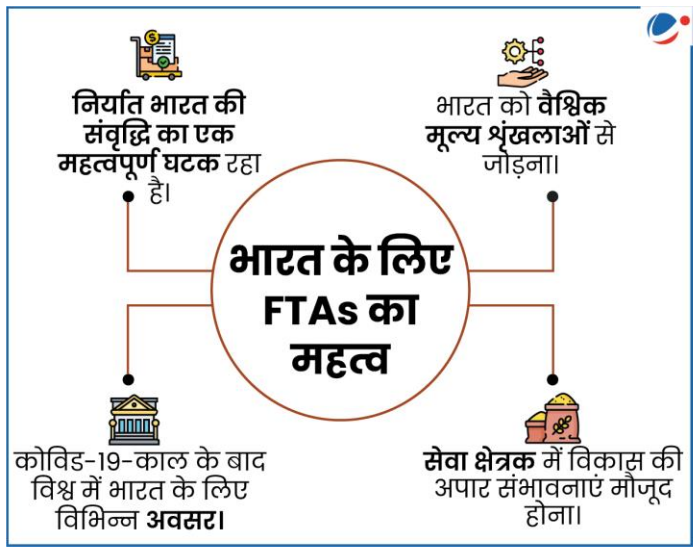

- **निम्न-मूल्य-वर्धित वस्तुएं:** विनिर्मित वस्तुओं के निर्यात में उच्च-प्रौद्योगिकी वाली वस्तुओं का अनुपात पिछले दशक से लगभग 10% के स्तर पर ही बना हुआ है।
- **लागत और गुणवत्ता संबंधी मुद्दे:** उदाहरण के लिए, भारत-जापान FTA संपन्न होने के बाद के वर्षों में गुणवत्ता और लागत जैसी शिकायतों के कारण भारत से जापान में फ्यूल निर्यात में 65% तक की गिरावट दर्ज की गई।
- **गैर-प्रशुल्क बाधाएं (NTBs):** इनकी वजह से **व्यापार में लगभग 2% से 11% की कमी** आती है।
- **क्षेत्रीय देशों के साथ व्यापार समझौते का अभाव:** दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) जैसे समझौते होने के बावजूद भी भारत का क्षेत्रीय समूहों के साथ सीमित स्तर पर व्यापार होता है।
- **स्पेगेटी बाउल प्रभाव:** एक ही देश के साथ कई स्तरों पर FTA होने से नीतियों में भ्रम और टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है।
  - उदाहरण के लिए, **भारत का मलेशिया और सिंगापुर के साथ अलग-अलग FTA है,** जबकि वे **भारत-आसियान CECA के भी सदस्य** हैं।

आगे की राह

- **व्यापार को सुगम बनाने के उपाय:** लॉजिस्टिक की उच्च लागत, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, रूल ऑफ ओरिजिन जैसी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
- **सेवा क्षेत्रक पर समान ध्यान देना:** सेवा क्षेत्रक में व्यापार को बढ़ावा देने वाले प्रावधानों को शामिल करने हेतु मौजूदा FTAs पर फिर से वार्ता शुरू करने की जरूरत है।
- **भविष्य के FTAs को 'आत्मनिर्भर भारत' रणनीति के अनुरूप करना:** वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) के साथ भारत को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए FTA के तहत समय के साथ आयात शुल्क में चरणबद्ध रूप से कमी करनी चाहिए।
- **उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाना:** भारत को मध्यम अवधि में अधिक मांग वाली विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

भारत की विकसित होती FTA रणनीति अब उच्च उपयोग दर तथा डिजिटल व्यापार एवं सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने जैसे सकारात्मक ट्रेंड दर्शा रहे हैं। हालांकि, इन समझौतों का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए गैर-प्रशुल्क बाधाओं और वस्तुओं की गुणवत्ता से जुड़ी चिंताओं को दूर करने और एक-दूसरे की आवश्यकताओं को समझने की आवश्यकता है।

6.4. द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty: BIT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025 में **मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के प्रावधानों में संशोधन** के संबंध में घोषणा की गई थी, ताकि इसे और अधिक **निवेशक-अनुकूल** बनाया जा सके।

द्विपक्षीय निवेश संधियों (BIT) के बारे में

- **परिभाषा:** इन्हें **अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौतों (IIAs)**[20] के नाम से भी जाना जाता है। ये समझौते विदेशी निवेशकों को उन नीतिगत या नियामक उपायों के विरुद्ध सुरक्षा का आश्वासन देते हैं, जो उनके निवेश को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- **उद्देश्य:** निवेशकों को यह अधिकार **निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS)**[21] प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है, जबकि **निवेशक के गृह देश** (जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका) को **राज्य-राज्य विवाद निपटान**[22] के माध्यम से यह अधिकार प्रदान किया जाता है।
- भारत ने **2015 में नए मॉडल BIT को मंजूरी दी थी,** जिसने **भारतीय मॉडल BIT, 1993** का स्थान लिया है।
  - नए मॉडल BIT का उपयोग न केवल नए BITs के लिए, बल्कि व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों (CECA), व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौतों (CEPA) और मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के निवेश संबंधी प्रावधानों पर वार्ता या पुनः वार्ता के आधार के रूप में किया जा रहा है।
  - हाल ही में, **उज्बेकिस्तान (2024 में) और संयुक्त अरब अमीरात (2024 में)** के साथ BITs पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

मॉडल BIT 2015 की प्रमुख विशेषताएं

- **निवेश की "उद्यम" आधारित परिभाषा:** इसका तात्पर्य एक ऐसे उद्यम से है, जिसे देश के घरेलू कानूनों के अनुसार एक निवेशक द्वारा पूर्ण विश्वास के साथ गठित, संगठित और संचालित किया जाता है।
- **उचित प्रक्रिया के माध्यम से गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार:** इसके तहत प्रत्येक पक्ष (संधिकर्ता देश) द्वारा निवेश और निवेशकों को पूर्ण संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- **एक्सप्रोप्रिएशन (स्वत्वाधिहरण) के खिलाफ सुरक्षा**[23] **:** कोई भी पक्ष किसी निवेशक के निवेश का प्रत्यक्ष रूप से या उस निवेश के स्वामित्व पर अधिकार कर निवेश का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकता।
- **कुछ गतिविधियों को इसके दायरे से बाहर रखा जाना:** जैसे- सरकारी खरीद, कराधान, सब्सिडी, अनिवार्य लाइसेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा।
- **निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) की व्यवस्था:** एक विदेशी निवेशक को ISDS तंत्र अपनाने से पहले कम-से-कम पांच वर्ष की अवधि के लिए उस देश के स्थानीय विवाद निपटान तंत्रों का उपयोग करना चाहिए।

भारत के वर्तमान BIT ढांचे से जुड़ी समस्याएं

- **अस्पष्टता:** इसमें "निवेश", "प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून (CIL)[24]" आदि शब्दावली में स्पष्टता का अभाव है। विदेश मामलों की समिति (2021-22) के अनुसार, भारत को विवाद से संबंधित **37 नोटिस** प्राप्त हुए हैं। इनमें से **8 अभी भी अलग-अलग मध्यस्थता चरणों** में हैं।
- **न्यायिक विलंब:** स्थानीय उपाय संबंधी 5-वर्ष का नियम लंबित मामलों की स्थिति को और गंभीर बनाता है।
- **ISDS अधिकरणों के अधिकार क्षेत्र पर प्रतिबंध:** उन्हें घरेलू न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के "मेरिट" की समीक्षा करने से रोक दिया गया है, बिना यह परिभाषित किए कि "मेरिट" का क्या अर्थ है।
- **मॉडल BIT में निम्नलिखित मुद्दों के कारण विदेशी निवेशकों को सीमित अधिकार प्राप्त हैं:**
  - **"निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार" मानकों को छोड़** दिया गया है। इसके अलावा, **मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) और "वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation)"** के सिद्धांत भी अनुपस्थित हैं।

---

[20] International Investment Agreements

[21] Investor-State Dispute Settlement

[22] State-to-State Dispute Settlement

[23] Protections against expropriation

[24] Customary International Law

© Vision IAS

- **कर-संबंधी विनियामक उपायों को शामिल न करने से** निवेशकों का विश्वास कम हो जाता है।
- ISDS अधिकरण केवल यही फैसला दे सकते हैं कि अगर किसी विदेशी निवेशक को नुकसान हुआ है, तो उसे पैसे के रूप में **मुआवजा** दिया जाए।

- **ICSID सम्मेलन में शामिल न होना:** भारत **निवेश संबंधी विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)** का सदस्य **नहीं** है। इस वजह से, जो निवेशक ICSID के माध्यम से भारत में अपने फैसले लागू करवाना चाहते हैं, उनके पास सीमित विकल्प ही बचते हैं।

निष्कर्ष

भारत के मॉडल BIT में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य मौजूदा निवेशकों की चिंताओं को दूर करना है। एक अधिक संतुलित और निवेशक-अनुकूल ढाँचा विदेशी निवेश को प्रोत्साहित कर सकता है, साथ ही भारत की नियामक स्वायत्तता की भी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।

6.5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment: FDI)

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)

भारत में FDI की स्थिति

2000 से 2024 तक: सितंबर 2024 में भारत में कुल FDI **1 ट्रिलियन डॉलर** को पार कर गया।	**वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में महाराष्ट्र को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ,** उसके बाद **कर्नाटक और दिल्ली** का स्थान रहा।	वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में सबसे अधिक FDI सिंगापुर से हुआ, उसके बाद मॉरीशस और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान रहा।	वित्त वर्ष 2023-24 में **कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्रक को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ,** इसके बाद **सेवा क्षेत्रक** का स्थान रहा।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) से संबंधित चुनौतियां

जटिल विनियमन और नीतिगत अनिश्चितता: उदाहरण के लिए- वोडाफोन पर **प्रत्यक्ष कर को पूर्वव्यापी प्रभाव (Retrospective) से लागू करने के कारण** कानूनी विवाद उत्पन्न हुआ था।	**संस्थागत कमियां:** उदाहरण के लिए- फ्लिपकार्ट विवाद के कारण भारत को अमेरिका के जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंसेज (GSP) के तहत मिलने वाले वरीयता लाभ से वंचित होना पड़ा।	**कुछ राज्यों और क्षेत्रकों को अधिक FDI प्राप्त होना:** भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मुख्य रूप से कुछ ही क्षेत्रकों (जैसे- सेवा) और कुछ चुनिंदा राज्यों (जैसे- महाराष्ट्र, कर्नाटक) के शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा है।	**अन्य:** स्थानीय व्यवसायों पर प्रभाव और श्रम बाजार पर प्रभाव आदि

भारत में FDI को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

योजनाएं: मेक इन इंडिया (MII), स्टार्ट-अप इंडिया, उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना, आदि	**व्यवसाय करने की सुगमता (EoDB) को बढ़ावा देना:** उदाहरण के लिए- **जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023**	**राज्य निवेश शिखर सम्मेलन:** उदाहरण के लिए- वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन से गुजरात को 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2002-22) की FDI आकर्षित करने में मदद मिली है।	**तकनीकी उपाय:** नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) और विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल, आदि	**परियोजना विकास प्रकोष्ठ (PDCs):** निवेश को तेजी से मंजूरी देने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/ विभागों में एक संस्थागत तंत्र के रूप में स्थापित किया गया है।

आगे की राह

प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना: मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, मजबूत बुनियादी ढांचे और कार्यबल को कौशल प्रदान करने को बढ़ावा देना चाहिए	**नीतिगत सुधार: बाबा कल्याणी समिति** की सिफारिशों के अनुसार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक के विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के लिए अलग-अलग नियम और प्रक्रियाएं बनानी चाहिए, ताकि विनिर्माण क्षेत्रक में भी FDI को आकर्षित करने पर पर्याप्त जोर दिया जा सके।	**विवाद समाधान और अनुबंध को लागू करना:** पर्याप्त संख्या में माध्यस्थम (आर्बिट्रेशन) और वाणिज्यिक अदालतों की स्थापना करके विवाद समाधान को बढ़ावा देना चाहिए।	**द्विपक्षीय निवेश संधियां (BITs):** द्विपक्षीय निवेश संधियों को मजबूत और अपडेट करने से विदेशी निवेश के लिए नियम और शर्तें स्थापित हो सकती हैं तथा निवेशकों का विश्वास बढ़ सकता है।	**अन्य:** अनुबंधों को प्रभावी तरीके से लागू करने से विदेशी निवेशक, कानून या नियमों के बारे में आश्वस्त रहेंगे। छोटे शहरों में FDI को प्रोत्साहित करना चाहिए, आदि

Mains 365 - अर्थव्यवस्था

6.5.1. FPI का FDI के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए फ्रेमवर्क (Framework for Reclassification of FPI to FDI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RBI ने FPI को FDI में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- वर्तमान विनियमों के अनुसार, **विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs) किसी भारतीय कंपनी में उसकी कुल पेड-अप इक्विटी पूंजी का अधिकतम 10% तक ही पोर्टफोलियो निवेश के रूप में निवेश** कर सकते हैं।
    - वह राशि जो कंपनी को शेयरधारकों से शेयरों के बदले में प्राप्त होती है उसे **पेड-अप इक्विटी पूंजी कहते हैं।**
- इससे पहले FPIs के लिए निर्धारित इस **10% की सीमा को पार करने पर** FPIs के पास **दो विकल्प होते थे-** अधिशेष **शेयरों को बेचना** या **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रूप में रीक्लासिफ़ाइ** हो जाना।
- यदि कोई **FPI अपने संस्थागत विदेशी निवेश को FDI में रीक्लासिफ़ाइ करने का इरादा रखता है**, तो उस FPI को नीचे दिए गए ऑपरेशनल फ्रेमवर्क का पालन करना होगा:

FPI को FDI के रूप में रीक्लासिफ़ाइ करने के संबंध में RBI का नया ऑपरेशनल फ्रेमवर्क

- **FDI के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रकों में इस** रीक्लासिफिकेशन की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसे- चिट फंड, गैंबलिंग आदि।
- **विशेष रूप से सीमावर्ती देशों** से FPI निवेश के लिए **सरकारी अनुमोदन अनिवार्य है,** तथा **संबंधित भारतीय कंपनी की सहमति भी आवश्यक है।**
- साथ ही, निवेश को FDI के नियमों के तहत **प्रवेश मार्ग, सेक्टोरल कैप्स, निवेश सीमा, मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश और अन्य संबंधित शर्तों** का पालन करना चाहिए।
- FPI का रीक्लासिफिकेशन **"विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान की विधि और गैर-ऋण लिखतों की रिपोर्टिंग) विनियमन, 2019"** द्वारा निर्देशित होगा।

निष्कर्ष

FPI को FDI में रीक्लासिफ़ाइ करने के लिए RBI द्वारा तैयार किया गया फ्रेमवर्क विनियामकीय स्पष्टता और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाता है, क्योंकि यह निष्क्रिय निवेश से रणनीतिक निवेश की ओर स्थानांतरण के लिए एक सुनियोजित मार्ग प्रदान करता है। यह पहल विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहित करने, दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि को समर्थन देने और भारत के विकसित होते निवेश इकोसिस्टम के साथ तालमेल स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

6.6. वैश्विक मूल्य श्रृंखला: एक नज़र में (Global Value Chain at a Glance)

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं (GVCs)

वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) में वास्तव में उपभोक्ता के लिए उत्पाद को अंतिम रूप से तैयार करने वाला प्रत्येक चरण शामिल होता है और प्रत्येक चरण (जैसे- उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, परिवहन, वितरण आदि) **कुछ मूल्य जोड़ता है।** इसमें, कम-से-कम **दो चरण अलग-अलग देशों में संपन्न होने आवश्यक** हैं।

GVCs में भाग लेने से संबंधित प्रमुख लाभ

उत्पादकता में वृद्धि: प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि सामान्य व्यापार की तुलना में लगभग दोगुनी है।	**गरीबी के स्तर में कमी:** रोजगार के अवसरों में वृद्धि और कंपनी के उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण।	**विशेषज्ञता के लिए अधिक संभावना:** कोई देश किसी विशेष मूल्य श्रृंखला चरण के लिए लक्षित उद्योग स्थापित कर सकता है।	**ज्ञान को साझा करने में सुविधा:** इससे औद्योगिक उन्नयन, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार आदि संभव है।	**स्थानीय कंपनियों को मजबूत बनाना:** इकोनॉमी ऑफ स्केल को प्राप्त करके, जानकारी और प्रौद्योगिकी को साझा करके, आदि।

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में भारत के शामिल होने के समक्ष बाधाएं

इस संबंध में बड़ी कम्पनियों की सीमित संख्या: कच्चे माल की कमी, वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुंच, जटिल कस्टम प्रक्रियाओं आदि के कारण।	**MSMEs का लाभ न उठा पाना:** नवाचार की कमी, बड़ी कम्पनियों के साथ जुड़ाव न होना आदि के कारण।	**क्षेत्रीय एकीकरण की कमी:** SAARC जैसी क्षेत्रीय संगठन निष्क्रिय हो चुके हैं और भारत ने हाल ही में क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) से भी अलग हो गया है।	**तकनीकी बदलाव:** भारत में कार्यबल रीस्किलिंग और अप-स्किलिंग की गति धीमी है।

भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने के लिए उठाए गए कदम

उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना: भारत को ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स जैसे 14 प्रमुख क्षेत्रकों में विनिर्माण का केंद्र बनाना।	**श्रम सुधार:** वेतन, संहिता; व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता; , औद्योगिक संबंध संहिता और सामाजिक सुरक्षा संहिता बनाई गई है।	**अवसंरचना संबंधी विकास:** भारतमाला, सागरमाला, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन कार्यक्रम, पीएम गति शक्ति, आदि।	**प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** भारत में अर्थव्यवस्था के अधिकतर क्षेत्रकों में 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है।	**विदेश व्यापार नीति 2023:** इसका उद्देश्य निर्यातकों के लिए व्यापार करना आसान बनाने के लिए **प्रक्रिया को उदार और स्वचालित बनाना** है।

भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में एकीकृत करने के उपाय

कौशल विकास: उच्च-प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रकों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर आदि के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना।	**क्षेत्रक का विविधीकरण:** रक्षा, एयरोस्पेस जैसे क्षेत्रक GVC में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ावा दे सकते हैं।	**MSMEs को सहायता: निरंतर** ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना, वित्तपोषण प्राप्त करना सुनिश्चित करना और डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करना और सुगम बनाना, आदि।	**अवसंरचना को अपग्रेड करना:** ICT , ब्रॉडबैंड और 5G कनेक्टिविटी को बढ़ाना, 'राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति' का प्रभावी कार्यान्वियन, आदि।	**अन्य:** व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाना, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) से मजबूत संपर्क को सुनिश्चित करना, इत्यादि।

6.7. संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि (UN Global Tax Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र की तदर्थ समिति को "अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन" के लिए विचारार्थ विषय का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। हाल ही में, इस समिति ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर कन्वेंशन हेतु मार्गदर्शन के एक सेट को मंजूरी दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य वैध, निष्पक्ष, स्थिर, समावेशी और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली के लिए **संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर संधि** स्थापित करना है।
- **भारत सहित अधिकतर विकासशील देशों** ने संधि के विचारार्थ विषय के **पक्ष** में मतदान किया। इसके विपरीत **ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका** जैसे औद्योगिक देशों ने इसके **खिलाफ** मतदान किया।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कर कन्वेंशन के उद्देश्य

- **अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग को मजबूत करना** और इसे समावेशी एवं प्रभावी बनाना;
- बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) के डिटिजल व्यवसाय और उनके वैश्विक व्यवसाय पर **कर लगाने संबंधी मौजूदा चुनौतियों का समाधान** करना;
- संधारणीय विकास के लिए **घरेलू संसाधन जुटाना** और **कर नीति का उपयोग** करना;
- **'विकास के लिए वित्त-पोषण पर अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा'** और **'सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के लिए 2030 एजेंडा'** के कार्यान्वयन में तेजी लाना आदि।

वैश्विक स्तर पर कर संबंधी दुरुपयोग (स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस, 2024 रिपोर्ट)

- वैश्विक स्तर पर कर संबंधी दुरुपयोग के कारण देशों को **प्रति वर्ष 492 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान** हो रहा है। इससे ग्लोबल साउथ के देशों को अपने कुल कर राजस्व के सबसे बड़े हिस्से का नुकसान हो रहा है।
- इसमें से **दो-तिहाई का नुकसान बहुराष्ट्रीय कंपनियों** द्वारा किया जाता है। ये कंपनियां अपने लाभ को ऐसे देशों में स्थानांतरित करती हैं, जहां कर दरें बहुत कम होती हैं, ताकि कम कर का भुगतान करना पड़े। **शेष एक-तिहाई** का नुकसान उन धनी व्यक्तियों के कारण होता है, जो अपनी संपत्ति को विदेशों में छुपाते हैं।
- **43% नुकसान आठ प्रमुख OECD सदस्य देशों** के कारण होता है, जो **यूनाइटेड नेशन टैक्स कन्वेंशन** का विरोध कर रहे हैं।

वैश्विक कर सुधार

- **आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) की वैश्विक न्यूनतम कर (GMT) नीतिः** इसमें कॉर्पोरेट मुनाफे पर 15% की न्यूनतम प्रभावी दर से कर लगाने का प्रावधान किया गया है।
- **OECD की 'बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग (BEPS)' कार्य योजना:** यह कर की चोरी से निपटने के लिए सरकारों को साधन उपलब्ध कराती है।
- **OECD का कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड (CRS):** यह वित्तीय खातों के बारे में सूचना के स्वतः आदान-प्रदान की सुविधा देता है।

निष्कर्ष

यूनाइटेड नेशन टैक्स कन्वेंशन और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कर सहयोग फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर वार्ता (2025–2027) कर चोरी रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली को अधिक न्यायसंगत बनाने का अवसर प्रदान करती है। साथ ही, अतिरिक्त लाभ और संपत्ति पर कर लगाने से आर्थिक असमानता कम तथा एकाधिकार की शक्ति सीमित हो सकती है। इससे समाज से सबसे अधिक लाभ कमाने वाले लोगों द्वारा सामाजिक कल्याण में आनुपातिक रूप से योगदान सुनिश्चित हो सकता है।

6.8. दोहरा कराधान परिहार समझौता (Double Taxation Avoidance Agreement: DTAA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

स्विट्ज़रलैंड ने भारत के साथ अपने **दोहरे कराधान परिहार समझौते (DTAA)** में **मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) क्लॉज** को निलंबित कर दिया है।

DTAA के बारे में

- **परिचय:** यह **दो या अधिक देशों** के बीच एक ऐसी संधि होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि करदाता (व्यक्तियों या व्यवसायों) को एक ही आय पर दोनों देशों में कर का भुगतान न करना पड़े।
- भारत ने 90 से अधिक देशों के साथ DTAA पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें विश्व की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं, जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, मॉरीशस, आदि।
- भारत और स्विटजरलैंड **मूल रूप से 1994** में DTAA में शामिल हुए थे और बाद में **2010** में इसमें **संशोधन** किया गया।
- DTAA (और इसके तहत MFN क्लॉज) प्रावधान यह सुनिश्चित नहीं करता कि भारत द्वारा किसी अन्य देश को दी गई बेहतर कर दरों वाली रियायतें स्वतः ही सभी समझौता साझेदारों को भी मिलें।

दोहरे कराधान परिहार समझौते (DTAA) में MFN क्लॉज

- **परिभाषा:** DTAA के अंतर्गत MFN क्लॉज कर संधि से जुड़ा एक प्रावधान है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई देश दूसरे देश को भी वही या उससे बेहतर कर लाभ प्रदान करे जो वह अपने किसी अन्य "सबसे पसंदीदा (Most favored)" संधि साझेदार को प्रदान करता है।
- यदि भारत **किसी तीसरे देश (जैसे फ्रांस)** को **लाभांश या अन्य आय** पर **कम कर दर (Tax rate) की पेशकश** करता है, तो **स्विट्ज़रलैंड** भी अपने करदाताओं के लिए **समान अनुकूल दर** का दावा कर सकता है।
- **MFN सिद्धांत WTO फ्रेमवर्क में भी शामिल है।**

वैश्विक कर प्रशासन में DTAA का महत्व				
कानूनी निश्चितता: DTAAs करदाताओं को उनके कर दायित्वों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं।	**DTAA के तहत 'पारस्परिक समझौता प्रक्रिया (MAP)[25]:** जैसे- भारत और जापान के बीच **ट्रांसफर प्राइसिंग विवादों को सुलझाने के लिए** इसका इस्तेमाल किया जाता है।	**राजस्व की चोरी पर लगाम:** ये समझौते सीमा पार आय के लिए निश्चित कर अनुपालन उपाय निर्धारित करके कर चोरी पर अंकुश लगाने में मदद करते हैं।	**कुछ DTAA में एंटी-एब्यूज धाराएं शामिल की गई हैं,** जैसे कि भारत-मॉरीशस DTAA को ट्रीटी शॉपिंग और धन की राउंड-ट्रिपिंग को रोकने के लिए संशोधित किया गया है।	**कर बचत:** DTAA का लाभ उठाकर व्यक्ति और व्यवसाय देशों के बीच कम कर दरों का लाभ उठा सकते हैं, जिससे कर बचत होगी।

DTAA की संरचना से जुड़ी हुई चुनौतियां

- **ट्रीटी शॉपिंग एवं इसका दुरुपयोग:** उदाहरण के लिए- मॉरीशस का इस्तेमाल विदेशी निवेशकों द्वारा भारत-मॉरीशस DTAA के तहत पूंजीगत लाभ कर छूट का दावा करने के लिए भारत में फंड भेजने के लिए किया जाता था।
- **DTAA की व्याख्या एवं इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन से जुड़े हुए मुद्दे:** देशों के बीच DTAA प्रावधानों की व्याख्या में मतभेद विवादों और दोहरे कराधान को जन्म देते हैं।
  - विवादों के समाधान में देरी और अकुशलता करदाताओं के लिए अनिश्चितता पैदा करती है।
- **घरेलू कानूनों के साथ सामंजस्य का अभाव:** उदाहरण- हाल ही में चर्चा में रहा 2023 का भारत-स्विट्ज़रलैंड नेस्ले मुद्दा।
- **विवाद समाधान तंत्र की अक्षमता:** पारस्परिक समझौता प्रक्रिया (MAP) के तहत विवादों को सुलझाने में देरी और दक्षता की कमी वास्तव में करदाताओं के लिए अनिश्चितता पैदा करती है।
  - **MAP करदाताओं के लिए कर विवादों के समाधान के लिए उपलब्ध एक विकल्प है,** जो न्यायिक या आर्थिक प्रकृति के दोहरे कराधान को जन्म देता है।

[25] Mutual Agreement Procedures

निष्कर्ष

स्विट्जरलैंड द्वारा भारत-स्विट्जरलैंड DTAA के MFN क्लॉज़ को निलंबित करना उभरते वैश्विक कर मानदंडों को और बेहतर बनाने की जरूरत को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही, यह संधि की स्पष्ट व्याख्या, घरेलू कानूनों का पालन और अंतर्राष्ट्रीय कर मानकों के अनुरूप समायोजन की आवश्यकता पर भी जोर देता है।

6.9. भारत में विप्रेषण: एक नज़र में (Remittances to India at a Glance)

भारत में विप्रेषण

भारत में विप्रेषण या रेमिटेंस प्राप्ति के मुख्य ट्रेंड

2024 में वैश्विक विप्रेषण का 14.3% ($129 बिलियन) आया , जो अब तक का सर्वाधिक है (विश्व बैंक)।	शीर्ष 3 स्रोत देश (2023-24): अमेरिका (27.7%) >UAE>UK	भारत के रेमिटेंस में खाड़ी देशों की हिस्सेदारी कम होकर 38% रह गई है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 50% से अधिक हो गई है।	**रेमिटेंस प्राप्तकर्ता शीर्ष 3 राज्य (2023-24): महाराष्ट्र (20.5%)>केरल>तमिलनाडु।**

रेमिटेंस प्राप्ति के ट्रेंड में बदलाव की वजहें

रेमिटेंस भेजने में कम लागत: डिजिटलीकरण के कारण भारत में रेमिटेंस भेजने की लागत वैश्विक औसत से कम हो गई है।	**अमेरिका और यूरोप में नौकरियों में वृद्धि, वेतन वृद्धि और प्रोत्साहन से प्रवासियों की आय में वृद्धि हुई है।**	खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में ऑटोमेशन और विविधीकरण के कारण कम कुशल श्रमिकों के लिए नौकरी की संभावनाएं घट रही हैं।	कनाडा, यू.के. और ऑस्ट्रेलिया भारतीय विद्यार्थियों के लिए शीर्ष अध्ययन केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं; भारत-यू.के. माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप (2021) जैसे समझौतों से सहायता मिली है। उदाहरण के लिए, 2020 और 2023 के बीच यू.के. में भारतीय प्रवासियों की संख्या तीन गुनी हो गई।

अर्थव्यवस्था के लिए रेमिटेंस का महत्व

भुगतान संतुलन (BoP): निवल रेमिटेंस से व्यापार घाटे का लगभग 50% वित्त-पोषित होता है, तथा बाहरी आर्थिक संकटों से निपटने में अहम भूमिका निभाता है।	**घरेलू स्तर पर:** रेमिटेंस के रूप में प्राप्त राशि से भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है, तथा जीवन स्तर में सुधार होता है। **उदाहरण के लिए, 2021 में, केरल के राज्य घरेलू उत्पाद में रेमिटेंस का योगदान 36% से अधिक था।**	**मैक्रो-इकोनॉमिक भूमिका:** वर्ष 2000 से भारत के सकल घरेलू उत्पाद में रेमिटेंस की हिस्सेदारी 3-3.5% के बीच रही है।	**ऋण भुगतान की क्षमता बढ़ती है:** रेमिटेंस से देश का जोखिम और उधार लेने की लागत कम होती है, जिससे राजकोषीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।

6.10. रुपये का मूल्यह्रास (Rupee Depreciation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रुपये की विनिमय दर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले **85 के स्तर को पार कर गई।** इसका मतलब है कि एक डॉलर के लिए 85 रुपये का भुगतान करना पड़ रहा है। पिछले दो वर्षों में रुपये का **सबसे तेजी से मूल्यह्रास** हुआ है।

रुपये का मूल्यह्रास क्या है?

- यह **अमेरिकी डॉलर (USD) या अन्य प्रमुख वैश्विक मुद्राओं** के सापेक्ष **भारतीय रुपये (INR) के मूल्य में होने वाली गिरावट** है।

रुपये के मूल्यह्रास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक

- **मुद्रास्फीति:** अपने व्यापारिक साझेदारों की तुलना में भारत में **उच्च मुद्रास्फीति दर भारतीय रुपये की क्रय शक्ति** को कमजोर कर देती है और विनिमय दर को प्रभावित करती है।
- **पूंजी का बहिर्गमन (Capital Outflows): विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार से पूंजी निकालने से** विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है, जिससे रुपये का मूल्यह्रास होता है।
- **व्यापार घाटा:** जब **आयात मूल्य, निर्यात से अधिक हो जाता है**, तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, जिससे रुपया कमजोर होता है।
- **उच्च मूल्य के आयातित वस्तुओं के लिए भारत में मांग:** भारत की **पेट्रोलियम उत्पादों और सोने के आयात पर अत्यधिक निर्भता** डॉलर की मांग को बढ़ाता है।

 © Vision IAS

- **इलिक्विडिटी या अतरलता:** यह अल्पावधि विदेशी मुद्रा ऋण के विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से अधिक हो जाने के कारण उत्पन्न होती है।
- **वैश्विक आर्थिक कारक: कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में वृद्धि, या वैश्विक आर्थिक मंदी** जैसे कारक भी रुपये के मूल्यह्रास में योगदान देते हैं।

रुपये के मूल्यह्रास का प्रभाव

सकारात्मक	नकारात्मक
• **निर्यात को बढ़ावा:** डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत कम होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय वस्तुएं और सेवाएं सस्ती हो जाती हैं। • **उच्च विप्रेषण (रेमिटेंस) धनराशि मिलना:** अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा भेजे गए डॉलर के बदले देश में अधिक भारतीय रुपया प्राप्त होता है, जिससे उनके परिवारों को अधिक फायदा होता है। • **पूंजी और निवेश पर प्रभाव:** रुपये के मूल्यह्रास के कारण निर्यात में वृद्धि होती है जिससे देश में **घरेलू निवेश को बढ़ावा मिल सकता है।**	• **उच्च आयात लागत:** रुपये का मूल्यह्रास आयात को और अधिक महंगा बना देता है, खासकर कच्चे तेल के मामले में। इससे व्यापार घाटा और भी बढ़ जाता है। • **उच्च मुद्रास्फीति:** जो उद्योग आयात पर निर्भर होते हैं, उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है। • **पूंजी और निवेश पर प्रभाव:** रुपये का मूल्यह्रास भारत से पूंजी की निकासी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में गिरावट का कारण बन सकता है। • **अन्य:** विदेशी कर्ज का भुगतान महंगा हो जाता है, उपभोक्ताओं की **क्रय शक्ति घट जाती है**, जिससे **उपभोक्ता व्यय प्रभावित होती है।**

रुपये को स्थिर बनाने के लिए आगे की राह

- **अल्पकालिक उपाय:**
  - RBI बाजार में डॉलर बेच सकता है।
  - भारत अन्य देशों के साथ करेंसी स्वैप समझौते कर सकता है।
  - विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए मौद्रिक नीति में बदलाव किए जा सकते हैं।
  - गैर-जरूरी आयात को प्रतिबंधित करने के लिए आयात नीति में बदलाव किए जा सकते हैं, आदि।
- **दीर्घकालिक उपाय:**
  - **व्यापार के भुगतान में विविधता लाना:** आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, रुपये के अधिमूल्यन या मूल्य-वृद्धि के लिए विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करनी होगी और व्यापार भुगतान के अन्य विकल्पों को अपनाना चाहिए (उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपये का उपयोग करना)।
  - **निर्यात को प्रोत्साहन:** भुगतान संतुलन पर रंगराजन समिति (1993) की रिपोर्ट के अनुसार, निर्यात को प्रोत्साहन देने से **चालू खाता घाटा** कम हो सकता है और रुपये के मूल्य में स्थिरता सुनिश्चित होगी।
  - **अन्य उपाय:** राजकोषीय विवेकशीलता (Fiscal Prudence) अपनाना, मुद्रास्फीति को कम करना, पेट्रोलियम-प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता को कम करना, आदि।

निष्कर्ष

घरेलू और वैश्विक दोनों कारकों से प्रेरित रुपये का मूल्यह्रास भारतीय अर्थव्यवस्था पर मिश्रित प्रभाव डालता है - जहाँ यह निर्यात को लाभ पहुँचाता है, वहीं आयात लागत और महँगाई में वृद्धि करता है। इस स्थिति से निपटने के लिए अल्पकालिक मुद्रा प्रबंधन और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों, जैसे कि निर्यात प्रोत्साहन, व्यापार विविधीकरण और समष्टि आर्थिक स्थिरता का संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है, जिससे आर्थिक लचीलापन बढ़े और निवेशकों का विश्वास बना रहे।

ऑप्शनल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज़
✓ भूगोल ✓ समाजशास्त्र ✓ दर्शनशास्त्र ✓ हिंदी साहित्य
✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध
2025 ENGLISH MEDIUM 13 JULY हिन्दी माध्यम 13 जुलाई
2026 ENGLISH MEDIUM 13 JULY हिन्दी माध्यम 13 जुलाई

6.11. रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण: एक नज़र में (Internationalization of Rupee at a Glance)

रूपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है जिसे जारी करने वाले देश के अलावा विदेशों में भी लेन-देन हेतु और विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में आरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। केवल जारी करने वाले देश के नागरिक ही नहीं बल्कि अन्य देशों के नागरिक भी ऐसी मुद्रा का उपयोग लेन-देन के लिए करते हैं।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लाभ

संकटों में कमी: विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम करने से, अर्थव्यवस्था में विनिमय दर में आकस्मिक उतार-चढ़ाव, मुद्रा संकट और मुद्रास्फीति दबाव से बचा जा सकता है।	**विनिमय दर से जुड़े जोखिमों में कमी:** इससे व्यवसाय करने की लागत कम हो जाती है और व्यवसाय का बेहतर विकास संभव हो जाता है।	**घाटे का वित्त-पोषण:** वैश्विक स्तर पर भारतीय रुपये के उपयोग से सरकार को अपनी मुद्रा में ऋण जुटाने में मदद मिलती है, जिससे विदेशी मुद्रा पर निर्भरता से जुड़े जोखिम कम हो जाते हैं।	**अन्य:** विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता कम हो जाना, भारत के वित्तीय बाजारों को मजबूती मिलना आदि।

रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में चुनौतियां

मौद्रिक नीति दुविधा या ट्रिफिन डाइलेमा: स्थानीय मौद्रिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए विश्व में अपनी मुद्रा की आपूर्ति को बनाए रखना ताकि मांग को पूरा किया जा सके (जैसे अमेरिका द्वारा डॉलर की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना)	**रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता:** INR चालू खाता में पूरी तरह परिवर्तनीय है, लेकिन पूंजी खाता में आंशिक रूप से परिवर्तनीय है, जिससे इसकी वैश्विक स्वीकार्यता सीमित हो जाती है।	**बाहरी खतरे का जोखिम:** देश से बाहर फंड की स्वतंत्र आवाजाही से वित्तीय प्रणाली में अस्थिरता बढ़ सकती है।	**अन्य:** विश्व में रुपये का कम उपयोग होना, विनिमय दर अस्थिरता में वृद्धि की आशंका, आदि।

शुरू की गयी पहलें

UPI का अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए प्रयास	स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार लेनदेन के लिए संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं	2024-25 के लिए RBI की रणनीतिक कार्य-योजना का उद्देश्य भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना है	**स्पेशल रूपी वोस्ट्रो अकाउंट (SVRA)** की अनुमति देना	**अन्य:** द्विपक्षीय करेंसी स्वैप समझौते, श्रीलंका में विदेशी मुद्रा के रूप में INR को मान्यता, रुपये-मूल्य वाले बॉण्ड यानी मसाला बॉण्ड जारी किए गए है।

आगे की राह

कंटिन्यूस लिंक्ड सेटलमेंट (CLS) में INR को शामिल करना: CLS विदेशी मुद्रा में लेन-देन के सेटलमेंट के लिए वैश्विक प्रणाली है।	**करेंसी स्वैप और लोकल करेंसी सेटलमेंट:** यह स्थानीय मुद्रा को स्थिर करता है, व्यवसायों को मुद्रा जोखिम से बचाता है और लेन-देन की लागत को कम करता है।	**वित्तीय बाजारों को मजबूत बनाना:** RBI-SEBI KYC मानदंडों में सामंजस्य स्थापित करना, 24x5 वैश्विक INR बाजार को सक्षम बनाना तथा भारतीय बॉण्ड्स को वैश्विक सूचकांकों में शामिल करना, आदि।	**अन्य:** SDR बास्केट में भारतीय रुपये को शामिल करने के प्रयास, भारतीय भुगतान प्रणालियों (NEFT, RTGS, UPI आदि) का अंतर्राष्ट्रीयकरण:

6.12. सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (Sovereign Credit Ratings)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केयरएज **भारत** की ऐसी पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जिसने सॉवरेन रेटिंग सहित वैश्विक स्तर की रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश किया है।

सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (SCR) के बारे में

- **क्रेडिट रेटिंग** किसी संस्था की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उसकी सापेक्ष क्षमता यानी, ऋण जोखिम या उधारकर्ता की सापेक्ष उधार पात्रता पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा जाहिर की गई राय होती है।

- **मापदंड:** आमतौर पर, रेटिंग एजेंसियां किसी संप्रभु राष्ट्र की रेटिंग के लिए विभिन्न मापदंडों का उपयोग करती हैं, जिनमें आर्थिक संवृद्धि दर, मुद्रास्फीति, सरकारी ऋण, GDP के अनुपात में अल्पकालिक बाह्य ऋण, और राजनीतिक स्थिरता शामिल होते हैं।
- **सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (SCR)** दरअसल **किसी देश या संप्रभु संस्था के ऋण और उस पर ब्याज चुकाने के दायित्व को समय पर पूरा** करने का आकलन है। इसमें संबंधित **देश या संस्था की ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छाशक्ति,** दोनों को महत्त्व दिया जाता है।
- SCR **कम लागत पर वैश्विक पूंजी बाजारों से उधार लेने की सुविधा** प्रदान करती है। साथ ही, यह **निवेशकों का विश्वास बढ़ाती है तथा विदेशी निवेश को आकर्षित** करती है।
- वर्तमान में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग पर **S&P, मूडीज और फिच रेटिंग** जैसी एजेंसियों का वर्चस्व है। ये एजेंसियां **संयुक्त राज्य अमेरिका** में स्थित हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित रेटिंग एजेंसियों की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग (SCR) से जुड़ी चिंताएं

- रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग निर्धारण पद्धतियों में **पारदर्शिता का अभाव है।**
- रेटिंग के क्रम में **अर्थव्यवस्था की अधिकतर बुनियादी स्थितियों पर विचार नहीं किया** जाता है।
- **वैश्विक रेटिंग एजेंसियां उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ भेदभाव** करती हैं। भारत **विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** है। साथ ही, इसका कोई **डिफ़ॉल्ट इतिहास भी** नहीं है। इसके बावजूद, इन एजेंसियों ने भारत को कम रेटिंग दी है।

भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CRA) के बारे में

- **सेबी** घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (क्रिसिल, ICRA, केयर, आदि) को विनियमित करता है।
- **क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CRA): सेबी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) विनियम, 1999** में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CRA) को परिभाषित किया गया है।
  - क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CRA) एक ऐसी कॉर्पोरेट संस्था होती है जो उन प्रतिभूतियों की रेटिंग करती है या करने का प्रस्ताव रखती है, जो SEBI द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध होने वाली हैं।

निष्कर्ष

सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग किसी देश की उधारी क्षमता और निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करती है। भारत की CareEdge एजेंसी का वैश्विक रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश घरेलू क्षमताओं को मजबूत करता है, विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता को कम करता है, और वैश्विक वित्तीय मूल्यांकन को अधिक संतुलित बनाने में योगदान देता है।

6.13. भारत और विश्व व्यापार संगठन: एक नज़र में (India and World Trade Organization at a Glance)

भारत और विश्व व्यापार संगठन

विश्व व्यापार संगठन: उद्भव और वैश्विक व्यापार में भूमिका

WTO की उत्पत्ति: GATT का जगह स्थापित हुआ; 1986-94 के उरूग्वे दौर की वार्ता के बाद 1995 में स्थापित, जिसमें GATS, TRIPS, विवाद निपटान समझौता और व्यापार नीति समीक्षा तंत्र को जोड़ा गया।	**दोहा राउंड (2001-वर्तमान):** इसमें 20 क्षेत्रक शामिल हैं (जैसे कृषि, सेवा, पर्यावरण); 2008 में सब्सिडी और पेटेंट युक्त दवाओं के मुद्दे के कारण अवरुद्ध हुआ; समस्या समाधान के प्रयासों में **बाली और नैरोबी पैकेज** शामिल हैं।	**प्रमुख भूमिकाएं:** व्यापार संबंधी नियमों के लिए एकल वैश्विक मंच; भेदभाव के विरुद्ध लघु और कमजोर राष्ट्रों की सुरक्षा; मजबूत आर्थिक एकीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा देना।

विश्व व्यापार संगठन की सफलताएं (भारत के नजरिये से)

एक दशक से भी कम समय में भारत का निर्यात लगभग दोगुना हो गया।	व्यापार उदारीकरण के कारण सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में तेजी से वृद्धि।	श्रम प्रधान क्षेत्रकों के विकास के कारण रोजगार सृजन।	आर्थिक विकास के चलते गरीबी उन्मूलन में सहायक।

WTO को वर्तमान में प्रभावित करने वाले कारक जो इसके भविष्य पर असर डाल सकते हैं

ई-कॉमर्स जैसे **नए क्षेत्र चर्चा के लिए** सामने आ रहे हैं	विकासशील देशों में वृद्धि के रूप में 1995 से वैश्विक आर्थिक वितरण में परिवर्तन हुआ है।	चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच उभरता व्यापार युद्ध।	हाल के वर्षों में WTO अपीलीय निकाय निष्क्रिय हो गया है	द्विपक्षीय/क्षेत्रीय/बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को प्राथमिकता दी जा रही है, जैसे-RCEP.

वर्तमान विश्व में विश्व व्यापार संगठन की प्रासंगिकता

व्यापार बाधाओं, जैसे टैरिफ और कोटा को कम करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को शासित करने वाले नियमों को **स्थापित और प्रशासित** करता है।	विश्व व्यापार संगठन के नियमों में संशोधन करके HIV/एड्स और कोविड-19 महामारी जैसी चुनौतियों से निपटा गया।	यह **चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता** है और सदस्यों को लोक हित के मुद्दों पर सहयोग करने में सहायता करता है।	यह **सभी देशों द्वारा साझा संसाधनों की सुरक्षा** में मदद करता है। उदाहरण के लिए, मात्स्यिकी सब्सिडी पर समझौता।

भारत अपने हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठा सकता है

राष्ट्रीय लक्ष्यों को वैश्विक लक्ष्यों के साथ संस्थागत रूप से जोड़ना: इससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बीच चयन करने के समक्ष मौजूद निरंतर द्वंद्व को हल करने में मदद मिलेगी।	**आत्मनिर्भरता और तुलनात्मक लाभ के बीच संतुलन:** आत्मनिर्भर भारत के साथ-साथ श्रम गहन क्षेत्रकों जैसे तुलनात्मक लाभ वाले क्षेत्रों पर भी अतिरिक्त ध्यान दिया जाना चाहिए।	बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य में बेहतर बदलाव के लिए भू-राजनीतिक पूंजी का निर्माण करना।	ई-कॉमर्स जैसे **उभरते क्षेत्रकों में सक्रिय भूमिका निभाना।**	वैश्विक व्यापार में गैर-भेदभाव और समानता की रक्षा के लिए अलग व्यापार समूह की स्थापना की बजाय WTO में सुधार को प्राथमिकता देना।

6.14. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	मुक्त व्यापार समझौता	क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी	व्यापार घाटा	वैश्विक मूल्य श्रृंखला

© Vision IAS

चीन प्लस वन रणनीति	गैर-टैरिफ बाधाएं	आत्मनिर्भर भारत	सार्वजनिक ऋण	सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग
रुपये का मूल्यह्रास	मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) क्लॉज	दोहरा कराधान परिहार समझौता	आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण	वैश्विक न्यूनतम कर

6.15. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़े व्यापार समझौतों का क्या महत्व है, इस पर चर्चा कीजिए। साथ ही, ऐसे समझौतों से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। लाभों को अधिकतम करने और जोखिमों को कम करने हेतु उपायों का सुझाव दीजिए।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
हालिया संदर्भ दीजिए	भारत के लिए बड़े व्यापार समझौतों का महत्व	मुख्य चुनौतियां	आगे की राह

7. कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां (Agriculture and Allied Activities)

7.1. कृषि क्षेत्रक: एक नज़र में (Agriculture at a Glance)

कृषि क्षेत्रक

मुख्य तथ्य

वित्त वर्ष 24 में चालू मूल्यों पर देश के **सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16% का योगदान** (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)।	**आजीविका:** यह लगभग 46.1% आबादी को रोजगार प्रदान करता है।	वित्त वर्ष 17 से वित्त वर्ष 23 के दौरान 5% औसत वार्षिक संवृद्धि दर (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)।	पिछले दशक में **कृषि आय में सालाना 5.23% की वृद्धि दर्ज की गई है** (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)।

चुनौतियाँ

भूखंडों (कृषि जोत) का आकार छोटा होना: परिचालन योग्य जोतों का औसत आकार 1970-71 में 2.28 हेक्टेयर से घटकर 1980-81 में 1.84 हेक्टेयर, 1995-96 में 1.41 हेक्टेयर तथा 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर रह गया।	**अन्य फसलों की खेती की उपेक्षा:** उदाहरण के लिए-2023-24 में सभी अनाजों के उत्पादन के सकल मूल्य में धान और गेहूं उपज का मूल्य लगभग 85% था (NSO रिपोर्ट)।	**जलवायु संकट का खतरा:** उदाहरण के लिए, 2099 तक वार्षिक तापमान में संभावित 2°C वृद्धि और वार्षिक वर्षा में 7 प्रतिशत की वृद्धि से भारतीय कृषि उत्पादकता में 8-12% की गिरावट हो सकती है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)।	**फसल कटाई के बाद नुकसान:** लगभग 1,52,790 करोड़ रुपये सालाना की हानि (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 2022 अध्ययन)	**अन्य:** जल संकट, अपर्याप्त कृषि अनुसंधान आदि

पहलें

कृषि निवेश कोष	डिजिटल कृषि मिशन	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना	एकीकृत बागवानी विकास मिशन	**अन्य:** मत्स्य पालन एवं जलकृषि अवसंरचना विकास निधि; प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना; राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आदि

आगे की राह (डॉ. अशोक दलवई समिति की सिफारिशें)

कृषि में अधिशेष श्रम को गैर-कृषि कार्यों में लगाना: ताकि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके।	**द्वितीयक कृषि अपनाना:** मुख्य उपज के अलावा कृषि से उत्पन्न प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मूल्य वर्धन गतिविधियों को बढ़ावा देना।	**कृषि क्षेत्रक को पुनः परिभाषित करके अन्य गतिविधियों को इसमें शामिल करना:** रसायन, निर्माण, ऊर्जा, फाइबर, खाद्य जैसे औद्योगिक उद्यमों के कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	**जल प्रबंधन:** सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल का प्रभावी उपयोग, भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना और कृषि जलवायु अनुकूल फसल/उत्पादन प्रणाली।	**कृषि क्षेत्रक का विविधीकरण:** उदाहरण-खाद्यान्न (अनाज + दालें) से लेकर फल, सब्जियों और फूलों की खेती को प्रोत्साहन देना।

7.1.1. प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (Prime Minister Dhan Dhaanya Krishi Yojana: PMDKY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY) शुरू करने की घोषणा की।

प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY) के बारे में

- **कवरेज:** इस योजना के तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा।

© Vision IAS

- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित:** PMDKY **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)** की तर्ज पर बनाई गई है। गौरतलब है कि देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों का तेजी से और प्रभावी तरीके से विकास करने हेतु आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में की गई थी।

PMDKY के उद्देश्य

- कृषि उत्पादकता को बढ़ाना
- फसल विविधीकरण और संधारणीय कृषि पद्धतियों को अपनाना
- पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के पश्चात भंडारण को बढ़ाना
- सिंचाई सुविधाओं में सुधार
- दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता

7.1.2. डिजिटल कृषि मिशन: एक नज़र में (Digital Agriculture Mission at A Glance)

डिजिटल कृषि मिशन (DAM)

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी। इसके लिए कुल 2,817 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

2 आधारभूत पिलर्स पर आधारित है

एग्री स्टैक (किसान की पहचान): यह किसान-केंद्रित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए सेवाओं और योजनाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाना है। इसके 3 प्रमुख घटक हैं: **किसानों की रजिस्ट्री** (इसके तहत 'किसान ID' जारी की जाएगी); **जियो-रेफ़रेंस्ड गाँव के नक्शे; फसल बुआई रजिस्ट्री**	**कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (DSS)** फसल, मृदा, मौसम और जल संसाधनों पर सुदूर संवेदन डेटा को एक व्यापक भू-स्थानिक प्रणाली में एकीकृत करना।

मुख्य लक्ष्य

3 वर्षों में 11 करोड़ किसानों के लिए डिजिटल पहचान बनाई जाएगी और 2 वर्षों में देश भर में डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा, तथा वित्त वर्ष 2025-26 तक सभी जिलों को कवर करेगा।

डिजिटल कृषि मिशन का महत्त्व

डेटा और विश्लेषण के आधार पर निर्णय लेने में सहायता	फसल क्षेत्र और उपज के बारे में सटीक डेटा	फसल कटाई के बाद नुकसान को रोकना और कम करना: जैसे क्रॉप मैपिंग और फसल की निगरानी	कृषकों को प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं में सुधार करना

प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन में चुनौतियां

कृषि भूमि का छोटा आकार	शुरुआत में अधिक लागत और डिजिटल साक्षरता का अभाव	विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त अवसंरचना	उपलब्ध तकनीक उपयोग के बारे में स्थानीय भाषाओं में जानकारी उपलब्ध नहीं होना

आगे की राह

किसानों का सुरक्षित डेटा संग्रह, भू-स्वामित्व अधिकार सुनिश्चित करना	खुले, इंटरऑपरेबल और स्केलेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विकसित करना	किफायती, बहुभाषी ऐप्स, AI टूल्स आदि विकसित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।	अधिकतम प्रभाव के लिए **डिजिटल कृषि मिशन** को पीएम-किसान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, e-NAM जैसी योजनाओं के साथ समन्वित करना।

CSAT क्लासेस 2026
ENGLISH MEDIUM 12 JUNE, 11 AM
हिन्दी माध्यम 12 जून, 2 PM

7.1.3. कृषि निर्यात: एक नज़र में (Agriculture Export at A Glance)

कृषि निर्यात

मुख्य तथ्य

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के कृषि निर्यात में 8 प्रतिशत की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई और 2022 तक 60 बिलियन डॉलर के कृषि नियत लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।	कृषि निर्यात 2022-23 में 53.2 बिलियन डॉलर से घटकर 2023-24 में 48.9 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि आयात 8% घटकर 32.8 बिलियन डॉलर (2023-24) हो गया।	WTO की व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा (2023) के अनुसार, 2022 में **विश्व कृषि उत्पाद निर्यात और आयात में भारत की हिस्सेदारी क्रमशः 2.4 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत** थी। विश्व में **कृषि निर्यातक देशों की सूची में भारत 9वें स्थान पर** था।	**कृषि निर्यात नीति (AEP) 2018** › **परिचय:** यह निर्यातोन्मुख कृषि उत्पादन, किसानों को लाभ, निर्यात संवर्धन और नीतियों में तालमेल आदि पर केंद्रित है। › **उद्देश्य:** मूल्य वर्धन के माध्यम से किसान की आय में वृद्धि करना और मूल्य श्रृंखला में नुकसान को कम करना

नई निर्यात नीति की आवश्यकता क्यों है?

निर्यात पर कई तरह के अवरोधों की मौजूदगी: जैसे निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, निर्यात पर प्रशुल्क लगाना, निर्यात वाली वस्तु का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय करना आदि	**वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव:** वैश्विक कीमतों में उछाल के साथ भारत का कृषि-निर्यात बढ़ता है, लेकिन वैश्विक कीमतों में गिरावट आने पर इसमें गिरावट आती है।	**WTO से जुड़े मुद्दे:** प्रमुख कृषि उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंध अक्सर विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों का उल्लंघन हैं। उदाहरण के लिए, भारत द्वारा चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से वैश्विक कीमतों में 25% की वृद्धि हुई।	**निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सीमित संख्या:** जैसे भारत के कुल कृषि निर्यात में चावल और चीनी की हिस्सेदारी 37.4 प्रतिशत है।	**अप्रत्यक्ष रूप से जल का निर्यात:** 16.3 मिलियन टन चावल का निर्यात 32.6 बिलियन क्यूबिक मीटर जल के निर्यात के बराबर है। बिजली और उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी के चलते पर्यावरण को हुई हानि प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती है।

कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (TIES)	बाजार पहुंच पहल (MAI) योजना	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना	परिवहन और विपणन सहायता योजना	APEDA किसान कनेक्ट पोर्ट

आगे की राह

वास्तविक निर्यात प्रतिस्पर्धा: उत्पादकता में वृद्धि, अलग-अलग उत्पादों को शामिल करने, मूल्य वर्धन, बाजार पहुंच और ब्रांडिंग के माध्यम से घरेलू उत्पादन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना	**प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग:** उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए परिशुद्ध खेती (प्रिसिजन फार्मिंग), दक्ष सिंचाई प्रणाली और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना	**ऑर्गेनिक और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों पर जोर देना:** किसान उत्पादक संगठनों की मदद से "ऑर्गेनिक" या "कीटनाशक मुक्त" क्लस्टर्स का विकास करने की आवश्यकता है।	**पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना:** जैसे कम जल और उर्वरकों की खपत वाली दलहनी और तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना	**आयात नीतियां बनाते समय जलवायु परिवर्तन का ध्यान रखना:** खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और कीमतों को स्थिर करना

7.1.4. मखाना (Makhana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में **मखाना बोर्ड के गठन** की घोषणा की गई।

मखाना के बारे में

- **फॉक्सनट** को आमतौर पर मखाना कहा जाता है। यह **जलीय पुष्पी-फसल** है। इसका वानस्पतिक नाम **यूरीले फेरोक्स/Euryale ferox (कांटेदार वाटर लिली)** है।

© Vision IAS

- मखाने की खेती **शांत बारहमासी** जल स्रोतों; तालाबों, गड्ढों, गोखुर झील (oxbow lakes), दलदल वाले क्षेत्रों में की जाती है।
- मखाना की पहचान अब **सुपर फूड के रूप में** की जाने लगी है।
    - मखाना न केवल उच्च पोषण और विविध स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है, बल्कि यह किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है और आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **मखाना की खेती के लिए आदर्श जलवायु दशाएं:**
    - **तापमान:** 20 से 35 डिग्री सेल्सियस
    - **वार्षिक वर्षा:** 100 से.मी. से 250 से.मी. के बीच
- **प्रमुख उत्पादक क्षेत्र:** बिहार (यहाँ देश का **90%** मखाना उत्पादित होता है), पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, इत्यादि।
    - **अन्य देश:** मखाना नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान, रूस और कोरिया में भी उगाया जाता है।

मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदम

- **राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा (बिहार):** इसे 2001 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत स्थापित किया गया है।
- **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान:** यह मखाना प्रोसेसिंग गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
- **एक जिला एक उत्पाद (ODOP):** बिहार के **दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों** में मखाना किंग को ODOP के तहत मान्यता दी गई है।
- **GI टैग:** 2022 में **'मिथिला मखाना'** को भौगोलिक संकेतक (GI) का दर्जा प्रदान किया गया।

मखाना की खेती में चुनौतियां

- **निम्न उत्पादकता:** किसान मखाना की खेती पारंपरिक तरीकों से कर रहे हैं जिसके कारण वे प्रति हेक्टेयर 1.7-1.9 टन मखाना उत्पादित कर रहे हैं। वहीं आधुनिक तकनीकों से मखाना का 3–3.5 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन संभव है।
- **मखाना की प्रोसेसिंग के लिए अवसंरचना की कमी:** इसके चलते किसानों को कच्चा मखाना अक्सर बिहार के बाहर की कंपनियों को कम कीमतों पर बेचना पड़ता है।
- **निर्यात से जुड़ी समस्याएं:** फ़ूड सेफ्टी और स्वच्छता प्रमाणन की आवश्यकता जैसे सख्त वैश्विक गुणवत्ता मानकों की वजह से मखाना का अधिक निर्यात नहीं हो पाता है। वर्तमान में, बिहार का केवल 2 प्रतिशत मखाना ही अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- **बाजार से जुड़ी समस्याएं:** बाजार में मखाना बेचने के लिए संगठित मार्केटिंग चेन का अभाव है। ज्यादातर किसान बिचौलियों को कम कीमत पर मखाना बेचने को मजबूर हैं, जिससे उन्हें कम मुनाफा मिलता है।
- **अन्य समस्याएं:** मखाना उगाने वाले जल स्रोतों में खरपतवार प्रबंधन की कमी, बेहतर गुणवत्ता वाले टूल्स और संबंधित सहायक टूल्स का अभाव, बेहतर कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं नहीं होना आदि अन्य महत्वपूर्ण समस्याएं हैं।

निष्कर्ष

मखाना बोर्ड की स्थापना भारत में मखाना की खेती को संगठित तरीके से बढ़ावा देने, अनुसंधान करने और वाणिज्यिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बोर्ड पारंपरिक खेती की कमजोरियों, कटाई के बाद होने वाले नुकसान और विश्व के बाजारों तक नहीं पहुंचने जैसी चुनौतियों का समाधान करके, मखाना को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी सुपर फूड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

7.1.5. कपास उत्पादकता मिशन (Mission for Cotton Productivity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में **'कपास उत्पादकता मिशन'** की घोषणा की गई।

कपास उत्पादकता मिशन के बारे में

- यह **पांच-वर्षीय मिशन** है। इसके उद्देश्य हैं- **कपास की उत्पादकता और उत्पादन सततता में सुधार** करना तथा **एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ELS) वाली कपास की किस्मों** के उत्पादन को बढ़ावा देना।
  - **एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (≥234.925 mm) कॉटन:** यह कॉटन की एक प्रीमियम किस्म है जिसकी खेती लगभग 10% कॉटन उत्पादन क्षेत्र में की जाती है। वैश्विक कॉटन उत्पादन में इसका योगदान 4% है।
- **क्रियान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय **वस्त्र मंत्रालय**
  - यह **सरकार के समग्र 5F विजन** के अनुरूप है। **वस्त्र क्षेत्रक का 5F विजन:** फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन।
- यह कपास उत्पादक किसानों को **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता** प्रदान करेगा।
- यह **आयात पर निर्भरता को कम करने** तथा **भारत के वस्त्र क्षेत्रक को विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने** में मदद करेगा। इस क्षेत्र में **80% भागीदारी MSME क्षेत्रक की है**।

कपास मिशन की आवश्यकता क्यों है?

- **उत्पादकता में वृद्धि नहीं होना:** कपास की उत्पादकता 2023-24 में 435 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, और **2024-25 में भी लगभग समान (447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) स्तर पर** बनी रही। इस तरह उत्पादकता बढ़ नहीं रही है।
- **वर्षा-सिंचित फसल:** लगभग **67% कपास उत्पादन वर्षा सिंचित क्षेत्रों में** और **33% उत्पादन सिंचित भूमि पर** होता है।
- **कीटों का हमला:** कपास की फसल पर **कीटों के हमले और बीमारियों के संक्रमण का खतरा बना रहता** है। उदाहरण के लिए, **गुलाबी सुंडी (पिंक बॉलवर्म)**, आदि।
- **कीमतों में उतार-चढ़ाव:** कपास की कीमतों में **अधिक उतार-चढ़ाव** देखा जाता है। इसके **बाजार की अवसंरचना भी विकसित नहीं है**। साथ ही, **कपास निर्यात नीति** में भी स्पष्टता का अभाव है।

भारत में कपास का उत्पादन, उत्पादकता और खपत

- **उत्पादन:** भारत **कपास उत्पादन क्षेत्र** के मामले में **दुनिया में प्रथम स्थान** पर है। भारत में **वैश्विक कपास उत्पादक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 40%** है।
- भारत **कपास के उत्पादन** के मामले में **विश्व में दूसरे स्थान** पर है। भारत में **2022-23 में 343.47 लाख गांठ (5.84 मिलियन मीट्रिक टन) का उत्पादन** हुआ था, जो **वैश्विक उत्पादन का 23.83%** है।
- **उत्पादकता: भारत कपास उत्पादकता के मामले में विश्व में 39वें स्थान** पर है। भारत की उत्पादकता **संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील** जैसे देशों से कम है।
- **खपत:** भारत **दुनिया में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता** है।

भारत में कपास उत्पादन का महत्त्व

- **आर्थिक महत्त्व:** कपास **वाणिज्यिक फसल** है। इसे **'सफेद सोना (व्हाइट गोल्ड)'** भी कहा जाता है, क्योंकि इसका भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान:** कपास के निर्यात से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और इससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है।
- **निर्यात की क्षमता:** भारत ने **2022-23 में लगभग 30 लाख गांठ कपास का निर्यात किया था (वैश्विक निर्यात का 6 प्रतिशत)**।
- **आजीविका का स्रोत: कपास वस्त्र उद्योग, भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता (50-50 मिलियन) है**। कृषि क्षेत्रक प्रथम स्थान पर है।

कपास उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए किए गए अन्य उपाय

- **कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना:** कृषि मंत्रालय ने **कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)** की सिफारिश पर **फेयर एवरेज क्वालिटी (FAQ)** की दो मूलभूत किस्मों; **मीडियम स्टेपल और लॉन्ग स्टेपल लंबाई वाली कपास के लिए MSP** की घोषणा की।
- **भारतीय कपास की ब्रांडिंग: "कस्तूरी इंडियन कॉटन"** ब्रांड लॉन्च किया गया, जिससे भारत **आत्मनिर्भर** बने और **स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा** मिले।

 © Vision IAS

- **मोबाइल ऐप "Cott-Ally":** किसानों को **MSP, सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों और नज़दीकी CCI खरीद केंद्रों** की जानकारी देना।
- **तकनीकी पहलें:** इनमें **हाई-डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम (HDPS),** गुणवत्ता का वैज्ञानिक मूल्यांकन, **आधुनिक जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों में कॉटन प्रोसेसिंग, एक्सटेंशन सर्विसेज,** आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष

कॉटन प्रोसेसिंग में सुधार को **सिर्फ धागा और बुनाई तक सीमित न रखकर, इसमें तैयार उत्पादों के निर्माण** को शामिल करने की आवश्यकता है। कपास आधारित वस्त्र उद्योग में **MSMEs की भूमिका महत्वपूर्ण** है, क्योंकि वे भारत के **कपास वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका** निभाते हैं। **कपास मिशन गुणवत्ता युक्त कपास उत्पादन को बढ़ावा देगा**, जिससे **किसानों की आय में वृद्धि होगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा**, और **ब्रांड इंडिया को मजबूत बनाने** में मदद मिलेगी, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा।

7.1.6. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-तिलहन) {National Mission on Edible Oils – Oilseeds (NMEO-Oilseeds)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **2024-25 से 2030-31 तक** सात साल की अवधि के लिए **राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (NMEO-तिलहन)** को मंजूरी दी।

NMEO-OS की मुख्य विशेषताएं

- यह **कृषोन्नति योजना (KY)** के तहत एक **केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)** होगी।
- **उद्देश्य:** आयातित खाद्य तेलों पर भारत की निर्भरता को कम करना तथा घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देकर किसानों की आय में सुधार करना।
- **'सीड ऑथेंटिसिटी, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी' (साथी/SATHI) पोर्टल:** यह समय पर बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन 5-वर्षीय रोलिंग सीड प्लान है।
- 347 चुने हुए जिलों में **600 मूल्य श्रृंखला क्लस्टरों का विकास किया जाएगा।**
- इन क्लस्टरों में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, **अच्छी कृषि पद्धतियों (GAP) का प्रशिक्षण के संबंध में सलाहकारी सेवाएं** प्राप्त होंगी।

खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों है?

- **महत्त्व:** क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत में खाद्यान्न के बाद तिलहन दूसरी सबसे बड़ी फसल श्रेणी है। विविध कृषि-पारिस्थितिक स्थितियों में **तिलहन की 9 वार्षिक फसलें** उगाई जाती हैं।
- **मांग में वृद्धि:** भारत में बढ़ता शहरीकरण और औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCI) में वृद्धि की वजह से खाद्य तेल की उच्च मात्रा वाले प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की खपत में वृद्धि होने का अनुमान है।
- **आयात पर बढ़ती निर्भरता:** भारत खाद्य तेलों के मामले में आयात पर बहुत अधिक निर्भर है। भारत खाद्य तेलों की घरेलू मांग का 57% आयात करता है।

भारत में खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में चुनौतियां

- **प्रति हेक्टेयर कम उपज:** उपज में अंतर का मुख्य कारण अन्य देशों में आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) शाकनाशी-सहिष्णु फसल किस्मों का उपयोग किया जाना है। भारत में इसकी अनुमति नहीं है।
- **खेती से जुड़ी चुनौतियां:** तिलहनी फसलों की 76% खेती वर्षा पर निर्भर है। इसकी वजह से फसलों पर जैविक और अजैविक संकटों का खतरा बना रहता है।
- **तिलहनी फसलों का कुछ ही राज्यों में केंद्रित होना:** कुछ प्रमुख तिलहनी फसलों का उत्पादन कुछ राज्यों में ही केंद्रित है।
  - उदाहरण के लिए- गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक सामूहिक रूप से देश के कुल मूंगफली उत्पादन में 83.4% का योगदान करते हैं।
- **मांग और आपूर्ति में अंतर:** भारत में वनस्पति तेलों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात में उच्च वृद्धि बने रहने का अनुमान है।

निष्कर्ष

NEMO-तिलहन का लक्ष्य बेहतर बीजों, बेहतर अवसंरचना और मूल्य श्रृंखला के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देना है। परती भूमि पर तिलहन की खेती को बढ़ावा देने, अनुसंधान और सार्वजनिक-निजी भागीदारी से इस क्षेत्रक को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

7.2. कृषि विपणन: एक नज़र में (Agriculture Marketing at a Glance)

भारत में कृषि विपणन

इसे सरल शब्दों में कृषि उत्पादों को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने से संबंधित सभी वाणिज्यिक कार्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

कृषि-बाजारों का महत्व

बाजार में **कृषि उत्पादों का मुद्रीकरण**	बाजार की जानकारी और मूल्य के संकेत के स्रोत के रूप में कार्य करना	बिचौलियों की भूमिका को कम करना	कृषि में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से उत्पादन में मूल्य वर्धन

भारत में कृषि बाजारों के समक्ष मौजूद समस्याएं

संस्थागत बाधाएँ: नए व्यापारियों के लिए जटिल लाइसेंसिंग प्रक्रिया; उच्च बाजार शुल्क (APMCs सहित); एक समान ग्रेडिंग मानक का नहीं होना।	**अवसंरचना का अभाव:** असमान बाजार पहुंच; अपर्याप्त ड्राइंग यार्ड और कोल्ड स्टोरेज; कम व्यावहारिक परियोजनाएं और लाभ मिलने में लगने वाला लंबा समय।	**सूचना की कमी:** कृषि उपज की मांग पर रियल टाइम आंकड़े का अभाव; किसानों के लिए सीमित कंटेंट; सूचना के नए माध्यमों के बारे में कम जागरूकता होना।	**एकीकरण एवं वित्त-पोषण का अभाव:** कोई राष्ट्रीय एकीकृत बाजार नहीं होना; विपणन संबंधी अवसंरचना में सार्वजनिक (पब्लिक) निवेश कम होना ।

बाजारों के समग्र सुधार को सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

APMC में सुधार जैसे कि एक स्वतंत्र विनियामक की नियुक्ति और APMCs में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करना (निजी थोक बाजार, एकीकृत एकल पंजीकरण आदि के माध्यम से)।	थर्ड पार्टी मूल्यांकन प्रमाणीकरण के माध्यम से **eNAM को मजबूत करके राष्ट्रीय एकीकृत बाजार की स्थापना** करना, किसान समूहों और अन्य हितधारकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।	कृषि उपज के भंडारण और परिवहन पर दीर्घकालिक राष्ट्रीय नीति बनाकर **विपणन अवसंरचना विकास में निवेश को बढ़ावा** देना।	अधिक सुलभ तरीकों को लोकप्रिय बनाकर, मोबाइल उपकरणों के माध्यम से व्यक्तिगत किसान की आवश्यकता के अनुसार सूचना उपलब्ध कराकर और किसानों को व्यापक जानकारी प्रदान करके अधिक मजबूत सूचना प्रसार प्रणाली बनाना।	मंडी शुल्क/कमीशन चार्जेज को उपज के मूल्य के अधिकतम 2% तक सीमित करना।

7.3. कृषि विस्तार प्रणाली (Agriculture Extension System)

सुर्खियों में क्यों?

प्रधान मंत्री ने **वाराणसी में स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण-पत्र** प्रदान किए।

कृषि सखी के बारे में

- कृषि सखियां **अनुभवी महिला कृषक और जमीनी स्तर पर कृषि कार्य में प्रशिक्षित पैरा एक्सटेंशन पेशेवर** हैं।
    - **कृषि विस्तार प्रणाली** शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना के माध्यम से कृषि पद्धतियों में **वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवीनतम ज्ञान के उपयोग में** किसानों व ग्रामीण उत्पादकों को सहायता प्रदान करती है।

भारत में कृषि विस्तार प्रणाली

- वर्तमान में, भारत में कृषि अनुसंधान एवं विकास प्रणाली पर **सार्वजनिक क्षेत्रक का प्रभुत्व है और इसका नेतृत्व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** करता है।
    - **विस्तार/ VISTAAR (कृषि तकनीकों पर विकसित की जाने वाली वीडियोज़, वीडियोज़ की तकनीकी जांच, राज्य नोडल एजेंसियों व हितधारकों की निगरानी):** यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) आधारित परस्पर-क्रियात्मक प्रौद्योगिकी सूचना विस्तार से संबंधित पहल है।
    - देश भर में कृषि में **ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रसार करना** एवं इसके उपयोग को बढ़ावा देना।
- **राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन (NMAET)[26]:** इन उप-मिशनों को किसानों को कृषि कार्य हेतु नवीन तकनीक उपलब्ध कराने और इन तकनीकों को अपनाने तथा वर्तमान कृषि पद्धतियों में सुधार करने के लिए शुरू किया गया है।
- **कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs):** कृषि विज्ञान केंद्र **ICAR की क्षेत्रीय अनुसंधान इकाइयां हैं।** यह बीज की नवीन किस्मों, कृषि पद्धतियों, मशीनरी आदि का किसानों द्वारा अपनाए जाने से पहले विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों में खेतों में उनका परीक्षण करता है।
    - इसके अतिरिक्त, वे सीधे खेत में ही कृषि पद्धति आदि के प्रदर्शन, प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से किसान आउटरीच कार्यक्रम भी संचालित करते हैं।
    - ICT-आधारित योजनाओं में **m-किसान, किसान कॉल सेंटर** आदि शामिल हैं।
- **निजी क्षेत्रक द्वारा प्रदान की जाने वाली कृषि विस्तार सेवाएं:** उदाहरण के लिए- इफको (IFFCO), कृभको (KRIBHCO) जैसी कंपनियां किसानों की संगोष्ठियां आयोजित करके, फसलों से संबंधित सेमिनार आयोजित करके और मृदा परीक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करके विस्तार गतिविधियां (एक्सटेंशन एक्टिविटीज) संचालित करती हैं।

भारत की कृषि विस्तार प्रणाली के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **निवेश की कमी:** भारत अपने **कृषि-सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का केवल 0.7%** ही कृषि-अनुसंधान एवं शिक्षा (R&E) तथा विस्तार और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर व्यय करता है। इसमें से भी केवल **0.16% फंड ही विस्तार और प्रशिक्षण के लिए आवंटित** किया जाता है।
- **क्षेत्रीय विविधताएं:** कृषि पर अत्यधिक निर्भर और सबसे कम कृषि उत्पादकता वाले **पूर्वी राज्य** देश के सबसे गरीब राज्य हैं। साथ ही, ये कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा (R&E) पर **सबसे कम व्यय करने वाले राज्य** भी हैं।

---

[26] National Mission on Agriculture Extension and Technology

- **विषम आवंटन:** भारत में कृषि विस्तार और प्रशिक्षण संबंधी आवंटन **फसल उत्पादन (92%) की ओर अत्यधिक झुका** हुआ है, जबकि पशुधन क्षेत्रक भी कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
- **परिणाम-आधारित तंत्र का अभाव:** सार्वजनिक विस्तार वितरण प्रणाली, **लक्षित परिणाम-आधारित तंत्र की बजाय लक्षित गतिविधि आधारित-तंत्र** के रूप में अधिक कार्य करती है।

निष्कर्ष

भारत की कृषि विस्तार प्रणाली में बाजार-संचालित, तकनीक-सक्षम और विविधतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। कृषि सखियों जैसी जमीनी पहलों को मजबूत करना और निवेश, क्षेत्रीय संतुलन एवं आउटकम में सुधार करना किसानों को सशक्त बनाने और ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर (NISA)

ICAR-NISA की स्थापना **1924 में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान (Indian Institute of Natural Resins and Gums)** के रूप में **रांची, झारखंड** में की गई थी।

- 2022 में इसका **नाम बदलकर ICAR-NISA** कर दिया गया था। यह **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय** के अंतर्गत आता है।
- **सेकेंडरी एग्रीकल्चर:** सेकेंडरी एग्रीकल्चर में **प्राथमिक कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन के साथ-साथ मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, कृषि पर्यटन** जैसी अन्य कृषि-संबंधी गतिविधियां शामिल हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे **1929** में **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था।
- **उद्देश्य:** पूरे देश में बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान और शिक्षा का समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन करना।
- यह केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के **कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन** है।

7.4. कृषि आदान (Agriculture Input)

7.4.1. कृषि आदान (इनपुट): एक नज़र में (Agriculture Input at a Glance)

कृषि आदान (Agricultural Inputs)

कृषि आदानों का आशय फसलों के उत्पादन, अधिक उपज और रखरखाव में उपयोग किए जाने वाले सभी पदार्थ या सामग्री से है।

मृदा

चुनौतियां/मुद्दे

मृदा में जैविक (ऑर्गेनिक) पदार्थों की कमी होना	मृदा उर्वरता कम होना	मृदा की भौतिक स्थितियों जैसे मृदा की संरचना, स्थिरता, आदि में गिरावट	मृदा अम्लीकरण, लवणीकरण, क्षारीकरण और जलभराव	**अन्य:** अनुपजाऊ भूमि को कृषि भूमि में शामिल किया गया, बिना विश्लेषण किए बिना अस्थायी तौर पर अधिक उर्वरक उपयोग।

मुख्य उपाय

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: यह प्रभावी मृदा स्वास्थ्य निगरानी और प्रबंधन पर केंद्रित योजना है।	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY):** इसका उद्देश्य मृदा की ऊपरी परत के क्षरण को रोकना; फसल उत्पादन में बढ़ोतरी करना;	**नाबार्ड से ऋण–** ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF) **के तहत मृदा और जल संरक्षण योजना**

जल

चुनौतियां/मुद्दे

जल की सामान्य कमी और जल के उपयोग में क्षेत्रीय असंतुलन।	अधिक वर्षा-सिंचित कृषि क्षेत्र।	मौजूदा सिंचाई सुविधाओं की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करना।	निम्नस्तरीय सिंचाई दक्षता।	कृषि में इस्तेमाल होने वाले जल की खराब गुणवत्ता।

किए गए उपाय

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) खेती वाले क्षेत्रों को सुनिश्चित सिंचाई प्रदान करने, जल की बर्बादी को कम करने और जल उपयोग की दक्षता में सुधार करने पर लक्षित है।	**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना**–लघु सिंचाई संरचना जैसी अवसंरचना के निर्माण पर ध्यान देना।	**राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY):** इसके तहत जल संरक्षण और प्रबंधन गतिविधियों के लिए फंड उपलब्ध कराया जाता है।	**अटल भूजल योजना:** जन-सहभागिता के साथ भूजल का संधारणीय प्रबंधन।

बीज

चुनौतियां/चिंताएं

बीज उत्पादन: इसमें बीजों की गुणवत्ता, कीमत और उपलब्धता जैसी मुख्य चिंताएं शामिल हैं।	**बीज वितरण प्रणाली की धीमी प्रगति:** प्रमाणित/लेबल युक्त **बीज की उपलब्धता** केवल 35-40 प्रतिशत के आसपास है।	**बीज की मांग का प्रभावी तरीके से आकलन नहीं करना।**

मुख्य उपाय

राष्ट्रीय बीज निगम (NSC),1963	उच्च उपज किस्म कार्यक्रम (HYVP)-(1966-67)	राष्ट्रीय बीज नीति, 2002	अलग-अलग कानून लागू: जैसे- बीज अधिनियम, 1966; पादप किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001	बीज ग्राम कार्यक्रम (SVP), 2005

कीटनाशक

चुनौतियां/चिंताएं

निम्न गुणवत्ता वाले कीटनाशक।	कीटनाशकों का अधिकतम उपयोग न करना।	एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) तकनीकों की सीमित पहुंच, जो जैव कीटनाशकों के उपयोग पर बल देती है।	कीटनाशकों का मूल्य नियंत्रण नहीं होना।

मुख्य उपाय

कीटनाशी अधिनियम, 1968	राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी (MPRNL) के लिए योजना।	अन्य पहलें, जैसे- कीट निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, क्षेत्रीय कीटनाशक परीक्षण प्रयोगशालाएं, मीडिया के माध्यम से किसानों को जागरूक करना, आदि।	परम्परागत कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना।	अनुसंधान संगठनों (ICAR/SAU) द्वारा किए जाने वाले उपायों में कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास, एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) सिफारिशों का समय पर प्रसार करना, आदि शामिल हैं।

कृषि मशीनीकरण

चुनौतियां/चिंताएं

कृषि-जोत का आकार छोटा होना।	पहाड़ी और उबड़-खाबड़ स्थलाकृति।	मिश्रित फसल और एकीकृत खेती।	बिजली की निरंतर आपूर्ति नहीं होना	**अन्य: मशीन की सर्विसिंग की खराब सुविधाएं, कृषि में अधिशेष श्रमिक होने से इनके बेरोजगार होने का खतरा**

मुख्य उपाय

कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (SMAM): इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं: 'कस्टम हायरिंग सेंटर्स और हाई-वैल्यू मशीनों के हाई-टेक हब' को बढ़ावा देना। जागरूकता पैदा करना।	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उन्नत तथा **महिलाओं द्वारा उपयोग अनुकूल कृषि-उपकरणों** के लिए सहायता प्रदान करना।	**भूमि संरक्षण विभाग** मशीन खरीदने के लिए महिला के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों को 90% सब्सिडी प्रदान करता है।	**नाबार्ड ऋण योजना के तहत सब्सिडी प्रदान की जाती है।**

आगे की राह की संभावनाएं

उच्चतर इंजीनियरिंग इनपुट और उच्च क्षमता, सटीक, विश्वसनीय तथा ऊर्जा कुशल उपकरणों का विकास करना।	बागवानी और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसलों के लिए मशीनीकरण का विकास करना।	जिला स्तर पर 'कृषि मशीन बैंक' (AMB) की स्थापना करना।	किसानों के अनुकूल, स्थान-विशिष्ट और आसान तरीके से प्रबंधित की जाने वाली कृषि मशीनरी को विकसित करने के लिए स्वदेशी स्तर पर अनुसंधान एवं विकास करना।	प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना।

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION
SANDHAN
Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज
(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

- UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों का विशाल संग्रह
- अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधा
- परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट (PIT)
- टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर फीडबैक

अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

2026 | ENGLISH MEDIUM 13 JULY | हिन्दी माध्यम 13 जुलाई

© Vision IAS

7.4.2. कृषि ऋण:एक नज़र में (Agriculture Credit at a Glance)

भारत में कृषि ऋण

भारत में कृषि ऋण की स्थिति

पिछले दशक (2014-15 से 2023-24) में कृषि ऋण वितरण में औसतन 13% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई है।	वित्त वर्ष 2023-24 में कृषि ऋण वितरण 25.48 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया।	वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने कृषि के लिए 27.5 लाख करोड़ रुपये ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें संबद्ध गतिविधियों के लिए 4.20 लाख करोड़ रुपये ऋण वितरण के उप-लक्ष्य शामिल हैं।

चुनौतियाँ

ऋण लेने के लिए **गैर-सांस्थानिक (महाजनों से) विकल्पों पर अधिक निर्भरता**	**किसी क्षेत्र या राज्य को अधिक ऋण मिलना और किसी क्षेत्र को कम ऋण मिलना**	**कृषि ऋणों का** गैर-कृषि उद्देश्यों **के लिए उपयोग**	केवल 41% लघु और सीमांत किसानों, जिनके पास 86% कृषि योग्य भूमि है, वही किसान बैंक ऋण का लाभ ले पाते हैं।

शुरू की गयी पहलें

नाबार्ड की **समर्पित दीर्घकालिक सिंचाई निधि (LEIF)।**	**प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान/PM-KISAN)**	**किसान क्रेडिट कार्ड योजना:** लघु और सीमांत किसानों के लिए बिना किसी परेशानी के ऋण सुनिश्चित करना	**संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS)**

आगे की राह

पूंजीगत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए **दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना।**	क्षेत्रीय असंतुलन से निपटने के लिए **पूर्वी, मध्य, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि ऋण वितरण पर विशेष ध्यान देना।**	**प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण** मानदंडों की समीक्षा की जानी चाहिए	लघु और सीमांत किसानों को आसानी से और आसान शर्तों पर ऋण की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

7.4.2.1. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) {Primary Agricultural CREDITS Societies (PACS)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

देश भर में **पैक्स (PACS)** के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए कई पहलें आरंभ की गई हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **पैक्स के विस्तार के लिए पहल:** गोदामों और अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए **500 नए पैक्स की आधारशिला** रखी गई है।
- **पैक्स के आधुनिकीकरण के लिए पहलें:**
  - देश भर में **18,000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन** किया गया है। **"पैक्स के कम्प्यूटरीकरण"** के लिए एक **केंद्र प्रायोजित परियोजना** शुरू की गई है।
  - सहकारिता मंत्रालय ने **राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD)**[27] का उद्घाटन किया है।

पैक्स के बारे में

- **परिभाषा:** पैक्स **सहकारी ऋण संरचना** में **जमीनी स्तर की शाखाएं** हैं। ये मुख्यतः **अल्पावधि वाले ऋणों का वितरण** करते हैं।
- **पुनर्वित्त:** इन्हें **DCCBs और SCBs** के माध्यम से नाबार्ड (NABARD) द्वारा पुनर्वित्त किया जाता है।
- **कार्य:** ये मुख्य रूप ग्रामीणों को अल्पावधि वाले ऋण प्रदान करते हैं और उनसे ऋण की पुनर्वसूली करते हैं। ये सदस्य किसानों को **बीज, उर्वरक** और **कीटनाशक** भी उपलब्ध कराते हैं।
- **महत्त्व: वित्तीय समावेशन** में पैक्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। देश में सभी संस्थाओं (बैंकों आदि) द्वारा दिए गए KCC[28] ऋणों में **पैक्स का हिस्सा 41%** है। इसके अलावा, 2022 के डेटा के अनुसार, पैक्स के माध्यम से दिए गए KCC ऋणों में से 95% ऋण **लघु और सीमांत किसानों** को दिए गए हैं।

[27] National Cooperative Database

[28] किसान क्रेडिट कार्ड

* **वर्तमान स्थिति:** देश भर में **65,000 से अधिक पैक्स चालू अवस्था में हैं।**

पैक्स को मजबूत करने वाली अन्य पहलें

* **पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)[29] का गठन:** राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)[30] के सहयोग से पैक्स द्वारा **1,100 अतिरिक्त FPOs का गठन किया जाएगा।**
* **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC):** इसे 1963 में स्थापित किया गया था। **NCDC** प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की सहकारी समितियों के वित्त-पोषण के लिए राज्य सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है।
* **पैक्स के व्यवसाय पोर्टफोलियो में विविधता लाना:**
    * **पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने के लिए मॉडल उप-नियम:** इसके तहत पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां करके अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सक्षम बनाया जा रहा है। इन गतिविधियां में डेयरी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, गोदामों की स्थापना आदि शामिल हैं।
    * **'प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केंद्र' के रूप में पैक्स:** इसका उद्देश्य किसानों को एक ही दुकान पर उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट्स प्रदान करना है।
    * **'प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र' के रूप में पैक्स:** इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों के लिए **जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।**

निष्कर्ष

PACS को मजबूत करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है। इसमें CAS और MIS जैसी आधुनिक तकनीक को अपनाना, जोखिम आधारित ऋण और विविधीकरण के माध्यम से वित्तीय मजबूती को बढ़ाना, कुशल मानव संसाधनों में निवेश करना, और अनुचित हस्तक्षेप से मुक्त पारदर्शी, जवाबदेह शासन सुनिश्चित करना शामिल होना चाहिए।

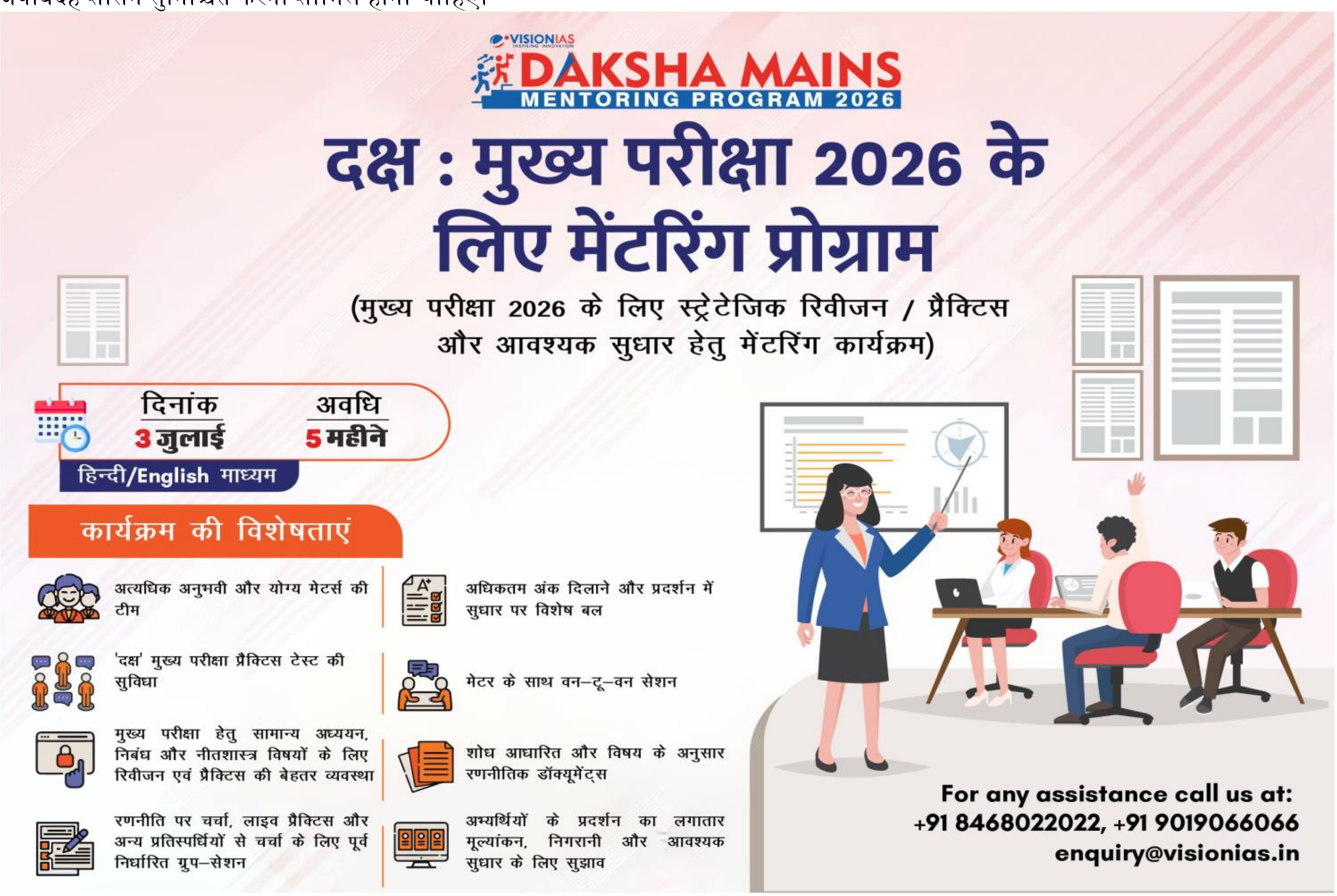

[29] Farmer Producer Organizations

[30] National Cooperative Development Corporation

7.5. संबद्ध क्षेत्रक (Allied Sectors)

7.5.1. पशुधन क्षेत्रक: एक नज़र में (Livestock Sector at a Glance)

भारत में पशुधन क्षेत्रक

भारत में पशुधन क्षेत्रक की स्थिति

विश्व में पशुधन की सबसे अधिक संख्या भारत में है।	भारत, **भैंस के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक** और **बकरी के मांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।**	**GDP में योगदान:** 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रक GVA में पशुधन क्षेत्रक का 30.19% योगदान तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की कुल GVA में पशुधन क्षेत्रका का योगदान 5.73%।	**रोजगार:** भारत में 70% से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत।

भारत के पशुधन क्षेत्रक के लिए प्रमुख पहलें

राष्ट्रीय गोकुल मिशन	**राष्ट्रीय पशुधन मिशन**	**पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम**	**राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम**	**पशु स्वास्थ्य अवसंरचना विकास निधि आदि**

भारत में पशुधन क्षेत्रक से जुड़ी समस्याएं

पशु रोगों जैसे ब्रुसेलोसिस **के कारण उच्च आर्थिक नुकसान**	**अवसंरचना का अभाव:** जैसे भारत में मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या 60 से भी कम है।	**एंटी-माइक्रोबियल रेजिस्टेंस:** पशुओं में एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है।	केवल 15.47% पशुधन को बीमा कवर प्राप्त है।	**अन्य:** कम उत्पादकता, चारे की कमी, पशुधन से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन आदि।

आगे की राह

राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित करना चाहिए	दूरदराज के क्षेत्रों के लिए **मोबाइल पशु चिकित्सा सेवाएं शुरू करनी चाहिए**	**पशुधन आधारित एकीकृत कृषि प्रणाली (IFS) को बढ़ावा देना चाहिए**	**बीमा कवरेज बढ़ाना; क्षेत्र (एरिया)-विशेष नीति तैयार करना आदि।**

7.5.2. भारत का डेयरी सहकारी क्षेत्रक (India's Dairy Cooperative Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने **'श्वेत क्रांति 2.0'** के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसका उद्देश्य भारत के डेयरी सहकारी क्षेत्रक में बदलाव लाना है।

श्वेत क्रांति 2.0 के मुख्य उद्देश्य

- **डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में वृद्धि:** इसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना है।
- **महिला कृषकों को सशक्त बनाना:** ग्रामीण क्षेत्रों में **डेयरी क्षेत्रक में रोजगार सृजन** के माध्यम से महिलाओं को **आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना**।
- **डेयरी संबंधी अवसंरचनाओं को मजबूत बनाना: गांव के स्तर पर दूध खरीद प्रणाली, गुणवत्तापूर्ण दूध खरीद हेतु मिल्क चिलिंग प्लांट** स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना:** दूध के परीक्षण के लिए आवश्यक उपकरणों को स्वदेशी स्तर पर विकसित करके, बल्क में दूध की खरीद करके एवं डेयरी संबंधी अवसंरचनाओं के विकास के माध्यम से डेयरी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **वित्तीय समावेशन:** इस कार्यक्रम के तहत किसानों को ब्याज मुक्त नकद ऋण प्रदान कराया जाएगा और **डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो-ए.टी.एम. वितरित** किए जाएंगे।

श्वेत क्रांति के बारे में

- देश में 'श्वेत क्रांति' 1970 में **ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम** के साथ शुरू हुई थी। यह एक डेयरी विकास कार्यक्रम था, जिसे भारत को **दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर** बनाने के लिए शुरू किया गया था।
- ऑपरेशन फ्लड को **भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)** द्वारा संचालित किया गया।

डेयरी क्षेत्रक में सहकारिता (कोऑपरेटिव्स) का महत्व

- **किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देना:** अमूल और नंदिनी जैसी सहकारी समितियां।
- **बाजार तक पहुंच:** सहकारी समितियां लघु किसानों को अपने उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराती हैं। इससे उनकी **सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति** बढ़ती है।
- **महिला सशक्तीकरण का समर्थन:** डेयरी सहकारी समितियों में 35% प्रतिभागी महिलाएं हैं।
- **वित्तीय समावेशन को बढ़ावा:** सहकारी बैंक किसानों और अपने सदस्यों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं।
- **संकट से निपटने की क्षमता और जोखिम न्यूनीकरण:** सहकारी समितियां **बुरे दौर में मजबूत सहायता नेटवर्क** उपलब्ध कराकर अपने सदस्यों को आर्थिक संकट से निपटने में मदद करती हैं।

भारत की डेयरी सहकारी समितियों के समक्ष चुनौतियां: वित्त-पोषण, मिल्क ग्रिड बनाने में बाधाएं, उपभोक्ता प्राथमिकताएं और बाजार के ट्रेंड, सीमित प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा, गुणवत्ता संबंधी समस्याएं, आदि।

डेयरी क्षेत्रक को मजबूत करने के लिए शुरू की गई पहलें

- **राष्ट्रीय गोकुल मिशन:** इसे **गाय की देशज नस्लों** के विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जा रहा है।
- **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP)**[31]: इसका उद्देश्य रोगनिरोधी टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना है।
- **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि:** इसका उद्देश्य उद्यमियों, निजी कंपनियों आदि द्वारा डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना स्थापित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):** इसके तहत पशुपालकों और डेयरी किसानों को बैंकों से आसानी से और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- **संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD):** 10,000 नई डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना, **2 दुग्ध उत्पादक कंपनियों का गठन,** आदि।

आगे की राह

- **तकनीकों को अपनाना:** प्रमुख स्थानों पर **साइबर स्टोर स्थापित करना** चाहिए और ग्राहक डेटाबेस तैयार करना चाहिए। इससे बाजार के वर्गीकरण में मदद मिलेगी और लक्षित बिक्री बढ़ाई जा सकेगी।
- **दुग्ध का दक्षतापूर्वक प्रसंस्करण:** अधिक समय तक दूध की गुणवत्ता बनाए रखने और दुग्ध का सुचारू परिवहन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कोल्ड चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना आवश्यक है। दुग्ध ब्रांड के प्रचार के लिए ऑनलाइन माध्यमों, इंटरैक्टिव वेब-साइट्स और विपणन की नई रणनीतियों के माध्यम से ब्रांड वैल्यू बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।

---
[31] Livestock Health & Disease Control Programme

- **निर्यात को बढ़ावा देना:**
    - **प्रतिस्पर्धात्मकता:** अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के समक्ष घरेलू ब्रांड्स की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाकर देश के डेयरी ब्रांड्स में विश्वास पैदा करना चाहिए।
    - **व्यावसायिक नजरिया रखना:** किसानों को डेयरी सहकारी समितियों का प्रबंधन व्यावसायिक सोच के साथ करना चाहिए, जिसमें लाभप्रदता और संधारणीयता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
    - **मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखना:** देश के दुग्ध उत्पादकों एवं घरेलू मिल्क ब्रांड्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए डेयरी क्षेत्रक को मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) से बाहर रखा जाना चाहिए।

निष्कर्ष

सहकारी मॉडल का लाभ उठाकर, भारत का डेयरी क्षेत्रक अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त कर सकता है। इससे भारत को वैश्विक स्तर पर डेयरी उत्पादों का अग्रणी निर्यातक बनाया जा सकेगा।

7.5.3. भारत में बागवानी क्षेत्रक: एक नज़र में (Horticulture Sector in India at a Glance)

भारत में बागवानी क्षेत्रक

भारत के बागवानी क्षेत्रक की स्थिति

उत्पादन: कुल कृषि क्षेत्र के 13.1% भाग पर बागवानी की जाती है और 2022-23 में इसका उत्पादन 355.48 मिलियन टन रहा।	**कृषि GVA में योगदान 33%**	**विश्व में स्थिति:** फलों और सब्जियों के उत्पादन के मामले में चीन के बाद भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है।	**निर्यात:** सब्जियों के मामले में भारत 14वें और फलों के मामले में 23वें स्थान पर है।

भारत के लिए बागवानी क्षेत्रक का महत्व

उच्च आय क्षमता: किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक।	**खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में वृद्धि:** यह आवश्यक विटामिन एवं खनिज प्रदान करता है।	यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करता है।	**विदेशी मुद्रा अर्जन: भारत मसालों, आमों, केलों और फ्लोरीकल्चर आधारित उत्पादों का अग्रणी निर्यातक है।**

शुरू की गयी पहलें

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (2014)	जियोइन्फोमेटिक्स का उपयोग करते हुए बागवानी आकलन और प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम (चमन/ CHAMAN)	पूंजी निवेश सब्सिडी योजना, क्लीन प्लांट प्रोग्राम आदि	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन

चुनौतियां

निर्यात में कम हिस्सेदारी: वैश्विक बागवानी उत्पाद बाजार में भारत की हिस्सेदारी केवल 1% है।	सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी उपायों जैसी गैर-प्रशुल्क व्यापार बाधाओं के कारण भारतीय कृषि निर्यात को विदेशों में फूड सेफ्टी एवं मानकों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है।	**अवसंरचना की कमी: कुल कोल्ड स्टोरेज वितरण क्षमता का 59% केवल 4 राज्यों में मौजूद है।**	**अन्य:** लघु कृषि भूमि-जोत; सीमित मूल्य वर्धन, ऋण मिलने में परेशानी, जलवायु परिवर्तन जनित चरम मौसमी घटनाएँ बढ़ना, आदि।

आगे की राह

कोल्ड स्टोरेज क्षमता का विस्तार करके आपूर्ति श्रृंखला संबंधी दक्षता में सुधार करना चाहिए।	**मूल्यवर्धित बागवानी उत्पादों के विकास को प्रोत्साहित करना चाहिए।**	**परिशुद्ध कृषि, हाइड्रोपोनिक्स जैसी कृषि प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना चाहिए।**	**क्लाइमेट-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को विकसित करना और बढ़ावा देना चाहिए।**

7.5.4. मात्स्यिकी क्षेत्रक: एक नज़र में (Fisheries Sector at a Glance)

भारत में मात्स्यिकी क्षेत्रक

भारत के मात्स्यिकी क्षेत्रक की स्थिति

विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश, वैश्विक मछली उत्पादन में 8% का योगदान।	**भारत जलीय-कृषि (एक्वाकल्चर) उत्पादन में दूसरे स्थान पर तथा श्रिम्प उत्पादन और निर्यात में अग्रणी है।**	1.9 मिलियन टन के साथ भारत अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान पर है।

महत्त्व

आर्थिक संवृद्धि: मछली उत्पादन भारत की GDP में लगभग 1% और कृषि GDP में 5% से अधिक का योगदान देता है।	**आजीविका का साधन:** लगभग 3 करोड़ मछुआरों और मत्स्य कृषकों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत।	**पोषण सुरक्षा:** मछली पशु आधारित प्रोटीन का एक किफायती और समृद्ध स्रोत है।

शुरू की गई पहलें

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना	प्रधान मंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना	राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड	मत्स्य पालन अवसंरचना विकास निधि	किसान क्रेडिट कार्ड मत्स्य पालन योजना

चुनौतियां

अत्यधिक मछली पकड़ना एवं संसाधनों का ह्रास	कोल्ड चैन, भंडारण, लैंडिंग केंद्र और प्रोसेसिंग यूनिट्स की कमी होना।	केंद्र और राज्यों के मध्य गवर्नेंस के मामले में समन्वय का अभाव	अवैध, असूचित और अविनियमित (IUU) मत्स्यन गतिविधियां	बैंकों से ऋण, मिलने में समस्या, मछली पकड़ने के बाद बड़ी मात्रा में मछलियां ख़राब हो जाना।

आगे की राह

अवसंरचना को मजबूत करना: मछली पकड़ने के आधुनिक बंदरगाहों, कोल्ड चैन आदि का विस्तार करना।	**संधारणीय मात्स्यिकी को बढ़ावा:** समुद्री संरक्षित क्षेत्र और कुछ मौसमों में मछली मारने पर प्रतिबंध लागू करना।	**ऋण एवं बीमा का कवरेज प्रदान करना:** बैंकों से वित्त-पोषण, ऋण गारंटी आदि तक पहुंच में सुधार करना।	**अन्य:** मात्स्यिकी पर एकीकृत राष्ट्रीय नीति बनाना, गुणवत्ता नियंत्रण, ब्रांडिंग और वैश्विक मानकों के अनुपालन को बढ़ावा देना।

7.6. किसान उत्पादक संगठन: एक नज़र में {Farmer Producer Organisations (FPOs) at a Glance}

किसान उत्पादक संगठन (FPOs)

FPOs का गठन कृषि उत्पादकों (किसानों, दूध उत्पादकों आदि) के समूह द्वारा किया जाता है। वे उत्पादक संगठन में शेयरधारक होते हैं।	**FPOs को या तो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत या संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के तहत पंजीकृत किया जाता है।**	देश में लगभग 30 लाख किसान FPOs से जुड़े हैं, जिनमें से लगभग 40% महिलाएं हैं।

FPOs के लाभ

कृषि उत्पादों के **प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलने से मूल्य वर्धन होती है।**	किसानों की **सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ावा** तथा उत्पादन एवं प्रसंस्करण कार्यों में अधिक गुणवत्ता सुनिश्चित होती है।	आसानी से सूचनाएं उपलब्ध कराकर **बाजार स्थितियों के बारे जानकारी** प्रदान करते हैं।	संयुक्त भंडारण और मूल्य वर्धन सुविधाओं को बढ़ावा देकर फसल कटाई के बाद नुकसान को कम किया जा सकता है।

FPOs के समक्ष मौजूद चुनौतियां

पेशेवर प्रबंधन कौशल का अभाव	फसल कटाई के बाद का नुकसान	निवेश और ऋण प्राप्ति में चुनौती	जलवायु परिवर्तन और बाजार में उतार-चढ़ाव

आगे की राह

प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना	प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करना	FPO के अलग-अलग चरणों के लिए एक **मानक स्कोरिंग मॉडल** बनाना	निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करना

7.7. अनाज भंडारण और खाद्य सुरक्षा (Grain Storage and Food Security)

7.7.1. भारत की अनाज भंडारण प्रणाली (Grain storage system in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के पायलट चरण के अंतर्गत, **11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) में 9,750 मीट्रिक टन क्षमता वाली भंडारण इकाइयों** का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया था।

सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के बारे में

- **मंत्रालय:** सहकारिता मंत्रालय
- **उद्देश्य:** मौजूदा योजनाओं अर्थात **कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना योजना** आदि का अभिसरण करके PACS के स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण सुविधाओं के साथ-साथ अन्य कृषि अवसंरचनाओं जैसे गोदामों, प्रसंस्करण इकाइयों आदि की स्थापना करना।

भंडारण क्षमता को मजबूत करने के लिए शुरू की गई अन्य पहलें

- **नेशनल कोल्ड चेन डेवलपमेंट स्कीम (NCCD):** शीघ्र ख़राब होने वाले कृषि उत्पादों के लिए कोल्ड चेन भंडारण का निर्माण करना।
- **ग्रामीण भंडारण योजना:** इसके तहत गांवों में भंडारण की कमी को दूर करने के लिए ग्रामीण गोदामों को सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- **अन्य: प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी (PEG) योजना, पी.एम. किसान संपदा योजना आदि।**

भारत में अनाज भंडारण प्रणाली

- **लघु किसानों द्वारा भंडारण:** उत्पादित खाद्यान्न का लगभग 60-70% हिस्सा घरेलू स्तर पर विभिन्न स्वदेशी और **पारंपरिक भंडारण** संरचनाओं, जैसे- मोराई, मिट्टी की कोठी आदि का उपयोग करके भंडारित किया जाता है।

- **सरकारी भंडारण एजेंसियां:**
  - **भारतीय खाद्य निगम (FCI):** FCI देश में खाद्यान्न भंडारण के लिए मुख्य एजेंसी है।
  - **केंद्रीय भंडारण निगम (CWC):** इसे **भंडारण निगम अधिनियम, 1962** के तहत कृषि उपज और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण के लिए स्थापित किया गया था।
  - **राज्य भंडारण निगम:** इसे राज्यों में संबंधित राज्य भंडारण अधिनियमों के तहत कुछ वस्तुओं के भंडारण को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया है।
- **निजी एजेंसियां:** FCI **निजी स्वामियों** से भंडारण क्षमता किराए पर भी लेती है।

भारत में अनाज भंडारण से जुड़ी चुनौतियां

- **अवैज्ञानिक भंडारण:** लगभग 80% हैंडलिंग और गोदाम सुविधाएं मशीनों से लैस नहीं हैं।
- **सीमित भंडारण क्षमता:** FAO[32] के सांख्यिकीय डेटा के अनुसार, भारत में खाद्यान्न उत्पादन 311 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) के आस-पास है, जबकि भारत में कुल भंडारण क्षमता केवल 145 MMT ही है। इसका मतलब यह है कि 166 MMT खाद्यान्न के लिए भंडारण सुविधा का अभाव है।
- **अधिशेष बफर स्टॉक:** FCI बफर स्टॉकिंग मानदंडों से कहीं अधिक बफर स्टॉक रखता है।
- **फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान:** पारंपरिक भंडारण प्रणाली फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान से सुरक्षा की गारंटी नहीं देती हैं।
- **भंडारण में निजी निवेश की कमी:** निजी क्षेत्रक भंडारण सुविधाओं में निवेश करने में झिझकता है। जमीन की पर्याप्त उपलब्धता न होना और निर्माण से पहले कई रेगुलेटरी लाइसेंस जैसी चुनौतियां निवेश में बाधा बनती हैं।

निष्कर्ष

भारत की अनाज भंडारण प्रणाली को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है ताकि कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सके, अधिशेष अनाज का बेहतर प्रबंधन हो सके और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए PACS के स्तर पर विकेंद्रीकृत और आधुनिक गोदामों का निर्माण आवश्यक है। इस लक्ष्य को पाने के लिए अधिक निवेश, वैज्ञानिक भंडारण तकनीकें अपनाना और विभिन्न योजनाओं का समन्वय करना बेहद महत्वपूर्ण है।

7.7.2. भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India: FCI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए FCI की **कार्यशील पूंजी (Working capital)** बढ़ाने हेतु **10,700 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी** दी है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बारे में

- **परिचय:** FCI केंद्रीय **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय** के तहत **सार्वजनिक क्षेत्रक का एक उपक्रम** है।
- **स्थापना:** FCI **खाद्य निगम अधिनियम, 1964** के तहत स्थापित **एक वैधानिक संस्था** है।
- **मुख्य भूमिका:** यह भारत सरकार की **खाद्य नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार** मुख्य एजेंसी है।
- **कार्य:** यह **खाद्यान्न की खरीद, भंडारण, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने, वितरण और बिक्री के लिए उत्तरदायी** नोडल एजेंसी है।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) की कार्य-प्रणाली

- **FCI, राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर, किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** पर अनाज खरीदती है।
- **FCI दो प्रकार की खरीद प्रणाली अपनाती है:**
  - **प्रत्यक्ष खरीद:** FCI या राज्य सरकार एजेंसियां (SGAs) सीधे किसानों से खाद्यान्न खरीदती हैं। इसके बाद FCI इन खाद्यान्नों का **भंडारण और वितरण** सुनिश्चित करती है।

---

32 Food and Agriculture Organization/ खाद्य और कृषि संगठन

© Vision IAS

- o **विकेंद्रीकृत खरीद (Decentralized Procurement: DCP):** राज्य एजेंसियां अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण का प्रबंधन करती हैं और इसके बाद बचे अधिशेष अनाज को केंद्रीय पूल के लिए FCI को सौंप देती हैं।

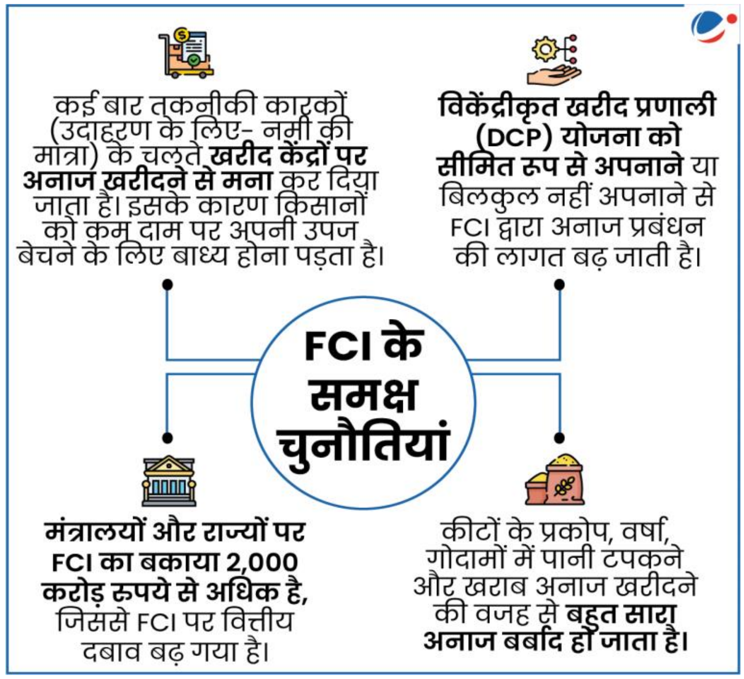

FCI की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए की गई पहलें

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) पहल: "एक राष्ट्र, एक MSP"** के तहत सरकार किसानों से खरीदे गए अनाज का मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन भेज रही है।
- **भंडारण केंद्रों का आधुनिकीकरण:** FCI में अनाज के भंडारण के लिए पहले **कवर एंड प्लिंथ** भंडारण तकनीक का उपयोग होता था। **2014** में इसकी भंडारण क्षमता **30.25 लाख मीट्रिक टन (LMT)** थी। अब इस विधि की जगह वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित **भंडारण डिपो** और **साइलो विधि** को अपनाया जा रहा है।
- **स्टील साइलो:** वर्तमान में 22.75 LMT क्षमता के स्टील साइलो कार्य कर रहे हैं। अतिरिक्त **41 LMT** क्षमता के स्टील साइलो का निर्माण किया जा रहा है।
- **डिजिटल सुधार:** इसके तहत निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:
  - o आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस **आधारित वीडियो निगरानी,**
  - o अनाजों के स्रोत से वितरण स्थल की समस्त आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन के लिए **अन्न दर्पण पोर्टल,**
  - o **व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, आदि**

निष्कर्ष

भारत में खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने में भारतीय खाद्य निगम (FCI) की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। डिजिटल निगरानी, वैज्ञानिक तरीके से भंडारण और विकेंद्रीकृत खरीद जैसे सुधारों के साथ-साथ पूंजी निवेश में बढ़ोतरी से FCI देश की बदलती खाद्य वितरण आवश्यकताओं के प्रति अब और अधिक कुशल, पारदर्शी एवं अनुकूल बनने के लिए तैयार है।

7.7.2.1. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) {Public Distribution System (PDS) in India}

सुर्ख़ियों में क्यों?

ICRIER ने "भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को युक्तिसंगत बनाना[33]" शीर्षक से पॉलिसी ब्रीफ जारी किया।

PDS के बारे में

- यह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक खाद्य सुरक्षा प्रणाली है।
- इसमें उचित मूल्य की दुकानें (FPSs) शामिल हैं, जिन्हें समाज के जरूरतमंद वर्गों को बहुत सस्ते दामों पर बुनियादी खाद्य और गैर-खाद्य वस्तुओं को वितरित करने का काम सौंपा गया है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन केन्द्र और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी** के तहत किया जाता है।

पॉलिसी ब्रीफ के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **PDS लीकेज:** भारतीय खाद्य निगम (FCI) और राज्य सरकारों द्वारा आपूर्ति किया गया **28% आवंटित अनाज वास्तविक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच** पाता है।
  - o इससे लगभग **69,108 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान** हुआ है।

[33] Rationalising the Public Distribution System (PDS) in India

- **हालिया सुधारों का प्रभाव:** राशन कार्ड को **आधार नंबर से जोड़ने** और 95% **उचित मूल्य की दुकानों (FPS) पर पॉइंट ऑफ सेल (PoS)** मशीनों की उपलब्धता से अनाज वितरण में दक्षता बढ़ी है। हालांकि, अभी भी **लीकेज पूरी तरह खत्म नहीं** हुई है।
- **अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग स्थिति: बिहार और पश्चिम बंगाल** जैसे राज्यों ने PDS लीकेज को कम करने में अधिक सुधार दर्ज किए हैं। वहीं, **अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों और गुजरात में उच्च लीकेज** की स्थिति बनी हुई है।
    - विशेष रूप से **पूर्वोत्तर राज्यों में PDS का डिजिटलीकरण नहीं होने** की वजह से उच्च लीकेज जारी है।

मुख्य सिफारिशें

- **वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करना:** वर्तमान में देश की **लगभग 57% आबादी को PDS के तहत मुफ्त अनाज** वितरित किया जा रहा है। इसके बदले में **सबसे गरीब 15% लाभार्थियों को मुफ्त अनाज** देना चाहिए। शेष लाभार्थियों को **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की 50% की दर** से खाद्यान्न वितरित करना चाहिए।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का विस्तार करना चाहिए। इसके निम्नलिखित लाभ हैं:**
    - DBT अनाज के लीकेज को कम करता है,
    - यह प्रशासनिक लागत को कम करता है और
    - यह नागरिकों को अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार आहार चुनने में सशक्त बनाता है।
- **उचित मूल्य की दुकानों (FPS) को पोषण केंद्रों में बदलना:** अनाज की हेराफेरी की समस्या से निपटने के लिए **चुनिंदा FPS में फ़ूड कूपन** जारी करने की व्यवस्था लागू की जा सकती है।

निष्कर्ष

अध्ययन से पता चलता है कि सुधारों के बावजूद PDS में लीकेज की समस्या अब भी बनी हुई है। इसे ठीक करने के लिए अब लक्षित कवरेज, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), और पोषण-केंद्रित उचित मूल्य की दुकानों की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। इससे प्रणाली की दक्षता बढ़ेगी, नुकसान कम होंगे और खाद्य सुरक्षा बेहतर होगी।

7.7.3. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक: एक नज़र में (Food Processing Sector at a Glance)

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की स्थिति

यह एक **सनराइज सेक्टर** है। इसका चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 7.3% (वित्त वर्ष 2015-2022) है। इसका योगदान 2020-21 में विनिर्माण GVA में 10.54% और कृषि GVA में 11.57% था।	2021-22 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में **20.68 लाख कर्मचारी कार्य कर रहे थे।**	देश भर में स्वीकृत 41 में से **24 मेगा फूड पार्क कार्य कर रहे हैं।**	**कृषि-निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी 2023-24 में बढ़कर 23.4% हो गई।**

खाद्य प्रसंस्करण का महत्त्व

कृषि को उद्योग जगत से जोड़ना: खेत और बाजार पहुंच के बीच की खाई को पाटना, कृषि को अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना।	प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के माध्यम से **कृषि-निर्यात आधारित आय में वृद्धि,** व्यापार संतुलन में सुधार।	**मूल्य वर्धन:** फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करता है और कृषि उपज के मूल्य को बढ़ाता है।	**ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है:** निर्यात में वृद्धि के जरिए उच्च कृषि आय सुनिश्चित करके।	**रोजगार:** ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और अकुशल श्रमिकों सहित बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करता है।

योजनाएं/ पहलें

पी.एम. किसान संपदा योजना: मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य वर्धन अवसंरचना के विकास के लिए।	प्रधान मंत्री- सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना (PM-FME)	चयनित उत्पादों में SME को अपग्रेड करने के लिए PM-FME के तहत **एक जिला एक उत्पाद पहल आरंभ की गई है।**	कृषि आधारित प्रसंस्करण में **100% FDI की अनुमति,** और कृषि निर्यात नीति-2018 जारी की गई, आदि।	माल ढुलाई दरों में कमी लाने के लिए **कृषि उड़ान और कृषि रेल योजनाएं।**

बाधाएं

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का अनौपचारिक रूप; कच्चे माल की प्राप्ति में व्याप्त बाधाएं, आदि।	**दक्ष आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना की कमी,** लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियां और **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का अभाव।**	**शुरूआत में अधिक पूंजी की आवश्यकता;** बेहतर सटीकता वाले और ऑटोमेटेड उपकरणों की कम उपलब्धता।	**ऋण प्राप्त करने में परेशानी, नौकरशाही संबंधी बाधाएं और कड़े श्रम कानून।**	**बेहतर गुणवत्ता-नियंत्रण एवं परीक्षण अवसंरचना की कमी के कारण कीट संक्रमण, फसल में रासायनिक अवशेष रह जाने जैसी समस्याएं।**

आगे की राह

नीति: श्रम और खाद्य सुरक्षा कानूनों तथा पैकेजिंग मानकों को कारगर बनाना।	**वित्तीय:** खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने के लिए उचित कर प्रोत्साहन तथा कर-छूट प्रदान करना।	**आधारभूत संरचना:** किसान-उत्पादक-निवेशक -अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के लिंकेज के माध्यम से **आपूर्ति पक्ष और बुनियादी ढांचे संबंधी बाधाओं को दूर करना।**	निर्वाह कृषि की बजाय खाद्य प्रसंस्करण आधारित बाजार-उन्मुख कृषि को अपनाना।	बाजार की मांग के आधार पर किसानों और फ़ूड-प्रोसेसिंग उद्योग के बीच **बेहतर तालमेल को बढ़ावा देना।**

7.8. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
खाद्य सुरक्षा	कृषि उत्पादकता	न्यूनतम समर्थन मूल्य	कृषि ऋण	किसान क्रेडिट कार्ड
संगठित विपणन श्रृंखलाएं	विदेशी मुद्रा भंडार	वैश्विक बाजार	फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान	लघु और सीमांत किसान
दक्ष आपूर्ति श्रृंखला	छोटी भूमि जोत	कृषि मशीनीकरण	बफर स्टॉक	सार्वजनिक वितरण प्रणाली

7.9. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

हालांकि भारत की डेयरी सहकारिताओं ने किसानों को सशक्त बनाने में सफलता प्राप्त की है, फिर भी वे कई संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इन चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उपाय सुझाइए।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
डेयरी सहकारी समितियों का परिचय दीजिए	संरचनात्मक चुनौतियां	उपाय	निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए

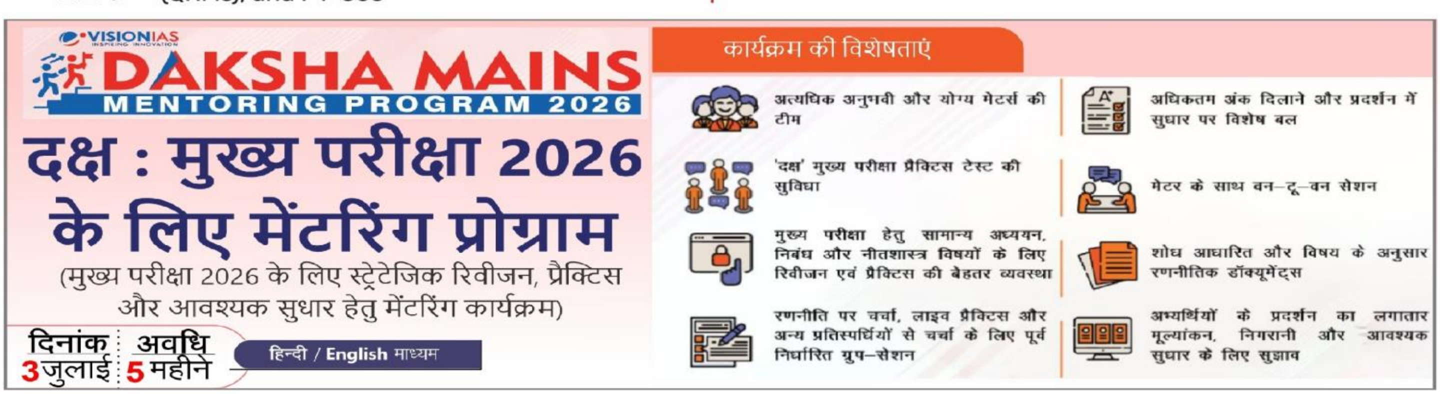

8. उद्योग एवं औद्योगिक नीति (Industry and Industrial Policy)

8.1. मेक इन इंडिया के 10 वर्ष (10 Years of Make in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

"मेक इन इंडिया" पहल के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। गौरतलब है कि **मेक इन इंडिया** पहल की शुरुआत 25 सितंबर, 2014 को हुई थी।

"मेक इन इंडिया" के बारे में

- **उद्देश्य:** इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत को विश्व का प्रमुख डिजाइन और विनिर्माण केंद्र बनाना है।
- **अन्य उद्देश्य:**
  - भारतीय उद्योग की **संवृद्धि दर को बढ़ाकर प्रति वर्ष 12-14%** तक करना।
  - **2022 तक औद्योगिक क्षेत्रकों में 100 मिलियन रोजगार के अवसर** सृजित करना।
  - 2022 तक भारत के **सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25%** करना। अब इसे संशोधित करके 2025 तक कर दिया गया है।

"मेक इन इंडिया" के तहत प्रमुख उपलब्धियां

- **भारत की नई विनिर्माण क्षमता:** भारत प्रतिवर्ष 400 मिलियन खिलौने बना रहा है और यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश बना गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माता देश बन गया है और अब 99% मोबाइल देश में ही विनिर्मित होते हैं।
- **विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट** में भारत 2014 में 142वें स्थान पर था। 2019 में भारत 63वें स्थान पर आ गया, जो सुधारों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
- **भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिला:** एशियाई देशों में भारत में कर की दरें सबसे कम हैं, त्वरित अनुमोदन आदि के लिए राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम से प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई।
- **उच्च-मूल्य वाले विनिर्माण और अनुसंधान एवं विकास को प्राथमिकता देना:** इसके परिणामस्वरूप, 2015 से वैश्विक नवाचार सूचकांक (ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स) में भारत की रैंकिंग में 42 स्थानों का सुधार हुआ है।
- **अन्य: बढ़ता रक्षा निर्यात, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह में वृद्धि, संधारणीय विकास की ओर उठाया गया कदम** (राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन), आदि

कृषि से सेवा क्षेत्रक की ओर बदलाव के निहितार्थ या प्रभाव

- **आर्थिक संवृद्धि:** कृषि और विनिर्माण की तुलना में सेवा क्षेत्रक ने सकल घरेलू उत्पाद में काफी अधिक योगदान दिया है।
  - वर्तमान मूल्यों पर कुल GVA में इसका योगदान वित्त वर्ष 2014 में 50.6% था, जो बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में लगभग 55% हो गया है (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)।
- **रोजगार का पैटर्न:** जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि क्षेत्रक में कार्यरत है, जबकि यह GDP में तुलनात्मक रूप से कम योगदान देता है।
- **क्षेत्रीय संकेन्द्रण:** सेवा क्षेत्रक द्वारा संचालित विकास कुछ राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि में अधिक केंद्रित है।
- **प्रीमैच्युर डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन:** अधिकांश देश कृषि से विनिर्माण और फिर सेवा क्षेत्रक की ओर अग्रसर हुए, वहीं भारत ने बड़े पैमाने पर विनिर्माण चरण को नजरअंदाज कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन कम हुआ है।

"मेक इन इंडिया" से जुड़ी चिंताएं

- **GDP में विनिर्माण क्षेत्रक की 25% हिस्सेदारी का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ:** इस योजना के बावजूद, GDP में विनिर्माण क्षेत्रक की हिस्सेदारी **2023 में 17.7%** पर स्थिर रही।
- **विनिर्माण क्षेत्रक में रोजगार के अवसरों में कमी:** विनिर्माण क्षेत्रक में श्रमबल **2017 के 51 मिलियन से घटकर 2023 में 35 मिलियन** हो गया।

- **वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (GVA) में गिरावट:** राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (NAS) के अनुसार, विनिर्माण क्षेत्रक की वास्तविक GVA वृद्धि दर **2012 के लगभग 8% से घटकर 2023 में 5.5% रह गई।**
- **निवेश दरों में गिरावट:** भारत की उत्पादक निवेश दर (सकल पूंजी निर्माण) में कमी हुई है। यह 2008 के 39.1% से घटकर 2023 में 32.2% रह गई।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में गिरावट:** 2017 के बाद से लगभग 70% FDI **केवल 9 क्षेत्रकों (विशेषकर IT सेवाएं), में केंद्रित** रहा है, जबकि अन्य **53 क्षेत्रकों (अधिकांशतः विनिर्माण) को कुल FDI का केवल 30% प्राप्त हुआ है।**
- **निर्यात प्रदर्शन में गिरावट:** कुल मात्रा के आधार पर अधिक FDI आने के बावजूद भारत के पण्य (मर्केंटाइल) निर्यात में सापेक्ष रूप से गिरावट दर्ज हुई है। यह **2013-14 में GDP का लगभग 10% था, जो 2022-23 में घटकर लगभग 8% रह गया।**

मेक इन इंडिया को सक्षम बनाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम					
उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाएं	GST लागू करने जैसे कर सुधार	पी.एम. गति शक्ति	स्टार्ट-अप इंडिया	राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (2022)	**अन्य:** सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकास, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम, आदि

आगे की राह

- **क्षमता में सुधार:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीकों को अपनाकर, श्रम बल को तेजी से कौशल प्रदान करके क्षमताओं में सुधार किया जा सकता है।
- **उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करना और नवाचार हेतु अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना:**
  - ज्ञान को संपदा में बदलने के लिए शैक्षिक जगत, उद्योग जगत और सरकार के बीच सहयोग का एक ट्रिपल हेलिक्स मॉडल आवश्यक है। जैसे- **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF)**
  - नए विचारों और नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए देश के लोकतांत्रिक मूल्य का लाभ उठाना चाहिए।
  - **देश के सबल पक्षों का उपयोग करना जैसे-** सेवाओं और विनिर्माण-संबंधित सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना आसान है।

निष्कर्ष

आज "मेक इन इंडिया" पहल अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रही है। यह भारत के अपने विनिर्माण क्षेत्रक को नई दिशा देने और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।

8.2. MSME क्षेत्रक: एक नज़र में (MSME Sector at a Glance)

MSME क्षेत्रक

वर्गीकरण

सूक्ष्म उद्यम	लघु उद्यम	मध्यम उद्यम
➤ निवेश सीमा 2.5 करोड़ रुपये तक और ➤ टर्नओवर सीमा 10 करोड़ रुपये तक।	➤ निवेश सीमा 25 करोड़ रुपये तक और ➤ टर्नओवर सीमा 100 करोड़ रुपये तक।	➤ निवेश सीमा 125 करोड़ रुपये तक और ➤ टर्नओवर सीमा 500 करोड़ रुपये तक।

भारत के लिए MSMEs का महत्व

योगदान: सकल घरेलू उत्पाद में 30% और कुल निर्यात में लगभग 45% तक।	**विनिर्माण में योगदान: 36% तक।**	**रोजगार: लगभग 7.5 करोड़ लोग।**	**अन्य:** ये क्षेत्रक छिपी हुई बेरोजगारी को कम करते हैं; ग्रामीण विकास (ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 50% MSMEs) में योगदान देते हैं आदि।

MSMEs के समक्ष चुनौतियां

वित्तीय समस्याएं: अधिकतर MSMEs की अनौपचारिक प्रकृति हैं।	**अवसंरचना संबंधी समस्याएं:** खराब सड़कें, अनियमित बिजली आपूर्ति और डिजिटल सुविधाओं की कमी के कारण MSMEs के लिए व्यवसाय करना मुश्किल हो जाता है।	**भुगतान प्राप्ति में देरी:** नकदी प्रवाह और कार्यशील पूंजी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।	**विनियामक और अनुपालन संबंधी बोझ:** जटिल कराधान, श्रम कानून और नीतिगत परिवर्तन।	**व्यवसाय विस्तार नहीं:** MSMEs समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाते हैं और लघु श्रेणी में ही रहते हैं।

शुरू की गई पहलें

व्यापार सक्षमता और विपणन (TEAM) पहल	**पी.एम. विश्वकर्मा**	**आत्मनिर्भर भारत निधि योजना**	**राइजिंग एंड एक्सीलेरेटेड MSME प्रोडक्टिविटी (RAMP)" योजना**	**अन्य:** MSMEs के लिए डिजिटल फुटप्रिंट-आधारित ऋण; सहायता मंच; सार्वजनिक खरीद नीति आदि।

आगे की राह

नीतिगत समर्थन जैसे कर में छूट	**ऋण उपलब्धता सुनिश्चित** करना	**बाजार तक पहुंच और विस्तार** जैसे B2B नेटवर्किंग के लिए प्लेटफॉर्म्स तैयार करना	**विनियामक फ्रेमवर्क का सरलीकरण** जैसे अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।	**अन्य:** वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण; तकनीक को अपनाना और डिजिटलीकरण आदि।

8.3. राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (National Industrial Corridor Development Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत **12 नए औद्योगिक नोड्स/ शहरों को मंजूरी** दी है। नए औद्योगिक शहरों का विकास **'प्लग-एंड-प्ले'** और **'वॉक-टू-वर्क'** की अवधारणाओं के आधार पर विकसित किया जाएगा।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के बारे में

- राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2007 में दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) के शुभारंभ के साथ हुई थी।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य **नए औद्योगिक शहरों को "स्मार्ट सिटी" के रूप में विकसित करना है।**
- इन औद्योगिक गलियारों को विनिर्माण क्षेत्रक में **विकास को गति देने** और **व्यवस्थित शहरीकरण** को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।

औद्योगिक शहरों का महत्व

- **निवेश आकर्षित करना:** NICDP का उद्देश्य परिवर्तनशील **औद्योगिक इकोसिस्टम का विकास** करना है।
- **स्मार्ट शहर और आधुनिक अवसंरचना:** NICDP के तहत ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसमें संधारणीय और दक्षता-पूर्वक संचालन के लिए अत्याधुनिक अवसंरचनाओं का उपयोग किया जाएगा।
- **कनेक्टिविटी और परिवहन में सुधार:** ये परियोजनाएं **पी.एम. गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान** के साथ मेल खाती हैं, इन्हें **मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी** अवसंरचना को एकीकृत किया जाएगा। इनमें औद्योगिक शहर **'विकास केंद्र यानी ग्रोथ सेंटर'** के रूप में काम करेंगे।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं:** NICDP औद्योगिक गतिविधियों के लिए **विकसित भूखंड उपलब्ध कराएगा ताकि इनपर औद्योगिक गतिविधियां तत्काल शुरू** हो सके।

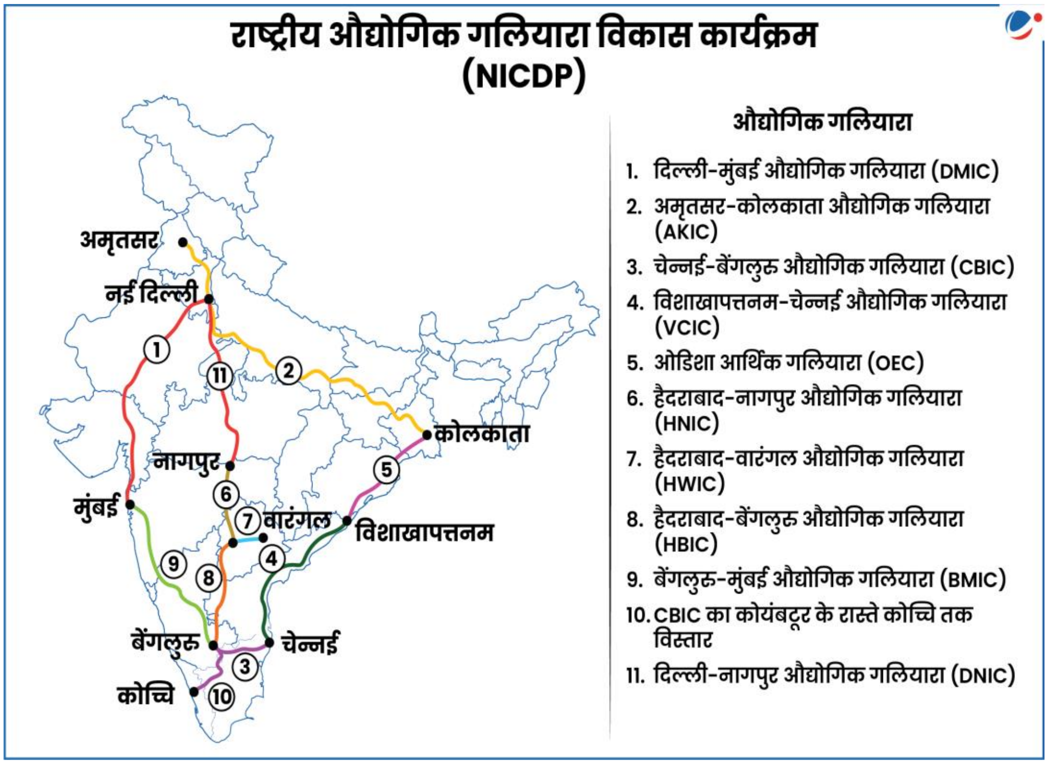

- **रोजगार सृजन:** एक अनुमान के अनुसार, इस कार्यक्रम से 10 लाख प्रत्यक्ष और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।

औद्योगिक गलियारों के विकास में मौजूद चुनौतियां

- **गवर्नेंस संबंधी मुद्दे:**
  - **नियोजन संबंधी खामी:** नियोजन में स्थानीय सरकार की न्यूनतम भागीदारी।
  - **क्षेत्राधिकार को लेकर संशय:** स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) और स्थानीय निकायों के मध्य।
    - उदाहरण के लिए- **तुमकुरु औद्योगिक टाउनशिप लिमिटेड** नामक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) स्थानीय पंचायतों, नगर निगमों या नगर नियोजन विभाग से स्वतंत्र होकर काम करता है।
- **संस्थागत क्षमता:** नए शहरों के उभरने और पूरी तरह विकसित होने में **लंबा समय** लगता है। शहरी **कर्मचारियों में क्षमता और प्रशिक्षण की कमी है।**
- **भूमि अधिग्रहण:** इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट-2009 के अनुसार, अवसंरचना और विकास संबंधी अन्य गतिविधियों में 70 प्रतिशत देरी की वजह **भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं** रही हैं।
- **अन्य:** कृषि भूमि का गैर-कृषि कार्यों में उपयोग के लिए भूमि का हस्तांतरण,पर्यावरण संबंधी चिंताएं **आदि**।

आगे की राह

- स्थान-विशेष की चुनौतियों का समाधान करने के लिए **नियोजन प्रक्रियाओं में स्थानीय प्राधिकरणों और समुदायों को शामिल** करना चाहिए।
- स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPVs) और औद्योगिक हितधारकों सहित सरकार एवं अन्य भागीदारों के बीच **समन्वय स्थापित करने का प्रयास** करना चाहिए।
- भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए किसानों को **परियोजनाओं के आस-पास लघु भूखंड आवंटित करना चाहिए** ताकि उन्हें भी इन परियोजनाओं से लाभ मिल सके।
- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए **एक मजबूत फ्रेमवर्क स्थापित करना** चाहिए। इससे **औद्योगिक गलियारों के लिए बेहतर योजना** बनाई जा सकेगी।
- परियोजना प्रबंधन और निगरानी हेतु **एडवांस प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने** से दक्षता में सुधार होगा, लागत में कमी आएगी।

© Vision IAS

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम भारत के औद्योगिक और शहरी विकास में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम है। इसका उद्देश्य स्मार्ट, संधारणीय और निवेश के लिए तैयार शहरों का विकास करना है। यह पहल रोजगार सृजन और आर्थिक विकास की वृहद् संभावनाएं रखती है। हालांकि, इसकी सफलता और दीर्घकालिक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए शासन व्यवस्था (गवर्नेंस), भूमि अधिग्रहण और संस्थागत क्षमता जैसी चुनौतियों का समाधान करना बहुत जरूरी होगा।

8.4. इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना: एक नज़र में (Electronics Component Manufacturing Scheme at a Glance)

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना

योजना के बारे में

मंत्रालय: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)	**उद्देश्य:** घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़कर **इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण को बढ़ावा देना।**	**राजकोषीय प्रोत्साहन:** टर्नओवर-लिंक्ड, कैपेक्स (पूंजीगत व्यय)-लिंक्ड, तथा दोनों का हाइब्रिड प्रोत्साहन।	**पात्रता:** ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड निवेश

भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटक क्षेत्रक का महत्त्व

आर्थिक क्षमता: 2030 तक 500 बिलियन डॉलर। **निर्यात वृद्धि:** वित्त वर्ष 2015 से 20% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)	**राष्ट्रीय सुरक्षा:** उदाहरण के लिए- सैन्य हार्डवेयर हेतु अमेरिका के साथ पहला राष्ट्रीय **सुरक्षा चिप संयंत्र** स्थापित किया जाएगा।	**तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना:** जैसे रिमोट सर्जरी, ऑटोनोमस वाहन आदि।	**भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक:** › वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में 4% की हिस्सेदारी। › घरेलू उत्पादन: 9.52 लाख करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2024)।

इलेक्ट्रॉनिक घटक क्षेत्रक द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

विनिर्माण की उच्च लागत: टैरिफ और सामग्री लागत के कारण चीन की तुलना में घटकों के मामले में 4%-5% का आर्थिक नुकसान होता है।	**अनुसंधान एवं विकास और डिजाइन इकोसिस्टम की कमी:** भारत अनुसंधान एवं विकास पर GDP का 1% से भी कम खर्च करता है।	**वैश्विक मांग तक पहुँच की कमी:** प्रमुख वैश्विक ब्रांड्स इलेक्ट्रॉनिक बाजार के 80% हिस्से पर नियंत्रण रखते हैं।	**महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर भारी निर्भरता:** इससे यह क्षेत्रक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रति सुभेद्य बन जाता है।	**लंबी जेस्टेशन अवधि:** निवेश और उत्पादन के बीच 1-2 वर्ष की जेस्टेशन अवधि होती है।

शुरू की गई पहलें

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)	**चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम**	**IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना 2.0**	**बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (LSEM) के लिए PLI योजना**	**इलेक्ट्रॉनिक्स पर राष्ट्रीय नीति 2019**

आगे की राह

विनिर्माण को बढ़ाने के लिए **परिचालन व्यय समर्थन** जैसे राजकोषीय प्रोत्साहन।	प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए **इनपुट पर टैरिफ/ शुल्कों को युक्तिसंगत बनाना।**	शीघ्र वीज़ा अनुमोदन के माध्यम से **उच्च स्तरीय विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करना।**	**शिक्षा जगत और उद्योग जगत के बीच सहयोग** को बढ़ावा देना	**अन्य:** बड़े क्लस्टर विकसित करना, अनुसंधान एवं विकास (वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का <1%) को बढ़ाना आदि।

8.4.1. भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्रक (Semiconductor Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में **पांचवीं सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी** दी। यह इकाई **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM)** के तहत स्वीकृत की गई है और इसे **गुजरात के साणंद** में स्थापित किया जाएगा।

भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण के विकास पर क्यों ध्यान केंद्रित कर रहा है?

- **आयात पर निर्भरता को कम करना:** उदाहरण के लिए, 2019 में भारत से सेमीकंडक्टर निर्यात का मूल्य 0.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि आयात मूल्य 4.65 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- **भू-राजनीतिक कारण:** चीन-ताइवान तनाव के कारण वैश्विक चिप आपूर्ति संकट में है, तथा अमेरिका-चीन चिप युद्ध और रूस-यूक्रेन संघर्ष से सेमीकंडक्टरों के लिए महत्वपूर्ण निऑन आपूर्ति बाधित हो रही है।
- **सुरक्षा को मजबूत करना:** रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधीकरण लाना:** विश्व का लगभग 70% सेमीकंडक्टर विनिर्माण पांच देशों (दक्षिण कोरिया, ताइवान, चीन, अमेरिका और जापान) में केंद्रित है।
- **आर्थिक गुणक प्रभाव:** इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में लगाया गया प्रत्येक डॉलर व्यापक रूप से अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त 1.32 डॉलर का सृजन करता है।

सेमीकंडक्टर क्षेत्रक में भारत के समक्ष क्या चुनौतियां मौजूद हैं?

- **उच्च पूंजीगत लागत और प्रतिफल मिलने में लगाने वाला अधिक समय**: यह अर्धचालक विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना में देखने को मिलता है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** भारत को चीन और **चिप 4 अलायंस** (अमेरिका, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया) से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।
- **श्रम-गहन नहीं:** इससे प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10,000-15,000 नौकरियां ही सृजित होंगी।
- **अवसंरचना की कमी:** चिप विनिर्माण संयंत्रों को स्वच्छ कक्ष संबंधी सुविधाओं, निर्बाध बिजली आपूर्ति आदि की आवश्यकता होती है।

इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- **इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM):**
  - **परिचय:** यह MeitY के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक विशेष व्यवसाय प्रभाग है।
  - **उद्देश्य:** भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और डिजाइन के लिए वैश्विक केंद्र बनाने हेतु एक सक्षम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण करना।
  - यह सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के तहत स्वीकृत योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है।
- **सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के बारे में**
  - इसका उद्देश्य **कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना** है।

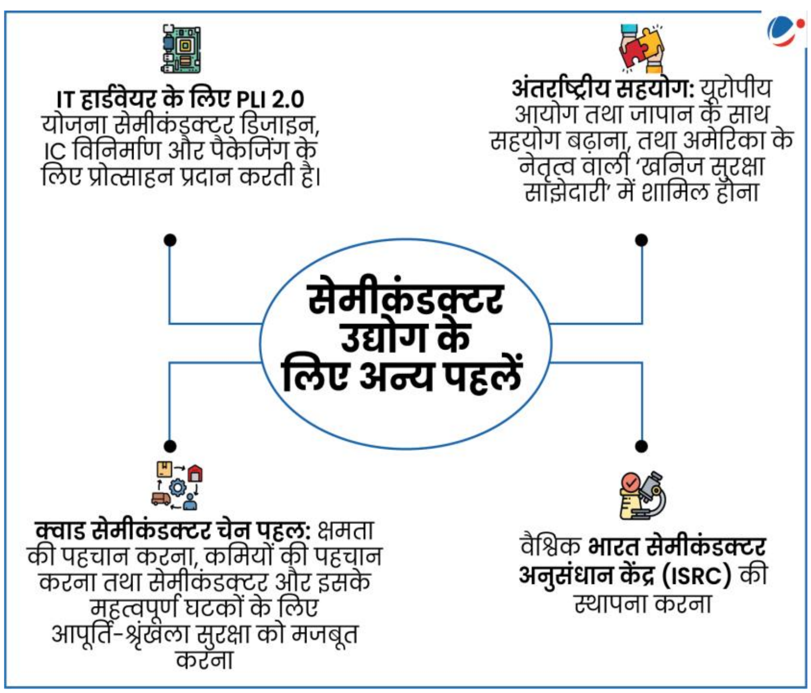

निष्कर्ष

लगातार प्रयासों और सक्रिय नीतियों के साथ, भारत तेजी से एक प्रमुख सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो देश की तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास में बड़ा योगदान देगा।

VISION IAS INSPIRING INNOVATION
UPSC के लिए करेंट अफेयर्स की समग्र तैयारी हेतु एकमात्र समाधान
Digital Current Affairs 2.0
मुख्य विशेषताएं: विजन इंटेलिजेंस, डेली प्रैक्टिस, डेली न्यूज समरी, स्टूडेंट डैशबोर्ड, क्विक नोट्स और हाइलाइट्स, संधान तक पहुंच की सुविधा
QR कोड स्कैन करें

8.5. भारत की जैव अर्थव्यवस्था: एक नज़र में (India's Bioeconomy at a Glance)

भारत की जैव अर्थव्यवस्था

भारत की विकास यात्रा में जैव अर्थव्यवस्था का महत्व

आर्थिक संवृद्धि: वर्ष 2050 तक इसके वैश्विक GDP के 12% तक पहुंचने की उम्मीद है।	**खाद्य सुरक्षा:** अनुवांशिक रूप से संशोधित तकनीक ने फसल की पैदावार में 21% की वृद्धि की है।	**रोजगार के अवसर:** एक अनुमान के अनुसार 2030 तक जैव अर्थव्यवस्था से 35 मिलियन रोजगार सृजित होंगे।	**स्वास्थ्य देखभाल:** नई दवाओं, टीकों आदि का विकास संभव हुआ है।	**पर्यावरणीय लाभ:** चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा; पर्यावरण प्रदूषण में कमी; जैव विविधता का संरक्षण; पारिस्थितिकी का पुनरुद्धार (Eco-restoration); आदि।

चुनौतियां

विनियामकीय चुनौतियां: भारत में विनियामक परिदृश्य बहुत बिखरा हुआ है। इसके अलावा, विभिन्न भारतीय राज्यों में **जटिल और अलग-अलग विनियम,** परिचालन संबंधी बाधाएं उत्पन्न करते हैं।	**वित्त-पोषण संबंधी मुद्दे:** उच्च अग्रिम लागत और रिटर्न प्राप्त होने में लगने वाला अधिक समय।	**बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण** से जुड़े मुद्दे और बायोपायरेसी की समस्या।	**विस्तार की सीमित क्षमता:** ऐसा शैक्षणिक और उद्योग जगत के मध्य सीमित जुड़ाव के कारण है।	**अन्य:** आपूर्ति श्रृंखला संबंधी मुद्दे और वैश्विक स्तर पर बहुत अधिक **प्रतिस्पर्धा;** जैव विविधता और भूमि उपयोग पर संभावित प्रभाव; आदि।

जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत में शुरू की गई विभिन्न पहलें

नीति निर्माण: BioE3 नीति; क्षेत्रक विशेष नीतिगत पहलें, जैसे- राष्ट्रीय जैव-अर्थव्यवस्था मिशन, 2016; राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति (2020-2025) का ड्राफ्ट आदि।	**योजनाएं और पहलें: बायो-राइड (Bio- RIDE) योजना; बायोटेक विज्ञान क्लस्टर; वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन;** राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन; फार्मास्यूटिकल्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना; आदि।	**गवर्नेंस एवं विनियामक पहलें:** BRIC; BioRRAP; बौद्धिक संपदा (IP) दिशा-निर्देश, 2023; आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड कीटों के लिए दिशा-निर्देश, 2023; आदि।	**क्षेत्रीय पहलें:** उत्तर प्रदेश फार्मास्युटिकल और मेडिकल डिवाइसेज़ उद्योग नीति 2023; तमिलनाडु की इथेनॉल मिश्रण नीति; आदि।

आगे की राह

विनियामकीय फ्रेमवर्क को अपडेट करना: विनियामकीय सुधार और वैश्विक मानकों के अनुरूप रणनीतिक सुधार।	***अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:*** वैश्विक बायोटेक हब एवं कंपनियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना।	**सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** वित्त-पोषण के स्रोतों को बढ़ाने और इसमें विविधता लाने के लिए।	**अनुसंधान के लिए नए साझेदारी केंद्र (PaCeR)**	**स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देना:** नए और उभरते क्षेत्रों तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में।

8.6. तकनीकी वस्त्र: एक नज़र में (Technical Textiles at a Glance)

तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles)

तकनीकी वस्त्र के बारे में

तकनीकी वस्त्र: इन वस्त्र उत्पादों का उपयोग उनके तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के कारण किया जाता है।	इनका उपयोग **कृषि, सड़क, रेलवे ट्रैक, खेलकूद परिधान, स्वास्थ्य क्षेत्रक** आदि में किया जाता है।	भारतीय तकनीकी वस्त्र बाजार **विश्व में पांचवां सबसे बड़ा बाजार** है।	वर्ष 2021-22 में इस क्षेत्रक में **28.4 प्रतिशत की निर्यात वृद्धि** दर्ज की गई थी।

तकनीकी वस्त्रों का महत्व

उत्पादकता में वृद्धि: एग्रो टेक्सटाइल्स **बागवानी कृषि की उत्पादकता में 2-5 गुना तक की वृद्धि** करते हैं।	**पर्यावरण संरक्षण:** फ्लोर सीलिंग, एयर क्लीनिंग आदि में उपयोगी।	**आपदा प्रबंधन में सहायक: ऑस्ट्रिया** में, हिमस्खलन से उत्पन्न गाद को जलाशय में प्रवेश करने से रोकने के लिए जियोटेक अवरोधों का उपयोग किया जाता है।	**अन्य:** विस्तार करने की क्षमता से युक्त, उच्च वेतन वाले कार्यबल के सृजन की क्षमता, आदि।

सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM)	वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना	प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीज़न्स एंड अपैरल पार्क्स (PM- MITRA) योजना	एकीकृत वस्त्र पार्क्स योजना (SITP)	समर्थ (SAMARTH) योजना

आगे की राह

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि के लिए तकनीकी वस्त्रों में **संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा** देना चाहिए।	इनक्यूबेशन केंद्रों का निर्माण करके तथा उद्यमिता विकास को समर्थन देकर **स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा** देना चाहिए।	**भारतीय ब्रांड्स को वैश्विक चैम्पियंस** के रूप में विकसित करना चाहिए।	डिजाइनिंग, क्षमता निर्माण आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर आधारित उत्कृष्टता केंद्र** की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।	**अन्य:** जागरूकता सृजन, कौशल प्रदान करना एवं शिक्षा आदि।

8.7. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम	प्लग-एंड-प्ले और वॉक-टू-वर्क अवधारणा	स्मार्ट सिटी	पी.एम. गति शक्ति	भूमि अधिग्रहण संबंधी चुनौतियां
स्पेशल पर्पज व्हीकल	मेक इन इंडिया पहल	सेमीकंडक्टर विनिर्माण	इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन	वैश्विक मूल्य श्रृंखलाएं
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस	सकल पूंजी निर्माण	राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन	MSME क्षेत्रक	जैव अर्थव्यवस्था

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026
▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
DELHI : 15 जुलाई, 2 PM | JAIPUR : 24 जून | JODHPUR : 2 जुलाई
Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.
/visionias.upsc /c/VisionIASdelhi /c/VisionIASdelhi /t.me/s/VisionIAS_UPSC
DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 CONTACT: 8468022022, 9019066066
AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

© Vision IAS

8.8. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) भारत के विनिर्माण क्षेत्र को कैसे रूपांतरित करने का प्रयास करता है, इसका परीक्षण कीजिए। इसके कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिए और उन्हें दूर करने के लिए उपाय सुझाइए।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के बारे में परिचय दीजिए	मुख्य चुनौतियां	उपाय सुझाएँ	निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए

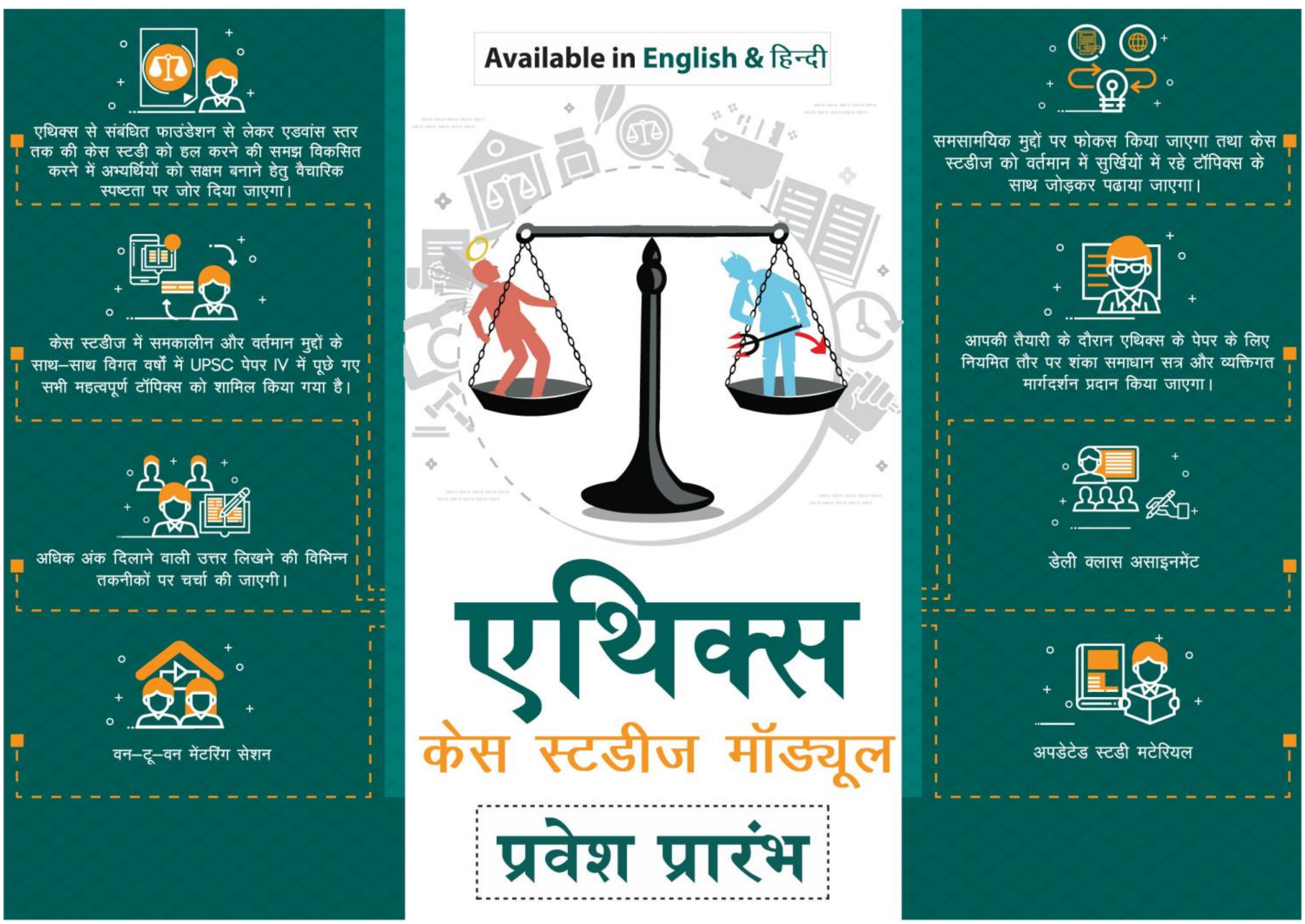

9. सेवा क्षेत्रक (Services)

9.1. भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था (India's Digital Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने **"भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकलन और माप[34]"** शीर्षक से एक व्यापक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है?

- इसमें आमतौर पर **सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) क्षेत्रक** को शामिल किया जाता है। इसमें **दूरसंचार, इंटरनेट, ICT सेवाएं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर** शामिल होते हैं। **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष** के अनुसार, इसमें पारंपरिक क्षेत्रकों के वे घटक भी शामिल हैं, जो **डिजिटल तकनीक** के साथ एकीकृत हो चुके हैं।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था (2022-23) का एक अवलोकन

स्थिति	योगदान	अनुमानित वृद्धि
› भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट-2024 के अनुसार- **भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटाइज़्ड** देश है। › व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के डिजिटाइजेशन स्तर के मामले में **भारत G-20 देशों में 12वें स्थान** पर है।	› भारत की **राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान।** › भारत की **GDP में 402 अरब डॉलर का योगदान।** › इसमें कुल 14.67 मिलियन कर्मी कार्यरत हैं। › वर्ष 2023 में भारत विश्व में **दूसरा सबसे बड़ा ICT सेवा निर्यातक** देश था।	› 2024-25 तक बढ़कर **13.42% की वृद्धि दर** अनुमानित है। › देश की अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी **कृषि और विनिर्माण क्षेत्रकों से अधिक हो जाने का अनुमान** है (छह वर्षों से कम समय में)। › **2029-30** तक इसकी **सकल मूल्य वर्धन (GVA) में हिस्सेदारी बढ़कर 20%** हो जाने का अनुमान है।

क्षेत्रकवार अनुमान

डिजिटल समर्थित उद्योग: सकल मूल्य वर्धन (GVA) में **7.83% का योगदान** (सबसे अधिक योगदान) › इसमें **सूचना और संचार सेवाएं** जैसे क्षेत्रक शामिल हैं।	**नवीन डिजिटल उद्योग:** इनका **GVA में 2%** का योगदान है। › इसमें शामिल हैं- **बिग टेक कंपनियां,** अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एवं इंटरमीडियरीज, तथा डिजिटल इंटरमीडियरीज पर निर्भर कंपनियां।	**अन्य** तीन परंपरागत उद्योगों **{बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (BFSI); व्यापार तथा शिक्षा}** का राष्ट्रीय GVA में 2% का योगदान है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौतियां

- **सभी के लिए स्वीकृत परिभाषा का अभाव:** डिजिटल तकनीक के एक-दूसरे से जुड़े और एकीकृत होने के कारण, **डिजिटल अर्थव्यवस्था की सटीक परिभाषा निर्धारित करना कठिन** हो जाता है।
- **साइबर हमले और साइबर अपराध:** उदाहरण: **डिजिटल अरेस्ट** और **साइबर स्लेवरी** जैसी नई चुनौतियां उभरकर आई हैं।
- **निजता का हनन और इससे जुड़ी चिंताएं:** उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग, **दुष्प्रचार, डिजिटल मोनोपोली** जैसी कई अन्य चिंताएं मौजूद हैं।
- **डिजिटल साक्षरता की कमी:** NSSO के मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे 2023 के अनुसार, 15-29 वर्ष के 70% भारतीय युवा ई-मेल के साथ फाइल अटैच नहीं कर पाते हैं।
- **अन्य चुनौतियां:** भारत में **सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण की वृद्धि दर धीमी है** और मोबाइल फोन विनिर्माण में देश में कम घटक जोड़े जाते हैं **(कम मूल्य संवर्धन)**।

[34] Estimation and Measurement of India's Digital Economy

© Vision IAS

निष्कर्ष

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से सेवा वितरण में आमूलचूल बदलाव ला रही है तथा निर्यात और नवाचार को बढ़ावा दे रही है। इसकी पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए भारत को विश्वसनीय डेटा संग्रह, सभी के लिए ब्रॉडबैंड सुविधा, डिजिटल कौशल और मजबूत साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

9.2. क्रिएटिव इकोनॉमी: एक नज़र में (Creative Economy at a Glance)

क्रिएटिव इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी

हाल ही में, मुंबई में भारत के पहले **वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स/ WAVES),** 2025 का उद्घाटन किया गया।

क्रिएटिव इकोनॉमी की विशेषताएं

ज्ञान आधारित आर्थिक गतिविधियां	इसमें बौद्धिक संपदा का सृजन और उपयोग शामिल है।	**बिना-दोहराव वाली तथा तकनीकी परिवर्तन और मशीनीकरण के अनुकूल होना।**	इसके तहत किसी व्यक्ति के मूल विचार को उत्पादन और वितरण के माध्यम से सांस्कृतिक उत्पाद के रूप में विकसित किया जाता है।

भारत में क्रिएटिव इकोनॉमी की स्थिति

GDP में योगदान: क्रिएटिव कारोबार का देश के **समग्र GVA में लगभग 20% का** योगदान है।	**निर्यात:** 2010 से 2019 तक क्रिएटिव गुड्स के निर्यात में **1.5 गुना वृद्धि हुई है।**	रोजगार: यह अब **लगभग 30 बिलियन डॉलर का उद्योग** बन गया है और **भारत की लगभग 8% कार्यशील आबादी** को रोजगार देता है।

क्रिएटिव इकोनॉमी का महत्व

आर्थिक पहलू: संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, क्रिएटिव इकोनॉमी से संबंधित उद्योग 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करते हैं। साथ ही, ये विश्व भर में रोजगार के लगभग 50 मिलियन अवसर प्रदान करते हैं।	**सामाजिक पहलू:** क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में कार्यरत 23% लोग 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के हैं। यह किसी भी अन्य क्षेत्रक की तुलना में अधिक है।	**क्रिएटिव इंडस्ट्रीज मुख्य रूप से पर्यावरण-अनुकूल होती है: क्योंकि क्रिएटिव गतिविधियों के लिए प्राथमिक इनपुट प्राकृतिक संसाधनों (जैसे- खनन, कृषि आदि) पर निर्भर होने की बजाय क्रिएटिविटी आधारित होते हैं।**

क्रिएटिव इकोनॉमी के विकास में बाधाएं

डिजिटलीकरण की चुनौतियां: जैसे डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा संबंधी चिंताएं	**ग्रामीण-शहरी विभाजन:** भारत में सभी क्रिएटिव वर्कर्स का **67.07% हिस्सा शहरी क्षेत्रों में है।**	**भारत की बौद्धिक संपदा व्यवस्था:** उदाहरण के लिए- भारत में पेटेंट आवेदन के निपटान में **औसतन 58 महीने** लगते हैं, जबकि **चीन में लगभग 20 महीने और संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 महीने** ही लगते हैं।	क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ का विखंडित (अलग-अलग) होना; बाजार तक उचित पहुंच और वितरण नहीं होना; **अपेक्षित मान्यता नहीं मिलना और जागरूकता की कमी** आदि।

क्रिएटिव इकोनॉमी को समर्थन देने हेतु पहलें

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति (2016), राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार आदि।	**यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क**	संयुक्त राष्ट्र ने **वर्ष 2021 को 'सतत विकास के लिए क्रिएटिव इकोनॉमी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष'** घोषित किया था।

आगे की राह

वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति की पहचान बढ़ानी चाहिए।	**यूरोपीय आयोग के "क्राउडफंडिंग4 कल्चर" (Crowdfunding4Culture) पोर्टल जैसे वैश्विक सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों को अपनाने की जरूरत है।**	**बौद्धिक संपदा अधिकार फ्रेमवर्क में सुधार करना चाहिए।**	**क्रिएटिव जिलों/ हब्स की स्थापना, क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए एक विशेष संस्था का गठन, आदि।**

9.3. भारत में पर्यटन क्षेत्रक: एक नज़र में (Tourism Sector in India at a Glance)

भारत में पर्यटन क्षेत्रक

भारत में पर्यटन क्षेत्रक की स्थिति

वर्ष 2023 में **18.89 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों** का आगमन हुआ था।	वर्ष 2023 के दौरान **9.52 मिलियन विदेशी पर्यटकों** का आगमन हुआ था।	**वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन के मामले में 24वां स्थान। (संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन बैरोमीटर)।**	विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित **यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 39 वां स्थान।**

भारत के लिए पर्यटन का महत्व

आर्थिक: वर्ष 2024 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग **6.8% का योगदान।**	**कूटनीतिक:** जैसे- योग और आयुर्वेद भारत की छवि को एक वेलनेस गंतव्य के रूप में बढ़ा रहे हैं।	**चिकित्सा पर्यटन:** › इसके **2026 तक 13.42 बिलियन डॉलर** तक पहुंचने का अनुमान है। › **ई-मेडिकल वीज़ा सूची में 170 से अधिक देश** सूचीबद्ध हैं।	**सांस्कृतिक:** › लुप्तप्राय कला का पुनरुद्धार, उदाहरण के लिए- **मधुबनी पेंटिंग।** › धरोहर संरक्षण, उदाहरण के लिए- **'एडॉप्ट ए हेरिटेज' योजना।** › राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, उदाहरण के लिए- **'देखो अपना देश' अभियान।'**

भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें

अवसंरचनाओं का विकास: स्वदेश दर्शन 2.0 योजना; प्रसाद (PRASHAD) योजना; RCS-उड़ान योजना आदि।	अभियान: अतुल्य भारत अभियान, देखो अपना देश, भारत भ्रमण वर्ष 2023, भारत पर्व 2024 आदि।	**PPP:** अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम, लग्ज़री ट्रेन (पैलेस ऑन व्हील्स) केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित 'हील इन इंडिया' पहल आदि।	**क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण:** हुनर से रोजगार तक, पर्यटकों को भाषा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम, आदि।	**विशिष्ट पर्यटन (Niche tourism):** इको-टूरिज्म (सुंदरबन), साहसिक पर्यटन (हिल स्टेशन), क्रूज़ पर्यटन (क्रूज़ भारत मिशन) आदि।

आगे की राह

कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाना: उदाहरणार्थ बहुभाषी साइनेज और वाई-फाई।	**विशिष्ट पर्यटन को बढ़ावा देना:** जैसे सिंगल-विंडो क्लीयरेंस की सुविधा प्रदान करना आदि।	**संधारणीय पर्यटन:** जैसे भूदृश्य क्षेत्रीकरण और भूमि उपयोग योजना।	**प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** योजना आदि के लिए AI-संचालित पर्यटन प्लेटफॉर्म्स विकसित करना।

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION
न्यूज़ टुडे
रोजाना 9 PM पर न्यूज टुडे वीडियो बुलेटिन देखिए
न्यूज टुडे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए
न्यूज़ टुडे क्विज़ के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए
अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची
"न्यूज टुडे" डेली करेंट अफेयर्स की एक संक्षिप्त प्रस्तुति है। इस डॉक्यूमेंट की मदद से न्यूज-पेपर को पढ़ना काफी आसान हो जाता है और इससे अभ्यर्थी दैनिक घटनाक्रमों के बारे में अपडेट भी रहते हैं। इससे अभ्यर्थियों को कई अन्य तरह के लाभ भी मिलते हैं, जैसे:
किसी भी न्यूज़ से जुड़े घटनाक्रमों के बारे मे बेहतर समझ विकसित करने के लिए
न्यूज पढ़ने का एक ऐसा नजरिया विकसित करने के लिए, जिससे अभ्यर्थी आसानी से समझ सकें हैं कि न्यूज पेपर्स में से कौन-सी न्यूज पढ़नी है
टेक्निकल टर्म्स और न्यूज़ से जुड़े जटिल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सरल समझ विकसित करने के लिए

9.4. भारत में बीमा क्षेत्रक: एक नज़र में (Insurance Sector in India at a Glance)

भारत में बीमा क्षेत्रक

मुख्य तथ्य

वर्तमान स्थिति: ➤ **विश्व स्तर पर 10वां सबसे बड़ा बीमा क्षेत्रक।** ➤ **जीवन बीमा सेगमेंट: >76% हिस्सेदारी।**	**संभावना:** 2032 तक **छठा सबसे बड़ा बीमा बाज़ार।** (स्विस री रिपोर्ट)	**बीमा पैठ: > 3.7% (2023-24)**	**बीमा घनत्व: 95 डॉलर (2023-24)**

बीमा क्षेत्रक पर स्थायी समिति की टिप्पणियां

सरकारी नीतियां: उच्च GST दर (18%) और TDS बीमा क्षेत्रक के विकास में बाधा डालते हैं।	**निजी क्षेत्रक:** बाजार हिस्सेदारी 48% (वित्त वर्ष 20) से बढ़कर 62.5% (वित्त वर्ष 23) हो गई।	**आपदा कवरेज की आवश्यकता:** प्राकृतिक आपदा की आवृत्ति के मामले में भारत विश्व में **तीसरे** स्थान पर है।	**अन्य: स्वास्थ्य बीमा में मिसिंग मिडिल; सार्वजनिक क्षेत्रक की बीमा कंपनियों में कम पूंजी संबंधी मुद्दे आदि।**

बीमा क्षेत्रक में FDI की सीमा में वृद्धि

बजट 2025: भारत में पूर्ण प्रीमियम निवेश करने वाली कंपनियों के लिए **FDI को बढ़ाकर 100%** किया गया है।	**FDI में वृद्धि: बीमा अधिनियम, LIC अधिनियम और IRDA अधिनियम में संशोधन** करना आवश्यक है।

समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें

सूक्ष्म बीमा: समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नए बीमा उत्पाद विकसित करने चाहिए। लघु बीमा कंपनी स्थापित करने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता जैसे उपाय किए जाने चाहिए आदि।	**आपदा-ग्रस्त क्षेत्रों में पैरामीट्रिक इंश्योरेंस:** सुभेद्य घरों के लिए सरकार समर्थित कवर; उदाहरण के लिए, फ्लोरिडा का बीमा मॉडल।	**समग्र लाइसेंसिंग (Composite Licensing):** बीमा कंपनियों को जीवन बीमा और अन्य बीमा उत्पादों दोनों की पेशकश करने की अनुमति देनी चाहिए।	**अन्य:** स्वास्थ्य बीमा के लिए GST कम करना चाहिए; सार्वजनिक क्षेत्रक की कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने चाहिए आदि।

9.5. अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था: एक नज़र में (Space Economy at a Glance)

अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

भारत में अंतरिक्ष क्षेत्रक

वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर	**वृद्धि की संभावना:** 2033 तक 44 बिलियन डॉलर होने की संभावना।	**निजी क्षेत्रक:** >200 अंतरिक्ष-आधारित स्टार्ट-अप्स

अंतरिक्ष आधारित तकनीक के क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली पहलें

भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023: यह सभी अंतरिक्ष क्षेत्रकों में गैर-सरकारी संस्थाओं को पूर्ण भागीदारी की अनुमति देती है।	**FDI नीति:** उपग्रह विनिर्माण/संचालन में 74% FDI, प्रक्षेपण यानों और स्पेस पोर्ट्स में 49% FDI की अनुमति।	**स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क:** स्टार्ट-अप्स तथा लघु और मध्यम उद्यमों के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग।	**अन्य:** कर में छूट; ATL स्पेस चैलेंज; अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AIC) योजना आदि।

आगे की राह

अंतरिक्ष गतिविधियां अधिनियम बनाना: अंतरिक्ष उद्योग में कार्य की स्पष्टता, फोकस और प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु।	**मूल्य श्रृंखला की मैपिंग:** बाजार सृजन को सक्षम करने के लिए चुनौतियों, प्रवृत्तियों और मानदंडों की पहचान करना।	**क्षमता निर्माण:** जैसे-सिस्टम इंजीनियरिंग से जुड़े कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना।	**अंतरिक्ष क्षेत्रक में तालमेल बनाना:** विशेषज्ञता और बाजार तक पहुंच के लिए स्टार्ट-अप्स, इसरो एवं विदेशी कंपनियों के बीच साझेदारी बढ़ानी चाहिए।	**अन्य उपाय:** प्रौद्योगिकी विकास निधि आरंभिक कोष में वृद्धि करना, , वायबिलिटी गैप फंडिंग, आदि।

9.6. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
डिजिटल अर्थव्यवस्था	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	डिजिटल इंडिया मिशन	डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर	इंडिया स्टैक
भाषिणी	स्टार्ट-अप इंडिया	डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क	डिजिटल साक्षरता	क्रिएटिव इकोनॉमी

9.7. अभ्यास प्रश्न (Practice Questions)

उत्तर लेखन प्रारूप

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था आर्थिक संवृद्धि और नवाचार की एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में उभरी है। सेवा वितरण में परिवर्तन और निर्यात को बढ़ावा देने में इसकी महत्ता का परीक्षण कीजिए, साथ ही इसका सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु उन प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए जिन्हें दूर करना आवश्यक है।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
डिजिटल अर्थव्यवस्था का परिचय दीजिए	सेवा वितरण और निर्यात में इसके महत्व का उल्लेख कीजिए	मुख्य चुनौतियां	निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए

10. अवसंरचना (Infrastructure)

10.1. भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) फ्रेमवर्क: एक नज़र में {Public-Private Partnership (PPP) Framework In India At A Glance}

भारत में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) फ्रेमवर्क

भारत में विभिन्न PPP मॉडल्स

बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (BOT): यह अधिकतम निजी भागीदारी सुनिश्चित करता है।	**बिल्ड ओन ऑपरेट (BOO):** निजी संगठन सरकार से कुछ प्रोत्साहन प्राप्त करके किसी परियोजना या संरचना का निर्माण करता है, स्वामित्व धारण करता है और संचालन करता है।	**BOT-एन्युटी:** सरकार अनुबंधों के माध्यम से निजी क्षेत्रक की दक्षता का उपयोग करती है।	**ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (सर्विस कॉन्ट्रैक्ट):** विशिष्ट सेवाओं या परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए किसी निजी संस्था को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है	**इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (EPC):** निजी संस्था EPC का प्रबंधन करती है। परियोजना प्रबंधन में उसकी कोई भूमिका नहीं होती।	**हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM):** इसमें EPC (40%) और BOT-एन्युटी (60%) को शामिल किया जाता है।

भारत में PPP के समक्ष मौजूद चुनौतियां

विनियामकीय मुद्दे: जैसे भूमि अधिग्रहण के मुद्दे, पर्यावरण मंजूरी में देरी आदि।	**वित्त-पोषण की समस्या:** जैसे.राष्ट्रीय अवसंरचना योजना के लिए अगले पांच वर्षों में 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है।	**दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट संबंधी मुद्दे:** आर्थिक या नीतिगत परिवर्तनों के कारण निजी क्षेत्रक अपनी सौदेबाजी की क्षमता को खो देता है।	**अन्य:** विवाद समाधान तंत्र, राज्य के स्वामित्व वाली संस्थाओं की भागीदारी आदि।

भारत में PPP को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

PPP मूल्यांकन समिति	**राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP)**	**वायबिलिटी फंडिंग गैप (VGF)**	**अन्य:** अवसंरचना परियोजना विकास निधि, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) आदि

भारत में PPP में सुधार के लिए आगे की राह (विजय केलकर समिति के अनुसार)

सेवा वितरण पर फोकस करना: कॉन्ट्रैक्ट में केवल वित्तीय लाभ अर्जित करने की बजाय गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।	**जोखिम प्रबंधन:** दक्षता और लागत-प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए उन्नत मॉडल्स का उपयोग करना चाहिए।	**विशेषज्ञ तंत्र:** विवाद समाधान के लिए PPP समीक्षा समिति और अधिकरण की स्थापना करनी चाहिए।	**अन्य:** कानून में संशोधन, स्वतंत्र विनियमन आदि।

10.2. लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स/ LEADS) 2024 {Logistics Ease Across Different States (Leads) 2024}

सुर्ख़ियों में क्यों?

लीड्स रिपोर्ट 2024, **वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** द्वारा जारी की गई है।

लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (लीड्स/ LEADS) के बारे में

- **उद्देश्य:** राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन में सुधार के बारे में जानकारी प्रदान करना।
  - लीड्स को **विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI)** की तर्ज पर **2018** में विकसित किया गया था।
    - विश्व बैंक का LPI पूरी तरह से **धारणा-आधारित सर्वेक्षणों** पर निर्भर है। इसके विपरीत, लीड्स में धारणा के साथ-साथ **वस्तुनिष्ठ माप (Objectivity)** भी शामिल है।

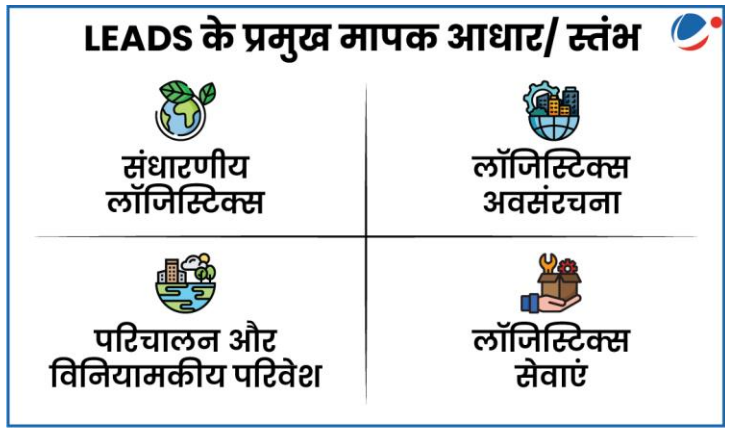

- **मापदंड:** इसके तहत **चार मापक आधार/ स्तंभ पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन** किया जाता है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणियां:** इन्हें निम्नलिखित चार समूहों में वर्गीकृत किया गया है-
  - **तटीय, स्थल-रुद्ध, पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेश।**
    - इसके अलावा प्रदर्शन के आधार पर इन्हें **अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायरर्स** का टैग प्रदान किया जाता है।
- **2024 में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन-**
  - **अचीवर्स:** गुजरात, हरियाणा, असम, चंडीगढ़, आदि।
  - **फास्ट मूवर्स:** आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि।
  - **एस्पायरर्स:** केरल, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, छत्तीसगढ़, आदि।

लीड्स फ्रेमवर्क

- **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को लीड्स फ्रेमवर्क** यानी लोंगेविटी, दक्षता एवं प्रभावशीलता, एक्सेसिबिलिटी व जवाबदेही तथा प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को अपनाने का आग्रह किया है, ताकि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को नया रूप दिया जा सके।
- **साथ ही, मंत्रालय ने निम्नलिखित उपायों का भी सुझाव दिया है:**
  - **हरित लॉजिस्टिक्स और संधारणीय परिवहन** पहल को बढ़ावा देना।
  - **मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब** को बढ़वा देने के लिए **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** को प्रोत्साहित करना।
  - लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए **क्षेत्रीय और शहर स्तर पर लॉजिस्टिक्स योजनाएं** विकसित करना।
  - **लैंगिक समावेशिता** को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

LEADS 2024 रिपोर्ट भारत की लॉजिस्टिक्स दक्षता को डेटा-आधारित मूल्यांकन और सुधार के माध्यम से बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की पहचान कर, LEAD फ्रेमवर्क के तहत टिकाऊ, समावेशी और तकनीक आधारित समाधान को प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्रपक को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम में बदला जा सके।

10.3. पारगमन उन्मुख विकास: एक नज़र में (Transit-Oriented Development at A Glance)

पारगमन उन्मुख विकास (TOD)

TOD के बारे में

अवधारणा: इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों के आसपास मिश्रित भूमि उपयोग के साथ योजनाबद्ध संधारणीय नगरीय विकास केंद्रों का विकास करना है।	**TOD के घटक:** › **विस्तार क्षेत्र (Influence Zone): ट्रांजिट स्टेशन के आस-पास का क्षेत्र;** › **अनिवार्य और समावेशी आवास; और** › **आकर्षक सार्वजनिक स्थल**

ट्रांजिट ओरिएंटेड/ पारगमन उन्मुख विकास (TOD) का महत्व

रहने योग्य शहर गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रों और कम आवागमन दूरी पर केंद्रित; उदाहरण के लिए- **दिल्ली एवं मुंबई** को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में संयुक्त रूप से **141वें स्थान** पर रखा गया है।	**जलवायु-अनुकूल:** TOD ऊर्जा उपयोग और उत्सर्जन में कटौती करता है; उदाहरण के लिए- स्टॉकहोम ने प्रति व्यक्ति GHG में 35% की कटौती (1993 से 2010) की है।	**वित्त-पोषण:** पारगमन स्टेशन के निकट भूमि का मूल्य बढ़ता है, जिससे अवसंरचना और आवास को वित्त-पोषित किया जाता है। उदाहरण के लिए- हांगकांग ने 6 लाख सार्वजनिक आवास इकाइयों (1980-2005) के लिए 140 बिलियन हांगकांग डॉलर जुटाए थे।	**अन्य:** संकुलन प्रभाव (Agglomeration effects); दक्ष पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, हरित क्षेत्रों में वृद्धि आदि

TOD के लिए सरकारी पहलें

राष्ट्रीय पारगमन उन्मुख विकास नीति	मेट्रो रेल नीति 2017	स्मार्ट सिटीज़ मिशन	शहरी अवसंरचना विकास कोष	**अन्य:** प्रधान मंत्री आवास योजना, मल्टीमॉडल परिवहन विकास आदि।

आगे की राह - विश्व बैंक का 3 वैल्यू (3V) फ्रेमवर्क

नोड वैल्यू: यह ट्रैफिक कनेक्टिविटी और केंद्रीयता के आधार पर स्टेशन के महत्त्व को दर्शाता है।	**प्लेस वैल्यू:** यह स्टेशन के आसपास के क्षेत्र की गुणवत्ता और आकर्षण को दर्शाता है।	**बाजार संभावित मूल्य:** यह स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों का अप्राप्त (भविष्य) बाजार मूल्य है।

10.4. रेलवे (Railways)

10.4.1. रेलवे में सुधार (Railways Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 लोक सभा में पारित हुआ। साथ ही, रेलवे पर संसद की स्थायी समिति ने **"रेलवे का आधुनिकीकरण और वित्तीय स्थिरता"** पर केंद्रित एक रिपोर्ट जारी की है।

रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024 के बारे में

- **सरलीकृत कानूनी फ्रेमवर्क**
  - यह विधेयक **भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 को निरस्त करके** इसके प्रावधानों को **भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 में समाहित** करने का प्रस्ताव करता है।
  - इसका उद्देश्य रेलवे प्रशासन के लिए दो अलग-अलग कानूनों के संदर्भ लेने से बचना है।
- **रेलवे बोर्ड के गठन पर केंद्र सरकार को अतिरिक्त शक्ति:** केन्द्र सरकार निम्नलिखित निर्धारित करेगी:
  - बोर्ड के सदस्यों की संख्या,
  - सदस्यों के लिए योग्यताएं, अनुभव, सेवा की शर्तें और नियम, तथा
  - बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का तरीका।

हाल ही में संसदीय स्थायी समिति ने भी दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और सेवा गुणवत्ता में सुधार के लिए **रेलवे प्रशासन में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित किया था।**

संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

मापदंड	टिप्पणी	सिफारिशें
वित्तीय	• भारतीय रेलवे की **अधिकांश आय** उसकी **माल ढुलाई सेवाओं** से आती है।	• अलग-अलग रेलगाड़ियों और श्रेणियों में **यात्री किराये की व्यापक समीक्षा** की जानी चाहिए।
परिचालन	• पिछले 11 वर्षों से मालगाड़ियों की **औसत गति 25 कि.मी./घंटा** पर स्थिर बनी हुई है।	• गति, माल लदान और आय बढ़ाने के लिए नए **समर्पित माल गलियारों** के निर्माण पर शीघ्रता से कार्य करना चाहिए।
बुनियादी ढांचा और आधुनिकीकरण	• **निवेश** ○ सकल बजटीय सहायता में वृद्धि के कारण मुख्य रूप से **पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में वृद्धि** हुई। ○ पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर निर्भरता कम हो गई है, क्योंकि बाजार से उधार लेने के कारण ऋण दायित्वों को पूरा करना होता है, और इससे वित्तीय देनदारियां बढ़ जाती हैं। • **रोड ओवर ब्रिज (RoBs) और रोड अंडर ब्रिज (RuBs):** पिछले तीन वर्षों में RoB/ RuB का निर्माण करने के लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं।	• **निवेश:** रेलवे के बुनियादी ढांचे और स्टेशन पुनर्विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। • **RoBs और RuBs:** समिति ने नई नीति की सराहना की है, क्योंकि परियोजना के लिए पूरा फंड अब रेलवे प्रदान करेगा। इससे लागत-साझा करने में राज्य की निष्क्रियता के कारण रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा किया जा सकेगा, तथा लंबित कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित होगा।
अनुसंधान	• **रेलवे अनुसंधान निधि का कम आवंटन और कम उपयोग** (उदाहरण के लिए 2024-25 के लिए रेलवे अनुसंधान के लिए बजट आवंटन मात्र 72 करोड़ रुपये है)	• नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा **आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने** के लिए **अनुसंधान एवं विकास का दायरा बढ़ाना चाहिए।**
ग्रीन रेलवे	• भारतीय रेलवे ने **2030 तक खुद को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने का लक्ष्य** रखा है।	• वित्तीय आवंटन में **'ग्रीन बजट'** पद्धति को शामिल करना चाहिए।

निष्कर्ष

हालांकि भारतीय रेलवे ने काफी प्रगति की है, फिर भी उसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाकर बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने तथा संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक अप्रोच अपनाना होगा। साथ ही उसे वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप परिचालन दक्षता को बढ़ाना होगा। रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए **अमृत भारत स्टेशन योजना (2022)** और माल परिवहन की दक्षता में सुधार के लिए **राष्ट्रीय रेल योजना (2020)** इस दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026
प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
DELHI : 15 जुलाई, 2 PM
JAIPUR : 24 जून
JODHPUR : 2 जुलाई
Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.
/visionias.upsc
/c/VisionIASdelhi
/c/VisionIASdelhi
/t.me/s/VisionIAS_UPSC
DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 CONTACT: 8468022022, 9019066066
AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

10.4.2. भारतीय रेलवे की सुरक्षा (Indian Railways Safety)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पिछले कुछ महीनों में ट्रेन के पटरी से उतरने/ टकराने की कई घटनाओं ने रेलवे सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है।

रेल दुर्घटनाओं के कारण

- **ट्रेनों का पटरी से उतरना:** इसका कारण इंजन, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक, सिग्नल आदि का सही ढंग से रख-रखाव न करना एवं परिचालन संबंधी अन्य अनियमितताएं हो सकती हैं।
- **मानवीय भूल (ह्यूमन एरर):** भारतीय रेलवे के अनुसार, **लगभग 75% रेल दुर्घटनाएं 'रेलवे स्टाफ की गलती' के कारण होती हैं (भारतीय रेल)।**
- **सिग्नल फेलियर: उदाहरण के लिए-** दोषपूर्ण सिग्नल सर्किट मॉडिफिकेशन के कारण गलत सिग्नलिंग हुई, जिसके कारण 2023 में बालासोर में ट्रेन की टक्कर हुई।
- **रेलवे कोचों में आग लगने की घटनाएं:** यात्रियों द्वारा अपने साथ ज्वलनशील पदार्थ ले जाने; शॉर्ट सर्किट लगने; पैंट्री कार के कर्मचारियों, लीज ठेकेदार की लापरवाही जैसे कारणों से इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं।
- **मानव संसाधन:** भारतीय रेलवे के सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यबल में लगभग 20,000 पद रिक्त हैं।

रेलवे सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

- **कवच प्रणाली (KAVACH System)**: यह **स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली (ATP)**[35] है। यह सिस्टम कैब सिग्नलिंग जैसी विशेषताएं से युक्त है जो उच्च रफ्तार और कोहरे वाले मौसम में भी कार्य कर सकता है।
    - फरवरी 2024 तक, कवच को दक्षिण मध्य रेलवे के 1465 रूट कि.मी. और 139 इंजनों (इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रेक सहित) में स्थापित किया जा चुका है।
- **राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (RRSK):** इसकी स्थापना वर्ष 2017-18 में 1 लाख करोड़ रुपए की निधि से की गई थी। इसे पाँच वर्ष की अवधि में रेलवे सुरक्षा से जुड़ी महत्त्वपूर्ण अवसंरचनाओं को अपग्रेड करने संबंधी कार्यों के लिए स्थापित किया गया था।
- **बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना:** स्टेशनों पर पॉइंट्स और सिग्नल्स के सेंट्रलाइज़्ड रूप से संचालन के साथ इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जैसे कदम उठाए गए हैं; लेवल क्रॉसिंग (LC) गेटों की इंटरलॉकिंग की सुविधा शुरू की गई है, आदि।
- **नई प्रौद्योगिकी का उपयोग: जैसे-** GPS आधारित फॉग सेफ्टी डिवाइस, आदि।
- **मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त किया गया है:** ब्रॉड गेज (BG) मार्ग पर सभी "मानव रहित लेवल क्रॉसिंग (UMLCs)" को जनवरी 2019 तक समाप्त कर दिया गया था।
- **सुरक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली (SIMS):** दुर्घटना की रिपोर्टिंग, विश्लेषण और जानकारी साझा करने के लिए एक वेब आधारित एप्लिकेशन SIMS विकसित किया गया है।

आगे की राह

- **रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण:** काकोदकर समिति की सिफारिश के अनुरूप रेलवे के परिचालन मोड पर सुरक्षा निगरानी रखने के लिए एक वैधानिक "रेलवे सुरक्षा प्राधिकरण" गठित किए जाने की आवश्यकता है।
- **विस्तृत आउटकम फ्रेमवर्क:** नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की 'भारत में रेलवे का ट्रैक से उतरना' शीर्षक वाली 2021 की रिपोर्ट में सुरक्षा कार्यों के लिए एक '**विस्तृत आउटकम फ्रेमवर्क**' बनाने की सिफारिश की गई है। इसे राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष (RRSK) से फंड प्राप्त होगा।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित एप्लिकेशन विकसित करना:** AI, स्टेशनों और ट्रेनों से बड़े पैमाने पर प्राप्त होने वाले डिजिटल डेटा का विश्लेषण कर सकता है, गंभीर अनियमितताओं की पहचान कर सकता है और बेहतर सुरक्षा निगरानी के लिए शीर्ष रेलवे प्रबंधन को तुरंत सचेत कर सकता है।
- **ट्रैक सुरक्षा सहनशीलता (Track Safety Tolerances)**: खन्ना समिति की सिफारिश के अनुसार अलग-अलग स्पीड और ट्रैक की श्रेणियों के लिए सुरक्षा सहनशीलता निर्धारित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन (RDSO) द्वारा विश्व के देशों में अपनाई जाने वाली कार्य पद्धतियों तथा रेल व्हील इंटरेक्शन के सभी पक्षों का अध्ययन करने की जरूरत है।
- **बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाना:** मुंबई उपनगर की लंबे समय से चली आ रही स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणालियां एक सफल मॉडल के रूप में काम करती हैं। ट्रेन सुरक्षा के लिए देश भर में इनका उपयोग किया जा सकता है।

[35] Automatic Train Protection

निष्कर्ष

भारत के विशाल और तेजी से बढ़ते रेल नेटवर्क के लिए रेलवे सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। हालांकि कवच जैसे कदम और तकनीकी उन्नयन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मानवीय त्रुटियां, स्टाफ की कमी और पुरानी हो चुकी अवसंरचना जैसी चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। दुर्घटनाओं को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र सुरक्षा प्राधिकरण, AI-आधारित निगरानी, और वैश्विक स्तर की सर्वोत्तम सुरक्षा पद्धति को अपनाना आवश्यक है।

10.5. बंदरगाह और जलमार्ग (Port and Waterways)

10.5.1. ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (Transshipment Port)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने केरल के **विझिनजाम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट डीपवाटर मल्टीपर्पज सी-पोर्ट** में नवनिर्मित अर्ध-स्वचालित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर अपने पहले मालवाहक जहाज का स्वागत किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- विझिनजाम बंदरगाह का स्वामित्व **केरल सरकार** के पास है।
- इसे मुख्य रूप से बहुउद्देशीय एवं ब्रेक-बल्क कार्गो के अलावा **कंटेनर ट्रांसशिपमेंट** संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में भारत का महत्व

- **राजस्व सृजन: भारत के लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो** को भारत के बाहर के बंदरगाहों पर हैंडल किया जाता है।
- दक्षता बढ़ाकर **लॉजिस्टिक लागत और शिपिंग लागत में कमी।**
  - भारतीय बंदरगाहों के लिए औसत टर्नअराउंड समय 4.3 दिन (2012-13) से **घटकर 2.1 दिन (2022-23) हो गया।**
- **आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना:** देश का अपना ट्रांसशिपमेंट हब होने से विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय बचत होगी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होगा और व्यापार में वृद्धि होगी।
  - बंदरगाह के आसपास जहाजों से जुड़े व्यवसायों का विकास होगा, जैसे- **जहाज़ की मरम्मत, वेयरहाउसिंग, बंकरिंग आदि।**
- **राष्ट्रीय सुरक्षा** बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत हिंद महासागर में बंदरगाह संबंधी अवसंरचनाओं में **चीन का बढ़ता प्रभाव** एवं विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता **देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा** है।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण:** शिपिंग कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होने से वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत का एकीकरण बाधित हुआ है।
  - **विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी लगभग 2%** ही है।

ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह के विकास में मौजूद समस्याएं

- **भारतीय बंदरगाहों के पास जल की प्राकृतिक गहराई अपेक्षाकृत कम है:** मुंबई, चेन्नई, मैंगलोर और तूतीकोरिन जैसे बड़े भारतीय बंदरगाहों की प्राकृतिक गहराई केवल 10-14 मीटर है। एक अच्छे ट्रांसशिपमेंट हब के लिए **20-मीटर गहराई की आवश्यकता** होती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइनों से दूरी:** उदाहरण के लिए- पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर मौजूद हमारे देश के बड़े बंदरगाह प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से काफी दूरी पर अवस्थित हैं।
- **श्रम संबंधी मुद्दे:** बड़े भारतीय बंदरगाह अपने-अपने बंदरगाहों पर लगातार श्रमिक हड़तालों, भीड़भाड़, दक्षता की कमी एवं कर्मियों की कम उत्पादकता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।

 © Vision IAS

- **अन्य समस्याएं:** फंडिंग की कमी, भूमि अधिग्रहण में देरी, लॉजिस्टिक्स एवं कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई अक्षमताएं, **विदेशी बंदरगाहों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ना** (जैसे कोलंबो, दुबई, सिंगापुर, जबेल अली, पोर्ट केलांग, आदि)।

भारत में बंदरगाहों के विकास के लिए शुरू की गई पहलें

- **मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047:** यह भारत के समुद्री क्षेत्र को बदलने के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा है।
- **नए अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का विकास:** इनका विकास अंडमान और निकोबार द्वीप में ग्रेट निकोबार की गैलाथिया खाड़ी तथा कोचीन के वल्लारपदम में किया जा रहा है (मानचित्र देखिए)।
- **टैरिफ दिशा-निर्देश, 2021:** ये दिशा-निर्देश PPP ऑपरेटर्स को बाजार द्वारा निर्धारित टैरिफ को तय करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इससे बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी।

आगे की राह

- **बुनियादी ढांचे में निवेश:** मौजूदा बंदरगाहों **(विशेष रूप से ड्राई कार्गो के मामले में)** की क्षमता बढ़ाने के लिए **आधुनिक कार्गो हैंडलिंग तकनीकों** में निवेश बढ़ाने की जरुरत है।
- **सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (PPP) के आधार पर परियोजनाएं शुरू करना:** विदेशी शिपिंग कंपनियों को **आकर्षित करने** के लिए करों को व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए तथा **PPP परियोजनाओं को मंजूरी देने** के लिए सिंगल विंडो सिस्टम प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के साथ प्रतिस्पर्धा:** भारतीय बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के समकक्ष लाने के लिए लागत दक्षता, टर्नअराउंड समय एवं ग्राहक सेवा से जुड़ी प्रमुख समस्यायों की पहचान करनी होगी एवं इन्हें दूर करने का प्रयास करना होगा।
- **तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (CZMP)[36] तैयार करना:** बंदरगाहों को पूर्व में जारी पर्यावरण मंजूरी के आधार पर भविष्य की निर्माण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए CZMP तैयार करने की अनुमति दी जा सकती है।

निष्कर्ष

भारत का ट्रांसशिपमेंट हब बनने की दिशा में कदम, विशेष रूप से विजिंजम पोर्ट की शुरुआत, व्यापारिक दक्षता बढ़ाने, विदेशी निर्भरता कम करने और आर्थिक व समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है। यदि उचित बुनियादी ढांचा, नीतिगत समर्थन और वैश्विक एकीकरण सुनिश्चित किया जाए, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला देश बन सकता है।

10.5.2. राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025 {National Waterways (Construction of Jetties/Terminals) Regulations, 2025}

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI)[37] ने **राष्ट्रीय जलमार्ग (जेटी/ टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2025** जारी किए।

विनियम के बारे में

- **उद्देश्य:** टर्मिनल स्थापित करने में **निजी क्षेत्र से निवेश** आकर्षित करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और भारत के विशाल जलमार्ग नेटवर्क के प्रभावी तरीके से उपयोग को बढ़ावा देना।

विनियम के मुख्य प्रावधान

- **किन पर लागू होगा:** कोई भी इकाई, जिसमें निजी क्षेत्र की इकाई भी शामिल है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल बनाना या संचालित करना चाहती है।
  - ये नियम पहले से स्थापित और नए, दोनों तरह के टर्मिनल्स पर लागू होते हैं, चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी।
- **टर्मिनल हेतु आवेदन के लिए डिजिटल पोर्टल:** इसे दक्षता, पारदर्शिता और टर्मिनल तक पहुंच बढ़ाने के लिए IWAI द्वारा विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य व्यवसाय सुगमता को आसान बनाना है।

[36] Coastal Zone Management Plan

[37] Inland Waterways Authority of India

© Vision IAS

अंतर्देशीय जल परिवहन

- **लाभ:**
    - **ईंधन का बेहतर उपयोग:** 1 लीटर ईंधन में सड़क मार्ग से एक किलोमीटर तक 24 टन, रेल मार्ग से एक किलोमीटर तक 95 टन और अंतर्देशीय जलमार्ग से एक किलोमीटर तक 215 टन का भार परिवहन किया जा सकता है।
    - **किफायती:** अलग-अलग परिवहन साधनों से, माल ढुलाई की प्रति टन प्रति किलोमीटर लागत रेलमार्ग से 1.36 रुपये, राजमार्गों से 2.50 रुपये और अंतर्देशीय जल परिवहन (IWT) से 1.06 रुपये है।
    - **अन्य:** यातायात पर भीड़ को कम करना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, आदि।

भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की स्थिति

- **नौगम्य जलमार्ग:** भारत में लगभग **14,500 किलोमीटर** नौगम्य जलमार्ग हैं, जिनमें नदियां, नहरें, बैकवॉटर क्रीक आदि शामिल हैं।
- **अन्य देशों से तुलना:** भारत में केवल 3.5% व्यापार जलमार्गों से होता है, जबकि चीन में 47%, यूरोप में 40% और बांग्लादेश में 35% व्यापार जलमार्गों से होता है।

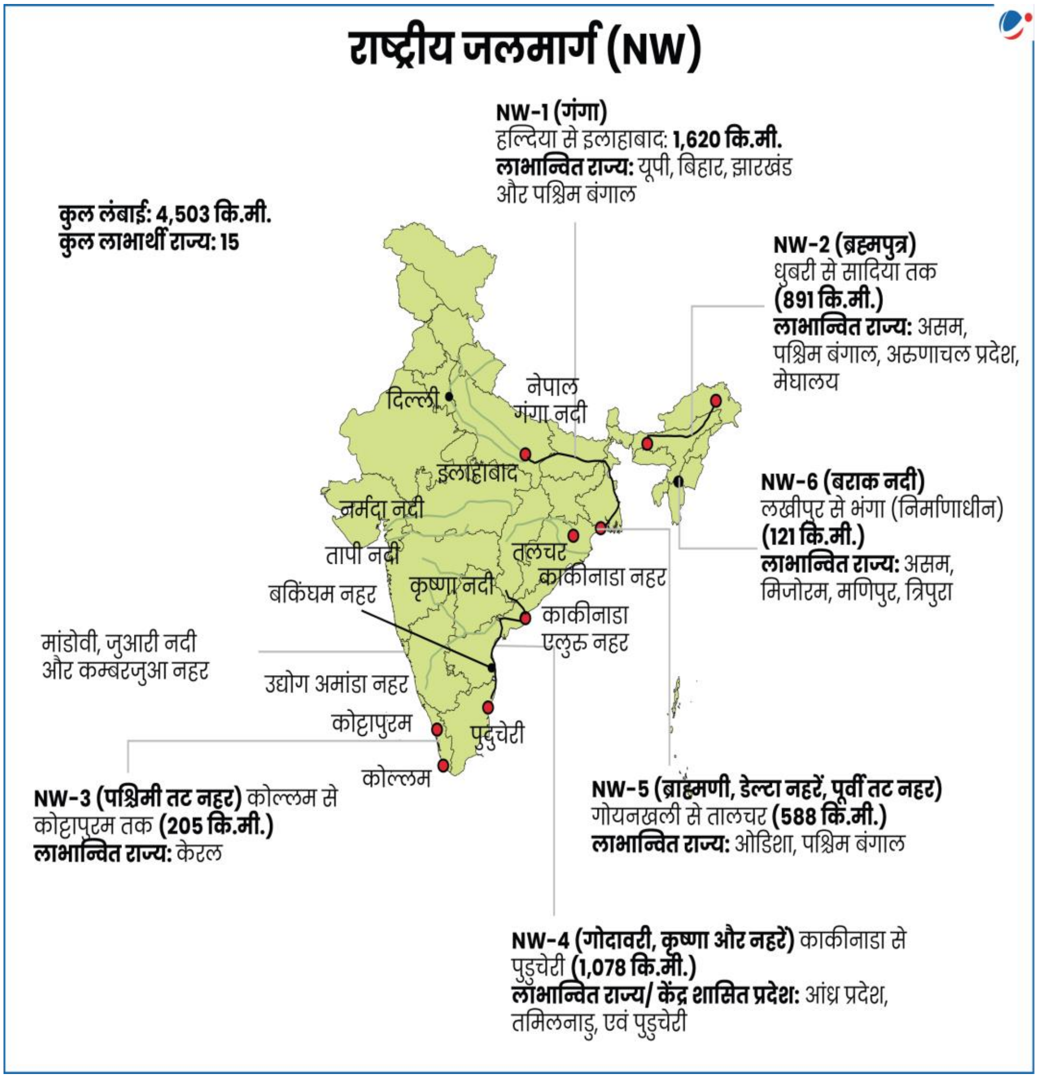

अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदम

- **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI):** 1986 में स्थापित यह संगठन केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक नोडल एजेंसी है। इसे **राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित और प्रशासित करने** का अधिकार है।
- **सागरमाला कार्यक्रम (2015):** इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्रक में क्रांतिकारी बदलाव लाना है।
    - यह वस्तुओं के परिवहन के लिए तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा देता है, जिससे सड़क और रेल नेटवर्क पर निर्भरता कम होती है।
- **जलवाहक योजना (2024):** इसका उद्देश्य किफायती तरीके से अंतर्देशीय जलमार्गों के जरिए सुरक्षित और समय पर कार्गो की डिलीवरी करने के साथ व्यापार उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।

निष्कर्ष

अंतर्देशीय जलमार्गों की पूरी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए समग्र और समन्वित नीति बनाने की आवश्यकता है। इसमें अवसंरचना में सुधार करना, निजी निवेश को बढ़ावा देना, आधुनिक तकनीकों को अपनाना, और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना शामिल है। उचित नीतियां बनाने और क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने से वस्तुओं के परिवहन को और अधिक गति मिलेगी तथा जलमार्गों को संधारणीय परिवहन साधन और व्यापार का एक प्रमुख आधार बनाया जा सकेगा।

10.6. सड़क सुरक्षा: एक नज़र में (Road Safety at a Glance)

भारत में सड़क सुरक्षा

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति

- **WHO की सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023** के अनुसार 2010 से 2021 के बीच, भारत में सड़क हादसों से होने वाली मौतों में 15% की वृद्धि हुई है।
- केवल 2024 में ही, भारत में **1.8 लाख लोगों** की जान सड़क दुर्घटनाओं में चली गई थी।
- **इन दुर्घटनाओं में 66% पीड़ित 18 से 34 वर्ष के युवा थे।**

सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- ***मोटर वाहन अधिनियम (2019) में संशोधन:*** उल्लंघन के लिए कठोर दंड, वाहन सुरक्षा मानदंडों में सुधार आदि।
- **4,000 से अधिक ब्लैक स्पॉट्स (दुर्घटना संभावित क्षेत्र) की पहचान** की गई है एवं उन्हें ठीक किया गया है।
- **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति (2010):** यह जागरूकता अभियान, प्रवर्तन और सुरक्षित सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देती है।
- **उन्नत वाहन सुरक्षा मानक;** उदाहरणार्थ, भारत NCAP क्रैश परीक्षणों का कार्यान्वयन।

भारत में सड़क सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां

- **उच्च मृत्यु दर और उपचार-लागत का बोझ:** 2022 में विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में **11% मौतें** भारत में दर्ज की गई थी।
- **तेज गति और लापरवाह ड्राइविंग:** ये सड़क दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण हैं।
- **दुर्घटना के बाद तुरंत उपचार नहीं मिलना:** सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 50% मौतों की वजह समय पर उपचार नहीं मिलना है।
- **अन्य:** यातायात संबंधी कानून के प्रवर्तन का अभाव, अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन और वाहनों की बढ़ती संख्या आदि।

सिफारिशें: सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक कार्य-योजना (2021-2030) का सेफ सिस्टम अप्रोच: WHO

- **सेफ सिस्टम अप्रोच:** यह सुनिश्चित करना है कि सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान नहीं जाए
- **पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिलिंग और पैदल यात्रा** को बढ़ावा देकर सड़क दुर्घटना जोखिम को कम करना।
- **सुरक्षित सड़क अवसंरचना,** यातायात कानूनों को मजबूत बनाना, स्पीड मैनेजमेंट आदि।
- **सभी वाहनों में उन्नत सुरक्षा सुविधाओं को अनिवार्य करना, आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में सुधार करना आदि।**

10.7. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
पारगमन उन्मुख विकास	रेलवे में सुधार	रेलवे का आधुनिकीकरण	रेलवे सुरक्षा	कवच प्रणाली
सार्वजनिक निजी भागीदारी	डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर	इंडिया स्टैक	लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स	ट्रांसशिपमेंट पोर्ट
विझिनजाम पोर्ट	मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047	अंतर्देशीय जलमार्ग	राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष	राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016

10.8. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

भारत के लिए विजिंजम जैसे ट्रांसशिपमेंट बंदरगाहों के विकास की रणनीतिक और आर्थिक महत्ता का परीक्षण कीजिए। ऐसे बंदरगाह भारत की विदेशी ट्रांसशिपमेंट हब्स पर निर्भरता को कैसे कम कर सकते हैं और वैश्विक समुद्री व्यापार में अपनी स्थिति को कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं?

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का परिचय दीजिए	महत्व	यह विदेशी केंद्रों पर भारत की निर्भरता को कैसे कम करता है	निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए

11. खनन गतिविधियां एवं अन्य संसाधन (Mining and other Resources)

11.1. राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (National Critical Mineral Mission: NCMM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) को शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है।

NCMM के बारे में

- **शुरुआत:** केंद्रीय बजट 2024-25 में राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था।
- **कवरेज:** इस मिशन में **मूल्य श्रृंखला** के सभी चरण शामिल होंगे; जैसे कि खनिजों की खोज, **खनन, उन्हें लाभकारी या उपयोगी बनाना (बेनेफिकेशन), प्रोसेसिंग** और **उत्पाद के अनुपयोगी हो जाने पर उनसे उपयोगी सामग्रियों की रिकवरी।**
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - इस **मिशन के तहत क्रिटिकल मिनरल्स की खोज** के लिए **वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान** किया जाएगा तथा **माइन ओवरबर्डन और माइन टेलिंग्स** से इन खनिजों की प्राप्ति को **बढ़ावा दिया जाएगा।**
    - खनिज अयस्क तक पहुँचने के लिए हटाई गई चट्टान या मिट्टी की परत को **'ओवरबर्डन (Overburden)' कहा जाता है, जबकि "टेलिंग्स" (Tailings)** का मतलब है अयस्क से मूल्यवान सामग्री निकालने के बाद बचा हुआ अपशिष्ट। इनमें खनिज के अंश होते हैं।
  - इस मिशन का उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित खनन परियोजनाओं के लिए **फास्ट ट्रैक विनियामक मंजूरी प्रक्रिया स्थापित** करना है।
  - यह मिशन **भारत के सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों (PSUs)** और **निजी क्षेत्रक की कंपनियों** को **विदेशों में क्रिटिकल मिनरल्स परिसंपत्तियों का अधिग्रहण** करने और खनिज **संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित** करेगा।
  - इस मिशन में देश के भीतर **क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार** विकसित करने का प्रस्ताव है।
  - यह मिशन अपतटीय क्षेत्रों यानी **महासागर** में पॉलिमेटेलिक नोड्यूल के खनन को भी बढ़ावा देगा। पॉलिमेटेलिक नोड्यूल में कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिज पाए जाते हैं।
- **गवर्नेंस फ्रेमवर्क:**
  - **"क्रिटिकल मिनरल्स पर अधिकार प्राप्त समिति"** क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़ी अलग-अलग गतिविधियों में समन्वय का कार्य करेगी।
  - **केंद्रीय खान मंत्रालय** इस मिशन का प्रशासनिक मंत्रालय होगा।

क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में

- **परिभाषा:** क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे खनिज हैं जो **किसी भी देश के आर्थिक विकास** और **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक** हैं।
- भारत सरकार ने देश के लिए **30 क्रिटिकल मिनरल्स** की सूची जारी की है। इनमें बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, फास्फोरस, पोटाश, रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE), सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम आदि शामिल हैं।
- वर्तमान में, भारत **क्रिटिकल मिनरल्स की मांग की पूर्ति के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर** है।

महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) का महत्व

पर्यावरण
- सौर पैनल और पवन टर्बाइन जैसी **नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों** के लिए महत्वपूर्ण।
- **बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS)** के लिए भी महत्वपूर्ण।

राष्ट्रीय सुरक्षा
- मिसाइल प्रणालियों, एयरोस्पेस और संचार प्रौद्योगिकियों सहित **भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक।**

आर्थिक और इलेक्ट्रॉनिक
- **इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs)** को अपनाने के लिए लिथियम-आयन बैटरी की आवश्यकता होती है।
- **सेमीकंडक्टर चिप्स** के लिए आवश्यक।

भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स सुरक्षित करने की राह में बाधाएं

- **देश में बहुत कम भंडार:** उदाहरण के लिए- वर्तमान में, देश में उत्पादन उद्देश्यों के लिए **कोबाल्ट, निकल, लिथियम और नियोडिमियम** के लिए कोई संचालित खनन पट्टा नहीं दिया गया है।
- **क्रिटिकल मिनरल्स की खोज से जुड़ी चुनौतियां:** जैसे: जम्मू-कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार होने का अनुमान है, लेकिन इसे प्राप्त करना जोखिम भरा है।
- **आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान: वैश्विक स्तर पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एवं क्रिटिकल मिनरल्स का लगभग 60% उत्पादन एवं 85% प्रसंस्करण** चीन में होता है।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएं:** जैसे- इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (IRENA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग **54% खनिज भंडार देशज समुदायों की भूमि के आस-पास स्थित हैं।**

क्रिटिकल मिनरल्स की प्राप्ति हेतु शुरू की गई अन्य पहलें

- **नीति और विनियामकीय फ्रेमवर्क**
  - **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023:** इसमें क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और खनन से संबंधित प्रावधान हैं।
  - **राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019:** यह क्रिटिकल मिनरल्स के संधारणीय तरीके से खोज और खनन को बढ़ावा देती है।
  - केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत सरकार ने अधिकतर क्रिटिकल मिनरल्स पर **सीमा शुल्क समाप्त कर दिया** है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार समझौते**
  - **खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL):** यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसे 2019 में केंद्रीय खान मंत्रालय ने गठित किया था। इसका उद्देश्य विश्व भर में क्रिटिकल मिनरल्स परिसंपत्तियों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है।
    - KABIL अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खनिज प्राप्ति में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।
  - **खनिज सुरक्षा भागीदारी[38]:** संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली इस पहल में भारत 2023 में शामिल हुआ। इस पहल में शामिल होने का उद्देश्य देश के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

भारत क्रिटिकल मिनरल्स की लंबे समय तक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन-से उपाय कर सकता है?

- **देश में क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन को बढ़ावा देना: अधिक निजी निवेश आकर्षित करने** के लिए खनिज क्षेत्र के **आवंटन की वैकल्पिक प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए।**
- **घरेलू स्तर पर प्रोसेसिंग क्षमताएं विकसित करना:** प्रोसेसिंग फैसिलिटी में निवेश करने के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन, कर छूट और अन्य नीतिगत सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
  - **क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग पर केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)** स्थापित किए जा सकते हैं।
- **वैश्विक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता:** क्रिटिकल खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खनिज संपन्न देशों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना चाहिए।
- **व्यापक क्रिटिकल मिनरल्स रणनीति तैयार करना:** यह रणनीति आपूर्ति से जुड़े जोखिमों, घरेलू नीतियों और सस्टेनेबिलिटी से जुडी प्राथमिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है।
  - अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रकों में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग का **समय-समय पर विस्तृत आकलन करना चाहिए।**
  - **अत्याधुनिक ई-अपशिष्ट रीसाइक्लिंग फैसिलिटी स्थापित करना,** ई-अपशिष्ट रीसाइक्लिंग के बारे में जन जागरूकता एवं भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी "रीसाइकिल फॉर रिसोर्सेज" अभियान, जैसी पहलों के बारे में सोचना चाहिए।
  - एक से अधिक देशों से **आयात** के बारे में सोचना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत की आर्थिक संवृद्धि, एनर्जी ट्रांजीशन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है। देश में ही इन खनिजों के खनन, रिफाइनिंग और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रभावी नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। इससे इन खनिजों के आयात पर निर्भरता कम करने और लंबे समय तक इनकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

[38] Minerals Security Partnership

© Vision IAS

11.2. प्रमुख एवं लघु खनिज (Major and Minor Minerals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय खान मंत्रालय ने **बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक** और **क्वार्ट्ज** को लघु खनिजों की सूची से निकालकर "प्रमुख खनिजों" की श्रेणी में शामिल किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- खनिजों का पुनर्वर्गीकरण **डॉ. वी.के. सारस्वत** की अध्यक्षता वाली एक अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

खनिजों के पुनर्वर्गीकरण का कारण

- लघु खनिजों को **प्रमुख खनिजों की श्रेणी** में शामिल करने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि जिन चट्टानों में ये खनिज प्राप्त होते हैं उनमें कुछ क्रिटिकल मिनरल्स भी प्राप्त होते हैं। साथ ही, ये खनिज कई **हाई-टेक इंडस्ट्रीज** में भी प्रयुक्त होते हैं।

पैगमाटाइट चट्टानों में क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अभ्रक की प्राप्ति

- ये खनिज **पैगमाटाइट चट्टानों** में पाए जाते हैं, जिनमें **बेरिल, लिथियम, नियोबियम, टैंटलम, मोलिब्डेनम, टिन, टाइटेनियम और टंगस्टन** जैसे कई क्रिटिकल मिनरल्स भी मौजूद होते हैं।
- पहले जब क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अभ्रक को **लघु खनिज के रूप में पट्टे पर दिया जाता** था, तो पट्टाधारक क्रिटिकल मिनरल्स की मौजूदगी के बारे में या तो जानकारी नहीं देते थे या इनकी प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते थे।

बैराइट और इसका औद्योगिक महत्व

- बैराइट अक्सर **चूना पत्थर (लाइमस्टोन) और डोलोस्टोन** में **कंक्रीट एवं वेन फीलिंग्स के रूप में** पाया जाता है। साथ ही, यह **एंटीमनी, कोबाल्ट, तांबा, सीसा, मैंगनीज** और **चांदी के अयस्कों** में भी पाया जाता है।
- बैराइट का इस्तेमाल **अलग-अलग प्रकार के औद्योगिक कार्यों** में होता है। इसका उपयोग **ऑयल और गैस ड्रिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टी.वी. स्क्रीन, रबर, कांच, सिरेमिक, पेंट, एक्स-रे उत्सर्जन को रोकने, चिकित्सा उपकरणों के निर्माण आदि** में होता है।

प्रमुख एवं लघु खनिजों के बारे में

- खनिज प्राकृतिक पदार्थ हैं, जो कार्बनिक (ऑर्गेनिक) या अकार्बनिक (इनऑर्गेनिक) रूप से उत्पन्न होते हैं। इन खनिजों में कुछ **निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण मौजूद होते हैं**। ये खनिज वास्तव में चट्टानों एवं अयस्कों के रूप में मौजूद होते हैं।
- **खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957** के तहत खनिजों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है- **प्रमुख खनिज (Major minerals) और लघु खनिज (Minor minerals)**।
  - "लघु खनिज" उन खनिजों को संदर्भित करता है जो भवन निर्माण में उपयोग किए जाते हैं, जैसे- पत्थर, बजरी, साधारण मृदा, और विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली रेत। इसके अलावा, इसमें साधारण रेत और वे अन्य खनिज शामिल हैं, जिन्हें केंद्र सरकार लघु खनिज के रूप में अधिसूचित करती है।
  - **"प्रमुख खनिज"** में वे सभी खनिज शामिल होते हैं जो लघु खनिजों के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं। **प्रमुख खनिज के उदाहरण हैं-** कोयला, लोहा, जस्ता, चूना-पत्थर आदि।

निष्कर्ष

बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक (माइका) और क्वार्ट्ज को 'प्रमुख खनिजों' के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाना, इनकी बढ़ती रणनीतिक और औद्योगिक महत्ता को दर्शाता है। यह कदम बेहतर विनियमन सुनिश्चित करता है, क्रिटिकल मिनरल्स की खोज को प्रोत्साहित करता है, और भारत की खनिज नीति को नई तकनीकों के विकास की आवश्यकताओं और आर्थिक जरूरतों के अनुरूप बनाता है।

11.2.1. जिला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation: DMF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोयला खदानों और इस्पात पर संसदीय स्थायी समिति ने संसद में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में भारत में **जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) फंड** और **प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)** की कार्यप्रणाली की समीक्षा प्रस्तुत की गई है।

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के बारे में

- **गठन:** इसका गठन **2015** में हुआ था। इसका गठन खान और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957 में संशोधन करके किया गया था।
- **प्रकार:** खनिजों के खनन से प्रभावित प्रत्येक भारतीय जिले में **जिला खनिज फाउंडेशन का गठन किया जाता है। DMF फंड** एक **गैर-लाभकारी वैधानिक निधि** है। इसे गैर-लाभकारी ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया जाता है।
- **महत्व और स्थिति:**
  - **भागीदारी आधारित शासकीय कानूनों के अनुकूल:** जिला खनिज फाउंडेशन की कार्यप्रणाली संविधान की **पांचवीं और छठी अनुसूची (**आदिवासी क्षेत्र); पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996; तथा वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 से भी निर्देशित होती है।
  - **23 राज्यों के 645 जिलों में** जिला खनिज फाउंडेशन का गठन किया गया है।
  - जिला खनिज फाउंडेशन को पिछले एक दशक में **1 लाख करोड़ रुपये से अधिक फंड** प्राप्त हुए हैं।
  - **DMF फंड प्राप्त करने के मामले में शीर्ष राज्य:** ओडिशा (29%), छत्तीसगढ़ (14%), और झारखंड (13%)।

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) के बारे में

- **शुरुआत:** इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 2015 में **MMDR अधिनियम, 1957 की धारा 20A के तहत** की गई थी।
- **कार्यान्वयन तंत्र:** राज्य सरकारों को जिला खनिज फाउंडेशन से संबंधित नियमों में PMKKKY को शामिल करना अनिवार्य होता है।

जिला खनिज फाउंडेशन से जुड़ी चुनौतियां

- **गवर्नेंस संबंधी समस्याएं:**
  - **अधिकारियों का दबदबा:** DMFs ज़्यादातर **जिला कलेक्टरों** द्वारा नियंत्रित होते हैं। इनमें खनन से प्रभावित समुदाय का प्रतिनिधित्व बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए, iForest रिपोर्ट के अनुसार, केवल पाँच राज्यों ने ही DMFs के शासी परिषदों में खनन से प्रभावित लोगों को शामिल किया है।
  - **स्वायत्तता की कमी:** संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिला कलेक्टर ही जिला खनिज फाउंडेशन के **शासी परिषद** और **प्रबंधन समिति,** दोनों का अध्यक्ष होता है। इस वजह से ये फाउंडेशन स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं।
- **योजना और लाभार्थी की पहचान में कमी:** किसी भी जिले ने पाँच साल की परिप्रेक्ष्य योजना (पर्सपेक्टिव प्लान) प्रकाशित नहीं की है।
  - **उदाहरण के लिए,** संसदीय समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, ग्राम सभा की कम भागीदारी (जो टॉप-डाउन अप्रोच को दर्शाती है) सहभागी निर्णय लेने की प्रक्रिया को कमज़ोर करती है।
- **फंड के उपयोग से जुड़ी चुनौतियां:**
  - **कम खर्च:** iForest की रिपोर्ट के अनुसार, एकत्र किए गए **फंड का केवल 40% ही उपयोग किया गया है,** जो परियोजना के क्रियान्वयन में देरी को दर्शाता है। **उदाहरण के लिए-** झारखंड, ओडिशा और राजस्थान जैसे प्रमुख राज्यों में फंड का उपयोग काफी कम हुआ है।

© Vision IAS

- **शिकायत निवारण और निगरानी प्रक्रिया का मजबूत नहीं होना:** अधिकतर ज़िलों में शिकायत निवारण तंत्र सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। कितनी शिकायतों का समाधान हुआ, इस पर कोई डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।
  - उदाहरण के लिए- संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, **'DMF फंड उपयोग सूचकांक'** नहीं होने की वजह से फंड के उपयोग में पारदर्शिता नहीं आ पाती है।
- **आकांक्षी ज़िलों में PMKKKY लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई:** संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 112 आकांक्षी ज़िलों में से 106 DMF ज़िले हैं, फिर भी खनन के दुष्प्रभावों को कम करने का PMKKKY का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है।

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के गवर्नेंस और कार्यान्वयन में सुधार

- **गवर्नेंस संबंधी सुधार:**
  - यह सुनिश्चित करना चाहिए कि DMFs स्वतंत्र रूप से और समुदाय के नेतृत्व वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करें, न कि जिला प्रशासन की शासकीय यूनिट के रूप में। **उदाहरण के लिए-** DMFs के संचालन में ग्राम सभाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- **भागीदारीपूर्ण योजना और दीर्घकालिक दृष्टिकोण:** सभी DMFs को स्थानीय समुदाय के परामर्श से **पांच-वर्षीय व्यापक योजनाएं** तैयार करनी चाहिए।
  - ये योजनाएं जिला के विकास-लक्ष्यों के अनुरूप होनी चाहिए, लेकिन इसमें खनन-प्रभावित लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **PMKKKY दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करना:** DMF फंड का कम-से-कम **70%** अति-महत्वपूर्ण क्षेत्रकों को आवंटित किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रकों में स्वास्थ्य देखभाल सेवा, शिक्षा, आजीविका और कौशल विकास, तथा पेयजल आपूर्ति और सैनिटेशन शामिल हैं। राज्य सरकारों को राष्ट्रीय PMKKKY दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- **सोशल ऑडिट और वित्तीय समीक्षा अनिवार्य करना:** स्वतंत्र **थर्ड पार्टी एजेंसियों** द्वारा नियमित रूप से ऑडिट करवाया जा सकता है।
  - **नियंत्रक-महालेखापरीक्षक** को DMF के व्यय और उसके प्रभाव का **समय-समय पर मूल्यांकन** करना चाहिए।

निष्कर्ष

अपने गठन के एक दशक बाद भी, जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है। समस्या फंड की कमी नहीं, बल्कि वांछित उद्देश्यों को पूरा करने के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। DMF के तहत निर्धारित लक्ष्यों को वास्तव में पूरा करने के लिए, हमें तत्काल व्यवस्थागत सुधारों को अपनाने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में खनन से प्रभावित समुदायों को निर्णय लेने के प्रक्रिया के केंद्र में रखना आवश्यक है।

11.2.2. भारत में अपतटीय खनिज (Offshore Minerals in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने **अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024** तैयार किए हैं।

भारत में अपतटीय खनिजों के बारे में

- **अपतटीय खनन:** यह 200 मीटर से अधिक की गहराई पर, **गहरे समुद्र तल से खनिज भंडार प्राप्त करने की प्रक्रिया** है।
- **विस्तार:** दो मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक के **भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में बड़ी मात्रा में प्राप्ति योग्य अपतटीय खनिज संसाधन मौजूद** हैं।
- **खनिज भंडार:** भारत के अपतटीय खनिज भंडार में **सोना, हीरा, तांबा, निकल, कोबाल्ट, तांबा, मैंगनीज,** और विकास के लिए आवश्यक **रेयर अर्थ एलिमेंट्स** शामिल हैं।

अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024

- **किन खनिजों पर लागू होगा:** ये नियम **सभी खनिजों पर लागू** होते हैं, **सिवाय खनिज तेल, हाइड्रोकार्बन** तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की पहली **अनुसूची के भाग B में सूचीबद्ध खनिजों को छोड़कर।**

- **परिभाषाएं:** इसके लिए नियम में खनिज प्राप्ति के कई चरणों हेतु संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण (UNFC) और **खनिज भंडार अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग मानक समिति (CRIRSCO)**[39] टेम्पलेट के संशोधित संस्करण का उपयोग किया गया है। **ये चरण निम्नलिखित हैं:**
    - **अन्वेषण चरण (Exploration Stages):** किसी भी खनिज भंडार की खोज में चार चरण शामिल हैं:
        - **टोही सर्वेक्षण/Reconnaissance survey (G4)**
        - **प्रारंभिक अन्वेषण (G3)**
        - **सामान्य अन्वेषण (G2)**
        - **विस्तृत अन्वेषण (G1)**
    - **संभाव्यता अध्ययन (Feasibility Studies) चरण:** संभाव्यता अध्ययन के चरणों में- **भूवैज्ञानिक अध्ययन (F3), पूर्व-संभाव्यता अध्ययन (F2) और संभाव्यता अध्ययन (F1)** शामिल हैं।
- **अन्वेषण मानक (Exploration Standards):** नए नियम अपतटीय खनिज संसाधनों के सटीक आकलन और संधारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए सख्त अन्वेषण मानकों को अनिवार्य करते हैं।
    - **खनन पट्टे देने के लिए** संकेतित खनिज संसाधन की पुष्टि हेतु कम से कम **सामान्य अन्वेषण (G2)** उप-चरण पूरा होना आवश्यक है।
- **विशिष्ट अन्वेषण मानदंड:** ये नियम अलग-अलग प्रकार के खनिज भंडारों और खनिजों के लिए विशिष्ट अन्वेषण मानदंड निर्धारित करते हैं। इसके तहत कंस्ट्रक्शन-ग्रेड सिलिका सैंड, कैलकेरियस मृदा, फॉस्फेटिक तलछट, डीप-सी मिनरल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE) खनिज, हाइड्रोथर्मल खनिज और नोड्यूल आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष

'अपतटीय क्षेत्र (खनिज संसाधनों की विद्यमानता) नियम, 2024' भारत की विशाल समुद्री खनिज संसाधनों के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नियम खनिजों की खोज के लिए स्पष्ट मानक सुनिश्चित करके और वैश्विक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के दायरे में रहकर संसाधनों के संधारणीय और पारदर्शी उपयोग को बढ़ावा देते हैं। साथ ही ये निवेश आकर्षित करने और भारत के लिए सतत खनिज आपूर्ति सुनिश्चित करने का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं।

11.3. भारत में कोयला क्षेत्रक: एक नज़र में (Coal Sector in India at a Glance)

[39] Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards

11.4. भारत में इस्पात क्षेत्रक: एक नज़र में (Steel Sector in India at a Glance)

भारत में इस्पात क्षेत्रक

इस्पात क्षेत्रक: मुख्य तथ्य

उत्पादन लक्ष्य: 2034 तक 500 मिलियन टन।	**आर्थिक योगदान:** GDP का लगभग 2% तक।	**रोजगार के अवसर: रोजगार गुणक प्रभाव 6.8X और आउटपुट गुणक प्रभाव 1.4X तक।**

प्रमुख चुनौतियां

पूंजी-गहन: 1 टन इस्पात बनाने की ग्रीनफील्ड क्षमता स्थापित करने के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ती है।	**लॉजिस्टिक की उच्च लागत:** जमशेदपुर से मुंबई तक माल ढुलाई की लागत 50 डॉलर प्रति टन तक हो सकती है, जबकि रॉटरडैम से मुंबई तक यह प्रति टन 34 अमेरिकी डॉलर है।	**कच्चे माल की कमी:** उदाहरण के लिए- कोकिंग कोल का भंडार न के बराबर है।	**प्रति व्यक्ति खपत कम:** 2023-24 में 97.7 किग्रा (जबकि विश्व के लिए 219.3 किग्रा)।	**अन्य:** अत्यधिक ऊर्जा-गहन उद्योग, निर्यात संबंधी चुनौतियां आदि।

इस्पात क्षेत्रक को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहलें

राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017	मेक इन इंडिया पहल	स्पेशलिटी स्टील हेतु उत्पादन-से-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना	**अन्य:** मिशन पूर्वोदय, संशोधित इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (SIMS) 2.0 आदि।

आगे की राह

विकार्बनीकरण: इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी स्वच्छ तकनीक में निवेश करना।	**तकनीकी उन्नयन: अनुसंधान एवं विकास, AI, स्वचालन उत्पादकता को बढ़ावा देना आदि।**	**उत्पाद विविधीकरण:** उदाहरणार्थ- ऑटोमोटिव और एयरोस्पेस के इस्तेमाल के लिए विशेष मिश्र धातुएं।

11.5. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
अपतटीय खनन	क्रिटिकल मिनरल्स	खनिज अन्वेषण	विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ)	ऊर्जा सुरक्षा
संधारणीय खनन	खनिज भंडार	जिला खनिज फाउंडेशन	राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन	प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
पॉलीमेटेलिक नोड्यूल	दुर्लभ भू तत्व	कोल बेड मीथेन	शेल गैस	

11.6. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

भारत के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) की रणनीतिक महत्ता का परीक्षण कीजिए। क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में प्रमुख चुनौतियां क्या हैं?

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
NCCM का परिचय दीजिए	आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में NCCM का महत्व	क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में प्रमुख चुनौतियां	उचित निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए

© Vision IAS

12. नवाचार और उद्यमिता (Innovation and Entrepreneurship)

12.1. डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure: DPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

'DPI पर भारत के G-20 टास्क फोर्स की रिपोर्ट' जारी की गई है। यह रिपोर्ट **'आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए DPI पर भारत के G-20 टास्क फोर्स'** ने जारी की है।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) क्या है?

- यह **साझा डिजिटल सिस्टम्स** का एक सेट है, जो-
  - **सुरक्षित और इंटर-ऑपरेबल** होना चाहिए,
  - **खुले मानकों और विशिष्टताओं के आधार पर विकसित होना** चाहिए, ताकि यह सामाजिक स्तर पर सार्वजनिक और/ या निजी सेवाओं तक न्यायसंगत पहुंच और उनका वितरण सुनिश्चित कर सके।
  - **लागू कानूनी फ्रेमवर्क और सक्षम नियमों द्वारा शासित** होना चाहिए, ताकि विकास, समावेशन, नवाचार, विश्वास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सके तथा मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान कर सके।
- **DPI क्या 'नहीं' है?**
  - **ऐसे उपाय जो DPI के पूरक** हैं: उदाहरण के लिए- **कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर** जो भौतिक अवसंरचना के माध्यम से व्यक्तियों की मोबाइल और इंटरनेट तक पहुंच में सुधार करता है।
  - **ऐसी डिजिटल प्रक्रियाएं जो निजी नवाचार को बढ़ावा नहीं देती:** उदाहरण के लिए- सरकारी पोर्टल बनाने के लिए मौजूदा भौतिक प्रक्रियाओं या वर्कफ्लो को डिजिटल रूप देना।

DPI का महत्व

- **विकास में तेजी लाना:** इसका आर्थिक विकास पर काफी असर पड़ता है। उदाहरण के लिए- भारत ने DPI की मदद से एक दशक से भी कम समय में वित्तीय समावेशन का वह स्तर हासिल कर लिया है, जिसे DPI के बिना हासिल करने में पांच दशक लग जाते।
- **नवाचार को बढ़ावा:** DPI लेन-देन की लागत कम करता है, एक-दूसरे के बीच समन्वय के माध्यम से प्रतिस्पर्धा बनाए रखता है तथा निजी पूंजी को आकर्षित करता है। इसके परिणामस्वरूप नवाचार को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, **फोन-पे (फिनटेक कंपनी)** की 12 बिलियन डॉलर की कंपनी बनना काफी हद तक DPI के कारण संभव हुआ है।
- **समावेशी विकास:** DPI विशेष रूप से सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली आबादी, महिलाएं, SMEs जैसे कमजोर समूहों की विभिन्न सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है। इससे समूहों के बीच मौजूद असमानताओं को दूर करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए- भारत में खोले गए बैंक खातों की संख्या 2015 की 147.2 मिलियन से तीन गुना बढ़कर 2023 में 508.7 मिलियन हो गई। इनमें 55% खाते महिलाओं के नाम पर हैं।
- **प्रभावी तरीके से सार्वजनिक सेवा वितरण:** उदाहरण के लिए- DPI ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं के तहत प्रभावी तरीके से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) को संभव बनाया है। इससे सरकार को लगभग 41 बिलियन डॉलर की बचत हुई है।
- **संकट में भी कारगर:** उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी के दौरान, दुनिया भर के देशों ने अपने नागरिकों को टीकाकरण का डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करके महामारी से निपटने में DPI की मदद ली।
- **व्यक्तियों को सशक्त बनाना:** DPI **व्यक्तियों की आर्थिक प्रगति** सुनिश्चित करके तथा उनके पैसे और डेटा पर नियंत्रण जैसे प्रमुख **डिजिटल अधिकारों** की रक्षा करके व्यक्तियों को सशक्त बनाता है।
- **अन्य वजहें जो DPI के महत्त्व को उजागर करती हैं:**
  - यह **वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण** है क्योंकि इसमें सार्वजनिक और निजी, दोनों के वित्त-पोषण के मिश्रण का उपयोग किया जाता है।
  - यह **महत्वपूर्ण (क्रिटिकल) राष्ट्रीय अवसंरचना** पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करता है।

भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में

- **इंडिया स्टैक:** यह भारत का अपना मूलभूत DPI है। इसमें 3 परस्पर जुड़ी लेयर्स शामिल हैं:
  - **आइडेंटिटी लेयर-** (जैसे, आधार नंबर, e-KYC आदि),
  - **पेमेंट लेयर-** (जैसे, UPI, आधार पेमेंट ब्रिज आदि) और
  - **डेटा गवर्नेंस लेयर-** (जैसे, डिजिलॉकर, अकाउंट एग्रीगेटर आदि)।

आगे की राह

- ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के गहन शोध और विश्लेषण आधारित **व्यापक तथा चरणबद्ध दृष्टिकोण** को अपनाने की आवश्यकता है।
- **खुले और रीयूजेबल प्रौद्योगिकी फ्रेमवर्क का समर्थन करना चाहिए।**
  - उदाहरण के लिए- **देशों की संप्रभुता और डेटा स्वामित्व सुनिश्चित** करते हुए, कुछ तरह की DPI का उपयोग करने के लिए देशों को प्लग एंड प्ले करने की अनुमति देने हेतु **रीयूजेबल** प्रबंधित सर्विस मॉडल का पता लगाया जाना चाहिए।
- DPI के उपयोग से जुड़े अपने अनुभव साझा करने के लिए **वार्षिक DPI फोरम** आयोजन के जरिए संवाद और क्रियान्वयन को बढ़ावा देना चाहिए।
- **अन्य:** देशों के बीच **द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संपर्क को बढ़ावा देना;** DPI पर **केंद्रित संस्थान** की स्थापना की जानी चाहिए। यह संस्थान उचित तकनीक और शैक्षणिक विशेषज्ञता के साथ नीतिगत पहलुओं और रणनीतियों के निर्माण तथा इनके कार्यान्वयन पर कार्य करेगा; **DPI को अधिक प्रभावी और दक्ष बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का लाभ उठाना चाहिए।**

निष्कर्ष

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) समावेशी विकास, इनोवेशन और सरकारी सेवाओं के प्रभावी वितरण में व्यापक बदलाव लाने की दिशा में कार्य करता है। इंडिया स्टैक जैसी पहलों में भारत की सफलता यह दर्शाती है कि DPI वित्तीय समावेशन को तेजी से बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने की अपार क्षमता रखता है। भविष्य में, सतत विकास को वैश्विक स्तर पर प्राप्त करने के लिए वैश्विक सहयोग, लचीले मानक और रणनीतिक निवेश अत्यंत आवश्यक हैं।

12.2. डीप टेक के लिए इनोवेशन इकोसिस्टम (Innovation Ecosystem for Deep Tech)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने भारतीय स्टार्ट-अप्स से आग्रह किया कि वे डीप टेक इनोवेशन पर अधिक ध्यान केंद्रित करें।

डीप टेक स्टार्ट-अप्स क्या हैं?

- डीप टेक्नोलॉजी या डीप टेक से तात्पर्य **एडवांस वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताओं** पर आधारित इनोवेशन या नवाचार से है। इसमें कई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
- डीप टेक स्टार्टअप्स या तो मौजूदा **एडवांस तकनीकों का उपयोग करके जटिल और अक्सर अनसुलझी समस्याओं के नए समाधान** विकसित करते हैं, या फिर **मूलभूत विज्ञान और इंजीनियरिंग सिद्धांतों पर आधारित और भी अधिक एडवांस्ड तकनीकों का आविष्कार** करते हैं।

भारत में डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में

- **संख्या:** भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के अनुमान के अनुसार, वर्तमान में भारत में 4,000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स कार्यरत हैं तथा अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या 10,000 तक पहुंच जाएगी।
- **विश्व में भारत की स्थिति:** नैसकॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार, डीप टेक स्टार्टअप्स की तीसरी सर्वाधिक संख्या होने के बावजूद, भारत 2023 में **दुनिया के शीर्ष 9 डीप-टेक इकोसिस्टम में छठे स्थान पर था।**
- **फंडिंग:** नैसकॉम के अनुसार, भारत के 4,000 डीप-टेक स्टार्टअप्स ने 2024 में 1.6 बिलियन डॉलर आकर्षित किए, जो पिछले साल की तुलना में 78 प्रतिशत की वृद्धि है।

 © Vision IAS

भारत में डीप टेक स्टार्टअप्स क्यों पिछड़ रहे हैं?

- **संस्थाओं से समर्थन प्राप्ति में कमी: प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय** द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में सरकार द्वारा वित्त पोषित छह अनुसंधान और विकास संगठनों में से केवल एक ही डीप टेक स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करता है।
- **लगातार फंडिंग की कमी:** 2023 में, भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स ने पिछले वर्ष की तुलना में फंडिंग प्राप्त करने में गिरावट दर्ज की, लेकिन 2024 में इसमें वृद्धि देखी गई।
  - इसके अतिरिक्त, भारत में **वेंचर कैपिटल फंड** आमतौर पर अपने निवेश पर त्वरित लाभ की अपेक्षा रखते हैं और लंबे समय तक रिटर्न के लिए प्रतीक्षा करने को लेकर संकोच करते हैं।
- **लाभकारी बनने में समय लगाना:** डीप टेक स्टार्टअप को पूर्ण रूप से विकसित होने में लंबा वक्त और अधिक पूंजी की जरुरत पड़ती है। साथ ही, इसमें तकनीक के सफलता के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के स्टार्टअप में जोखिम अधिक होता है।
- **भारत में उपभोक्ता सेवा आधारित स्टार्टअप पर अधिक बल:** भारत में स्टार्टअप बूम उपभोक्ता-आधारित व्यवसायों (जैसे कि फूड डिलीवरी या ई-कॉमर्स ऐप) के कारण है। इनमें डीप-टेक स्टार्टअप की भागीदारी बहुत कम है।
- **अधिक नियमों के पालन का बोझ:** डीप टेक क्षेत्र के लिए विनियमन को लेकर स्पष्ट और सर्वमान्य दृष्टिकोण का अभाव है। इसके साथ ही, नीतिगत अस्थिरता (जैसे- एंजल टैक्स का लागू होना और फिर वापस लिया जाना), लालफीताशाही, और निवेशकों में जोखिम उठाने की सीमित इच्छा जैसे कारक इस क्षेत्र के विकास में प्रमुख बाधाएं उत्पन्न करते हैं।
- **शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग जगत के बीच समन्वय की कमी:** इस कारण शोध कार्यों को व्यावसायिक रूप देने और उन्हें व्यावहारिक उपयोग के अनुरूप डिजाइन करने में कठिनाई होती है, जिससे डीप टेक इकोसिस्टम के समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

भारत के डीप टेक इकोसिस्टम के लिए विभिन्न पहलें

डीप टेक फंड ऑफ फंड्स
केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित

राष्ट्रीय डीप टेक स्टार्ट-अप नीति का मसौदा
यह फंड ऑफ फंड्स का गठन करने तथा प्रौद्योगिकी के व्यवसायीकरण और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने वाला एक नीतिगत फ्रेमवर्क है।

अदिति (ADITI) योजना
क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुदान।

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन
इसका उद्देश्य एक "रिसर्च एंड इनोवेशन क्लाउड" तैयार करना है, जिससे कम उपयोग किए जा रहे वैज्ञानिक उपकरण और प्रयोगशालाएं सभी के लिए उपलब्ध हो सकें।

थीमेटिक मिशन
ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति, AIRAWAT, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, इंडियाAI मिशन, आदि

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
USA के साथ 'इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी (iCET)', जापान के साथ 'रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन' और क्वाड सदस्यों द्वारा 'QUIN'

निष्कर्ष

एक समृद्ध डीप-टेक इकोसिस्टम भारत को इनोवेशन के मामले में विश्व में अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकता है। लक्षित नीतिगत समर्थन, मजबूत अनुसंधान एवं विकास (R&D) फ्रेमवर्क, और दीर्घकालिक पूंजी निवेश से डीप-टेक स्टार्टअप्स 'राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों के नेक्स्ट जनरेशन समाधान' विकसित करने में सक्षम हो सकते हैं।

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026
▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
DELHI : 15 जुलाई, 2 PM | JAIPUR : 24 जून | JODHPUR : 2 जुलाई
Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.
/visionias.upsc /c/VisionIASdelhi /c/VisionIASdelhi /t.me/s/VisionIAS_UPSC
DELHI: GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 CONTACT: 8468022022, 9019066066
AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

12.2.1. भारत में अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र: एक नज़र में (Research and Development Ecosystem in India at a Glance)

भारत में अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम

राष्ट्रीय संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण

औद्योगिक रूपांतरण द्वारा, उत्पादकता बढ़ाकर, बाजारों का विस्तार करके, रोजगार सृजन करके तथा संपत्ति और पूंजी सृजन करके **आर्थिक संवृद्धि को बनाए रखना।**	**ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना।**	संधारणीय विकास के लिए **सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान** करना और भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करना।	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), रोबोटिक्स, बिग डेटा विश्लेषण जैसे **उभरते तकनीकी क्षेत्रकों में भविष्य की तैयारी को सुगम बनाना।**	**अन्य: विदेशी निवेश आकर्षित करना; आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और व्यापार असंतुलन का समाधान करना आदि।**

अनुसंधान एवं विकास क्षेत्रक के समक्ष मौजूद चुनौतियां

वित्तीय बाधा: वर्ष 2020-21 के दौरान निजी क्षेत्रक ने R&D (GERD) पर सकल व्यय में केवल **36.4% का योगदान** दिया था।	**भारत की शिक्षा प्रणाली में लगातार समस्याएं:** अनुसंधान के अवसर प्रदान करने वाले संस्थानों की कमी; पुराना पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति; आदि।	**सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे:** जोखिम-विरोधी पारितंत्र; प्रतिभा पलायन और समावेशिता का अभाव।	बुनियादी अनुसंधान पर अधिक ध्यान और कम उद्योग-अकादमिक अभिसरण के कारण अनुसंधान को सफल प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करने में चुनौतियां विद्यमान हैं।	**संरचनात्मक मुद्दे:** खंडित अनुसंधान एवं विकास पारितंत्र; संकीर्ण फोकस; योजना/ रणनीति बनाने में कमी आदि।

अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

अनुसंधान एवं विकास में निजी निवेश को सुगम बनाना: वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन, स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति आदि के माध्यम से।	पेटेंट दाखिल करने और अनुसंधान प्रस्तावों से संबंधित **विनियामकीय प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना।**	**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** संयुक्त राज्य अमेरिका, इजरायल आदि के साथ द्विपक्षीय समझौते।	**साथी (SATHI), SAIF आदि योजनाओं के माध्यम से शोधकर्ताओं को अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करना।**	रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करने हेतु **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना** की गई है।

आगे की राह: भारत को वैश्विक अनुसंधान एवं विकास का केंद्र बनाना

संयुक्त निवेश के लिए जोखिम-मुक्त तंत्र जैसे उपायों के माध्यम से **निजी क्षेत्रक से निवेश को प्रोत्साहित करके अनुसंधान एवं विकास निवेश में वृद्धि करना;** प्रोत्साहनों का प्रावधान करना आदि।	**शैक्षिक प्रणाली में सुधार:** कुशल गवर्नेंस तंत्र विकसित करना; नवाचार संबंधी मानसिकता को बढ़ावा देना; अनुसंधान को एक आकर्षक करियर विकल्प के रूप में बढ़ावा देना; आदि।	उद्योग-अकादमिक जगत के मध्य जुड़ाव को बढ़ाकर और अनुप्रयोग-उन्मुख अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में निवेश करके **अनुसंधान गतिविधियों का व्यवसायीकरण करना।**	प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और नीति आयोग जैसी संस्थाओं का उपयोग करके अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की रणनीति बनाना; अनुसंधान प्रोत्साहन गतिविधियों को राष्ट्रीय मिशनों के साथ जोड़ना; आदि।

12.3. वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2024 और सामाजिक उद्यमिता (Global Innovation Index 2024 and Social Entrepreneurship)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO), कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड (INSEAD) बिजनेस स्कूल** ने संयुक्त रूप से **वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII), 2024** जारी किए।

वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) 2024 के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

भारत की स्थिति:

- **भारत विश्व की 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर** है। 2023 में भारत 40वें स्थान पर था। इस तरह भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। भारत का स्कोर 38.3 है।
- ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट, रचनात्मक आउटपुट, संस्थान और व्यावसायिक आधुनिकता के मामले में भारत **निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं** तथा **मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहले स्थान पर** है।
- बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के शीर्ष 100 क्लस्टर्स** में शामिल हैं।

सामाजिक उद्यमिता और उद्यम

- सामाजिक उद्यमिता वास्तव में **गरीबी, पर्यावरणीय संधारणीयता और सामाजिक अन्याय** जैसी अनेक समस्याओं का समाधान करते हुए **आर्थिक संपदा का सृजन** है।
- यह **लाभकारी उद्यमियों की दक्षता, नवाचार और संसाधनों** को गैर-लाभकारी संगठनों के **जज़्बे, मूल्यों, मिशन और चिंताओं** के साथ जोड़ती है।

सामाजिक उद्यमिता और सामाजिक उद्यमों की क्षमता/ महत्व

- **आर्थिक संवृद्धि:** ये **वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर** का योगदान करते हैं।
  - **भारत में सामाजिक उद्यमों के लिए अनुमानित बाजार अवसर और क्षमता 2025 तक 8 बिलियन डॉलर** होने की संभावना व्यक्त की गई है।
- **विशेषज्ञता के माध्यम से नीति को प्रभावित करना:** उदाहरण के लिए- **इथियोपियाई** नीति निर्माताओं ने **टेबिटा (Tebita) एम्बुलेंस** के साथ सहयोग किया ताकि **आपातकालीन चिकित्सा सेवा मानक और लाइसेंसिंग प्रणाली** बनाई जा सके। **टेबिटा एम्बुलेंस** एक सामाजिक उद्यम है।
- **सतत विकास:** उदाहरण के लिए- **SELCO** भारत स्थित एक सामाजिक उद्यम है। यह **वंचित परिवारों** और व्यवसायियों को **संधारणीय ऊर्जा समाधान प्रदान** करता है।
- **कंपनियों में सामाजिक नवाचार को एकीकृत करना:** ये पारंपरिक कंपनियों को **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से कॉर्पोरेट सामाजिक नवाचार** की ओर उन्मुख करने में सहायता करते हैं।
- **सामाजिक परिवर्तन:** ये समाज के **वंचित और अभावग्रस्त वर्गों को सशक्त बनाने** और पारंपरिक व्यवसाय मॉडल के कारण बढ़ती **आर्थिक असमानता** का समाधान करते हैं।

सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा की गई पहलें

- अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने तथा भारतीय स्टार्ट-अप्स एवं MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित की शुरुआत की गई है-
  - **अटल इनोवेशन मिशन (AIM);**
  - **नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना (ASPIRE)**[40]; और
  - **आत्मनिर्भर भारत ARISE-ANIC कार्यक्रम**
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR): कंपनी अधिनियम, 2013** के तहत कुछ कंपनियों के लिए **सामाजिक कल्याण गतिविधियों** हेतु CSR परियोजनाएं शुरू करना अनिवार्य किया गया है।
- **सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE):** इसका उद्देश्य सामाजिक उद्यमों को **सामने लाना और वित्तीय स्रोत प्राप्त करने में मदद करना है।**
- **सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड:** उदाहरण के लिए- **स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड-इनकम हाउसिंग (SWAMIH) निवेश फंड** भारत का सबसे बड़ा सोशल इम्पैक्ट बॉण्ड है।

---

[40] A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industries and Entrepreneurship

निष्कर्ष

सामाजिक उद्यमिता और उद्यम वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए ये **व्यावसायिक नवाचार को सामाजिक लक्ष्यों** के साथ जोड़ते हैं। सहायक नीतियों, अवसंरचना में निवेश और वित्त-पोषण के जरिए ऐसा अनुकूल परिवेश बनाया जा सकता है जहां सामाजिक उद्यम विकसित हो सके, **संधारणीय विकास** को बढ़ावा मिले और वैश्विक स्तर पर स्थायी सकारात्मक प्रभाव पैदा हो।

12.4. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर या वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centers: GCC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

PwC की **"कैटालाइजिंग वैल्यू क्रिएशन इन इंडियन ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स"** नामक रिपोर्ट में कहा गया है कि **25% से भी कम** बिजनेस लीडर्स अपने GCC परिचालन को भारत से स्थानांतरित करने पर विचार कर रहे हैं।

वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) क्या है?

- ये **बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा स्थापित अपतटीय इकाइयां हैं,** जो अपने मूल संगठनों को IT, अनुसंधान एवं विकास, ग्राहक सहायता और व्यावसायिक परिचालन जैसी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करती हैं।
    - भारत में GCC की संख्या वित्त वर्ष 2019 में लगभग 1,430 थी। यह वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर **1,700** हो गयी।

भारत में वैश्विक क्षमता केंद्र विकास के मुख्य चालक

- **कुशल प्रतिभा युक्त कार्यबल:** IT, एनालिटिक्स और वित्त में विशेषज्ञता वाला एक बड़ा, विविध कार्यबल GCC को जटिल, हाई-वैल्यू वाले कार्यों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है।
- **सरकार द्वारा समर्थन: डिजिटल इंडिया** और **व्यापार-समर्थक सुधारों** जैसी पहलों ने GCC के विकास के लिए अनुकूल माहौल का सृजन किया है।
- **प्रौद्योगिकी को अपनाना:** AI, मशीन लर्निंग, IoT और ब्लॉकचेन का उपयोग GCC को नवाचार और डिजिटल रूपांतरण को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है।
- **रणनीतिक बदलाव:** भारत में GCCs अब केवल लागत-बचत इकाइयाँ नहीं रह गई हैं, बल्कि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाले रणनीतिक केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं।

भारत के कॉर्पोरेट परिदृश्य पर GCC का प्रभाव

- **आर्थिक संवृद्धि:** GCC हाई-वैल्यू वाले नौकरियों और नवाचार के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद में काफी योगदान देते हैं।
    - **2030 तक** इस क्षेत्रक का आकार 105 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है।
- **रोजगार सृजन और कौशल विकास:** वित्त वर्ष 24 तक, भारत में GCCs ने **लगभग 1.9 मिलियन पेशेवरों को रोजगार प्रदान किया** (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25)।
- **नवाचार एवं अनुसंधान एवं विकास:** कई GCCs अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वैश्विक नवाचार केन्द्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होती है।
    - उदाहरण के लिए, हैदराबाद में स्थित माइक्रोसॉफ्ट का सेंटर अमेरिका के बाहर उसका सबसे बड़ा सेंटर है।
- **बिजनेस प्रैक्टिस अपग्रेड:** जैसे गोल्डमैन सैक्स का बेंगलुरु स्थित GCC एनालिटिक्स और जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रमुख इकाई के रूप में विकसित हुआ है।
- **क्षेत्रीय विकास:** GCC का **टियर-2/3 शहरों तक विस्तार** क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दे रहा है, असमानताओं को कम कर रहा है, तथा स्थानीय अवसंरचना और रोजगार को बढ़ा रहा है।

निष्कर्ष

GCC ने भारत को लागत-बचत वाले गंतव्य से रणनीतिक नवाचार केंद्र में तब्दील किया है। प्रतिभा युक्त कार्यबल, प्रौद्योगिकी और नीतिगत समर्थन से GCC संधारणीय विकास को बढ़ावा देने और 2045 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के भारत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी।

© Vision IAS

12.5. मुख्य शब्दावलियां (Key Words)

मुख्य शब्दावलियां				
संरचनात्मक परिवर्तन	ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर	डीप टेक स्टार्टअप	वैश्विक नवाचार सूचकांक	सामाजिक उद्यमिता
सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद	उद्यम पूंजी	कॉर्पोरेट सामाजिक नवाचार	सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज	श्रम उत्पादकता
अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम	नीतिगत सुधार	सार्वजनिक अवसंरचना		

12.6. अभ्यास प्रश्न (Practice Question)

उत्तर लेखन प्रारूप

भारत में क्षेत्रीय विकास और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) की भूमिका पर चर्चा कीजिए। टियर-2 और टियर-3 शहरों तक इनके विस्तार से कैसे अधिक समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

भूमिका	मुख्य भाग 1	मुख्य भाग 2	निष्कर्ष
GCCs का परिचय दीजिए	क्षेत्रीय विकास और तकनीकी नवाचार में इसकी भूमिका	टियर - 2 और टियर-3 शहरों में विस्तार के कारण समावेशी विकास में योगदान	उचित निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए

13. अर्थव्यवस्था: विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न (2013-2024) - (सिलेबस के अनुसार) {Economy Previous Year Question 2013-2024 (Syllabus-Wise)}

सामान्य अध्ययन-III: प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन (GS-III: Technology, Economic Development, Biodiversity, Environment, Security and Disaster Management)

भारतीय अर्थव्यवस्था और नियोजन, संसाधन को जुटाने, प्रगति, विकास और रोजगार से संबंधित विषय (Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment)

- जीवन सामग्रियों के संदर्भ में बौद्धिक संपदा अधिकारों का वर्तमान विश्व परिदृश्य क्या है? यद्यपि भारत पेटेंट दाखिल करने के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, फिर भी केवल कुछ का ही व्यवसायीकरण किया गया है। इस कम व्यवसायीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए। **(2024, 10 अंक)**

  {What is the present world scenario of intellectual property rights with respect to life materials? Although, India is second in the world to file patents, still only a few have been commercialized. Explain the reasons behind this less commercialization. **(2024,10 Marks)**}
- 'देखभाल अर्थव्यवस्था' और 'मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था' के बीच अंतर कीजिए। महिला सशक्तीकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कैसे लाया जा सकता है? **(2023, 15 अंक)**

  {Distinguish between 'care economy' and 'monetised economy'. How can care economy be brought into monetised economy through women empowerment? **(2023, 15 marks)**}
- भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी प्रकृति में संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी की गणना के लिए अपनाई गई पद्धति का परीक्षण कीजिए और सुधार के सुझाव दीजिए। **(2023, 15 अंक)**

  {Most of the unemployment in India is structural in nature. Examine the methodology adopted to compute unemployment in the country and suggest improvements. **(2023, 15 marks)**}
- भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटिकरण की स्थिति क्या है? इस संबंध में आने वाली समस्याओं का परीक्षण कीजिए और सुधार के लिए सुझाव दीजिए। **(2023, 10 अंक)**

  {What is the status of digitalization in the Indian economy? Examine the problems faced in this regard and suggest improvements. **(2023, 10 marks)**}
- जी० डी० पी० में विनिर्माण क्षेत्र विशेषकर एम० एस० एम० ई० की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तेज आर्थिक संवृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर टिप्पणी कीजिए। **(2023, 10 अंक)**

  {Faster economic growth requires increased share of the manufacturing sector in GDP, particularly of MSMEs. Comment on the present policies of the government in this regard. **(2023, 10 marks)**}
- "हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है।" इस कथन को समझाइए। ऐसे संवृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। **(2022, 15 Marks)**

  {Economic growth in the recent past has been led by increase in labour activity." Explain this statement. Suggest the growth pattern that will lead to creation of more jobs without compromising labour productivity. **(2022, 15 Marks)**}
- भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात् परिकलन विधि में अन्तर की व्याख्या कीजिए। **(2021, 10 अंक)**

  {Explain the difference between computing methodology of India's Gross Domestic Product (GDP) before the year 2015 and after the year 2015. **(2021, 10 Marks)**}

© Vision IAS

- क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V-आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है ? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। **(2021, 15 अंक)**

  {Do you agree that the Indian economy has recently experienced V- shaped recovery? Give reasons in support of your answer. **(2021, 15 Marks)**}

- संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) को परिभाषित कीजिए तथा उसके निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। वे कौन-से कारक है, जो भारत को अपने संभाव्य सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) को साकार करने से रोकते रहे हैं? **(2020, 10 अंक)**

  {Define potential GDP and explain its determinants. What are the factors that have been inhibiting India from realizing its potential GDP? **(2020, 10 Marks)**}

- वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिए। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि (जी० एस० टी० कॉम्पेन्सेशन फंड) को प्रभावित और नये संघीय तनावों को उत्पन्न किया है? **(2020, 15 अंक)**

  {Explain the rationale behind the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act of 2017. How has COVID-19 impacted the GST compensation fund and created new federal tensions? **(2020, 15 Marks)**}

- उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जी० एस० टी०) में सम्मिलित किए गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जी० एस० टी० के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिए। **(2019, 10 अंक)**

  {Enumerate the indirect taxes which have been subsumed in the goods and services tax (GST) in India. Also, comment on the revenue implications of the GST introduced in India since July 2017. **(2019, 10 Marks)**}

- क्या आप इस मत से सहमत हैं कि सकल घरेलू उत्पाद (जी० डी० पी०) की स्थायी संवृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण दीजिए। **(2019, 10 अंक)**

  {Do you agree with the view that steady GDP growth and low inflation have left the Indian economy in good shape? Give reasons in support of your arguments. **(2019, 10 Marks)**}

- भारत में नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए जा रहे सिद्धांत इससे पूर्व के योजना आयोग द्वारा अनुसरित सिद्धान्तों से किस प्रकार भिन्न हैं? **(2018, 15 अंक)**

  {How are principles followed by the NITI Aayog different from those followed by the erstwhile Planning Commission in India? **(2018, 15 Marks)**}

- विश्व व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाजियों की हाल की परिघटनाएँ भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार से प्रभावित करेंगी? **(2018, 15 अंक)**

  {How would the recent phenomena of protectionism and currency manipulations in world trade affect macroeconomic stability of India? **(2018, 15 Marks)**}

- भारत की संभाव्य संवृद्धि के अनेक कारकों में बचत दर, सर्वाधिक प्रभावी है। क्या आप इससे सहमत हैं? संवृद्धि संभाव्यता के अन्य कौन से कारक उपलब्ध हैं? **(2017, 10 अंक)**

  {Among several factors for India's potential growth, savings rate is the most effective one. Do you agree? What are the other factors available for growth potential? **(2017, 10 Marks)**}

- हाल के समय में भारत में आर्थिक संवृद्धि की प्रकृति का वर्णन अक्सर नौकरीहीन संवृद्धि के तौर पर किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। **(2015, 12.5 अंक)**

  {The nature of economic growth in India in recent times is often described as jobless growth. Do you agree with this view? Give arguments in favour of your answer. **(2015, 12.5 Marks)**}

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के द्वारा कीमत सहायिकी का प्रतिस्थापन भारत में सहायिकियों के परिदृश्य का किस प्रकार परिवर्तन कर सकता है ? चर्चा कीजिए। **(2015, 12.5 अंक)**

{In what way could replacement of price subsidy with Direct Benefit Transfer (DBT) change the scenario of subsidies in India? Discuss. **(2015, 12.5 Marks)**}

- सोने के लिए भारतीयों के उन्माद ने हाल के वर्षों में सोने के आयात में प्रोत्कर्ष (उछाल) उत्पन्न कर दिया है और भुगतान संतुलन और रुपए के बाह्य मूल्य पर दबाव डाला है। इसको देखते हुए, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के गुणों का परीक्षण कीजिए। **(2015, 12.5 अंक)**

  {Craze for gold in Indians has led to a surge in import of gold in recent years and put pressure on balance of payments and external value of rupee. In view of this, examine the merits of Gold Monetization Scheme. **(2015, 12.5 Marks)**}
- "जिस समय हम भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) को शान से प्रदर्शित करते हैं, उस समय हम रोजगार योग्यता की पतनशील दरों को नजरअंदाज कर देते हैं।" क्या हम ऐसा करने में कोई चूक कर रहे हैं? भारत को जिन जॉबों की बेसबरी से दरकार है, वे जॉब कहाँ से आएँगे? स्पष्ट कीजिए। **(2014, 12.5 अंक)**

  {"While we flaunt India's demographic dividend, we ignore the dropping rates of employability." What are we missing while doing so? Where will the jobs that India desperately needs come from? Explain. **(2014, 12.5 Marks)**}
- पूंजीवाद ने विश्व अर्थव्यवस्था का अभूतपूर्व समृद्धि तक दिशा-निर्देशन किया है। परन्तु फिर भी, वह अक्सर अदूरदर्शिता को प्रोत्साहित करता है तथा धनवानों और निर्धनों के बीच विस्तृत असमताओं को बढ़ावा देता है। इसके प्रकाश में, भारत में समावेशी संवृद्धि को लाने के लिए क्या पूंजीवाद में विश्वास करना और उसको अपना लेना सही होगा? चर्चा कीजिए। **(2014, 12.5 अंक)**

  {Capitalism has guided the world economy to unprecedented prosperity. However, it often encourages short-sightedness and contributes to wide disparities between the rich and the poor. In this light, would it be correct to believe and adopt capitalism for bringing inclusive growth in India? Discuss. **(2014, 12.5 Marks)**}
- भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रारम्भ करने के मूलाधार की विवेचना कीजिए। इस व्यवस्था को लागू करने में विलम्ब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। (2013, 10 अंक)

  {Discuss the rationale for introducing Goods and Services Tax (GST) in India. Bring out critically the reasons for the delay in roll out for its regime. **(2013, 10 Marks)**}

समावेशी विकास तथा इससे उत्पन्न विषय (Inclusive growth and issues arising from it)

- भारत में सुधारों के उपरान्त की अवधि में, सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के स्वरूप एवं प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। किस सीमा तक यह समावेशी संवृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने के अनुरूप है? **(2024,10 अंक)**

  {Examine the pattern and trend of public expenditure on social services in the post-reforms period in India. To what extent this has been in consonance with achieving the objective of inclusive growth? **(2024,10 Marks)}**
- क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेश के महत्व का उल्लेख कीजिए। **(2022, 10 अंक)**

  {Is inclusive growth possible under market economy ? State the significance of financial inclusion in achieving economic growth in India. **(2022, 10 Marks)**}

- समावेशी संवृद्धि एवं संपोषणीय विकास के परिप्रेक्ष्य में, आंतर्पीढ़ी एवं अंतर्पीढ़ी साम्या के विषयों की व्याख्या कीजिए। **(2020, 10 अंक)**

  {Explain intra-generational and inter-generational issues of equity from the perspective of inclusive growth and sustainable development. **(2020, 10 Marks)**}
- यह तर्क दिया जाता है कि समावेशी संवृद्धि की रणनीति का आशय एक साथ समावेशिता और धारणीयता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। (2019, 15 अंक)

© Vision IAS

{It is argued that the strategy of inclusive growth is intended to meet the objectives of inclusiveness and sustainability together. Comment on this statement. **(2019, 15 Marks)**}

- 'समावेशी संवृद्धि' के प्रमुख अभिलक्षण क्या हैं? क्या भारत इस प्रकार के संवृद्धि प्रक्रम का अनुभव करता रहा है? विश्लेषण कीजिए एवं समावेशी संवृद्धि हेतु उपाय सुझाइए। **(2017, 15 अंक)**

  {What are the salient features of 'inclusive growth'? Has India been experiencing such a growth process? Analyse and suggest measures for inclusive growth. **(2017, 15 Marks)**}

- प्रधान मंत्री जन-धन योजना (PMJDY) बैंकरहितों को संस्थागत वित्त में लाने के लिए आवश्यक है। क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके के लोगों का वित्तीय समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। **(2016, 12.5 अंक)**

  {Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) is necessary for bringing unbanked to the institutional finance fold. Do you agree with this for financial inclusion of the poor section of the Indian society? Give arguments to justify your opinion. **(2016, 12.5 Marks)**}

- भारतीय सन्दर्भ में समावेशी विकास में निहित चुनौतियों, जिनमें लापरवाह और बेकार जनशक्ति शामिल है, पर टिप्पणी कीजिए। इन चुनौतियों का सामना करने के उपाय सुझाइए। **(2016, 12.5 अंक)**

  {Comment on the challenges for inclusive growth which include careless and useless manpower in the Indian context. Suggest measures to be taken for facing these challenges. **(2016, 12.5 Marks)**}

सरकारी बजट (Government Budgeting)

- पूंजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अन्तर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइए। **(2021, 10 अंक)**

  {Distinguish between Capital Budget and Revenue Budget. Explain the components of both these Budgets. **(2021, 10 Marks)**}

- उत्तर-उदारीकरण अवधि के दौरान, बजट निर्माण के संदर्भ में, लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है। इसको स्पष्ट कीजिए। **(2019, 15 अंक)**

  {The public expenditure management is a challenge to the Government of India in context of budget making during the post liberalization period. Clarify it. **(2019, 15 Marks)**}

- केन्द्रीय बजट, 2018-2019 में दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कर (एल० सी० जी० टी०) तथा लाभांश वितरण कर (डी० डी० टी०) के संबंध में प्रारंभ किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर टिप्पणी कीजिए। **(2018, 10 अंक)**

  {Comment on the important changes introduced in respect of the Long Term Capital Gains Tax (LTCGT) and Dividend Distribution Tax (DDT) in the Union Budget for 2018-2019. **(2018, 10 Marks)**}

- 2017-18 के संघीय बजट के अभीष्ट उद्देश्यों में से एक उद्देश्य 'भारत को रूपांतरित करना, ऊर्जावान बनाना और भारत को स्वच्छ करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बजट 2017-18 में सरकार द्वारा प्रस्तावित उपायों का विश्लेषण कीजिए। **(2017, 15 अंक)**

  {One of the intended objectives of Union-Budget 2017-18 is to 'transform, energize and clean India'. Analyze the measures proposed in the Budget 2017-18 to achieve the objective. **(2017, 15 Marks)**}

- वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 2003 को प्रारम्भ करने के क्या कारण थे? उसके प्रमुख प्रावधानों और उनकी प्रभाविता का समालोचनात्मक विवेचन कीजिए। **(2013, 10 अंक)**

  {What were the reasons for the introduction of Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003? Discuss critically its salient features and their effectiveness. **(2013, 10 Marks)**}

- 'कर खर्च' (Tax expenditure) का क्या अर्थ है? गृह क्षेत्र का उदाहरण लेते हुए विवेचना कीजिए कि यह शासन की बजट संबंधी नीतियों को कैसे प्रभावित करता है। **(2013, 10 अंक)**

  {What is the meaning of the term 'tax expenditure'? Taking housing sector as an example, discuss how it influences the budgetary policies of the government. **(2013, 10 Marks)**}

कृषि: मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसल पैटर्न (Agriculture: Major crops, Cropping patterns in various parts of the country)

- खपत पैटर्न एवं विपणन दशाओं में परिवर्तन के संदर्भ में, भारत में फसल प्रारूप (क्रॉपिंग पैटर्न) में हुए परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। **(2023, 15 अंक)**

  {Explain the changes in cropping patterns in India in the context of changes in consumption patterns and marketing conditions. **(2023, 15 marks)**}
- समेकित कृषि प्रणाली क्या है? भारत में लघु और सीमांत किसानों के लिए यह कैसे लाभदायक सकती है?

  {What is Integrated Farming System ? How is it helpful to small and marginal farmers in India? **(2022, 15 Marks)**}
- फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियां क्या हैं? उभरती प्रौद्योगिकियां फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती हैं ? **(2021, 15 अंक)**

  {What are the present challenges before crop diversification? How do emerging technologies provide an opportunity for crop diversification? (2021, 15 Marks)}
- धान-गेहूं प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन-से प्रमुख कारक उत्तरदायी है? इस सफलता के बावजूद यह प्रणाली भारत में अभिशाप कैसे बन गई है? **(2020, 15 अंक)**

  {What are the major factors responsible for making rice-wheat system a success? In spite of this success how has this system become bane in India? **(2020, 15 Marks)**}
- एकीकृत कृषि प्रणाली (आइ० एफ० एस०) किस सीमा तक कृषि उत्पादन को संधारित करने में सहायक है? **(2019, 10 अंक)**

  {How far is Integrated Farming System (IFS) helpful in sustaining agricultural production **(2019, 10 Marks)**}
- गत वर्षों में कुछ विशेष फसलों पर जोर ने सस्यन पैटर्नों में किस प्रकार परिवर्तन ला दिए हैं? मोटे अनाजों (मिलटों) के उत्पादन और उपभोग पर बल को विस्तारपूर्वक स्पष्ट कीजिए। **(2018, 15 अंक)**

  {How has the emphasis on certain crops brought about changes in cropping patterns in recent past? Elaborate the emphasis on millets production and consumption. **(2018, 15 Marks)**}
- बागवानी फार्मों के उत्पादन, उसकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि करने में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM) की भूमिका का आकलन कीजिए। यह किसानों की आय बढ़ाने में कहाँ तक सफल हुआ है? **(2018, 15 अंक)**

  {Assess the role of National Horticulture Mission (NHM) in boosting the production, productivity and income of horticulture farms. How far has it succeeded in increasing the income of farmers? **(2018, 15 Marks)**}
- सस्यन तंत्र में धान और गेहूं की गिरती हुई उपज के लिए क्या-क्या मुख्य कारण हैं? तंत्र में फसलों की उपज के स्थिरीकरण में, सस्य विविधीकरण किस प्रकार मददगार होता है? **(2017, 15 अंक)**

  {What are the major reasons for declining rice and wheat yield in the cropping system? How crop diversification is helpful to stabilise the yield of the crops in the system? **(2017, 15 Marks)**}

© Vision IAS

- सहायिकियां सस्यन प्रतिरूप, सस्य विविधता और कृषकों की आर्थिक स्थिति को किस प्रकार प्रभावित करती हैं ? लघु और सीमांत कृषकों के लिए, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्य प्रसंस्करण का क्या महत्त्व है? **(2017, 15 अंक)**
  {How do subsidies affect the cropping pattern, crop diversity and economy of farmers? What is the significance of crop insurance, minimum support price and food processing for small and marginal farmers? **(2017, 15 Marks)**}
- ऐलीलोपैथी क्या है? सिंचित कृषि क्षेत्रों की प्रमुख फसल पद्धतियों में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। **(2016, 12.5 अंक)**
  {What is allelopathy? Discuss its role in major cropping systems of irrigated agriculture. **(2016, 12.5 Marks)**}

सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणालियाँ (Different types of irrigation and irrigation systems)

- हाल के दिनों में भारतीय सिंचाई प्रणाली के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां हैं? कुशल सिंचाई प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों को बताइए। **(2024,15 अंक)**
  {What are the major challenges faced by Indian irrigation system in recent times? State the measures taken by the government for efficient irrigation management. **(2024,15 Marks)**}
- भारत के जल संकट के समाधान में, सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी ? **(2021, 10 अंक)**
  {How and to what extent would micro-irrigation help in solving India's water crisis? **(2021, 10 Marks)**}
- रिक्तीकरण परिदृश्य में विवेकी जल उपयोग के लिए जल भंडारण और सिंचाई प्रणाली में सुधार के उपायों को सुझाइए। **(2020, 15 अंक)**
  {Suggest measures to improve water storage and irrigation system to make its judicious use under depleting scenario. **(2020, 15 Marks)**}
- जल-प्रतिबलित क्षेत्रों से कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में राष्ट्रीय जल-विभाजक परियोजना के प्रभाव को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। **(2019, 10 अंक)**
  {Elaborate the impact of National Watershed Project in increasing agricultural production from water stressed areas. **(2019, 10 Marks)**}
- जल-उपयोग दक्षता से आप क्या समझते हैं? जल-उपयोग दक्षता को बढ़ाने में सूक्ष्म सिंचाई की भूमिका का वर्णन कीजिए। **(2016, 12.5 अंक)**
  {What is water-use efficiency? Describe the role of micro-irrigation in increasing the water-use efficiency. **(2016, 12.5 Marks)**}

कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन और विपणन तथा इससे संबंधित विषय और बाधाएं (Storage, transport and marketing of agricultural produce and issues and related constraints)

- भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या हैं? **(2022, 15 अंक)**
  {What are the main bottlenecks in upstream and downstream process of marketing of agricultural products in India? **(2022, 15 Marks)**}
- भारत में कृषि उत्पादों के परिवहन और विपणन में मुख्य बाधाएं क्या हैं? **(2020, 10 अंक)**
  {What are the main constraints in transport and marketing of agricultural produce in India? **(2020, 10 Marks)**}
- एक दृष्टिकोण यह भी है कि राज्य अधिनियमों के अधीन स्थापित कृषि उत्पादन बाजार समितियों (APMCs) ने भारत में न केवल कृषि के विकास को बाधित किया है, बल्कि वे खाद्यवस्तु महंगाई का कारण भी रही हैं। समालोचनापूर्वक परीक्षण कीजिए। (2014, 12.5 अंक)
  {There is also a point of view that Agricultural Produce Market Committees (APMCs) set up under the State Acts have not only impeded the development of agriculture but also have been the cause of food inflation in India. Critically examine. **(2014, 12.5 Marks)**}

किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी (E-technology in the aid of farmers)

- कृषि उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन में ई-तकनीक किसानों की किस प्रकार मदद करती है? इसे समझाइए। **(2023, 10 अंक)**
  {How does e-Technology help farmers in production and marketing of agricultural produce? Explain it. **(2023, 10 marks)**}
- विज्ञान हमारे जीवन में गहराई तक किस तरह गुथा हुआ है? विज्ञान-आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा कृषि में उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हैं? **(2020, 10 अंक)**
  {How is science interwoven deeply with our lives? What are the striking changes in agriculture triggered off by the science-based technologies? **(2020, 10 Marks)**}
- 'डिजिटल भारत' कार्यक्रम खेत उत्पादकता और आय को बढ़ाने में किसानों की किस प्रकार सहायता कर सकता है? सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं? **(2015, 12.5 अंक)** {How can the 'Digital India' programme help farmers to improve farm productivity and income? What steps has the Government taken in this regard? **(2015, 12.5 Marks)**}

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता और न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय (Issues related to direct and indirect farm subsidies and MSP)

- भारत में निरंतर उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण क्या है? इस प्रकार की मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में आर० बी० आई० की मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता पर टिप्पणी कीजिए। **(2024,10 अंक)**
  What are the causes of persistent high food inflation in India? Comment on the effectiveness of the monetary policy of the RBI to control this type of inflation. **(2024,10 Marks)**
- भारत में कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी क्या है? विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू० टी० ओ०) द्वारा उठाए गए कृषि सब्सिडी संबंधित मुद्दों की विवेचना कीजिए। **(2023, 15 अंक)**
  {What are the direct and indirect subsidies provided to farm sector in India. Discuss the issues raised by the World Trade Organization (WTO) in relation to agricultural subsidies. **(2023, 15 marks)**}
- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम० एस० पी०) से आप क्या समझते हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा? **(2018, 10 अंक)**
  {What do you mean by Minimum Support Price (MSP)? How will MSP rescue the farmers from the low income trap? **(2018, 10 Marks)**}
- भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनजर, फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। **(2016, 12.5 अंक)**
  {Given the vulnerability of Indian agriculture to vagaries of nature, discuss the need for crop insurance and bring out the salient features of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY). **(2016, 12.5 Marks)**}
- "गाँवों में सहकारी समिति को छोड़कर, ऋण संगठन का कोई भी अन्य ढांचा उपयुक्त नहीं होगा।" - अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में, इस कथन पर चर्चा कीजिए। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को किन बाध्यताओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिए प्रौद्योगिकी का किस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है? **(2014, 12.5 अंक)**
  {"In the villages itself no form of credit organization will be suitable except the cooperative society." — All India Rural Credit Survey. Discuss this statement in the background of agricultural finance in India. What constraints and challenges do financial institutions supplying agricultural finance face? How can technology be used to better reach and serve rural clients? **(2014, 12.5 Marks)**}

 © Vision IAS

- राष्ट्रीय व राजकीय स्तर पर कृषकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायताएं कौन-कौनसी हैं ? कृषि आर्थिक सहायता व्यवस्था का उसके द्वारा उत्पन्न विकृतियों के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। **(2013, 10 अंक)**

  {What are the different types of agriculture subsidies given to farmers at the national and at state levels? Critically analyse the agricultural subsidy regime with reference to the distortions created by it. **(2013, 10 Marks)**}

जन वितरण प्रणाली- उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधित विषय (Public Distribution System- objectives, functioning, limitations, revamping; Issues of buffer stocks and food security)

- भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइए। **(2024,10 अंक)**

  {Explain the role of millets for ensuring health and nutritional security in India. **(2024,10 Marks)**}
- भारत में कृषि कीमतों के स्थिरीकरण के लिए सुरक्षित भंडार (बफर स्टॉक) के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियां क्या है? विवेचना कीजिए। (**2024,15 अंक)**

  {Elucidate the importance of buffer stocks for stabilizing agricultural prices in India. What are the challenges associated with the storage of buffer stock? Discuss. (**2024,15 Marks)**}
- भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) की प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है? **(2022, 10 अंक)**

  {What are the major challenges of Public Distribution System (PDS) in India ? How can it be made effective and transparent? **(2022, 10 Marks)**}
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने में किस प्रकार सहायता की है? **(2021, 15 अंक)**

  {What are the salient features of the National Food Security Act, 2013? How has the Food Security Bill helped in eliminating hunger and malnutrition in India? **(2021, 15 Marks)**}
- अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए है? **(2019, 15 अंक)**

  {What are the reformative steps taken by the Government to make food grain distribution system more effective? **(2019, 15 Marks)**}
- खाद्य सुरक्षा बिल से भारत में भूख व कुपोषण के विलोपन की आशा है। उसके प्रभावी कार्यान्वयन में विभिन्न आशंकाओं का समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। साथ ही यह भी बताएं कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) में इससे कौनसी चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं ? **(2013, 10 अंक)**

  {Food Security Bill is expected to eliminate hunger and malnutrition in India. Critically discuss various apprehensions in its effective implementation along with the concerns it has generated in WTO. **(2013, 10 Marks)**}

प्रौद्योगिकी मिशन (Technology missions)

- जल इंजीनियरी और कृषि विज्ञान के क्षेत्रों में क्रमशः सर एम० विश्वेश्वरैया और डॉ० एम० एस० स्वामीनाथन के योगदानों से भारत को किस प्रकार लाभ पहुँचा था? **(2019, 10 अंक)**

  {How was India benefited from the contributions of Sir M. Visvesvaraya and Dr. M. S. Swaminathan in the fields of water engineering and agricultural science respectively? **(2019, 10 Marks)**}
- भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की है? **(2017, 10 अंक)**

  {Explain various types of revolutions, took place in Agriculture after Independence in India. How these revolutions have helped in poverty alleviation and food security in India? **(2017, 10 Marks)**}

- भारत में बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए खाद्य उद्योग में गुलाबी क्रांति प्रोन्नति हेतु उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस कथन पर आलोचनात्मक प्रकाश डालिए। **(2013, 10 अंक)**

  {India needs to strengthen measures to promote the pink revolution in food industry for ensuring better nutrition and health. Critically elucidate the statement. **(2013, 10 Marks)**}

पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र (Economics of animal-rearing)

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषीतर रोजगार और आय का प्रबंध करने में पशुधन पालन की बड़ी संभाव्यता है। भारत में इस क्षेत्रक की प्रोन्नति करने के उपयुक्त उपाय सुझाते हुए चर्चा कीजिए। **(2015, 12.5 अंक)**

  {Livestock rearing has a big potential for providing non-farm employment and income in rural areas. Discuss suggesting suitable measures to promote this sector in India. **(2015, 12.5 Marks)**}

भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग: कार्यक्षेत्र और महत्व, स्थान, ऊपर और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन (Food Processing & Related Industries: Scope and significance, Location, Upstream and downstream requirements, Supply chain management)

- भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्त्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। **(2022, 10 अंक)**

  {Elaborate the scope and significance of the food processing industry in India. **(2022, 10 Marks)**}
- देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियां एवं अवसर क्या है? खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है? **(2020, 10 अंक)**

  {What are the challenges and opportunities of food processing sector in the country? How can income of the farmers be substantially increased by encouraging food processing? **(2020, 10 Marks)**}
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति को सविस्तार स्पष्ट कीजिए। **(2019, 15 अंक)**

  {Elaborate the policy taken by the Government of India to meet the challenges of the food processing sector. **(2019, 15 Marks)**}
- फलों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों के आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुपर बाजारों की भूमिका की जाँच कीजिए। वे बिचौलियों की संख्या को किस प्रकार खत्म कर देते हैं? **(2018, 10 अंक)**

  {Examine the role of supermarkets in supply chain management of fruits, vegetables, and food items. How do they eliminate number of intermediaries? **(2018, 10 Marks)**}
- लागत प्रभावी छोटी प्रक्रमण इकाई की अल्प स्वीकारिता के क्या कारण हैं? खाद्य प्रक्रमण इकाई गरीब किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में किस प्रकार सहायक होगी ? **(2017, 10 अंक)**

  {What are the reasons for poor acceptance of cost-effective small processing unit? How the food processing unit will be helpful to uplift the socio-economic status of poor farmers? **(2017, 10 Marks)**}
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विकास करने की राह में विपणन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्या बाधाएं हैं? क्या इन बाधाओं पर काबू पाने में ई-वाणिज्य सहायक हो सकता है? **(2015, 12.5 अंक)**

  {What are the impediments in marketing and supply chain management in developing the food processing industry in India? Can e-commerce help in overcoming these bottlenecks? **(2015, 12.5 Marks)**}

आर्थिक सुधार: भारत में भूमि सुधार (Economic Reforms: Land reforms in India)

- देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे? स्पष्ट कीजिए। **(2024,10 अंक)**

  {What were the factors responsible for the successful implementation of land reforms in some parts of the country? Elaborate. **(2024,10 Marks)**}

© Vision IAS

- भारत में भूमि सुधार के उद्देश्यों एवं उपायों को बताइए। आर्थिक मापदंडों के अंतर्गत, भूमि जोत पर भूमि सीमा नीति को कैसे एक प्रभावी सुधार माना जा सकता है, विवेचना कीजिए। **(2023, 10 अंक)**

  {State the objectives and measures of land reforms in India. Discuss how land ceiling policy on landholding can be considered as an effective reform under economic criteria. **(2023, 10 marks)**}
- देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है? **(2021, 10 अंक)**

  {How did land reforms in some parts of the country help to improve the socio-economic conditions of marginal and small farmers? **(2021, 10 Marks)**}
- कृषि विकास में भूमि सुधारों की भूमिका की विवेचना कीजिए। भारत में भूमि सुधारों की सफलता के लिए उत्तरदायी कारकों को चिह्नित कीजिए। **(2016, 12.5 अंक)**

  Discuss the role of land reforms in agricultural development Identify the factors that were responsible for the success of land reforms in India. **(2016, 12.5 Marks)**
- भारत में कृषिभूमि धारणों के पतनोन्मुखी औसत आकार को देखते हुए, जिसके कारण अधिकांश किसानों के लिए कृषि अलाभकारी बन गई है, क्या संविदा कृषि को और भूमि को पट्टे पर देने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? इसके पक्ष-विपक्ष का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। **(2015, 12.5 अंक)**

  {In view of the declining average size of land holdings in India which has made agriculture non–viable for a majority of farmers, should contract farming and land leasing be promoted in agriculture? Critically evaluate the pros and cons. **(2015, 12.5 Marks)**}
- भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार, कृषि उत्पादकता और गरीबी उन्मूलन के बीच संबंध स्थापित कीजिए। भारत में कृषि अनुकूल भूमि सुधारों के रूपांकन व अनुपालन में कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। **(2013, 10 अंक)**

  {Establish relationship between land reforms, agriculture productivity and elimination of poverty in the Indian economy. Discuss the difficulties in designing and implementation of agriculture friendly land reforms in India. **(2013, 10 Marks)**}
- भूमि अर्जन, पुनरुद्धार और पुनर्वासन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 पहली जनवरी, 2014 से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने से कौन-से महत्त्वपूर्ण मुद्दों का समाधान निकलेगा? भारत में उद्योगीकरण और कृषि पर इसके क्या परिणाम होंगे? **(2014, 12.5 अंक)**

  {The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 has come into effect from 1st January, 2014. What are the key issues which would get addressed with the Act in place? What implications would it have on industrialization and agriculture in India? **(2014, 12.5 Marks)**}

उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन तथा औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव (Effects of liberalization on the economy, Changes in industrial policy and their effects on industrial growth)

- भारत में श्रम बाजार सुधारों के संदर्भ में, चार 'श्रम संहिताओं' के गुण व दोषों की विवेचना कीजिए। इस संबंध में, अभी तक क्या प्रगति हुई है? **(2024,15 अंक)**

  {Discuss the merits and demerits of the four 'Labour Codes' in the context of labour market reforms in India. What has been the progress so far in this regard? **(2024,15 Marks)**}
- श्रम-प्रधान निर्यातों के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्रक की विफलता के कारण बताइए। पूंजी-प्रधान निर्यातों की अपेक्षा अधिक श्रम-प्रधान निर्यातों के लिए, उपायों को सुझाइए। **(2017, 10 अंक)**

{Account for the failure of manufacturing sector in achieving the goal of labour-intensive exports. Suggest measures for more labour-intensive rather than capital-intensive exports. **(2017, 10 Marks)**}

- "सुधारोत्तर अवधि में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है।" कारण बताइए। औद्योगिक नीति में हाल में किए गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को बढ़ाने में कहां तक सक्षम हैं? **(2017, 7+8= 15 अंक)**

  {"Industrial growth rate has lagged behind in the overall growth of Gross-Domestic-Product (GDP) in the post-reform period" Give reasons. How far the recent changes in Industrial Policy are capable of increasing the industrial growth rate? **(2017, 7+8= 15 Marks)**}
- भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कैसे कम हुए? क्या बढ़ती हुई अनौपचारिकता देश के विकास के लिए हानिकारक है? **(2016, 12.5 अंक)**

  {How globalization has led to the reduction of employment in the formal sector of the Indian economy? Is increased informalization detrimental to the development of the country? **(2016, 12.5 Marks)**}
- भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की आवश्यकता की पुष्टि कीजिए। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों तथा वास्तविक एफ० डी० आइ० के बीच अंतर क्यों है? भारत में वास्तविक एफ० डी० आइ० को बढ़ाने के लिए सुधारात्मक कदम सुझाइए। **(2016, 12.5 अंक)**

  {Justify the need for FDI for the development of the Indian economy. Why there is gap between MoUs signed and actual FDIs? Suggest remedial steps to be taken for increasing actual FDIs in India. **(2016, 12.5 Marks)**}
- " मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की सफलता, 'कौशल भारत' कार्यक्रम और आमूल श्रम सुधारों की सफलता पर निर्भर करती है।" तर्कसम्मत दलीलों के साथ चर्चा कीजिए। **(2015, 12.5 अंक)** {"Success of 'Make in India' programme depends on the success of 'Skill India' programme and radical labour reforms." Discuss with logical arguments. **(2015, 12.5 Marks)**}
- इसकी स्पष्ट स्वीकृति है कि विशेष आर्थिक ज़ोन (एस.इ. जैड.) औद्योगिक विकास, विनिर्माण और निर्यातों के एक साधन हैं। इस संभाव्यता को मान्यता देते हुए, एस.ई.जैड. के संपूर्ण करणत्व में वृद्धि करने की आवश्यकता है। कराधान, नियंत्रक कानूनों और प्रशासन के संबंध में एस.ई. जैडॉ. की सफलता को परेशान करने वाले मुद्दों पर चर्चा कीजिए। (2015, 12.5 अंक)

  {There is a clear acknowledgement that Special Economic Zones (SEZs) are a tool of industrial development, manufacturing and exports. Recognising this potential, the whole instrumentality of SEZs require augmentation. Discuss the issues plaguing the success of SEZs with respect to taxation, governing laws and administration. (2015, 12.5 Marks)}
- सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अन्तरित होते हैं पर भारत सीधे ही कृषि से सेवाओं को अन्तरित हो गया है। देश में उद्योग के मुकाबले सेवाओं की विशाल संवृद्धि के क्या कारण है? क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश बन सकता है? **(2014, 12.5 अंक)**

  {Normally countries shift from agriculture to industry and then later to services, but India shifted directly from agriculture to services. What are the reasons for the huge growth of services vis-à-vis industry in the country? Can India become a developed country without a strong industrial base? **(2014, 12.5 Marks)**}
- रक्षा क्षेत्रक में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ० डी० आइ०) को अब उदारीकृत करने की तैयारी है। भारत की रक्षा और अर्थव्यवस्था पर अल्पकाल और दीर्घकाल में इसके क्या प्रभाव अपेक्षित हैं? **(2014, 12.5 अंक)**

  {Foreign Direct Investment (FDI) in the defence sector is now set to be liberalized. What influence this is expected to have on Indian defence and economy in the short and long run? **(2014, 12.5 Marks)**}
- भारतीय स्वामित्व वाली कंपनियों पर उदारीकरण के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। क्या वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से संतोषजनक ढंग से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं? विवेचना कीजिए। **(2013, 10 अंक)**

 © Vision IAS

{Examine the impact of liberalization on companies owned by Indians. Are they competing with the MNCs satisfactorily? Discuss. **(2013, 10 Marks)**}

- अर्थव्यवस्था के माल व्यापार पद्धति में बहुव्यापार खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवेश के प्रभाव की विवेचना कीजिए। **(2013, 5 अंक)**

  {Discuss the impact of FDI entry into Multi-trade retail sector on supply chain management in commodity trade pattern of the economy. **(2013, 5 Marks)**}

- यद्यपि भारत ने सितम्बर 2012 में संयुक्त संधि मार्ग द्वारा बहुमार्का खुदरा कहलाने वाले व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को स्वीकृति दे दी थी, पर इस निवेश में एक वर्ष पश्चात् भी कोई उन्नति नहीं हुई है। कारणों की विवेचना कीजिए। **(2013, 5 अंक)**

  {Though India allowed Foreign Direct Investment (FDI) in what is called multi-brand retail through the joint venture route in September 2012, the FDI, even after a year, has not picked up. Discuss the reasons. **(2013, 5 Marks)**}

- समावेशी विकास की रणनीति को ध्यान में रखते हुए, नए कंपनी बिल 2013 ने 'सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व' को अप्रत्यक्ष रूप से अनिवार्य कर्तव्य बना दिया है। इसके गंभीरता से पालन कराने में अपेक्षित चुनौतियों की विवेचना कीजिए। इस बिल की अन्य व्यवस्थाओं और उनकी उलझनों की भी चर्चा करें। **(2013, 10 अंक)**

  {With consideration towards the strategy of inclusive growth, the new Companies Bill, 2013 has indirectly made CSR a mandatory obligation. Discuss the challenges expected in its implementation in right earnest. Also discuss other provisions in the Bill and their implications. **(2013, 10 Marks)**}

बुनियादी ढांचा: ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे, आदि और निवेश मॉडल (Infra: Energy, Ports, Roads, Airports, Railways etc. and Investment models)

- राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक पथ कर संग्रह करने के लिए कौन-सी प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है? उसके क्या-क्या लाभ और क्या-क्या सीमाएँ हैं? वे कौन-से परिवर्तन प्रस्तावित हैं जो इस प्रक्रिया को निर्बाध बना देंगे? क्या यह परिवर्तन कोई संभावित खतरे लेकर आएगा? **(2024,10 अंक)**

  {What is the technology being employed for electronic toll collection on highways? What are its advantages and limitations? What are the proposed changes that will make this process seamless? Would this transition carry any potential hazards? **(2024,10 Marks)**}

- भारत में क्षेत्रीय वायु कनेक्टिविटी के विस्तार की क्या आवश्यकता है? इस संदर्भ में, सरकार की 'उड़ान' योजना तथा इसकी उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। **(2024,15 अंक)**

  {What is the need for expanding the regional air connectivity in India? In this context, discuss the government's UDAN Scheme and its achievements. **(2024,15 Marks)**}

- क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50 प्रतिशत भाग, वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपर्युक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा ? समझाइए। **(2022, 15 अंक)**

  {Do you think India will meet 50 percent of its energy needs from renewable energy by 2030? Justify your answer. How will the shift of subsidies from fossil fuels to renewables help achieve the above objective? Explain. **(2022, 15 Marks)**}

- बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी (पी.पी.पी.) की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पी.पी.पी. मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। **(2022, 10 अंक)**

  {Why is Public Private Partnership (PPP) required in infrastructural projects ? Examine the role of PPP model in the redevelopment of Railway Stations in India. **(2022, 10 Marks)**}

- "तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक संवृद्धि के लिए आधारिक अवसंरचना में निवेश आवश्यक है।" भारतीय अनुभव के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। **(2021, 15 अंक)**

{"Investment in infrastructure is essential for more rapid and inclusive economic growth. "Discuss in the light of India's experience. **(2021, 15 Marks)**}

- एक अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिए। उन कारकों की विवेचना कीजिए, जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रिआयत अनुबन्ध (कॉन्सेशन एग्रीमेंट) तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिए। **(2020, 15 अंक)**

  {Explain the meaning of investment in an economy in terms of capital formation. Discuss the factors to be considered while designing a concession agreement between a public entity and a private entity. **(2020, 15 Marks)**}
- पारम्परिक ऊर्जा उत्पादन के विपरीत सूर्य के प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लाभों का वर्णन कीजिए। इस प्रयोजनार्थ हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत पहल क्या है? **(2020, 15 अंक)**

  {Describe the benefits of deriving electric energy from sunlight in contrast to the conventional energy generation. What are the initiatives offered by our Government for this purpose? **(2020, 15 Marks)**}
- "वहनीय (ऐफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टेनबल) विकास लक्ष्यों (एस॰ डी॰ जी॰) को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है।" भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिए। **(2018, 10 अंक)**

  {"Access to affordable, reliable, sustainable and modern energy is the sine qua non to achieve Sustainable Development Goals (SDGs)." Comment on the progress made in India in this regard. **(2018, 10 Marks)**}
- ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिए? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों एवं भयों की विवेचना कीजिए। **(2018, 15 अंक)**

  {With growing energy needs should India keep on expanding its nuclear energy programme? Discuss the facts and fears associated with nuclear energy? **(2018, 15 Marks)**}
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अधीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भारत में विमानपत्तनों के विकास का परीक्षण कीजिए। इस संबंध में प्राधिकरणों के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? **(2017, 10 अंक)**

  {Examine the development of Airports in India through joint ventures under Public – Private Partnership (PPP) model. What are the challenges faced by the authorities in this regard? **(2017, 10 Marks)**}
- 'स्मार्ट शहरों' से क्या तात्पर्य है? भारत के शहरी विकास में इनकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। क्या इससे ग्रामीण तथा शहरी भेदभाव में बढ़ोतरी होगी? पी॰ यू॰ आर॰ ए॰ एवं आर॰ यू॰ आर॰ बी॰ ए॰ एन॰ मिशन के सन्दर्भ में 'स्मार्ट गाँवों' के लिए तर्क प्रस्तुत कीजिए। **(2016, 12.5 अंक)**

  {What are 'Smart Cities'? Examine their relevance for urban development in India. Will it increase ruralurban differences? Give arguments for 'Smart Villages' in the light of PURA and RURBAN Mission. **(2016, 12.5 Marks)**}
- देश में नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के संदर्भ में इनकी वर्तमान स्थिति और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का विवरण दीजिए। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल॰ ई॰ डी॰) पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के महत्त्व की विवेचना संक्षेप में कीजिए। **(2016, 12.5 अंक)**

  {Give an account of the current status and the targets to be achieved pertaining to renewable energy sources in the country. Discuss in brief the importance of the National Programme on Light Emitting Diodes (LEDs). **(2016, 12.5 Marks)**}
- सौर ऊर्जा की उपकरण लागतों और टैरिफ में हाल के नाटकीय पतन के क्या कारक बताए जा सकते हैं ? इस प्रवृत्ति के तापीय विद्युत उत्पादों और संबंधित उद्योग के लिए क्या निहितार्थ हैं? **(2015, 12.5 अंक)**

  {To what factors can the recent dramatic fall in equipment costs and tariff of solar energy be attributed? What implications does the trend have for the thermal power producers and the related industry? **(2015, 12.5 Marks)**}
- समझाइए कि दीर्घकालिक पक्कनावधि (जेस्टेशन) आधारिक संरचना परियोजनाओं में निजी लोक भागीदारी (प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप) किस प्रकार अधारणीय (अन्सस्टेनेबल) देयताओं को भविष्य पर अंतरित कर सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सक्षमताओं के साथ कोई समझौता न हो, क्या व्यवस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए? (2014, 12.5 अंक)

© Vision IAS

{Explain how Private Public Partnership arrangements, in long gestation infrastructure projects, can transfer unsustainable liabilities to the future. What arrangements need to be put in place to ensure that successive generations' capacities are not compromised? **(2014, 12.5 Marks)**}

- राष्ट्रीय नगरीय परिवहन नीति 'वाहनों की आवाजाही' के बजाय 'लोगों की आवाजाही' पर बल देती है। इस सम्बन्ध में सरकार की विविध रणनीतियों की सफलता की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। **(2014, 12.5 अंक)**

  {National Urban Transport Policy emphasises on 'moving people' instead of 'moving vehicles'. Discuss critically the success of the various strategies of the Government in this regard. **(2014, 12.5 Marks)**}

- परम्परागत ऊर्जा की कठिनाइयों को कम करने के लिए भारत की 'हरित ऊर्जा पट्टी' पर एक लेख लिखिए। **(2013, 10 अंक)**

  {Write a note on India's green energy corridor to alleviate the problem of conventional energy. **(2013, 10 Marks)**}

- देश में आधारभूत संरचना के विकास में गैर-सरकारी भागीदारी योजना (PPP) मॉडल का अंगीकरण आलोचना मुक्त नहीं है। इस मॉडल के पक्ष-विपक्ष की समालोचनात्मक विवेचना कीजिए। **(2013, 10 अंक)**

  {Adoption of PPP model for infrastructure development of the country has not been free of criticism. Critically discuss pros and cons of the model. **(2013, 10 Marks)**}

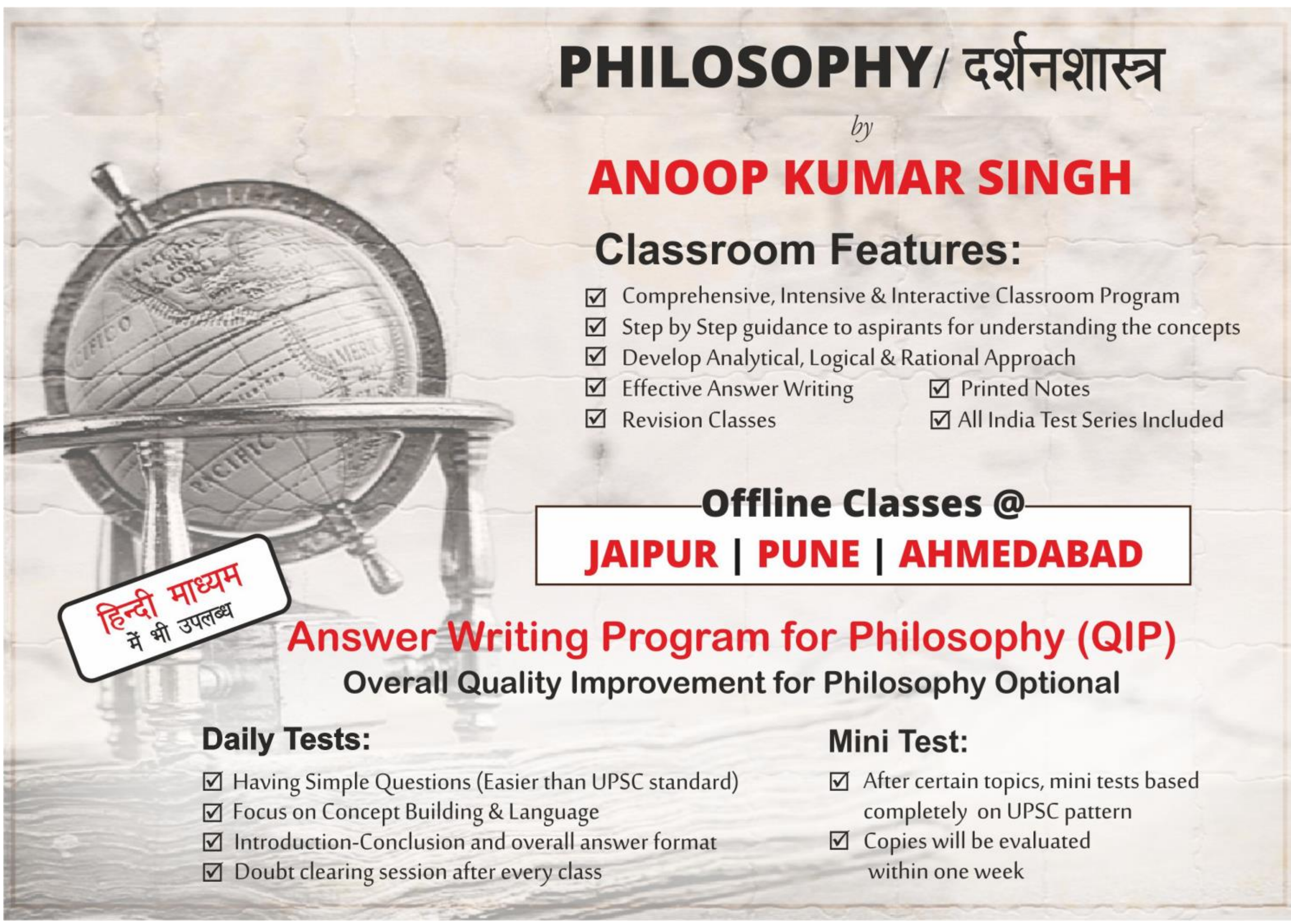

14. परिशिष्ट: प्रमुख आंकड़े एवं तथ्य (Appendix: Key Data and Facts)

परिशिष्ट: प्रमुख आंकड़े एवं तथ्य	
भारतीय अर्थव्यवस्था का एक संक्षिप्त विवरण	
भारतीय अर्थव्यवस्था: एक नज़र में	• 2024-25 में **चालू कीमतों पर भारत की GDP 331.03 लाख करोड़ रुपये** अनुमानित है। • वर्तमान में **भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था** है। • भारत से 2023-24 में **778.21 बिलियन यू.एस. डॉलर** का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया गया। • **बाह्य ऋण-GDP अनुपात 19.1%** था। • भारत में **चरम गरीबी** 2011-12 में 16.2% थी, जो **2022-23** में कम होकर केवल **2.3%** रह गई
भारत का संरचनात्मक परिवर्तन	• **क्षेत्रक-वार असंतुलन:** अभी भी समग्र रोजगार में कृषि की हिस्सेदारी 42% है। • 2019 में लगभग 12 प्रतिशत वर्कर्स निर्माण (कंस्ट्रक्शन) क्षेत्रक में संलग्न थे। • भारत को 2050 तक अपनी बढ़ती आबादी के लिए **कम-से-कम 143-324 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित करने होंगे।** • **भारत की श्रम शक्ति के** अन्य देशों की तुलना में **औपचारिक शिक्षा में कम वर्ष व्यतीत किए जाने के कारण** भारत में **शिक्षा की गुणवत्ता निम्न स्तर की** बनी हुई है। (ASER, 2023)
रोजगार, श्रम तथा कौशल विकास	
रोजगार	• अप्रैल 2025 में भारत में बेरोजगारी दर 5.1% थी। शहरी बेरोजगारी दर 6.5% है, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.5% दर्ज की गई है। (PLFS 2024) • **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 59.6%** है। (PLFS 2024) • कुल कार्यबल का **लगभग 45.76%** हिस्सा **कृषि में लगा हुआ है। (मौसमी रोजगार)**
कौशल विकास	• भारत की 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की है। • 15-29 वर्ष आयु वर्ग के **केवल 4.4% युवाओं** को **औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण** प्राप्त हुआ है (आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24) • अगले पांच वर्षों में, वैश्विक स्तर पर **23% नौकरियों की प्रकृति में बदलाव आएगा** (WEF की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, 2023)। • कौशल की कमी के कारण भारत के 90% से ज्यादा कामगार अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं।
संवृद्धि और विकास	
समावेशी विकास	• चरम गरीबी में रहने वाले **भारतीयों की संख्या 431 मिलियन (1990) से घटकर 129 मिलियन (2024)** रह गई है। **(विश्व बैंक)** • 2023 के अंत तक, भारत के सबसे **अमीर नागरिकों के पास देश की 40.1 प्रतिशत** संपत्ति थी (वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब स्टडी, 2024)। • **बेरोजगारी दर** में मामूली गिरावट दर्ज की गई (5.0% से 4.9%) (PLFS डेटा)
निर्धनता	• **निर्धनता हेडकाउंट अनुपात** 2013-14 के 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया। पिछले 9 वर्षों में 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल आए हैं। • चरम गरीबी में रहने वाले **भारतीयों की संख्या 431 मिलियन (1990) से घटकर 129 मिलियन (2024)** रह गई है। **(विश्व बैंक)**

© Vision IAS

	• **भारत में 53% महिलाएं घर की देखभाल की ज़िम्मेदारियों के कारण कार्य बल में शामिल नहीं** हैं (ILO)।
आर्थिक संकेतक	• 2024-25 में **चालू कीमतों पर भारत की GDP 331.03 लाख करोड़ रुपये** अनुमानित है। • दिसंबर, 2024 में भारत का बाह्य (विदेशी) ऋण 717.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। **बाह्य ऋण-GDP अनुपात 19.1%** था। • भारत को **2047 तक उच्च आय वाला देश (HIC)** बनने के लिए अगले **22 वर्षों में औसतन 7.8% की दर से विकास** करना होगा। • औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE) **ग्रामीण भारत में 4,122 रुपये** और **शहरी भारत में 6,996 रुपये** है। (**HCES: 2023-24**) • भारत में **R&D पर निवेश** GDP का केवल 0.64% व्यय किया जाता है। दूसरी ओर, **चीन में यह अनुपात 2.4%** और **संयुक्त राज्य अमेरिका में 3.47%** है।
वित्तीय समावेशन	• भारत में लगभग 78% वयस्क आबादी के पास बैंक खाता है **(विश्व बैंक ग्लोबल फ़िनडेक्स डेटाबेस, 2021)** • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का मार्च 2024 के लिए **वित्तीय समावेशन सूचकांक मूल्य 64.2** था, जबकि मार्च 2023 में यह **60.1** था। • NABARD का **SHG-BLP** विश्व का सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम **17.8 करोड़ परिवारों को 144 लाख** से अधिक SHGs के माध्यम से सशक्त बना रहा है। • 2016 से अब तक DBT के माध्यम से **90 करोड़ लोगों को 450 से अधिक योजनाओं का लाभ पहुंचाया** गया है। • अगस्त, 2024 तक **53.13 करोड़ जन धन खाते** खोले जा चुके थे।
असमानता	• भारत के **सबसे धनी 1%** लोगों के पास देश की सकल राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा है (वर्ल्ड इक्वेलिटी लैब रिपोर्ट, 2022-23) • **सबसे धनी** 5% भारतीयों के पास देश की 60% से अधिक संपत्ति है। • **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** औसत MPCE **ग्रामीण भारत में 3,773 रुपये** और **शहरी भारत में 6,459 रुपये** है। • **पारिश्रमिक के स्तर पर लैंगिक भेदभाव या असमानता:** विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत में, कुल श्रम आधारित आय का 82% पुरुष कमाते हैं, जबकि महिलाएं केवल 18% कमाती हैं।
ग्रामीण विकास	• कृषि निर्यात 2022-23 में 53.2 बिलियन डॉलर से घटकर 2023-24 में 48.9 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि आयात 8% घटकर 32.8 बिलियन डॉलर (2023-24) हो गया। • 2022 में **विश्व कृषि उत्पाद निर्यात और आयात में भारत की हिस्सेदारी क्रमशः 2.4 प्रतिशत और 1.9 प्रतिशत** थी। (WTO की व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा, 2023)
भूमि सुधार	• 2010-11 में **कृषि जोत का औसत आकार 1.15 हेक्टेयर** था। • भूमि का **10% से अधिक हिस्सा** गैर-कृषि उपयोग में है। • कुल भौगोलिक क्षेत्र के **25% हिस्से** पर वन है।
राजकोषीय नीति	
राज्य वित्त	• **सकल राजकोषीय घाटा (GFD) में गिरावट:** भारतीय राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा **1998-99 से 2003-04** के दौरान **GDP के औसतन 4.3%** के बराबर था। यह **2004-05 से 2023-24 के दौरान से घटकर 2.7%** हो गया। • **राजस्व घाटा:** राज्यों ने 2021-22 से 2023-24 के दौरान राजस्व घाटा **GDP के 0.2%** स्तर पर बनाए रखा है। • **व्यय की गुणवत्ता में सुधार:** पूंजीगत व्यय **2022-23 में GDP का 2.2%** था, जो बढ़कर **2023-24 में 2.6%** हो गया। • **राज्यों का ऋण:** यह मार्च, 2004 के अंत में **GDP के 31.8%** के बराबर था, जो **घटकर मार्च, 2024 के अंत में GDP के 28.5%** पर आ गया।

प्रत्यक्ष कराधान	• **वित्त वर्ष 2024-25 में कर-GDP अनुपात 11.7%** (प्रत्यक्ष करों के लिए 6.7% और अप्रत्यक्ष करों के लिए 5.0%) • **निगम कर (कॉर्पोरेट टैक्स) और व्यक्तिगत आयकर** का प्रत्यक्ष कर में सर्वाधिक योगदान है। • वित्त वर्ष 2021-22 में **डायरेक्ट टैक्स बॉयंसी** 2.52 थी, जो पिछले 15 वर्षों में सबसे अधिक थी, लेकिन **2022-23 में यह घटकर 1.18** हो गई। • **भारत के प्रत्यक्ष कर संग्रह** में पिछले वर्ष की तुलना में 2024-25 में **16.15% की वृद्धि** दर्ज की गई है, जो 25.86 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है।
बैंकिंग, भुगतान प्रणाली एवं वित्त बाजार	
बैंकिंग	• भारत में **12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSBs), 21 निजी क्षेत्रक के बैंक, 45 विदेशी बैंक** आदि हैं। • **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA)** अनुपात 13 वर्षों में सबसे कम होकर 2.7% पर आ गया। • **GNPA** अनुपात कृषि क्षेत्रक के लिए **सबसे अधिक (6.2%)** और **रिटेल लोन** के लिए सबसे कम (1.2%) रहा है। • **वित्त वर्ष 2022-23** में, कुल कृषि ऋण में **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 11.2%** हिस्सेदारी थी।
भुगतान प्रणाली	• RBI के अनुसार, **भारत में लगभग 50% लेन-देन कैश में होता है।** • भारत में **40% से अधिक भुगतान डिजिटल** माध्यम से होते हैं (विश्व में सर्वाधिक डिजिटल लेन-देन)। • भारत में मात्रा (वॉल्यूम) के मामले में **डिजिटल भुगतान के 50% हिस्से पर डेबिट कार्ड, UPI और IMPS का प्रभुत्व** है। • भारत में मूल्य (वैल्यू) के मामले में **डिजिटल भुगतान के 53% हिस्से पर RTGS और NEFT का प्रभुत्व है।** • **2019 में प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन-देन 22.4** रहा। (वर्ष 2014 में यह 2.4 था)।
बाह्य क्षेत्रक	
निर्यात क्षेत्रक	• 2024-25 में भारत का कुल निर्यात (वस्तुएं और सेवाओं को मिलाकर) **824.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के** बराबर था। • **2023 में, भारत का वैश्विक सेवा निर्यात में 4.3% और वस्तु निर्यात में 1.8%** हिस्सा था। (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25) • अंकटाड के अनुसार, भारत का निर्यात इसके **सकल घरेलू उत्पाद के 23% के बराबर है।**
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI)	• **2000 से 2024 तक:** सितंबर 2024 में भारत में कुल FDI **1 ट्रिलियन डॉलर** को पार कर गया। • **वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में महाराष्ट्र को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ,** उसके बाद **कर्नाटक और दिल्ली** का स्थान रहा। • वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में सबसे अधिक FDI सिंगापुर से हुआ, उसके बाद मॉरीशस और संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान रहा। • वित्त वर्ष 2023-24 में **कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्रक को सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ,** इसके बाद **सेवा क्षेत्रक** का स्थान रहा।
भारत में विप्रेषण या रेमिटेंस	• 2024 में वैश्विक विप्रेषण का **14.3% ($129 बिलियन)** आया, **जो अब तक का सर्वाधिक है (विश्व बैंक)।** • **शीर्ष 3 स्रोत देश (2023-24):** अमेरिका (27.7%) >UAE>UK • भारत के रेमिटेंस में **खाड़ी देशों की हिस्सेदारी कम होकर 38%** रह गई है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 50% से अधिक हो गई है। • **रेमिटेंस प्राप्तकर्ता शीर्ष 3 राज्य (2023-24):** महाराष्ट्र (20.5%)>केरल>तमिलनाडु।
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	
कृषि ऋण	• पिछले दशक (2014-15 से 2023-24) में **कृषि ऋण वितरण में औसतन 13% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर** दर्ज की गई है।

	• वित्त वर्ष 2023-24 में **कृषि ऋण वितरण 25.48 लाख करोड़ रुपए** तक पहुंच गया। • वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने कृषि के लिए **27.5 लाख करोड़ रुपये ऋण वितरण लक्ष्य** निर्धारित किया है जिसमें **संबद्ध गतिविधियों के लिए 4.20 लाख करोड़ रुपये** ऋण वितरण के उप-लक्ष्य शामिल हैं। • **केवल 41% लघु और सीमांत किसानों,** जिनके पास 86% कृषि योग्य भूमि है, वही किसान **बैंक ऋण** का लाभ ले पाते हैं।
संबद्ध क्षेत्रक	• **विश्व में पशुधन की सबसे अधिक संख्या** भारत में है। • भारत, **भैंस के मांस का सबसे बड़ा उत्पादक** और **बकरी के मांस का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है।** • **GDP में योगदान:** 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रक GVA में **पशुधन क्षेत्रक** का **30.19%** योगदान तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की कुल GVA में पशुधन क्षेत्रका का योगदान **5.73%**। • **पशुधन क्षेत्रक,** भारत में 70% से अधिक ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। • **भारत के बागवानी** क्षेत्रक का कृषि **GVA** में योगदान **33%** है। • **फलों और सब्जियों के उत्पादन** के मामले में चीन के बाद **भारत दुनिया में दूसरे स्थान** पर है। • **विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश,** वैश्विक मछली उत्पादन में **8% का योगदान** है। • 1.9 मिलियन टन के साथ **भारत अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान** पर है।
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक	• **खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक** एक **सनराइज सेक्टर** है। इसका चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 7.3% (वित्त वर्ष 2015-2022) है। इसका योगदान 2020-21 में विनिर्माण GVA में 10.54% और **कृषि GVA में 11.57%** था। • 2021-22 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में **20.68 लाख कर्मचारी कार्य कर रहे थे।** • देश भर में स्वीकृत 41 में से **24 मेगा फूड पार्क कार्य कर रहे हैं।** • कृषि-निर्यात में **प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी** 2023-24 **में बढ़कर 23.4%** हो गई।
उद्योग एवं औद्योगिक नीति	
MSME क्षेत्रक	• **योगदान: सकल घरेलू उत्पाद में 30%** और **कुल निर्यात में लगभग 45% तक।** • **विनिर्माण में योगदान: 36% तक।** • **रोजगार: लगभग 7.5 करोड़ लोग।**
इलेक्ट्रॉनिक घटक क्षेत्रक	• **आर्थिक क्षमता:** 2030 तक 500 बिलियन डॉलर। • **निर्यात वृद्धि:** वित्त वर्ष 2015 से 20% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर **(CAGR)**। • **भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक** की वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में **4%** की हिस्सेदारी है। • इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक में **घरेलू उत्पादन** 9.52 लाख करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2024) है।
भारत की जैव अर्थव्यवस्था	• **आर्थिक संवृद्धि:** वर्ष 2050 तक इसके **वैश्विक GDP के 12%** तक पहुंचने की उम्मीद है। • **खाद्य सुरक्षा:** अनुवांशिक रूप से संशोधित तकनीक ने फसल की पैदावार में **21% की वृद्धि** की है। • **रोजगार के अवसर:** 2030 तक जैव अर्थव्यवस्था से **35 मिलियन रोजगार सृजित** होंगे।
सेवा क्षेत्रक	
डिजिटल अर्थव्यवस्था	• भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट-2024 के अनुसार- **भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटाइज़्ड देश** है। • भारत की **राष्ट्रीय आय में 11.74% का योगदान।** • **सकल मूल्य वर्धन (GVA)** में **7.83% का योगदान** (सबसे अधिक योगदान)

क्रिएटिव इकोनॉमी या ऑरेंज इकोनॉमी	• **GDP में योगदान:** क्रिएटिव कारोबार का देश के **समग्र GVA में लगभग 20% का** योगदान है। • **निर्यात:** 2010 से 2019 तक क्रिएटिव गुड्स के निर्यात में **1.5 गुना वृद्धि** हुई है। • **रोजगार:** यह अब **लगभग 30 बिलियन डॉलर का उद्योग** बन गया है और **भारत की लगभग 8% कार्यशील आबादी** को रोजगार देता है।
पर्यटन क्षेत्रक	• वर्ष 2023 में **18.89 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों** का आगमन हुआ था। • वर्ष 2023 के दौरान **9.52 मिलियन विदेशी पर्यटकों** का आगमन हुआ था। • वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन के मामले में **24वां स्थान।** (संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन बैरोमीटर)। • विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित **यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में 39वां स्थान।**
बीमा क्षेत्रक	• विश्व स्तर पर **10वां सबसे बड़ा बीमा क्षेत्रक।** • जीवन बीमा सेगमेंट: **>76% हिस्सेदारी।** • **संभावना:** 2032 तक **छठा सबसे बड़ा** बीमा बाज़ार। (स्विस री रिपोर्ट) • **बीमा पैठ: > 3.7% (2023-24),** (वैश्विक औसत: 7%). • **बीमा घनत्व: 95 डॉलर (2023-24),** (वैश्विक औसत: $874).
अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था	• **वैश्विक स्तर पर भारत 5वें स्थान पर है।** • **वृद्धि की संभावना:** 2033 तक 44 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। • **निजी क्षेत्रक:** >200 अंतरिक्ष-आधारित स्टार्ट-अप्स।
अवसंरचना	
सड़क सुरक्षा	• **WHO की सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023** के अनुसार, 2010 से 2021 के बीच भारत में सड़क हादसों से होने वाली मौतों में **15% की वृद्धि** हुई है। • केवल 2024 में ही, भारत में **1.8 लाख लोगों** की जान सड़क दुर्घटनाओं में चली गई थी। • **इन दुर्घटनाओं में 66% पीड़ित** 18 से 34 वर्ष के युवा थे। • **राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति (2010):** यह जागरूकता अभियान, प्रवर्तन और सुरक्षित सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देती है।
खनन एवं अन्य संसाधन	
कोयला क्षेत्रक	• भारत के पास दुनिया का **5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार** है। • भारत दुनिया का **दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता और आयातक** देश है। • 2023 में, भारत की कुल बिजली का **50.7% से अधिक उत्पादन कोयला और लिग्नाइट** पर आधारित था।
इस्पात क्षेत्रक	• **उत्पादन लक्ष्य:** 2034 तक 500 मिलियन टन। • **आर्थिक योगदान:** GDP का लगभग 2% तक। • **रोजगार के अवसर:** रोजगार गुणक प्रभाव **6.8X** और आउटपुट गुणक प्रभाव **1.4X तक।**
नवाचार एवं उद्यमशीलता	
डीप टेक	• **डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम:** भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) के अनुमान के अनुसार, वर्तमान में भारत में **4,000 से अधिक डीप टेक स्टार्टअप्स** कार्यरत हैं तथा अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या **10,000** तक पहुंच जाएगी।

© Vision IAS

	• **विश्व में भारत की स्थिति:** डीप टेक स्टार्टअप्स की तीसरी सर्वाधिक संख्या होने के बावजूद, भारत 2023 में **दुनिया के शीर्ष 9 डीप-टेक इकोसिस्टम में छठे स्थान पर था।** (नैसकॉम) • भारत के 4,000 डीप-टेक स्टार्टअप्स ने 2024 में 1.6 बिलियन डॉलर आकर्षित किए, जो पिछले साल की तुलना में 78 प्रतिशत की वृद्धि है। (नैसकॉम)
वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2024 और सामाजिक उद्यमिता	• **भारत विश्व की 133 अर्थव्यवस्थाओं में 39वें स्थान पर** है। 2023 में भारत 40वें स्थान पर था। • ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट, रचनात्मक आउटपुट, संस्थान और व्यावसायिक आधुनिकता के मामले में भारत **निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं** तथा **मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहले स्थान पर** है। • बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के शीर्ष 100 क्लस्टर्स** में शामिल हैं। • **भारत में सामाजिक उद्यमों के लिए अनुमानित बाजार अवसर और क्षमता 2025 तक 8 बिलियन डॉलर** होने की संभावना है।
वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC)	• **25% से भी कम** बिजनेस लीडर्स अपने GCC परिचालन को भारत से स्थानांतरित करने पर विचार कर रहे हैं। (PwC की रिपोर्ट) • भारत में **1,700 से अधिक** वैश्विक क्षमता केंद्र (GCCs) हैं, जो **वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक संख्या है।** • **2030 तक** GCC क्षेत्रक का आकार 105 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की संभावना है।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स

2026 प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली

15 जुलाई, 2 PM

अवधि – 12 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए **QR कोड** को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए **QR** कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल **टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए**

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधिः 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधिः 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोटः अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन
अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित
विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन
इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़
प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें
प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी
अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates
10
in TOP 10 Selections in CSE 2024
from various programs of Vision IAS
1 AIR
Shakti Dubey
2 AIR
Harshita Goyal
GS Foundation Classroom Student
3 AIR
Dongre Archit Parag
GS Foundation Classroom Student
4 AIR
Shah Margi Chirag
5 AIR
Aakash Garg
6 AIR
Komal Punia
7 AIR
Aayushi Bansal
8 AIR
Raj Krishna Jha
9 AIR
Aditya Vikram Agarwal
10 AIR
Mayank Tripathi
हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में
137 AIR
Ankita Kanti
182 AIR
Ravi Raaz
438 AIR
Mamata
448 AIR
Sukh Ram
509 AIR
Amit Kumar Yadav
DELHI
HEAD OFFICE
33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005
MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar
GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009
FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call: +91 8468022022, +91 9019066066
enquiry@visionias.in
/@visioniashindi
/visionias.upsc
/vision_ias_hindi/
/hindi_visionias
अहमदाबाद
बेंगलूरु
भोपाल
चंडीगढ
दिल्ली
गुवाहाटी
हैदराबाद
जयपुर
जोधपुर
लखनऊ
प्रयागराज
पुणे
रांची